खण्ड–483, अंक–4
बुधवार, 01 फाल्गुन, शक संवत् 1934
(20 फरवरी, 2013 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2013)

(खण्ड 483 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-8
-नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (जारी)...	9
- प्रश्नोत्तर (जारी)	9
- नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग ...	9-11
- प्रश्नोत्तर	12-80
-अतारांकित प्रश्न संख्या-65 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	80-81
-प्रश्नों के वार निर्धारण के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	81
-विधान सभा के पूर्व सदस्यों सर्व श्री धनीराम वर्मा (पूर्व अध्यक्ष विधान सभा), श्री रामबाबू मिश्र, श्री ख्याली राम शास्त्री, श्री शिवलाल मित्तल, श्री नित्यानन्द स्वामी, श्री बृजलाल, श्री राम दयाल, श्री मुन्शी लाल, श्री जगदम्बा सिंह, श्री राम हर्ष मिश्र, श्री सईदुल हसन, श्री किशोरी लाल यादव, श्री मान सिंह आजाद, श्री प्रभु दयाल प्रधान तथा श्री श्याम बिहारी सिंह के निधन पर शोकोद्‌गार	82-89
- नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ	89-91
-जनपद लखनऊ की बादशाहनगर कालोनी में स्थित एल टाइप पार्क में हो रहे आवासीय निर्माण को तत्काल रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	91-92
- जनपद मिर्जापुर की कतिपय अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	92
- जनपद कुशीनगर के पड़रौना स्थित तहसील मुख्यालय तमकुहीराज को सीधा जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	92-93

विषय	पृष्ठ-संख्या
- जनपद सोनभद्र की दुद्धी विधान सभा के अन्तर्गत राजस्व विभाग की मिलीभगत से गरीब व्यक्तियों की जमीनों पर दबंगों द्वारा कब्जा किये जाने तथा सर्वे कराकर पैमाइश कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	93
- जनपद कौशाम्बी में व्याप्त पेयजल संकट को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	93-94
- जनपद मेरठ के प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों का कर्ज माफ किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	94
- जनपद सीतापुर के 12 विकास खण्डों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	94-95
- जनपद बलिया के सिकन्दरपुर अन्तर्गत घाघरा नदी के पीपे के पुल को तत्काल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	95
- जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त जू0 हाई स्कूल में कार्यरत कर्मियों को मकान किराया भत्ता की सुविधा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	95-96
- जनपद आगरा के क्षेत्र खैरागढ़ में जगनेर से बसेड़ी राजस्थान जाने वाले मार्ग की जर्जर हालत होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96
- जनपद चन्दौली अन्तर्गत मुगलसराय के शहरी क्षेत्र में सीवर की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96
- जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना में इरादतगंज हवाई पट्टी मार्ग एवं उस पर निर्मित पुलिया की जर्जर हालत होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	97

विषय	पृष्ठ-संख्या
- विधान सभा क्षेत्र बछरावां रायबरेली के अन्तर्गत कतिपय ड्रेनों की खुदाई एवं पटरी सड़कों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	97
- जनपद आजमगढ़ के तहबरपुर ब्लाक के खास बेगपुर इंटर कालेज के समीप सहलनी नदी पर बने पुराने पुल के ध्वस्त होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	97-98
- जनपद कुशीनगर और गोरखपुर के बीच कप्तानगंज से पिपराइच मार्ग को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	98
-नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग ...	98-99
- जनपद शाहजहाँपुर में वित्तीय वर्ष 2012-2013 की जिला योजना समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के अनुसार शासन द्वारा धन अवमुक्त न किये जाने से उत्पन्न स्थिति सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	99-100
-कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	100-103
-कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ	103-115
- श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	115-190
-नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ	190-194
- जनपद फैजाबाद के समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों में वृद्धा पेंशन, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन व चयनित शादी अनुदान के पात्रों को लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य	194-195
- नोएडा में डिप्टी डायरेक्टर (फैक्ट्रीज) के विरुद्ध जांच कराये जाने एवं उनका स्थानान्तरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	195-196
-नत्थियाँ	197-203

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक, 20 फरवरी, 2013

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-328

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय, मिश्र 'टेनी', श्री — लखीमपुरखीरी
4. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
5. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
6. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
7. अजीमुल हक पहलवान, श्री — अम्बेडकर नगर
   अंसारी, हाजी श्री
8. अताउररहमान, श्री — बरेली
9. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
10. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
11. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
12. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
13. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
14. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
15. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
16. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
17. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
18. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
19. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
20. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
21. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
22. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
23. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
24. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
25. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
26. अरूण कुमार कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
27. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
28. अली यूसुफ अली, श्री — रामपुर
29. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
30. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
31. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
32. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूल नगर
33. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
34. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
35. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
36. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
37. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
38. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
39. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराजनगर
40. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
41. आशीष यादव, श्री — बदायूं
42. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू,श्री — बदायूं

43. इकबाल, श्री बिजनौर
44. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
45. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
46. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
47. इन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
48. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
49. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
50. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
51. उदयराज, श्री उन्नाव
52. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
53. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
54. ओम कुमार, श्री बिजनौर
55. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
56. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
57. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
58. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
59. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
60. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
61. काली चरन सुमन, श्री आगरा
62. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
63. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
64. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
65. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
66. केशव प्रसाद, श्री कौशाम्बी
67. कैलाश, श्री गाजीपुर
68. कैलाश नाथ चौरसिया, श्री मिर्जापुर
69. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
70. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
71. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
72. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराजनगर
73. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
74. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
75. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
76. गुलाम मोहम्मद, श्री मेरठ
77. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
78. गोमती यादव, श्री लखनऊ
79. गोरख पासवान, श्री बलिया
80. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
81. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
82. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
83. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
84. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
85. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
86. जगपाल, श्री सहारनपुर
87. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
88. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
89. जफर आलम, श्री अलीगढ़
90. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
91. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
92. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
93. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
94. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
95. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
96. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर(भदोही)
97. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
बस्ती
98. तसलीम, श्री बिजनौर
99. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
100. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन

101. दलजीत सिंह, श्री बांदा
102. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
103. दिलवाज खान, श्री बुलन्दशहर
104. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
105. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
106. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
107. देवनरायन उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री महराजगंज
108. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
109. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
110. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
111. धर्मराज, श्री बाराबंकी
112. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
113. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशीलनगर
114. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
115. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
116. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
117. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
118. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
119. नारद राय, श्री बलिया
120. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
121. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
122. नीरज (कुशवाहा) मौर्य,श्री शाहजहांपुर
123. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
124. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
125. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
126. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
127. पीतमराम, श्री पीलीभीत
128. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
129. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
130. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
131. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
132. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
133. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
134. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
135. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
136. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
137. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
138. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
139. ''फसीहा मंजर'' ''(गजाला लारी)'', सुश्री देवरिया
140. फेरन लाल, श्री ललितपुर
141. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
142. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
143. बदलू खां, श्री उन्नाव
144. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
145. बाबू खां, श्री हरदोई
146. बाबूलाल, श्री गोण्डा
147. बावन सिंह, श्री गोण्डा
148. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
149. बृज लाल सोनकर, श्री आजगगढ़
150. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
151. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
152. बेचई सरोज, श्री आजगगढ़
153. बैजनाथ, श्री मऊ
154. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
155. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
156. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
157. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
158. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
159. भीम प्रसाद सोनकर,श्री अम्बेडकरनगर
160. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर

161. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
162. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
163. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर(भदोही)
164. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
165. मनीष रावत, श्री सीतापुर
166. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
167. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
168. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
169. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
170. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
171. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
172. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
173. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0 नगर
174. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
175. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
176. मानपाल सिंह, श्री काशीरामनगर
177. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
176. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
177. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
178. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
179. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
180. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
181. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
182. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
183. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
184. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
185. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
186. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
187. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
188. मो0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
189. यासर शाह, श्री बहराइच
190. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
191. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
192. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
193. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
194. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
195. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
196. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
197. रणजीत सुमन, श्री एटा
198. रमेश चन्द्र, श्री मिर्जापुर
199. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
200. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
201. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
202. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
203. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
204. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
205. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
206. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
207. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
208. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
209. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
210. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी

211. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
212. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
213. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
214. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
215. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
216. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
217. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
218. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
219. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
220. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
221. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
222. राधे श्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
223. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
224. राम करन आर्य, श्री बस्ती
225. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
226. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
227. राम गोविन्द, श्री बलिया
228. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
229. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
230. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
231. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
232. राम मगन, श्री बाराबंकी
233. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
234. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
235. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
236. रामवीर उपाध्याय, श्री महामायानगर
237. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
238. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
239. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
240. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
241. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
242. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
243. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
244. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
245. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
246. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
247. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीरनगर
248. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
249. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
250. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
251. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
252. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
253. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
254. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
255. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
256. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
257. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
258. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
259. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
260. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
261. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
262. विजय सिंह, श्री रामपुर
263. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रूखाबाद
264. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
265. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
266. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा

267. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
268. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
269. वीरपाल राठी, श्री बागपत
270. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
271. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
272. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्धनगर
273. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
274. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
275. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
276. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
277. शाकिर अली, श्री देवरिया
278. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
279. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
280. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
281. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
282. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
283. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
284. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
285. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
286. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
287. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
288. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
289. संजय कपूर, श्री रामपुर
290. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
291. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
292. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
293. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
294. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
295. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
296. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
297. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
298. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
299. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
300. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
301. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
302. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
303. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
304. सियाराम सागर, डा0 बरेली
305. सीमा, श्रीमती जौनपुर
306. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
307. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
308. सुदामा प्रसाद, श्री महाराजगंज
309. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
310. सुधाकर, श्री मऊ
311. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
312. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
313. सुब्बाराम, श्री गाजीपुर
314. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
315. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
316. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
317. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
318. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
319. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
320. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
321. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी

322. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर	325. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
323. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी	326. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
324. हरिओम यादव, श्री फिरोजाबाद	327. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत
	*328-रिक्त इलाहाबाद

नोट :-राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन) तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (श्री राम सकल गूजर) भी सदन में उपस्थित थे।

नियम-311 की सूचना को सर्व प्रथम लिये जाने की मांग

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले मुझे सुन लीजिए।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, आप बैठ जाइये, आपकी कोई चीज लिखी नही जायेगी आप बोलते रहिये। न आपका कुछ लिखा जायेगा न कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1

नियम 311 की सूचना को सर्व प्रथम लिये जाने की मांग (क्रमागत)

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री मुकेश श्रीवास्तव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी मेरी नोटिस है, मुझे बोलने दें।

श्री अध्यक्ष-

जब वह सभी दलों ने दिया है, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, बहुजन समाज पार्टी ने दिया है, आपने 311 में दिया है आपसे कहा कि जब वह बोलेंगे तो आप भी बोल लीजिएगा। अब क्या आप आफत मचाये हुए हैं ?

नहीं, कुछ नहीं लिखा जायेगा और न कार्यवाही का अंग माना जायेगा। बैठिये, आप नेता हैं आप वहां यह बात करते हैं और बाहर यह बात करते हैं। (घोर व्यवधान)

यह सभी दलों ने दिया है, आपने भी दिया है। जब सब बोलेंगे तो आप भी बोल लीजिएगा नियम 56 में, बैठिये।

मैं जब कह रहा हूँ कि यह नियम 56 में है सबका है तो आपका भी है।

(कांग्रेस के सदस्यों द्वारा वेल की तरफ बढ़ने पर)

अगर आप वेल में आते हैं तो आज कार्यवाही होगी, मैं मानने वाला नहीं हूँ। यह कौन सा तरीका है?

(कांग्रेस के कुछ सदस्य सदन के वेल में आकर बैठ गये)

(घोर व्यवधान के मध्य)

आप कार्य-मंत्रणा समिति में थे। तब यह तय हुआ था कि नियम-311 नहीं लिया जायेगा, मौर्या जी हैं, अब आप नियम-311 दे रहे हैं, नियम-56 में जब सब का लिया जायेगा तो आपका भी लिया जायेगा। फिर किसलिए यह सब कर रहे हैं, यह किस लिए कर रहे हैं।

माननीय सदस्यगण, वापस जाइये। यह अच्छी बात नहीं है कि अन्दर दूसरी बात करों और बाहर दूसरी बात करो आप चलिये बैठे रहिये, हम भी बैठे हैं। मैं। प्रश्न ले रहा हूँ।

(श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेद्र प्रताप का नाम पुकारे जाने पर)

नहीं हैं, चलिये बैठे रहिये।

क्या बात करें साहब, मैंने इन लोगों को समझाया अब इनकी मांग है कि यह अभी बोलेंगे तो मैंने पुकारा है जब नियम-56 आयेगा तब बोलियेगा। यह तो खाली लीड लेने के चक्कर में हैं कि मैं पहले आ जाऊँ।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मेरा 311 लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग जायें जब आपकी बात न मानी जाय तो आप कुछ करते। आपने दिया है अब 311 क्या लिया जाय, नहीं माना जायेगा।

माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी आप और ये नेता हैं, कुम्भ पर यह बोल चुके हैं नियम यह है कि जो एक बार चर्चा हो जाय उस पर नहीं बोला जाता। यह नहीं चलेगा जबरदस्ती आज।

मैंने आपसे कह दिया कि जब आपने दिया 311 में नेता विरोधी दल ने दिया 56 में, नेता भारतीय जनता पार्टी ने दिया 56 में, आपसे मैंने कहा कि 311 नहीं लिया जायेगा लेकिन फिर भी जब यह लोग बोलेंगे तब आप भी बोलेंगे। जो उसमें नियम होगा उसके अन्तर्गत आपको भी वही सुविधा मिलेगी तो अलग से यह करने की क्या जरूरत पड़ गयी?

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मुझे सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

जब आपने दिया 311 में नेता विरोधी दल ने दिया 56 में, नेता भाजपा ने दिया 56 में, मैंने कहा कि 311 में लेकिन जब यह लोग बोलेंगे तब आप भी बोलेंगे। जो उसमें नियम होगा उसके अन्तर्गत आपको भी सुविधा मिलेगी तो अलग से यह करने की क्या जरूरत पड़ गयी ?

(श्री प्रदीप माथुर द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

आप बोलते रहिये, यह कोई कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा, यह कार्यवाही का अंग नहीं माना जायेगा, न लिखा जायेगा।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष-

जब गम्भीर मामला है तो यह लोग गम्भीर नहीं हैं क्या, नेता विरोधी दल नहीं हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी नहीं है, सब बैठे हैं सब बोलेंगे अपनी बात कहेंगे, आप भी बोलियेगा। यह अलग से क्या बोलने लगे।

(श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

देखिये महाना जी, मैंने इनको समझा दिया, चैम्बर में भी बता दिया, चेम्बर में बात हो गयी कि जब सब लोग बोलेंगे तो आपको भी मौका मिलेगा और यह तय हुआ है कि नियम 56 में आप उसकी ग्राहयता पर एक मिनट दो मिनट बोल देंगे इसके बाद उसका जो निर्धारण होगा वक्तव्य होगा या चर्चा होगी उसका टाइम फिक्स हो जायेगा उसमें आप बोलियेगा। अब यह जो है, यह पता नहीं क्या इनका आ गया है। चलिये आप बैठे रहिये।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुर्नवास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो निर्देश दिया है मैं भी निवेदन करूँगा माननीय नेता कांग्रेस से कि जब आपने स्पष्ट निर्देश दे दिया कि जो नोटिस उन्होंने दी है उस पर उनको सुना जायेगा, उनका क्रम जो आप तय करेंगे वह बात मान ली जायेगी तो मेरा अनुरोध है उनसे कि वह अपने माननीय सदस्यगण को वेल से कृपापूर्वक वापस ले जायें।

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध भी कर लिया है, निर्देश भी दे दिया है, उसका सम्मान होना चाहिये। उन्होंने जब कह दिया है कि सुनेंगे तो मेरा पुनः माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप लोग चलें और समयुक्त ढंग से कार्यवाही चले। बड़ी कृपा होगी।

(तत्पश्चात् वेल में आये हुए माननीय सदस्यगण अपने स्थानों पर चले गये)

श्री हुकुम सिंह-

इन्होंने ही बुलाया था इनको, इनके कहने पर ही गये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं आभारी हूँ।

(श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेद्र प्रताप के खड़ें होने पर)

श्री अध्यक्ष-

पहले प्रश्न का समय खत्म हो गया, अब नहीं लिया जायेगा।

प्रदेश में बढ़ते एड्स तथा एच0आई0वी0 जनित रोगों को रोकने की योजना

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेद्र प्रताप-

**1-क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते एड्स तथा एच0आई0वी0 जनित रोगों को रोकने के लिये सरकार ने कोई कारगर योजना बनायी है यदि हां तो उसका विवरण क्या हैं यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

जी हाँ।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन 'नाको' भारत सरकार द्वारा एच0आई0वी0/एड्स की रोकथाम के लिये विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहें हैं। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी की स्थापना की गयी है जो 'नाको' द्वारा वित्त पोषित है तथा उसके दिशा निर्देशों पर कार्य करती है।

राज्य सरकार उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के माध्यम से एच0आई0वी0/एड्स की रोकथाम एवं एच0आई0वी0/एड्स संक्रमित व्यक्तियों (एड्स) हेतु सुविधाओं की उपलब्धता के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित है:-

प्रदेश में एच0आई0वी0 धनात्मक/एड्स मरीजों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराने हेतु 22 ए0आर0टी0 (एन्टी रिट्रोवायरल थेरेपी) केन्दों की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों पर एड्स रोगियों को निःशुल्क जांचें तथा ए0आर0वी0 दवाईयां उपलब्ध कराई जा रही हैं एवं अक्सरवादी संक्रमण के उपचार की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

प्रदेश में एड्स रोगियों को उनके निवास के निकट ए0आ0टी0 का उपचार प्रदान करने के उद्देश्य 35 जनपदों के जिला अस्पतालों में लिंक ए0आ0टी0/लिंक ए0आ0टी0 प्लस केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

एच0आई0वी0/एड्स संक्रमित व्यक्तियों की देखभाल एवं उन्हें सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 11 कम्यूनिटी केयर सेन्टर कार्यरत हैं।

पी0एल0एच0ए0 नेटवर्क (पिपुल लिविंग विथ एच0आई0वी0/एड्स) द्वारा एच0आई0वी0/एड्स संक्रमित व्यक्तियों की क्षमता वृद्धि व गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 07 ड्राप इन सेन्टर कार्यरत हैं। एच0आई0वी0/एड्स की परामर्श तथा निःशुल्क जाँच की सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रदेश के चिकित्सालयों में 264 आई0सी0टी0सी0 (एकीकृत परामर्श एवं जाँच केन्द्र) केन्दों की स्थापना की गयी है। इन केन्दों पर एच0आई0वी0 परामर्श एवं जांच, सन्दर्भन की सुविधा एवं धनात्मक गर्भवती स्त्रियों से नवजात शिशु को होने

वाले एच0आई0वी0 संक्रमण को रोकने के लिए उपचार की विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत माता एवं शिशु को निःशुल्क एन्टीरिट्रोवायरल औषधि की व्यवस्था है।

यौन रोगियों में एच0आई0वी0/एड्स होने की सम्भावना अधिक होती है। अतः यौन रोगों के उपचार हेतु प्रदेश में 96 एस0टी0आई0 (यौन जनित संक्रमण) क्लिनीक स्थापित है।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में स्वीकृत विद्युत परियोजनाएं तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलम्ब के कारण

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

*01-क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश कुल कितनी विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत हैं तथा निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण है ? क्या सरकार इन्हें शीघ्र पूरा करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण, सहकारिता, भूमि विकास, जल संसाधन तथा परती भूमि विकास मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

01-प्रदेश में कुल 31 नग विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत हैं। निगम वार विवरण इस प्रकार है-

1- उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम	07 नग
2- उ0प्र0 जल विद्युत निगम	10 नग
3- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0	10 नग
	31 नग

निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलम्ब के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :-

1- भूमि का अधिग्रहण।

2- पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र।

3- वित्तीय संस्थानों से वित्तीय प्रबन्ध।

4- दीर्घ कालीन कोल लिंकेज।

5- अन्य व्यवहारिक कठिनाईयों तथा अप्रत्याशित घटनायें।

उपर्युक्त परियोजनाओं को पूर्ण कराने हेतु सरकार द्वारा वांछित सहयोग दिया जायेगा। प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ कि तारांकित प्रश्न पर आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि प्रदेश में कुल 31 नग विद्युत परियोजनायें स्वीकृत हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इन स्वीकृत परियोजनाओं को कब स्वीकृत किया गया था और इनको कब तक पूरा किया जाना था तथा इन परियोजनाओं की लागत क्या है?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अभी बता दिया है कि कुल मिलाकर 31 नग परियोजनायें निगम के द्वारा स्वीकृत हैं और यह परियोजनायें पारीछा तापीय विस्तार 500 मेगावाट की प्रथम इकाई (इकाई संख्या-05) 17 जुलाई, 2012 से वाणिज्यिक भार पर उत्पादनरत, द्वितीय इकाई संख्या-6 250 मेगावाट की छठी इकाई अस्थायी चिमनी के द्वारा दिनांक 28-4-2012 को लाइटअप की गयी तथा 17-09-2012 को सिंकोनाइज की गयी तथा दिनांक 30-9-2012 को जनरेटर ट्रांसफारमर के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इस इकाई को वाणिज्यिक भार पर लिये जाने का कार्य विलम्बित हुआ है। अब इस ईकाई को 15 मार्च, 2013 तक वाणिज्यिक भार पर लिया जाना संभावित है।

हरदुआगंज तापीय विस्तार 500 मेगावाट प्रथम इकाई संख्या-8 दिनांक 1-2-2012 से वाणिज्यिक भार पर तथा द्वितीय इकाई संख्या-9 दिनांक 2-4-2012 को ग्रिड से सिंकोनाइज की गयी थी एवं दिनांक 25-05-2012 को इकाई से फुल लोड प्राप्त कर लिया गया था। दिनांक 8-10-2012 को मेसर्स बीएचईएल द्वारा निर्मित कुछ ईएसपी हापर्स क्षतिग्रस्त हो गये थे जिसके पुनर्निर्माण के पश्चात इकाई के दिनांक 30-6-2013 तक वाणिज्यिक भार पर आना संभावित है।

अनपरा-डी तापीय विस्तार 1000 मेगावाट परियोजना के बी0टी0जी0 ऐश हेन्डलिंग चिमनी व कुछ बीओपी (बैलेन्स आफ प्लान्ट) का कार्य मेसर्स बीएचईएल द्वारा कराया जा रहा है। परियोजना के प्रथम इकाई के ब्वायलर का हाइड्रोटेस्ट मेसर्स बीएचईएल द्वारा आंतरिक रूप से दिनांक 29-10-2012 को पूरा कर लिया गया है।

परियोजना पर हो रही देरी का मुख्य कारण बी0एच0ई0एल0 द्वारा सिविल कार्यों में अत्यधिक देरी, मेन पॉवर रिसोर्सेज की कमी एवं कार्य की धीमी गति है। 275 मीटर चिमनी अभी तक 38.10 मीटर की ऊँचाई तक बनी है। यह कार्य दिनांक 17-09-2012 में रुका हुआ है। कंकरीटिंग प्रारम्भ करने हेतु जाँच पूरी कर ली गयी है एवं कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त जिला सोनभद्र में खनन बंद होने के कारण गिट्टी की कमी से भी निर्माण कार्य प्रभावित रहा है। जनवरी, 2013 के प्रथम सप्ताह से

गिट्टी की आपूर्ति शुरू हो गई है। अनपरा-डी तापीय परियोजना के लिए मेसर्स बी0एच0ई0एल0 द्वारा उक्त इकाइयों को सिन्कोनाइजेशन की तिथियाँ कई बार बदली गई हैं। इस परियोजना की प्रथम इकाई सं0-6 15 नवम्बर, 2013 में तथा द्वितीय इकाई सं0-7, 15 फरवरी, 2014 तक सिन्कोनाइजेशन किया जाना लक्षित है। हरदुआगंज तापीय विस्तार स्टेज-2 660 मेगावाट, परियोजना को राज्य क्षेत्र में स्थापित करने का अनुमोदन उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हो गया है। परियोजना हेतु जल की उपलब्धता एवं चिमनी की ऊँचाई हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है। परियोजना हेतु तकनीकी सलाहाकार की नियुक्ति कर ली गई है। मेसर्स पी0एफ0सी0 द्वारा वित्त पोषण प्राप्त कर लिया गया है, कोयले की स्वीकृति उपलब्ध न होने के कारण एम0ओ0ई0एफ0 (पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार) से फाइनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। ओबरा-सी तापीय विस्तार 1320 मेगावाट, 2 660 मेगावाट सुपर कीटिकल इकाई ओबरा परियोजना क्षेत्र से ही स्थापित किये जाने का अनुमोदन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर दिया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु इनवायरमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट का अध्ययन पूरा कर लिया गया है जिसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में दिनांक 28-09-2012 को जमा कर दिया गया है। दिनाँक 05-11-2012 को पर्यावरण की एक्सपर्ट एप्रेजल कमेटी के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया जिसका कार्यवृत्त 10-12-2012 को प्राप्त हुआ है। तद्नुसार रिवाइज ई0आई0ए0 रिपोर्ट के आधार पर पब्लिक हियरिंग कराने हेतु एक्सपर्ट एप्रेजल कमेटी के समक्ष पुनः प्रस्तुतीकरण कर पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। मेजा तापीय योजना 1320 मेगावाट, इस परियोजना में अंश पूँजी एवं कण का अनुपात क्रमशः 30:70 का है तथा एन0टी0पी0सी0 एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की अंश पूंजी का अनुपात 50:50 है। परियोजना से उत्पादित ऊर्जा का 75 प्रतिशत उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा। परियोजना की जीरो तिथि मई, 2012, प्रथम इकाई वाणिज्यिक भार पर आने की तिथि सितम्बर, 2016 प्रस्तावित है, द्वितीय इकाई वाणिज्यिक भार पर आने की तिथि मार्च, 2017 प्रस्तावित है।

(माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आपका सवाल है कि कौन इकाई कब पूरी होगी, तो मा0 मंत्री जी सभी का पढ़ कर बता रहे हैं कि कौन सी इकाई कब पूरी होगी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

परियोजना पर लेवलिंग ड्रेसिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। चिमनी एवं ब्यालर फाउन्डेशन का सिविल कार्य प्रगति पर है। कोल लिंकेज के सम्बन्ध में सैद्धान्तिम किलयरेंस

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 09-03-2010 को साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, छत्तीसगढ़ द्वारा 5.59 एम0टी0पी0ए0 कोल आपूर्ति हेतु लेटर ऑफ एश्योरेस निर्गत किया गया है।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

माननीय अध्यक्ष जी, अब प्रश्न का उत्तर आ गया । अब अनुपूरक पूछने का अवसर दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आपका सवाल था कि ये परियोजनाएं कब तक पूरी होंगी। माननीय मंत्री जी उसी का उत्तर पढ़ रहे हैं। 31 परियोजनाओं के बारे में पूछा गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, 12.20 इसी में हो जाएंगे। आगे हमारा भी सवाल है।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्ध मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने 31 परियोजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से पूछा है कि किसमें कितना विलम्ब हुआ है और क्यों हुआ? विस्तृत विवरण पूछा है और विस्तृत विवरण सरकार के पास है वह सूचना मंत्री जी दे रहे हैं। अगर मा0 सदस्य और दूसरे लोग संतुष्ट हो गये हों तो अगला प्रश्न लीजिए।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, एक छोटी सी जानकारी चाहता हूँ।

(श्री रामवीर उपाध्याय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

श्रीवास्तव जी बैठ जाइये। मा0 उपाध्याय जी, पूर्व बिजली मंत्री जी खड़े हैं, उनको पूछ लेने दीजिए।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक परियोजना है उसके बारे में झूठी सूचना दी गयी है। यह वेस्टर्न यू0पी0 का महत्वपूर्ण बिजलीघर है। कृपया मुझे बोलने का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

अगर झूठी सूचना है तो इसके लिए नियमों में प्राविधान है, उसमें सूचना दीजिए, यहाँ कहने की क्या जरूरत है इसके लिए नियमों में अलग प्राविधान है। कृपया बैठ जाइये।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, एक चीज पूछना चाहता हूँ, मंत्री जी ने विलम्ब के पाँच कारण बताये हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप एक बार पूछ चुके, क्या बार-बार पूछेंगे ? इनको पूछ लेने दीजिए, यह भी विद्युत मंत्री रहे हैं इनको पूछने दीजिए। जब अनुमति दी जाती है तब पूछा जाता है। एक अनुपूरक पूछा उसका जवाब आ गया, दोबारा अनुपूरक पूछ लिया, अब दूसरे सदस्यों को मौका दीजिए। उपाध्याय जी खड़े हैं, इनको पूछने दीजिए। माननीय नेता लोक दल, आप बैठ जाइये।

श्री दलवीर सिंह-

अध्यक्ष जी मेरी विधान सभा क्षेत्र की इकाई है, मुझे बोलने का मौका दीजिए।

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो 31 परियोजनाऐं हैं यह हमारी सरकार में सारी स्वीकृत की गयी थी। 15 मार्च 2012 के बाद अगर कोई नई परियोजना शुरू की हो तो उसका नाम माननीय ऊर्जा मंत्री जी बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

उपाध्याय जी, यह प्रश्न से संबंधित नहीं है। प्रश्न यह था कि कितनी परियोजनाएं हैं और निर्माणाधीन परियोजानाओं के पूरा होने में विलम्ब के कारण क्या हैं ? वह बता दिया। यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

ये सारी परियोजाए हमारे सरकार के कार्यकाल की है।

कुवँर भारतेन्द्र-

मान्यवर बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर क्यों सदन का समय व्यर्थ किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठिये। माननीय मंत्री जी, उपाध्याय जी का कहना है कि जब वह विद्युत मंत्री थे तो ये 31 परियोजनायें स्वीकृत हुई थी । इनका कहना है कि 15 मार्च, 2012 के बाद आपकी सरकार बनी, तब से कोई नई परियोजना स्वीकृत हुई, हालाँकि यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न से संबंधित नहीं है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ। मा0 रामवीर उपाध्याय जी विद्युत मंत्री रहे हैं, मै उनसे पूछना चाहता हूँ, उनसे पहले हम भी

ऊर्जा मंत्री थे। हमने जितने एम0ओ0यू0 साइन किये थे, उन्हीं की इन्होंने पुन शरूआत कर दीं और उसके बावजूद भी, वैसे तो परियोजना 3 साल और 4 साल के अन्दर पूरी हो जानी चाहिए थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पाँच साल में कितनी योजनाओं को पूरा करा दिया था ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अध्यक्ष जी पाँच साल में इन्होंने एक भी परियोजना पूरी नहीं कराई जो परियोजनाएं मैंने शुरू कराई थी उनमें एक भी परियोजना पूरी नहीं हुई। अगर परियोजनाएं पूरी हो जाती तो 10 वर्ष में उत्तर प्रदेश में बिजली का कोई संकट नहीं होता । लगभग 12 हजार मेगावाट बिजली हम पैदा करने लगते।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस पर एक अनुपूरक प्रश्न कर लेने दें।

श्री अध्यक्ष-

अगला प्रश्न भी इसी तरह का है उस पर बाकी बाते आ जायेंगी।

नेता विरोधी दल(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न पूछा है तो माननीय रामवीर उपाध्याय जी उसका उत्तर देना चाहते हैं। श्री रामवीर जी जो पहले ऊर्जा मंत्री थे वह उसका उत्तर देना चाहते हैं इसलिए उनकी बात सुन ली जाय। अगर उनका उत्तर नहीं आयेगा तो माननीय मंत्री जी के शंका का समाधान नहीं होगा। इसलिए उनका उत्तर आना जरूरी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी ने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का उत्तर दे दिया कि एक भी परियोजना उसमें से पूरी नहीं हो सकी। इसलिए यह कंप्लीट ऐंसर हो गया। अब अगला अनुपूरक होना चाहिए।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोरगुल)

श्री अध्यक्ष-

हम इस पर नियम 49 में चर्चा करा देंगे। आप लोग बैठ जाइये। आप लिखकर भेज दीजिए नियम 49 में सब आ जायेगा। आज लिखकर दे दीजिए कल आ जायेगा। उसमें सबकी शंका का समाधान हो जायेगा। उपाध्याय जी आप लिखकर भेज दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय मंत्री जी ने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आना चाहिए। इस तरह पूरे सदन को गुमराह किया जायेगा। और पीठ का संरक्षण नहीं मिलेगा तो पीठ पर उंगली उठेगी। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि माननीय रामवीर उपाध्याय की बात आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल तमाम प्रकार की शंकाएं इस प्रश्न पर उपस्थित की गई हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह नियम 49 में आ जायेगा तो आपको भी अपनी बात कहने का अवसर मिल जायेगा और सरकार को भी अपनी बात कहने का मौका मिल जायेगा। आप इसको दे दीजिए कल कल शाम को हम इस पर आधे घण्टे की चर्चा करा आप लिखकर भेजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, एक मिनट में उत्तर आ रहा है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी हरदुआगंज की ढाई-ढाई सौ मेगावाट की।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री यागेश प्रताप सिंह, योगेश 'भइया')-

माननीय अध्यक्ष जी जब इस पर नियम 49 के तहत चर्चा की बात आपने कह दी उसके बाद अब क्या रह गया ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

हरदुआगंज की दो यूनिट को पूरा करने का काम हमने किया। पारीक्षा में काम बहुत तेजी से चल रहा था एक यूनिट आ चुकी थी दूसरी भी आने वाली थी। अनपरा डी में हमने काम बहुत तेजी से शुरू कराया था। आनपरा सी हमने पूरी करके दिखायी। एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ इनसे।

श्री अध्यक्ष-

नियम 49 में आयेगा तब पूछ लीजियेगा।

प्रदेश में बढ़ती हुई विद्युत मांग को पूरा करने की योजना

श्री सतीश महाना, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) एवं श्री पूरन प्रकाश-

*02-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई विद्युत मांग को पुरा करने हेतु सरकार कोई तात्कालिक योजना बना रही है ? यदि हाँ उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

प्रदेश में विद्युत की औसत मांग 10500-12000 मे0वा0 के मध्य है, जिसके सापेक्ष विभिन्न स्त्रोतों से विद्युत की उपलब्धता 8500-9000 मे0वा0 के मध्य है। विद्युत की मांग की

पूर्ति हेतु निम्नांकित व्यवस्था की गयी है:-

1-बैंकिंग व्यवस्था के आधार पर:- अन्य राज्यों से उनकी विद्युत उपलब्धता (सरप्लस) पर आपसी सहमति से विद्युत प्राप्त करते है तथा उ0प्र0 में विद्युत की उपलब्धता को दृष्टिगत् रखते हुए उन्हें वापस करते हैं।

2-द्विपक्षीय व्यवस्था के आधार पर- निविदा के माध्यम से अल्पकालीन विद्युत क्रय की व्यवस्था की जाती है जिसके लिए उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग से अनुमति आवश्यक है। इस हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा याचिका दाखिल की जा चुकी है।

3-उपरोक्त विद्युत प्रबन्ध के उपरान्त भी यदि तत्समय आवश्यकता पड़ी तो इनर्जी एक्सचेन्जों से दैनिक ब्रिड करते हुए 'डे अहेड' विद्युत क्रय धन की उपलब्धता के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

प्रश्न नहीं उठता।

(प्रश्न संख्या-2 पुकार जाने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य- मान्यवर, इससे ऊर्जा के प्रति सरकार की उदासीनता अपने आप जाहिर हो रही है।

शोर।

श्री अध्यक्ष-

हो गया मौर्या जी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

11 महीने के समय में एक भी लम्बित परियोजना को यह चालू नहीं कर सके। पूरे प्रदेश में जो बिजली का संकट है जो, हाहाकार गया हुआ है यहां तक की ग्रामीण क्षेत्रों में 3-3 घण्टे बिजली मिल रही है, शहरी क्षेत्रों में 5-6 घण्टे बिजली मिल रही है, बिजली का अभाव है, इसलिए मान्यवर, जो सरकार बिजली पानी नहीं दे सकती है उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम और हमारा दल सदन का बहिगर्मन करते हैं।

(नेता विरोधी दल और बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यगण सदन का बहिर्गमन करके चले गये)

(राष्ट्रीय लोक दल के नेता श्री दलवीर सिंह व अन्य सदस्य सदन के वैल में आ गये)

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, मेरे क्षेत्र का सवाल है, मेरी बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

देखिये माननीय नेता लोकदल सुनिये तो। जब उस पे हमने कहा नियम-49 में आ जायेगा पूरी बात आपकी आ जायेगी तो आप उसको नियम-49 में भेज दीजिए हो जाएगी पूरी बात। चलिये, बैठिये, आप बुजुर्ग हैं। चलिये अपनी सीट पर चलिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

चलिये अपने स्थान पर चलिये।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शोर न करें। आप लोग शान्त रहें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज जिस समय सर्दियों का टाइम है उस समय उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं है। यह बहुत गम्भीर बात थी और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने के बाद इस हाउस में जो सीन था मान्यवर, वह अच्छा नहीं था। मान्यवर, अगर किसी ने कुछ किया होता तो यह प्रश्न लगाने की आवश्यकता नहीं थी। चाहे उधर हो चाहे इधर। मैंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया था। मैंने पूछा था कि क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगें कि प्रदेश में बढ़ती हुई विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए सरकार कोई तात्कालिक योजना बना रही है ? मान्यवर, अभी इसके सम्बन्ध में पहला प्रश्न यह आया जिसमें माननीय मंत्री जी ने 31 योजनाएँ बताई। इस 31 योजना में से एक भी ऐसी योजना नहीं है जो समय से चल रही है, को समय से पूरी हो सके। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता था आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, आपने समय नहीं दिया। मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ इतना लम्बे प्रोजेक्ट्स में से कौन कौन कहाँ अटकी है और 1-2 बताते कि पूरी हो चुकी है तो भी मान्यवर सन्तुष्टि की बात थी जो उत्तर आया है मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उस पर एक निगाह डालें। मान्यवर, 8500-9000 मेंगावाट है और लगभग 12000 मेगावाट चाहिए। तीन हजार मेगावाट कम है, जवाब देते है कि बैंकिग व्यवस्था के आधार पर अन्य राज्यो से उनकी विद्युत उपलब्धता अगर सरप्लस है तो आपसी सहमति से विद्युत प्राप्त करते है। फिर उ0प्र0 मे विद्युत की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें वापस करते है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा सौभाग्य कभी आया कि आपके पास सरप्लस हो और आप उसे वापस कर सके। आपके पास अपने लिए हैं नहीं और आप कह रहे हैं दूसरों को उपलब्धता के आधार पर वापस कर देते है। मान्यवर मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या कभी उत्तर प्रदेश को पिछले पाँच छः वर्षों में यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपके पास अपने लिए जितनी विद्युत की आवश्यकता है उससे ज्यादा सरप्लस हुई हो और आपने किसी राज्य को दी हो। दूसरा प्रश्न यह कि द्विपक्षीय व्यवस्था के आधार पर निविदा के माध्यम से आप टेण्डर शो करके बिजली ले लेते हैं कितनी विद्युत दर थी और उससे कितने ज्यादा में खरीदी गई यह अपने आप में जाँच का विषय हो गया। आज प्रदेश की जनता विद्युत की कमी के कारण त्राहि-त्राहि कर रही है। फिर आपने तीसरे बिन्दु में आपने लिखा कि विद्युत प्रबन्ध के उपरान्त भी यदि तत्समय आवश्यकता पड़ी तो इनर्जी एक्सचेन्जों से दैनिक बिड करते हुए 'डे अहेड' विद्युत क्रय किया जा सके। मान्यवर, पिछले

दिनों अक्टूबर, नबम्बर में जिस समय किसान को बिजली की आवश्यकता थी उस समय भी आप क्रय नहीं की । वह कौन सी परिस्थितियां होगी वह कौन सा दिन होगा जिस दिन आप कहेगें कि अब हम उस सीमा को पार कर चुके हैं अब हम विद्युत क्रय को स्थिति में है। जब पूरा का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा तब आप बिजली का क्रय करेंगे। आप क्रय नहीं कर पा रहे है आपके पास विद्युत कभी सरप्लस थी ही नहीं। 31 परियोजनाओं में कोई ऐसी परियोजना नहीं हैं जिसको आप चालू कर सकें। अगर कोई ऐसी परियोजना नहीं है जिसको आप चालू कर सकें। अगर कोई परियोजना हो तो बता दीजिए। यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है मैं आपके माध्यम से जो बातें उन्होंने कही, केवल प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ बाकी बातें रिपीट नहीं करूँगा। क्या आपके पास सरप्लस विद्युत थी पिछले चार पाँच सालों में ? मैंने तात्कालिक पूछा है प्रश्न में, अब कब खरीदेंगे आपको कब लगेगा कि खरीदने की आवश्यकता है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय हमारे पास 8,633 मेगावाट बिजली उपलब्ध है और मुझे जरूरत पड़ती है बिजली की गर्मी में। इस समय हमारे पास जितनी माँग है उतनी बिजली है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप उत्तर को सुन लें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सही है कि बहुत गड़बड़ियाँ है। बिजली में चोरी भी होती है इस समय सर्दियों में बहुत चोरी हो रही है, लेकिन लॉसेज भी है लेकिन इस समय हमारे पास जितनी बिजली की जरूरत है उतनी है। घर-घर में हीटर, जो खाना बनाने के है वह चल रहे है लेकिन इसमें हमने सख्त कदम उठाए है चोरी रोकने के भी और लाइन लॉसेज रोकने के भी। हमने यह प्रयास किया है जो अभी पूर्व मंत्री जी कह रहे थे तो मैं बताना चाहूँगा कि घाटमपुर तापीय योजना की शुरूवात हमने कर दी है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

यह हमारे जमाने में आई थी।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

आपने कितना काम कराया मैं पूछना चाहता हूँ। (शोर) बहुत सी दिक्कतें हैं ट्रांसफार्मर भी बहुत फुंक रहे हैं.....

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, शांत रहे।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, जितनी भी पुरानी यूनिट हो चुकी है, उनकी क्षमता कम हुई है। अभी आप बता रहे है कि मैंने तो क्षमता बढ़ा दी, कितनी क्षमता बढ़ा दी ? मान्यवर, क्षमता बढ़ी नहीं थी, क्षमता घटी थी, उसके बावजूद भी हमने एक साल के अन्दर उनकी क्षमता को बढ़ाया है और इस समय हमारे पास कोई बिजली की कमी नहीं हैं, जितनी हमें जरूरत है मेरे पास बिजली है। माननीय अध्यक्ष जी, उसके बावजूद भी हर स्तर पर कड़े कदम उठाने की जरूरत है जो हमारी सरकार उठा रही है, कड़े कदम हम उठायेंगे और बिजली उपलब्ध करायेंगे और जितनी विद्युत की जरूरत है, उतनी विद्युत है, हमारे पास।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से बहुत छोटा प्रश्न पूछूँगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी महाना जी ने कहा कि इनकी करनी अच्छी होती तो आज यह विपक्ष में नहीं होते। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी ने ही ऊँचाहार परियोजना और टाण्डा थर्मल पावर बेचा था। आज सबसे बड़ा संकट का कारण तो भारतीय जनता पार्टी के लोग है, 'सूप बोले तो बोले, चलनियाँ बोले, जिसमें बहत्तर छेद' और अब मैं पूछ रहा हूँ माननीय ऊर्जा मंत्री जी से।

श्री अध्यक्ष-

आरोप-प्रत्यारोप न लगायें, प्रश्न पूछें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अभी आपने कहा, साढ़े आठ हजार और नौ हजार मेगावॉट बिजली है और 10500-12000 मेगावॉट की माँग है, यह आपने ही उत्तर दिया। गर्मियों में 15 मार्च को सरकार बनी, गर्मी बीच में आयी, मैं आयी, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन चार महीनों में आपने कितनी बिजली आयातित किया ?

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

आपके समय की 22 हजार करोड़ की देनदारी थी, जिसको हमने भरा है।

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहे, प्रश्नों का उत्तर सुनें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, गर्मियों में 10500-12000 मेगावॉट के मध्य आवश्यकता होती है और इस समय सर्दी में जरूरत है मुझे 8500 मेगावॉट, वह मेरे पास उपलब्ध है और जब गर्मी आयेगी, हम व्यवस्था करेंगे, चाहे मुझे खरीदना ही पड़े, कहीं से व्यवस्था करना पड़े, चाहे उसके लिए हमें धन की भी व्यवस्था करनी पड़े और जिन यूनिट की क्षमता कम हो गयी है, हम उनकी भी क्षमता बढ़ायेंगे। हमने क्षमता बढ़ायी भी है। नेता विरोधी दल, हमने क्षमता बढ़ायी भी है और आपने चोरी करवाई थी, हमें चोरी की आदतें भुलानी पड़ेगी। मैंने कहा है, हम सख्त कदम उठायेंगे और चोरी को भी रोकेंगे। लाइन लासेस भी रोकेंगे और जब तक गर्मी आयेगी, हम क्षमता बढ़ा लेंगे और पूरे प्रदेश को बिजली संकट से दूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब छोड़िए, जाने दीजिए। माननीय ठाकुर साहब।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, मैने पूछा था कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई में कितनी बिजली दिया, उसका उत्तर दिलाने के बजाय सरकार को छूट दे रहे है, यह सरासर अन्याय है, हम आपका संरक्षण चाहते है, मान्यवर, इसका उत्तर आना चाहिए।

यह सरासर अन्याय है। प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। उत्तर आना चाहिए।

(नेता विरोधी दल समेत बसपा के माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गये)

(नारेबाजी)

(नारेबाजी के कारण सदन में शोरशराबा उत्पन्न हो गया)

(शोरशराबे के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

चलिए, मौर्या जी, हम आपके प्रश्न का जवाब दिलवाते हैं। मेरा बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों से निवेदन है कि आप अपनी सीटों पर चलें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अपने कार्यालय में बहुजन समाज पार्टी ने जितने घोटाले किये हैं और बिजली में जितनी लूट की है उसको छिपाने के लिए यह सदन में हल्ला कर रहे है। यह जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। मान्यवर, प्रदेश में ट्रान्सफार्मर में जितने घोटाले हुए हैं और बिजली के जितने घोटाले हुए हैं उसकी सरकार जांच करायेगी और इसी भय के मारे वह सवाल को सुनना नहीं चाहते हैं। सारे सवालों के जवाब इनको दिये जा रहे हैं। प्रदेश की जनता देख रही है आप सवाल का जवाब दिलवाना चाहते हैं और यह सारे सवालों से मुँह

चुराना चाहते हैं। मान्यवर, इनको अपने अपराधों की सजा जरूर मिलेगी। जनता ने भी दिया और सरकार भी जांच कराकर देगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी आपका जवाब आएगा, अपनी सीट पर चलिए।

(शोरशराबे के कारण व्यवधान जारी।)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए सदन के वेल में आने का नाटक कर रहे हैं। इनको पता है कि इनके पापों के चलते उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था खराब हुयी है। पांच साल में बहुजन समाज पार्टी ने बिजली व्यवस्था को बिलकुल रसातल में पहुंचा दिया है। इसलिए मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कार्रवाई करें, ऐसे नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी, अपनी सीटों पर चलें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अगला प्रश्न ले लें हम उत्तर देने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों से आग्रह है कि आप अपनी सीटों पर चलें। महत्वपूर्ण सवाल आगे लगे हैं। क्यों सदन में व्यवधान कर रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम 49 में चर्चा की बात स्वयं अपनी ओर से कह दिया। यह चर्चा नहीं चाहते। आपने प्रश्न का उत्तर दिलवाने का निर्देश दे दिया। यह प्रश्न का उत्तर सुनना नहीं चाहते। इसलिए नहीं सुनना चाहते हैं कि इस प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को बर्बाद करने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किया है। घोटालों के अलावा कुछ नहीं किया है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अम्बिका चौधरी-

इसलिए मान्यवर, यह शोर कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सदन व्यवस्थित कराइये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी, अब आप लोग अपनी-अपनी जगहों पर चलें, अपना स्थान ग्रहण करें। देखिये, हम भी बैठे हैं, आप भी खड़े हैं, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए अब आप लोग अपनी जगह पर चलें।

(सदन के वेल में उपस्थित माननीय सदस्यगण सरकार विरोधी नारे लगाते रहे, जिससे लगातार व्यवधान की स्थिति बनी रही।)

श्री अध्यक्ष-

मैं पांच मिनट के लिए सदन स्थगित करता हूँ।

(श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 46 मिनट पर सदन को 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। 11 बजकर 51 मिनट पर सहायक मार्शल ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजे तक बढ़ा दिया। 12 बजे सहायक मार्शल ने सदन को पुन: सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है। 12 बजकर 05 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी आप प्रश्न संख्या दो के सन्दर्भ में अनुपूरक प्रश्न पूछना चाह रहे थे।

श्री हुकुम सिंह जी-

श्रीमन् इससे पहले कि मैं अपना प्रश्न पूछूँ यह कहना चाहता हूँ कि सदन में एक फैसन सा हो गया है कि जब भी सत्ता पक्ष से सवाल किया जाता है तो उसमें यह जवाब देना शुरू कर दिया जाता है कि 20-21 वर्ष पूर्व वह सरकार सत्ता में थी, उस समय यह बात हुई थी। कुछ स्थान केन्द्र सरकार को स्थान्तरित किये गये थे। मान्यवर मैं कहना चाहता हूँ कि वह स्थान या प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार को दिये गये तो वह कोई पाकिस्तान में या इटली में तो नहीं चले गये हैं। मान्यवर, वह प्रोजेक्ट कहीं पर भी स्थापित हुये हैं तो उससे उत्तर प्रदेश को भी बिजली मिल रही है। केन्द्र सरकार भी हमारे देश की सरकार है, कहीं और बाहर की सरकार नहीं है। हमने सवाल किया था कि आपके कार्यकाल में ऊर्जा उत्पादन कितना आगे बढ़ा है। उसका जवाब तो आपका जीरो है। मान्यवर, आज बिजली का उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। आज सरकार ने बिजली के क्षेत्र को कामधेनु बना दिया है, आप कितना निकालेंगें, कितना पायेंगे। सारे प्रदेश को आज इसकी कीमत देनी पड़ रही है। और देनी ही पड़ेगी। जब तक मान्यवर, कोई ईमानदार सरकार इस क्षेत्र में अच्छा कार्य नहीं करेगी तब तक उत्पादन नहीं बढ़ पायेगा। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ और न ही मैंने आपका नाम लिया है। जो हमारी परियोजनायें चल रही हैं उनके बारे में हमने कहा है। मान्यवर, ऊर्जा मंत्री हम भी रहे हैं और

अपने उस कार्य काल में हमनें कुछ करने का प्रयास किया है। अगर वह प्रयास सफल हो गया होता तो आज यह स्थिति नहीं हुई होती। आपने जो जवाब में बताया, जो परियोजनाएं गिनाई उसमें आपने पच्चीस वर्ष का कार्यकाल बताया है। आपने बैंकिंग सिस्टम लागू करने आदि के बारे में बताया है। मान्यवर, आपके ही कार्यकाल में पिछली बार गौतमबुद्ध नगर में बहुत बड़ा भू-खण्ड एक उद्योगपति को दिया गया उसमें गैस आधारित बिजली परियोजना लगनी थी । वहां पर कहीं प्रदूषण का मामला उसमें आ गया है। यह भी बात आई कि उसमें गैस मिलने में दिक्कत आयेगी। मान्यवर, चीन में बीजिंग में बिजली के कारखाने लगे हैं लेकिन वहां प्रदूषण के कारण लोगों को मुंह पर मास्क लगा कर चलना पड़ता है। क्योंकि वहां पर थर्मल पावर स्टेशन ज्यादा लगे हैं। आपने गौतमबुद्ध नगर में जमीन उपलब्ध कराके किसी से जबरदस्ती गैस आधारित बिजली परियोजना लगाने की बात की। आपने उनको भू-खण्ड उपलब्ध कराया। गैस आधारित बिजली परियोजना वहीं लगनी थी बिजली का उत्पादन वहां होना था, क्या उस परियोजना को लागू करायेगें। क्या सरकार उस पर विचार कर रही है? यदि नही, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वैसे तो बिजली का कुछ संकट है। बिजली आयात भी की गयी थी। हमारी सरकार ने जहाँ-जहाँ पर भी बिजली सरप्लस में है प्रदेशों में, वहां से हम बिजली को उपलब्ध कर लेते हैं। और जब हमारे यहां सरप्लस होती है तो हम उनको वापस कर देते हैं। मान्यवर, ऐसी काफी यूनिटें जिनकी क्षमता कम हो गयी थी उनकी क्षमता को बढ़ाने का काम यह सरकार कर रही है और क्षमता बढ़ाई भी गयी है। जहाँ बिजली सरप्लस में मिलती है वहाँ से हम खरीद लेते हैं। मान्यवर, दिक्कत आती है गर्मियों के मौसम में । अभी कोई दिक्कत नहीं है जितनी जरूरत है, हमारे पास है बिजली।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, प्रश्न है कि गौतमबुद्धनगर में एक विद्युतगृह जो लगाया जाना था उसके बारे में सरकार की क्या नीति है वह एक उत्तर छोटा सा दे दीजिए, बात खत्म।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, देखिये वह प्रश्न तो खत्म हो चुका था। वह तो खत्म हो चुका है उस पर कोई काम न हुआ है, न हो रहा है और न होगा । उसमें से गैस केन्द्र ने रोक भी दिया था हमने तो जमीन किसानों की सहमति से किसानों को उस जमीन का पैसा भी दिया था, जितना भी था किसानों की सहमति से जमीन को खरीदा था। लेकिन वहॉ पर असहयोग मिला और अगर सहयोग मिला होता आप सबका, कोई टैक्टर चला रहा था कोई कुछ कर रहा था तो उसमें अडंगा डाला गया था, वह प्लांट पूरा हो गया होता लेकिन केन्द्र सरकार ने कहां सहयोग दिया।

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया न हुआ है न हो पायेगा तो बात खत्म हो गयी अब उसको दोहराने की क्या जरूरत है।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे वह दिन याद है जब माननीय नेता जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने खड़े होकर इस प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया था कि इसमें बिजली बनेगी, प्रदेश स्वावलम्बी होगा, उनकी बात मैं कह रहा हूँ कार्यवाही में है। जब माननीय मुलायम सिंह जी ने प्रदेश को आश्वस्त किया था कि यह बिजली घर चलेगा भी और बिजली बनेगी भी इसमें और हमारा प्रदेश स्वावलम्बी हो जायेगा बिजली में। इतनी ज्यादा बात उस पर कही थी आज क्या हो गया एक पूंजीपति को आपने हजारों एकड़ जमीन दे दी और वह भू-खण्ड पड़ा हुआ है। किसानों से आपने सहमति से लिया हो या असहमति से लिया हो लेकिन जमीन तो ली गयी थी अब आज सरकार लाचार है। आज लाचारी दे रही है सरकार कि हमारे बस का नहीं है। इसमें घोषणा की गयी थी।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, गैस पर आधारित प्लांट था और जब गैस केन्द्र सरकार से नहीं मिली, सहयोग नहीं मिला और सहयोग किसी का नहीं मिला मान्यवर, अगर सबका सहयोग मिला होता। मान्यवर, किसानों की जब हमने जमीन ली थी तो जितना किसानों ने मांगा उसकी जमीन की कीमत वह किसानों को जमीन की कीमत दी। किसानों की सहमति से किसानों की जमीन खरीदी थी लेकिन वह प्लांट जब अवरोध पैदा किया गया, गैस ही नहीं मिली, जब कि गैस पर आधारित था, जब गैस नहीं मिली तो वह प्लांट नहीं लगा।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, हरदुआगंज तापीय विद्युत ग्रह मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। यहाँ अभी अधिकारियों ने सूचना दी है कि पिछली सरकार में 8 और 9 इकाई लगी जिसके लिए 2200 करोड़ रुपया लगभग तय हुआ था, इतनी उसमें अनियमितता, भ्रष्टाचार, बेइमानी की गयी, उसकी कास्ट 2900 करोड़ रुपया कर दी गयी, 2900 करोड़ रुपया कास्ट लगा दी गयी। एक दिन नहीं चला अभी सूचना अधिकारी दे रहे हैं कि 9 नवम्बर लाइटअप कर दी, 40 करोड़ का एस0पी0 जो बहुत कीमत का होता है वह धड़ाम से गिर गया। पूरी यूनिट पर 2900 करोड़ उसमें व्यय हुआ। मैंने तत्कालीन एम0 डी0 जो भ्रष्टाचार में लिप्त था, मैंने उसमें जांच कराई अभी तक पूरी नही हुई है 8 और 9 दोनों इकाइयां एक दिन काम नही कर रही हैं।

जो भी अधिकारी यह सूचना दे रहे हैं वह गलत दे रहे हैं मैं उसी क्षेत्र का हूँ रोज देखता हूँ। 9 नम्बर एक दिन नही चली 40 करोड़ का हैं एस0पी0 धड़ाम से गिर गया दोंनो यूनिटें काम नहीं कर रही हैं। वहीं का जी0एम0 बहुत अच्छा है। इसके साथ वहाँ पर 660 मेगावाट का विद्युतग्रह अभी इन्होंने स्वीकृत किया है। सभी औपचारिकतायें पूरी हो गयी हैं लेकिन अभी भारत सरकार की स्वीकृति शेष है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कृपया बताने का कष्ट करें कि भारत सरकार से कब तक उसे स्वीकृति मिल जायेगी जिससे वह चालू हो जाये। 5 और 7 दोनों मशीन पूरा पावर हाउस वेस्टर्न यू0पी0 का हरदुआगंज से ही फीडअप होता है। उस बिजली घर का चलना बहुत जरूरी है और 8 और 9 मशीनों में, पिछले समय में जो बेइमानी की गयी है, उसमें जांच कराई जाये और कार्यवाही कराई जाये।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल पूछिये।

श्री दलवीर सिंह-

जो जाँच मैंने कराई है, उसे आप कब तक पूरी करा रहे हैं। एम0डी0 को हटा दिया, एम0डी को हटाने से काम थोड़े ही चलता है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये। माननीय मंत्री जी, यह बता दें कि यह जो जाँच हो रही है भ्रष्टाचार की, वह जाँच कब तक पूरी हो जायेगी।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, यह जो यूनिट माननीय सदस्य बता रहे हैं तो बीएचईएल द्वारा इस पर काम कराने के लिये दिया गया था और यह भी बात सही है कि जितने समय में काम हो जाना चाहिये था उतने समय में काम जब नहीं हुआ तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गयी । उसकी जाँच चल रही है और शीघ्र ही इसकी जाँच करा दी जायेगी और यह यूनिट 30-6-2013 तक संभावित है, पूर्ण हो जायेगी।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि मैने जो प्रश्न किये थे, उसमें से एक का भी उत्तर नही मिला। उसके बाद मान्यवर, एक और अनुपूरक खड़ा हो गया, उसका भी उत्तर नही मिला कि कब करेंगे, कब नही करेंगे, न सरकार के पास कोई योजना है। मेरा सवाल यह है कि राजनीतिक मामलों में तो यह केन्द्र सरकार से घालमेल कर लेते हैं क्या जनता के इंट्रेस्ट में भी क्या इस तरह की बात करेंगे। मेरा कहना यह है कि

राजनीतिक बात तो सारी हो सकती है लेकिन बिजली के लिए बात नहीं हो सकती। तो क्या बिजली के लिये भी केन्द्र सरकार से बात करेंगे और उन पर दबाव डालेंगे कि वह इन परियोजनाओं को पूरा करने में सहयोग दे। दूसरी बात, जो इसी अनुपूरक में से आई है कि जो दादरी वाला प्लांट है मंत्री जी ने कहा कि न चला और न चल रहा है और न चलने की संभावना है। अगर आगे नही चलेगा तो जिस निमित्त वह जमीन एक्वायर की गयी थी, क्या वह जमीन उन किसानों को वापस की जायेगी। अगर नही की जायेगी तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वैसे तो जमीन की कीमत किसानों को दे दी गयी और यह मामला माननीय न्यायालय में है, अब न्यायालय में जो फैसला होगा, वह होगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

*03-श्री मनीष असीजा-

(4थे गुरुवार के तारांकित प्र0सं0-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

*04-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

(एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त)

उत्तर प्रदेश में मार्ग विकास नीति 1998 के अन्तर्गत कराये गये कार्य

*05-श्री सुरेश राणा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित प्रदेश की समस्त जर्जर एवं पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त सड़कों का सर्वे कराकर उनके निर्माण हेतु सरकार कोई नीति बनायेगी ? यदि हां तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

उत्तर प्रदेश मार्ग विकास नीति, 1998 वर्तमान में प्रभावी है।

साामान्य मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान मार्ग विकास नीति के अनुसार राष्ट्रीय मार्ग पर 03 वर्ष में, राज्य मार्ग पर 04 वर्ष में प्रमुख जिला मार्ग पर 04 वर्ष में, अन्य जिला मार्ग पर ग्रामीण भाग में 05 वर्ष में एवं शहरी भाग में 04 वर्ष में तथा ग्रामीण

---

* (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ-197 पर)।

* नोटः-तारांकित प्रश्न सं0 2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

मार्ग पर 08 वर्ष में नवीनीकरण का कार्य कराये जाने की व्यवस्था है। उक्त के अतिरिक्त विशेष मरम्मत व सुदृढीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वनरोजों से कृषि फसलों को नष्ट करने से बचाने की समस्या का समाधान

*06-श्री जय प्रकाश निषाद, श्री बंशी सिंह पहाड़िया एवं श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वनरोज कृषकों की फसलों को नष्ट कर रहे है, जिससे कृषकों को अत्यधिक आर्थिक क्षति हो रही है। यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के वनरोज की समस्या से निदान दिलाये जाने हेतु कोई कारगर योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

प्रदेश में वनरोजों से कृषि फसलों को क्षति पहुँचाये जाने की यदाकदा घटनायें प्रकाश में आयी हैं।

प्रदेश में वनरोजों से कृषि फसलों को नष्ट करने से बचाने के लिये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 यथासंशोधित धारा-4 (1) के तहत् शासनादेश संख्या 736/14-4-94-854-92, दिनांक 09-3-1994 एवं शासनादेश संख्या 2194/14-4-2001-854-92, दिनांक 28-9-2001 तथा शासनादेश संख्या 1464/14-4-2008-854-92, दिनांक 31-7-2008 द्वारा समस्त जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी के स्तर से लेकर मुख्य वन संरक्षक स्तर तक तथा राजस्व विभाग के समस्त तहसीलदारों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। वनरोजों के आतंक से प्रभावित कृषक अपने क्षेत्र के उक्त अधिकरियों से सम्पर्क कर उनकी अधिकारी सीमा के अन्तर्गत समस्या का समाधान कर सकते हैं।

प्रदेश की चीनी मिलों के विक्रय में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जाँच

*07-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पन्द्रहवीं विधान सभा के कार्यकाल में प्रदेश की 21 चीनों मिलों की बिक्री में सी0ए0जी0 की आपत्तियों में रुपये 1180 करोड़ के घोटाले का आरोप है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार चीनों मिलों को कम दामों पर बेचने तथा अन्य अनियमितताओं की विस्तृत जाँच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

* नोटः-तारांकित प्रश्न सं0 2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री अखिलेश यादव-

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की चीनों मिलों के विक्रय पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में लेखा परीक्षा के परिणामों के प्रभाव के अन्तर्गत, विक्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया में हुई कमियों का प्रभाव रु0 1179.84 करोड़ दर्शाया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की 10 चालू एवं 11 बंद चीनी मिलों के विक्रय के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जाँच/अन्वेषण लोक आयुक्त को प्रदत्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कृषकों की कर्ज माफी की योजना

*08-श्री संगीत सिंह सोम-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों का 50 हजार रुपये तक ऋण माफ करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो किस प्रकार के ऋण माफ किये जायेंगे और उसका प्ररूप क्या होगा तथा कब तक माफ कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

कृषकों की कर्ज माफी की योजना का लाभ केवल उन्हीं कृषकों को देय होगा, जिन्होंने अपनी कृषि योग्य भूमि बन्धक रख कर उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत कराया है तथा दिनांक 31 मार्च, 2012 को निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करते हों -

1-कृषक की कृषि योग्य भूमि बन्धक रखी गयी हो।

2-स्वीकृत ऋण का मूल धन रूपया 50 हजार से अधिक न हो।

3-लिये गये ऋण का 10 प्रतिशत की अदायगी कर दी गयी हो।

ऋण माफी योजना की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 द्वारा की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

ताज ट्रिपेजियम जोन टी0टी0 जेड0 क्षेत्र में 24 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग

*09-डा0 धर्मपाल सिंह एवं श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ताज ट्रिपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) क्षेत्र में विश्वदाय स्मारकों की पर्यावरणीय सुरक्षा की दृष्टि से 24 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति के आदेश

मा0 उच्चतम न्यायालय के हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार को जानकारी है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के उपरान्त भी टी0टी0जे0 क्षेत्र में कई-कई घण्टे तक लगाातार विद्युत कटौती की जा रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में टी0टी0जेड0 क्षेत्र को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

09-श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ

जी हाँ।

जी नहीं, किन्तु स्थानीय व्यवधान एवं ग्रिड की सुरक्षा के दृष्टिगत् कभी-कभी विद्युत आपूर्ति बाधित होती है।

जी हाँ।

प्रश्न नही उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बहराइच में सन्तनगर चौराहा ग्राम बुढ़नी भलुहिया में सहकारी समिति को संचालित करने की मांग

01-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद के विकास खण्ड विशेश्वरगंज में सन्तनगर चौराहा ग्राम बुढ़नी भलुहिया में सहकारी समिति का भवन 15 वर्षों से बनकर तैयार है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भवन में समिति संचालित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

जनपद रामपुर की उ0प्र0 सहकारी सहमति द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों के निष्पादन हेतु जमा किये गये शुल्क की जानकारी

02-श्री संजय कपूर-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-95 (क) के अन्तर्गत जारी प्रमाण-पत्रों के निष्पादन के समय उ0 प्र0 सहकारी

समिति नियमावली, 1968 के नियम संख्या-362 के अन्तर्गत निष्पादन शुल्क जमा करना होता है ? यदि हां, तो प्रदेश के कितने जनपदों में निष्पादन शुल्क अब तक जमा नहीं किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद रामपुर में 01-07-1995 से 30-6-2007 तक कितनी धनराशि जमा की गयी और कितनी शेष है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव -

जी हाँ।

सभी जनपदों में जमा किया जा रहा है।

जनपद रामपुर में 01-07-1995 से 30-06-2007 तक मु0 16,65,157.00 जमा की गई है, तथा कोई धनराशि उक्त प्रश्नगत अवधि की शेष नहीं है।

प्रदेश के जिला अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन मशीन लगाने की जानकारी

03-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन मशीन लगाने की कोई नीति है ? यदि हां तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय चिकित्सालयों में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों को स्थापित करना संबंधित चिकित्सा विशेषज्ञों, तकनीकी स्टाफ तथा प्रदेश सरकार की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बलिया में क्षतिग्रस्त सुखपुरा-गड़वार फेफना व गड़वार रतसर के जर्जर मार्गों की मरम्मत की मांग

04-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में क्षतिग्रस्त सुखपुरा-गड़वार फेफना एवं गड़वार-रतसर जर्जर मार्गों की मरम्मत कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सुखपुरा-गड़वार-फेफना मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

गड़वार-रतसर मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ में पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजना (हर्षनगर) में विकास कार्यों पर व्यय धनराशि की जानकारी

05-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ विकास प्राधिकरण की पं0 दीनदयाल उपाध्याय योजना (हर्षनगर) किस वित्तीय वर्ष में लागू की गयी थी तथा इस योजना में कितने भू-खण्ड विक्रय होने शेष हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना में वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में सडकों, पार्क, सीवर आदि पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्राधिकरण द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय योजना (हर्षनगर) हेतु 10.34 एकड़ भूमि का कब्जा दिनांक 09.04.1986 को नियमानुसार अधिग्रहण के उपरान्त प्राप्त किया गया था। अर्जित भूमि में से गढ़ रोड के चौड़ीकरण हेतु 3113.38 वर्ग मी0(0.77 एकड़) भूमि छोड़कर शेष 38782.60 वर्ग मी0 (9.57) एकड़ भूमि व्यवसायिक-कम-आवासीय प्रयोजनार्थ दिनांक 08.12.2000 को निविदा-सह-नीलामी के माध्यम से उच्चतम बोलीदाता मै0 जय कृष्ण स्टेट प्रा0 लि0 के पक्ष में आवंटित की गयी थी। हर्ष नगर, जिसे बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना नाम दिया गया है, में कोई अन्य भूखण्ड विक्रय हेतु शेष नहीं है।

भूखण्ड बल्क में विक्रय किया गया है, विकास कार्यों का दायित्व क्रेता का है। वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में सड़कों, पार्क, सीवर आदि कार्य मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं कराया गया है और न ही इन कार्यों पर प्राधिकरण द्वारा कोई धनराशि व्यय की गई है।

उपर्युक्तानुसार।

06-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

से सोमवार के अतांराकित प्रश्न सं0-70 के अन्तर्गत स्थानान्तरित

फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण में पूर्व कालिक वी0सी0 एवं सचिव की तैनाती की मांग

07-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद स्थित फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण में अनेक वर्षों से अपनी स्थापना से लेकर आज तक पूर्णकालिक वी0सी0 एवं सचिव न होने के कारण विकास प्राधिकरण का विकास कार्य

प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राधिकरण में पूर्णकालिक अधिकारियों यथा वी0सी0 एवं सचिव पदों पर तैनाती करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना दिनांक 07.04.1995 के अनुसार उपाध्यक्ष का पद जिलाधिकारी में निहित है। अतः इस पद पर अलग से तैनाती का प्रश्न नहीं है। सचिव के पद पर पूर्णकालिक अधिकारी की तैनाती नहीं है, उक्त पद का कार्य नगर मजिस्ट्रेट , फिरोजाबाद द्वारा देखा जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण में टूण्डला क्षेत्र को सम्मिलित करने की मांग

08-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद स्थित ''फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण'' में टूण्डला विधान सभा का बहुत बड़ा शहरी क्षेत्र सम्मिलित होने से रह जाने के कारण प्राधिकरण के गठन की मूल अवधारणा पूरी नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार टूण्डला क्षेत्र को ''फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण'' में सम्मिलित कर विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

फिरोजाबाद एवं शिकोहाबाद नगर पालिका सीमा तथा जनपद-फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद, शिकोहाबाद एवं जसराना के 110 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास क्षेत्र घोषित किया गया था। वर्तमान में तहसील फिरोजाबाद का 01, टूण्डला के 39 तथा शिकोहाबाद के 79 राजस्व ग्राम अर्थात कुल 119 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित कर फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास क्षेत्र की सीमा का विस्तार किये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्तानुसार।

उक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के मोहान रोड पर रंग-रेजाबाग वाली मस्जिद में ऐरियल बन्च कण्डक्टर लगवाये जाने की जानकारी

09-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2011 के प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-150 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रंग-रेजाबाग व बाग वाली मस्जिद में बंच ऐरियल लगवा दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बाग वाली मस्जिद में भी बंच एरियल लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

रंग-रेजाबाग व बाग वाली मस्जिद में ऐरियल बन्च कण्डक्टर दिनांक 26.04.2011 को लगवा दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय जर्जर एवं गड्ढायुक्त मार्गों की मरम्मत करवाये जाने की जानकारी

10श्री काली चरण सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नौ मील से लड़ामदा, मनकेड़ा, नगला कारे, नगला सावल तक तथा मलपुरा परिक्रमा मार्ग से वरारा नहर तक की सड़कें जर्जर एवं गड्ढायुक्त होने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सड़कें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

उक्त सड़कों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र पनियारा के अन्तर्गत बी0एम0सी0टी0 की क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत की मांग

11-श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र पनियारा के अन्तर्गत बी0एम0सी0टी0 मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में अत्यधिक कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। आबादी भाग में मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र पनियारा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरपुर तिवारी के संचालित होने की जानकारी

12-श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार क्ल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र पनियारा में शासन द्वारा मंसूरगंज व हरपुर में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगभग चार वर्षों से बनकर तैयार है ? यदि हां, तो इन्हें आज तक संचालित न कराने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त दोनों स्वास्थ्य केन्द्रों को संचालित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरपुर तिवारी स्वीकृत व संचालित है तथा मंसूरगंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरपुर तिवारी संचालित है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरपुर तिवारी संचालित है व मंसूरगंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वीकृत न होने के कारण संचालित किये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत करवाये जाने की मांग

13-श्री छोटेलाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में शैंया, इरादत नगर, शमसाबाद, फतेहाबाद व फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फतेहाबाद निबोहरा, पसारा, बैकुन्ठी, तिवरिया, शमसाबाद, राजाखेड़ा मार्ग तक, होरी डंडा, फतेहाबाद से बाईपास फतेहाबाद तक, बाबा मुंशी दास मार्ग पड़ावल मार्ग, सिकरा वरीपुरा मार्ग, फतेहाबाद वाह मार्ग से यांकुरीकलां वरना पीरा डन्डा मार्ग वर्तमान में क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

उक्त मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

सैंया-इरादतनगर-शमसाबाद-फतेहाबाद मार्ग व फतेहाबाद-फिरोजाबाद मार्ग विशेष मरम्मत के अन्तर्गत स्वीकृत है। फतेहाबाद निबोहरा मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत है। शेष अन्य मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद की विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के वार्ड न0 6, राहुल बिहार की गलियों में बिजली के खम्भे लगाये जाने सम्बंधी जानकारी

14-श्री सुरेश बंसल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद की विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के वार्ड नं0 6, राहुल बिहार की पांच गलियों में घरों में बिजली के मीटर लगे हुए हैं और उपभोक्ता विद्युत विभाग को बिल भी देते हैं, परन्तु इन गलियों में बांस-बल्लियों पर तार लगाकर विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गलियों में खम्भे लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

14-जनपद गाजियाबाद के गाजियाबाद विधान सभा क्षेत्र के वार्ड-6, राहुल बिहार की पांच गलियों में बिजली के मीटर लगे हुए हैं तथा उपभोक्ता बिलों का भुगतान कर रहे हैं। उक्त कालोनी की गलियों में बांस-बल्लियों के स्थान पर विद्युत पोल स्थापित कर दिये गये हैं तथा कोई भी बांस बल्लियाँ वर्तमान में नहीं लगी हैं।

गलियों में खम्भे लगा दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के न्यू कोर गांव में हाईटेंशन लाइन हटाये जाने की मांग

15-श्री सुरेश बंसल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद न्यू कोर गांव में गरीब लोगों के घरों के ऊपर से 11,000 वोल्ट की हाइटेंशन तार की लाइन जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार सुरक्षा की दृष्टि से उक्त लाइन को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

15-जी हाँ।

11 के0वी0 लाइन पहले से मौजूद थी, लोगों ने कालान्तर में लाइन के नीचे खाली भूमि पर मकान बना लिये हैं।

लाइन पूर्व में मौजूद थी, अतः जमा योजना के अन्तर्गत तकनीकी दृष्टि से बाधा रहित कौरीडोर की उपलब्धता के आधार पर हटाया जाना सम्भव होगा।

उक्त कार्य विधायक निधि से कराने का प्रस्ताव जिला प्रशासन को पत्र सं0 4738 दिनांक 2 नवम्बर 2012 के द्वारा भेजा गया है। धनराशि प्राप्त होने पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में चरण सिंह कालोनी एवं हरवंश नगर भट्टा रोड में विद्युत कनेक्शन को बांस-बल्लियों के स्थान पर खम्भे लगाये जाने की मांग

16-श्री सुरेश बंसल-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के गाजियाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चरण सिंह कालोनी (स्वराज सिंह दुर्गा मन्दिर के पीछे) तथा मोहल्ला हरवंश नगर भट्टा रोड के पास गलियों के विद्युत कनेक्शन को बांस बल्लियों के सहारे मानक के विपरीत लम्बे केबिलों से विद्युत आपूर्ति की जा रही है जिसमें कई बार अप्रिय घटना भी हो चुकी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में तारों को बांस-बल्लियों की जगह खम्भों को लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

16-जनपद गाजियाबाद की गाजियाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चरण सिंह कालोनी पूर्ण रूप से अविकसित है, जिसमें भवनों के निर्माण उपरान्त डूडा द्वारा वर्ष 1996 में विद्युतीकरण का कार्य किया गया था तथा हरवंश नगर भट्टा रोड की मुख्य सड़कें विद्युतीकृत

है। दोनों स्थानों पर निवासियों द्वारा छोटी गलियों में कच्चे/पक्के मकानों का निर्माण आगे की ओर किया गया है, जो नियोजित विकास न होने के कारण लम्बी दूरी से विद्युत का प्रयोग कर रहे हं। विगत एक वर्ष के अन्तराल में कोई विद्युत दुर्घटना नहीं हुई है।

उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने एवं आने वाली व्यय की धनराशि उपलब्ध कराने पर मानक के अनुसार खम्भा लगाकर विद्युतीकरण का कार्य कराया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुंगराबादशाहपुर में आयोजित नसबन्दी शिविर में न पहुंचने वाले चिकित्सक के विरूद्ध कार्यवाही

17-श्रीमती सीमा-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14-12-2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुंगराबादशाहपुर पर नसबन्दी के शिविर का आयोजन किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि जिस चिकित्सक की ड्यूटी थी वह 5 बजे तक नहीं आये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हाँ।

प्रभारी चिकित्साधिकारी मुंगराबादशाहपुर जौनपुर द्वारा उक्त केन्द्र पर दिनांक 14-12-12 को डा0 महेन्द्र यादव, सर्जन से वार्ता करके नसबन्दी शिविर का आयोजन किया गया था। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा उक्त की सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर को नहीं दी गयी थी। उक्त तिथि को ही मुख्य चिकित्साधिकारी जौनपुर द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बक्सा जौनपुर एवं सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र सुजानगंज में भी नसबन्दी शिविर का आयोजन किया गया था। बक्सा में डा0 के0 विजय, सर्जन, जिला महिला चिकित्सालय, जौनपुरी की ड्यूटी लगायी गयी थी परन्तु उनके शिविर में न पहुंचने के कारण मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर द्वारा डा0 महेन्द्र यादव को प्राथ0 स्वा0 केन्द्र बक्सा में भी नसबन्दी हेतु दूरभाष पर आदेशित किया गया। डा0 महेन्द्र यादव, सर्जन द्वारा बक्सा में 30 नसबन्दी आपरेशन करने के उपरान्त सामु0स्वा0केन्द्र सुजानगंज में नसबन्दी आपरेशन किया। तदोपरान्त डा0 यादव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुंगराबादशाहपुर जौनपुर सायं 5.30 बजे पहुँचे और वहाँ लगभग नसबन्दी आपरेशन किया गया।

डा0 के विजय प्रथम दृष्ट्या उत्तरदायी पाये गये हैं, जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी के सिराथू में नहरों में टेल और खेत तक पानी पहुँचाने हेतु रोस्टर की योजना

18-श्री केशव प्रसाद मौर्या (कुशवाहा)-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र की नहरों में टेल और खेत तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था के लिए रोस्टर के अनुसार पानी छोड़ा जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में टेल तक रोस्टर के अनुसार पानी पहुंचने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर में स्वीकृत 132 के0वी0 का विद्युत केन्द्र स्थापित कराये जाने की मांग

19-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर में स्वीकृत 132 के0वी0 का विद्युत केन्द्र अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है, जिसके कारण स्थानीय जनता को काफी परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो उसकी स्थापना कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

जिलाधिकारी पीलीभीत द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु धारा-6 द्वारा भूमि प्राप्त होने के उपरान्त 12 माह में उपकेन्द्र का कार्य पूर्ण हो सकेगा। निर्धारित अवधि में उपकेन्द्र का कार्य पूर्ण होना भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर की नहरों की सिल्ट सफाई का विवरण

20-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत कौन-कौन शाखा नहरें, उनके रजवाहे एवं अल्पिकायें हैं ? क्या इन सभी के अन्तर्गत नहरों तक पानी पहुंच रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन सभी नहरों की वर्ष 2000 से अगस्त, 2012 तक सिल्ट सफाई हुई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत बीसलपुर शाखा, भिठौरा रजवाहा, टिकरी रजवाहा, शेरगंज माइनर, परासी माइनर, कनगावां माइनर, साबेपुर रजवाहा, जसौली माइनर, भोगापुर माइनर, गोवल रजवाहा, बौनी माइनर, खरगापुर माइनर, शिवपुरी माइनर, बेनीपुरा माइनर एवं कोकिला माइनर हैं।

जो हाँ, परन्तु उन माइनरों/नहरों जो शाखा के टेल भाग में अवस्थित हैं उनके हेड रीच में अधिक जल उपयोग के कारण पूरी लम्बाई में हमेशा पानी पहुँचने में कठिनाई होती है। उपरोक्तानुसार।

वर्ष 2000 से अगस्त, 2012 तक वर्षवार आवश्यकतानुसार सिल्ट सफाई कराई गई है, जिसका विवरण संलग्न है*

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सृजन विहार कालोनी को विनियमितीकरण करने सम्बन्धी प्रस्ताव

21-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के गोमती नगर स्थित अम्बेडकर पार्क के पास सृजन विहार सोसाइटी में अधिकांश लोग मकान बनाकर रहने लगे हैं ? क्या उक्त बने हुए मकानों का बेटरमेंट शुल्क लेकर नियमितीकरण करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सृजन विहार कालोनी के विनियमितीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। विनियमितीकरण के उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही समीचीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

* देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ-198-203 पर)।

प्रदेश में जेनेटिक दवाओं हेतु माडल शाप खोले जाने की मांग

22-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तहसील स्तर पर ''जेनेरिक दवा'' की माडल शाप खोलने की योजना है ? क्या यह सही है कि एक साल्ट/फार्मूले के होने के बावजूद ब्रांडेड दवायें जेनेरिक दवाओं से कई गुना मंहगी होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार 'जेनेरिक दवाओं' की बिक्री एवं प्रचार-प्रसार के लिये प्रदेश में ''माडल शापों'' की एक श्रृंखला बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

जी नहीं।

जी नहीं।

(घ) प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार की व्यवस्था है। यदि जेनेरिक दवाओं से सम्बन्धित माडल शाप को खोले जाने की अनुमति दी जाती है, तो उन औषधियों के मूल्य का भुगतान रोगी को करना पड़ेगा। स्पष्ट है कि यह विरोधाभासी व्यवस्था जनहित में उचित न होगी।

प्रदेश के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में आरोग्य निधि योजना के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा

23-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 'आरोग्य निधि' के अन्तर्गत सरकारी सहायता की पात्रता रखने वाले गम्भीर रूप से बीमार रोगियों के लिये इलाज, अनुदान के लिये कुछ ही केन्द्र रखे गये हैं जिसके कारण गम्भीर रूप से बीमार रोगी यहां बाहर से आकर भर्ती होने एवं इलाज करा सकने में अधिकांशतः सफल नहीं हो पाते हैं ? यदि हां, तो क्या शासन इन केन्द्रों द्वारा अनुमन्य धनराशि सीधे मरीजों को प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

(क) राज्य आरोग्य निधि योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 कार्ड धारक अथवा जिसकी वार्षिक आय रु0 24000/- तक है, को प्रदेश के चिन्हित चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा उपलब्ध है।

(ख) रोगी को सीधे धनराशि उपलब्ध कराने का औचित्य नहीं है।

(ग) आरोग्य निधि योजना के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले रोगी को प्रदेश के राजकीय चिकित्सा संस्थानों क्रमशः छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय) लखनऊ, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज कानपुर, एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज इलाहाबाद, एस0एन0 कालेज आगरा, बी0आर0डी0 कालेज गोरखपुर, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झॉसी, एस0जी0पी0जीआई0 लखनऊ, सर सुन्दर लाल चिकित्सालय, बी0एच0यू0, वाराणसी, मेडिकल कालेज मेरठ तथा जे0एन0 मेडिकल कालेज मेरठ, मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में निःशुल्क चिकित्सा उपचार उपलब्ध है।

प्रदेश में विधायकों की संस्तुति पर सड़क बनवाने की मांग

24-श्री सतीश महाना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास के क्षेत्रीय संतुलन के दृष्टिगत प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा विधायकों की संस्तुति पर 15 कि0मी0 सड़क बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वर्तमान में इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा बेगमबाग में स्थित पार्क के रख-रखाव सम्बन्धी जानकारी

25-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के वित्तीय वर्ष 2008-09 के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक जोकि विधान मण्डल सदस्यों को मार्च, 2008 में प्राप्त हुआ है, के पेज नम्बर-89 एवं आवास एवं शहरी विभाग कार्यपूर्ति दिग्दर्शक, आय-व्ययक वित्तीय वर्ष 2009-10 पेज नम्बर-93 पर मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा बेगम बाग में एक सुन्दर पार्क का उल्लेख किया गया है ? यदि हां, तो इस पार्क का निर्माण किस वित्तीय वर्ष में किया गया तथा इसके निर्माण पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुयी तथा यह पार्क कितने क्षेत्रफल में है ? निर्माण वर्ष से आज तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पार्क के रख रखाव पर कितनी धनराशि खर्च हुई ? क्या सरकार इस पार्क की वास्तविक स्थिति की जानकारी हेतु स्थलीय निरीक्षण भी करेगी ? यदि नही तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हॉं।

बेगम बाग में वर्ष 1992-93 में एक पार्क का निर्माण किया गया। उक्त पार्क का निर्माण भवनों के निर्माण के साथ-साथ किया गया था। पार्क की लागत भवनों के निर्माण लागत में ही सम्मिलित थी। पार्क का कुल क्षेत्रफल 400 वर्गमीटर है।

पार्क के रख रखाव आदि का कार्य कालोनी की रेजीडेन्ट सोसायटी द्वारा किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा पार्क के रख रखाव हेतु कोई धनराशि खर्च नही की गई है।

प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा पार्क का स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है।

उपर्युक्तानुसार।

बरेली के जिला अस्पताल में नेफ्रोलाजिस्ट स्किन चिकित्सक के तैनाती की मांग

26–डा0 अरूण कुमार-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली के जिला अस्पताल में कई स्पेशलिस्ट (विशेषकर नेफ्रोलाजिस्ट, स्किन) डाक्टरों की तैनाती नही हुई है जिसके कारण मरीजों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार विषय विशेषज्ञ डाक्टरों की तैनाती करेगी ? यदि हाँ, तो कब ? तक यदि नही, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जिला चिकित्सालय बरेली में नेफ्रोलाजिस्ट की तैनाती हो गयी है, किन्तु अनुपलब्धता के कारण स्किन स्पेशलिस्ट की तैनाती नहीं हो पायी है।

प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सों के अभाव के बावजूद उक्त चिकित्सालय में फिजीशियन, चेस्ट फिजीशियन, बालरोग विशेषज्ञ, रेडियोलाजिस्ट, पैथोलाजिस्ट, कार्डियोलाजिस्ट, निश्चेतक, जनरल सर्जन, आर्थो सर्जन, ई0एन0टी0 सर्जन, नेत्र सर्जन, डेन्टल सर्जन आदि तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत उपकेन्द्र विशेश्वरगंज जनपद बहराइच के अन्तर्गत कौडिया बाजार जनपद गोण्डा विद्युत के ढीले तारों को ऊंचा कराये जाने के सम्बंध में जानकारी

27–श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत उपकेन्द्र विशेश्वरगंज जनपद बहराइच के अन्तर्गत कौडिया बाजार जनपद गोण्डा में लगे विद्युत पोल अत्यधिक ऊंचाई पर हैं तथा पोलों में लगे तार ढीले हो जाने के कारण दुर्घटना की समस्या बराबर बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार नये विद्युत पोल लगवाने पर विचार करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

विद्युत उपकेन्द्र विशेश्वरगंज जनपद बहराइच के अन्तर्गत कौडिया बाजार जनपद गोण्डा की विद्युत लाइन का पी0सी0सी0 पोल मानक के अनुसार ठीक ऊँचाई का है। ढीले

तारों को मानक के अनुसार ऊँचा करा दिया गया है। इस प्रकार दुर्घटना की समस्या का निराकरण कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

28-डा0 धर्मपाल सिंह-

[1ले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद देवरिया के बनकटा से अहिरौली बघेल (उत्तर पट्टी) सम्पर्क मार्ग की मरम्मत एवं नवीनीकरण कराये जाने की जानकारी

29-श्री सूरज पाल सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2012 के 1ले बुधवार के लिए निर्धारित श्री मुकेश श्रीवास्तव स0वि0स0 द्वारा पूछे गये अता0प्र0सं0-110 के उत्तर के क्रम में क्या लोक निर्माण मंत्री यह बतायेंगे कि जनपद देवरिया के बनकटा से अहिरौली बघेल (उत्तर पट्टी) सम्पर्क मार्ग लम्बाई 3.620 कि0मी0 में से 1.50 कि0मी0 के नवीनीकरण का कार्य करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सामान्य मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के चौरी-चौरा की निष्क्रिय साधन सहकारी समितियों को सक्रिय किये जाने की जानकारी

30–श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में निष्क्रिय साधन सहकारी समितियों को सक्रिय करने के लिए सरकार कोई प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

कुल 22 समितियों में से 10 समितियों को 5 लाख रुपये प्रति समिति की दर से रिवाल्विंग फण्ड उपलब्ध हो चुका है, शेष 12 समितियों को इस वित्तीय वर्ष में सक्रिय किए जाने की कोई योजना नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के चौरी-चौरा क्षेत्र की क्षति ग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण करवाने की मांग

31–श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के चौरी-चौरा क्षेत्र के अन्तर्गत मोती राम अड्डा से कुसुम्भी बाजार की सड़क तथा फुटहवा इनार से सुनवरसा बाजार तक की सड़कें अत्यन्त क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हाँ, तो क्या उक्त सड़कों का पुनर्निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

प्रश्नगत सड़कों का पुनर्निमाण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रहमपुर में मझना नाले पर पुल निर्माण की मांग

32–श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत विकास खण्ड ब्रहमपुर में ग्राम सभा हरैया (टोला झिरझरेवा) के पास मझना नाला पर पुल का निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मझना नाला पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

मझना नाला पर सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़हलगंज में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

33–श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में तहसील गोला अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़हलगंज में चिकित्सकों एवं

पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। पैरामेडिकल स्टाफ में फार्मासिस्ट, एक्स-रे टेक्नीशियन एवं एल0 टी0 का पद भरा हुआ है।

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त समय-समय प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर नियुक्ति/तैनाती की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रोन्नति/सेवानिवृत्ति/त्याग पत्र/पदों के सृजन आदि के कारण चिकित्सा अधिकारियों के समय-समय पर पद रिक्त होते रहते हैं। चिकित्सा अधिकरियों के पदों का रिक्त होना और उन पर नियुक्त किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। पैरामेडिकल स्टाफ में फार्मासिस्ट, एक्स-रे टेक्नीशियन एवं एल0 टी0 का पद भरा हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र (अतिरिक्त) मिश्रौली में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल कार्यरत स्टाफ सम्बंधी जानकारी

34–श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में तहसील गोला अन्तर्गत प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र (अतिरिक्त) मिश्रौली में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में स्थायी चिकित्सक एवं स्टाफ की व्यवस्था करेगी ? यदि हॉ, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

एक चिकित्सक तैनात है। इसके अतिरिक्त पैरामेडिकल स्टाफ में फार्मासिस्ट कार्यरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी एवं पसगवां की ग्राम पंचायतों, टोलों हेतु आवंटित धनराशि तथा उससें कराये गये कार्य

35–श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड मोहम्मदी व विकास खण्ड पसगवां के विभिन्न ग्राम पंचायतों, टोलों

में विद्युतीकरण एवं विद्युत व्यवस्था सुधारने हेतु वर्ष 2011-12 में कितनी धनराशि आवंटित की गयी एवं आवंटित धनराशि में से क्या क्या कार्य कराये गये तथा कितने कार्य कराये जाने शेष हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

35- विकास खण्ड मोहम्मदी एवं पसगवां के वर्ष 2011-12 में 19 ग्राम पंचायतों, टोलो का विद्युतीकरण हेतु डा0 अम्बेडकर ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में चयनित किया गया था जिनकी धनराशि रु0 1,54,46,582.00 के प्राक्कलन स्वीकृत किये गये थे। आवंटित धनराशि से 02 ग्रामों पालचक एवं एनुआ में पोल खड़ें किये गये थे। उपरोक्त सभी ग्राम पंचायतों एवं टोलो में विद्युतीकरण हेतु सभी कार्य कराये जाने शेष हैं।

डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना वर्तमान में बन्द हो गयी, अतः वर्तमान में विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराये जाने की मांग

36–श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में नगर पालिका परिषद् मोहम्मदी मुख्यालय पर उच्च आधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में 100 बेड वाला अस्पताल खुलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में नगर पालिका परिषद् मोहम्मदी मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहम्मदी 30 बेड का स्थापित एवं क्रियाशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर के सदर अस्पताल तथा सदर महिला अस्पतालों में नये बेड्स, गद्दे चादरे उपलब्ध कराकर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करवाने की मांग

37–श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सदर अस्पताल तथा सदर महिला अस्पताल लखीमपुर में व्याप्त भीषण दुर्गन्ध, गन्दे गड्डे, फटी

पुरानी मोरचा लगी चादरें, कम्बल तथा अस्पताल परिसर गेट से लगा जगह-जगह पर गन्दगी, वार्डो के गन्दे शौचालय आदि के कारण संक्रमण तथा बीमारियां फैलने की सम्भावना है ? क्या सरकार उक्त अस्पतालों नये बेड्स, गद्दे, चादरें उपलब्ध कराकर सफाई व्यवस्था सुनिचित करेंगी ? यदि हॉ तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं। जिला चिकित्सालय पुरूष में कान्ट्रैक्ट पर अतिरिक्त सफाई कर्मी लगाकर सफाई करायी जा रही है। बीमारी फैलने की सम्भावना नहीं है। उचित मात्रा में नये गद्दे एवं नयी चादरे उपलब्ध हैं। जिला महिला चिकित्सालय में अधिक प्रसव होने के कारण नियमित सफाई कर्मचारियों के साथ ही 10 अतिरिक्त सफाई कर्मी रखे गये है जो चिकित्सालय की पूरी सफाई करते हैं। शौचालय नियमित रूप से साफ कराया जाता है।

सफाई व्यवस्था उपरोक्तानुसार की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के पुवांया से निगोही, निगोही से तिलहर मार्ग की मरम्मत करवाये जाने की मांग

38–श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत पुवांया से निगोही, निगोही से तिलहर मार्ग अत्यन्त जर्जर हो जाने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है एवं आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त मार्गो की मरम्मत करायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

उक्त मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

पुवांया से निगोही मार्ग का सुदृढ़ीकरण पी0एम0जी0एस0वाई0 के फेज 10 के अन्तर्गत स्वीकृत है। निगोही से तिलहर मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

39–श्री रोशन लाल वर्मा-

[1 ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0-29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सहारनपुर के बेहट में रपटा पुल व सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

40–श्री महावीर सिंह राणा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत बाढ़ के कारण रपटापुल व सड़के अत्यन्त क्षतिग्रस्त हैं जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई होती है ? यदि हां तो क्या सरकार जनहित में बाढ़ से क्षतिग्रस्त रपटा पुल व सड़कों की मरम्मत करायेगी? यदि हॉ तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत कार्यों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत कतिपय विद्युत उपकेन्द्रों को चालू कराये जाने की जानकारी

41-श्री महावीर सिंह राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत बेहट में 220 के0वी0ए0 तथा विहारीग, खुर्रमपुर व पाड़ली काशमपुर में 33-33 के0वी0ए0 के पावर प्लान्ट बनकर तैयार हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही विद्युत समस्या को ध्यान में रखते हुए उक्त पावर प्लान्टों को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद सहारनपुर विधान सभा क्षेत्र बेहट में 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र पारेषण इकाई द्वारा निर्माणाधीन है। बिहारीगढ़, खुर्रमपुर एवं पाडली कासमपुर में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र निर्माणाधीन है।

220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का ऊर्जीकरण माह अप्रैल 2013 तक सम्भावित है। 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बिहारीगढ़ ? खुर्रमपुर के ऊर्जीकरण का कार्य मार्च, 2013 तथा 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र पाडली कासमपुर के ऊर्जीकरण का कार्य जून, 2013 में पूर्ण कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गरीबी रेखा से जीवन-यापन करने वाले नागरिकों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग

42-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को मुफ्त में विद्युत सप्लाई देने की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सम्प्रति किसी भी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता को मुफ्त में बिजली आपूर्ति की नीति नहीं है। अतः प्रारूप का प्रश्न नहीं उठता है।

वर्तमान में 01 किलोवाट भार के विद्युत उपभोक्ता (लाइफ लाइन उपभोक्ता) जिनका मासिक उपयोग 150 यूनिट तक है, उनके लिये अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं की अपेक्षा विद्युत की दर कम रखी गयी है। यह भी अवगत कराना है कि विद्युत दरों का निर्धारण उ0प्र0 राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाता है।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा व ददरौल के कुछ ग्रामों में पीड़ितों के मोतियाबिन्द आपरेशन कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

43-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेंड़ा व ददरौल के कुछ ग्रामों में पीड़ितों के मोतियाबिन्द के आपरेशन कराने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 07 अगस्त, 2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हाँ।

जनपद में वर्तमान में मात्र एक नेत्र शल्यक जिला चिकित्सालय में कार्यरत है। प्रा0स्वा0केन्द्र भावलखेड़ा एवं ददरौल में आई0ओ0एल0 आपरेशन कक्ष की व्यवस्था नहीं है। अतः प्रा0स्वा0केन्द्र स्तरों पर कैम्प लगाकर आपरेशन नहीं कराया जा सकता है।

प्रा0स्वा0केन्द्र भावलखेड़ा एवं ददरौल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों द्वारा आशाओं के सहयोग से ग्राम के सभी संदिग्ध मोतियाबिन्द के मरीजों की सूची बनाकर रजिस्टर में अंकन करने तथा नेत्र परीक्षण अधिकारी के सहयोग से चिन्हीकृत मोतियाबिन्द के रोगियों के जिला चिकित्सालय शाहजहांपुर में आपरेशन कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

इसके अतिरिक्त माह फरवरी एवं मार्च, 2013 में प्रत्येक सोमवार को प्रा0स्वा0 केन्द्रों पर स्क्रीनिंग कैम्प लगाकर मोतियाबिन्द चिन्हित रोगियों को सरकारी वाहन में जिला चिकित्सालय भेजकर निःशुल्क आपरेशन कराने की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के फतेहपुर कलसिया बेहट में राज्य सड़क निधि द्वारा स्वीकृत कार्य कराये जाने की मांग

44-श्री महावीर सिंह राणा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत फतेहपुर कलसिया बेहट में सन् 2011 में राज्य सड़क निधि द्वारा स्वीकृत होकर 4 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त हुई थी तथा निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका था किन्तु बाद का निर्माण कार्य रोक दिया गया है ? क्या सरकार उक्त अधूरे निर्माण कार्य को शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

उक्त कार्य के लिए स्वींकृत लागत रु0 25.05 करोड़ के सापेक्ष अब तक रु0 2.32 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है।

वर्तमान में कार्य प्रगति में है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज-गोरखपुर को मुख्यालयों से जोड़ने हेतु फोर लेन रोड की योजना

45-श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुख्यालयों को फोरलेन से जोड़ने की योजनान्तर्गत जनपद महराजगंज-गोरखपुर भी सम्मिलित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

नेपाल के सीमावर्ती जिलों मे 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग

46-श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेपाल के सीमावर्ती जिलों में माओंवादियों की घुसपैठ को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार पूर्व की भांति 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

46-सम्प्रति प्रश्नगत् क्षेत्र को ग्रामीण एवं तहसील स्तरीय नगरों के शिड्यूल के अनुसार 10 घण्टे (साप्ताहिक अदल-बदलकर) विद्युत आपूर्ति आदेशित है। विद्युत की मांग के सापेक्ष उपलब्धता में कमी एवं राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा के मानकों को दृष्टिगत् विद्युत आपूर्ति में वृद्धि सम्भव नहीं है।

जनपद आगरा में ग्राम पंचायत सहारा में घनी आबादी के ऊपर से गुजर रही हाईटेशन लाईन को हटवाये जाने की मांग

47-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में ग्राम पंचायत सहारा में घनी आबादी के अन्तर्गत अमर चन्द के घर से गांव की घनी आबादी में होती हुई ऊपर से हाइटेन्शन की विद्युत लाईन गुजर रही है। जिससे गांव में कभी भी हादसा हो सकता है। यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत लाइन को घनी आबादी के ऊपर से हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रश्नगत् हाईटेन्शन लाइन 25 वर्ष पुरानी है। यह लाइन गांव की घनी आबादी से नहीं वरन रोड के किनारे से गुजर रही है। इस लाइन को हटाना संभव नहीं है। लाइन के पास में ही श्री कमल सिंह पुत्र श्री रामपाल व श्री पप्पू पुत्र श्री नारायन सिंह ने बाद में अपने-अपने मकानों का विस्तार रोड साइड में कर लिया गया है। लाइन के नीचे अवैध रूप से किये जा रहे निर्माण के विरुद्ध नोटिस दी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर व शामली में नहरों/रजबाहों/नालों की सफाई कराये गये कार्य का विवरण

48-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर व शामली में वित्तीय वर्ष 2012-13 में नहरों/नालों की सफाई हेतु कितना धन आवंटित किया गया तथा उससे कौन-कौन से नहरों/नालों की सफाई कराई गई, उसका विवरण क्या है ? क्या यह सत्य है कि अवमुक्त की गई धनराशि से नहरो/रजबाहों/नालों की सफाई कराने में खानापूर्ति कर धनराशि का गबन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद मुजफ्फरनगर में वित्तीय वर्ष 2012-13 में नहरों की सफाई पर रु0 426.49 लाख का आवंटन किया गया है एवं नालों की सफाई पर रु0 91.900 लाख का आवंटन किया गया है।

जनपद शामली वित्तीय वर्ष 2012-13 में नहरों की सफाई पर रु0 44.06 लाख का आवंटन किया गया है एवं नालों की सफाई पर रु0 106.50 लाख का आवंटन किया गया है। नहरों/नालों की सफाई का विवरण संलग्न है-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्त प्रस्तर-2 के अनुसार।

जनपद मऊ के दोहरी घाट पम्प कैनाल के सुचारुरूप से कार्य करने की जानकारी

49-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ की विधान सभा क्षेत्र मधुवन के अन्तर्गत दोहरी घाट पम्प कैनाल वर्तमान में अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोहरी घाट पम्प कैनाल का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

वर्तमान में पम्प नहर सुचारु रूप से चल रही है।

जनपद आजमगढ़ दोहरी घाट मार्ग से विक्ट्री इण्टर कालेज होते हुए दोहरी घाट मऊ मार्ग तक की मरम्मत करवाये जाने की जानकारी

50-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-मऊ के ब्लाक दोहरी घाट के अन्तर्गत आजमगढ़ दोहरी घाट मार्ग से विक्ट्री इण्टर कालेज होते हुए दोहरी घाट मऊ मार्ग तक वर्ष 2012 में लोक निर्माण विभाग द्वारा अधोमानक के अनुसार कार्य न कराने से उक्त निर्मित सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है ? यदि हां ? तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। कार्य मानक के अनुरूप कराया गया है। ठण्ड के कारण छोटे-छोटे भाग मे कहीं-कहीं पी0सी0 एवं सीलकोट क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे ठीक करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विकास खण्ड बड़रांव के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं की क्षतिग्रस्त मार्गों व सड़क की मरम्मत करवाये जाने की मांग

51-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-मऊ के विकास खण्ड बड़रांव के अन्तर्गत ग्राम सभा सोना डीह के प्रा0 विद्यालय से बाह्मण बस्ती तक सड़क, ग्राम सभा कटिहारी पिंच मार्ग से टकटेउवां तक सड़क, ग्राम सभा बड़रांव से सरबसपुर तक सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सोनाडीह प्रा0 विद्यालय से ब्राह्मण बस्ती तक 1.00 कि0मी0 कटिहारी पिच मार्ग से टकटेउवा तक 3.00 कि0मी0 तथा बड़रांव से सरबसपुर मार्ग पर सरबसपुर के तरफ 1.00 कि0मी0 मार्ग खड़न्जा स्तर का है, जिसका स्वामित्व जिला पंचायत का है। इस मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

बड़रांव से सरबसपुर मार्ग पर 5.00 कि0मी0 मार्ग लेपित स्तर का है, जो कही-कहीं क्षतिग्रस्त हो गया है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

52-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम सभा लउवासाथ से ग्राम सभा अहिरूपुर चट्टी तक सड़क, ग्राम सभा दुबारी गजियापुर मार्ग से मिश्रौली कुवंर पुरवा बन्धा तक सड़क, ग्राम सभा दुबारी टमठा सड़क से नई बस्ती होते हुए खैरा देवरा बन्धे तक की सड़कें अत्यन्त जर्जर क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां ? तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

ग्राम सभा लऊवासाथ से अहिरूपुर चट्टी तक मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

दुबारी-गजियापुर मार्ग से मिश्रौली कुंवरपुरवा बन्धा तक तथा दुबारी-टमठा सड़क से नई बस्ती देवारा बन्धा तक का मार्ग ग्रामीण स्तर का है जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के मुख्यालय पर पोस्टमार्टम हाउस के क्रियाशील होने की जानकारी

53-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जनपद-लखीमपुर खीरी में प्रत्येक थाना क्षेत्र में दुर्घटना आदि होने के कारण तथा मुख्यालय 100 कि0मी0 दूरी पर होने से मृतक को घटनास्थल से पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने और वापस लाने के लिये स्थापित पी0एम0 हाउस को चालू करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद लखीमपुर खीरी में मुख्यालय पर चीरघर क्रियाशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

54-श्री जय प्रकाश निषाद-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर में ग्राम सभा हैरया (टोला झिरझरवा) का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

55-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर में ग्राम सभा हैरया (टोला झिरझरवा) का विद्युतीकरण न होने से क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार उक्त ग्राम सभा का विद्युतीकरण करायगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर में ग्राम सभा हैरया का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

भारत सरकार द्वारा योजना स्वीकृत होने के उपरान्त अपेक्षित कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों के अलावा पत्थर का घोड़ा आदि के सौन्दर्यीकरण कराये जाने की मांग

56-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों के अलावा ऐसे अन्य लेसर नॉन मोन्यूमेन्ट्स यथा पत्थर का घोड़ा, छिंगा मोदी पुल, चीनी का रोजा, महावत खां का मकबरा एवं कंस दरवाजा आदि के सौन्दर्यीकरण की कोई कार्ययोजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास मंत्री- (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

जी नहीं।

प्रश्नगत स्मारकों का सौन्दर्यीकरण/कार्य योजना बनाये जाने का कोई भी प्रस्ताव विभाग के अन्तर्गत विचाराधीन नहीं है, क्योंकि ये स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित है।

जनपद बलिया के भरौली मार्ग स्थित नरही राजेश्वरी मोड़ से दौलत होते हुए फिरोजपुर तक मार्ग के नवीनीकरण के कार्य की प्रगति

57-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में बलिया-भरौली मार्ग स्थित नरही राजेश्वरी मोड़ से दौलतपुर होते हुए फिरोजपुर व अमाव मोड़ से टुटवारी जाने वाली सड़के जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

बलिया-भरौली मार्ग स्थित नरही राजेश्वरी मोड़ से दौलतपुर होते हुए फिरोजपुर तक मार्ग पर नवीनीकरण का कार्य प्रगति में है।

अमाव मोड़ से टुटवारी मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में सागरपाली से बैरिया बंधा तक मार्ग का नवीनीकरण व अर्धनिर्मित पुल के निर्माण कराये जाने की जानकारी

58-श्री उपेन्द्र तिवारी

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में सागरपाली से कोट अजोरपुर मझरिया होते हुए बैरिया तक जाने वाली जर्जर सड़क एवं मार्ग पर अर्द्धनिर्मित पुल का निर्माण कार्य पूरा कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव

जी हाँ।

सागरपाली से बैरिया बंधा तक मार्ग की लम्बाई 11.00 कि0मी0 है। इसके 2.75 कि0मी0 लम्बाई पर नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत है। 2.00 किमी लम्बाई पर कार्य कराया जा चुका है। 3.00 कि0मी0 लम्बाई में विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अवशेष मार्ग की लम्बाई 3.25 कि0मी0 है, जो सिंचाई विभाग के बंधे पर स्थित है तथा लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है।

पुल के निर्माण का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण है, जिस पर यातायात चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के टी0टी0जेड0 क्षेत्र में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की मांग

59-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टी0टी0जेड0 क्षेत्र के जनपद फिरोजाबाद नगर में 24 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद हो रही विद्युत कटौती को रोकने के लिये प्रश्नकर्ता का पत्रांक ख-5 नं0-274259 दिनांक 07-01-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है। तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उक्त पत्र के संदर्भ में तत्काल प्रभाव से दिनांक 19-01-2013 तक फिरोजाबाद नगर को 08 बजे से 18 बजे तक आपात कटौती से मुक्त किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के महिला अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती करने की जानकारी

60-डा0 अरुण कुमार-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के महिला अस्पताल में जननी शिशु सुरक्षा योजना लागू होने के बाद भी बच्चों के डाक्टर की तैनाती नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार बरेली महिला अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती शीघ्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जिला महिला चिकित्सालय, बरेली में डा0 अलका शर्मा, बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती के फलस्वरूप उनके द्वारा दिनांक 21-11-2012 को उक्त चिकित्सालय में योगदान कर लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के जिला अस्पताल में अपर निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक के पदों पर तैनाती किये जाने की जानकारी

61-डा0 अरुण कुमार-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के जिला अस्पताल में अपर निदेशक पूर्व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का पद बहुत समय से रिक्त है ? यदि हां, तो उक्त पद को न भरने का क्या कारण है ? क्या सरकार जनपद बरेली के जिला अस्पताल में अपर निदेशक एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के रिक्त पद पर तैनाती समयबद्ध सीमा में करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के जिला अस्पताल में अपर निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक के पद पर डा0 अनिल कुमार जैन (वरिष्ठता क्रमांक-4342) की तैनाती पूर्व में ही की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में बीसलपुर मार्ग (प्र0 जिलामार्ग) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने की मांग

62-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बरेली में बीसलपुर मार्ग (प्र0 जिलामार्ग) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

बरेली-बीसलपुर मार्ग के कि0मी0 1 से 26 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृत है। उक्त मार्ग के कि0मी0 27 से 40.800 तक के भाग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद पीलीभीत की पंचायत क्षेत्र बिलसण्डा में मुड़िया भगवन्तपुर के पास स्थित पुलिया व ता0 रामपुर अमृत के मध्य बरसाती नाले की क्षतिग्रस्त पुलियों की मरम्मत कराये जाने की मांग

63-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर जनपद पीलीभीत के क्षेत्र पंचायत बिलसण्डा में मकरन्दपुर रोशनसिंह से जमुनिया महुआ सम्पर्क मार्ग पर गांव मुडिया भगवन्तपुर के पास स्थित पुलिया, बिलसण्डा में गांव सिमरा महीपत एवं मोहम्मदपुर ता0 रामपुर अमृत के बरसाती नाले की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलियों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मकरन्दपुर रौशन सिंह से जमुनिया महुआ मुख्य सम्पर्क मार्ग पर गांव मुडिया भगवन्तपुर के पास स्थित पुलिया लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पीलीभीत में वित्तीय वर्ष में स्वीकृत मार्ग व उनका निर्माण कराये जाने की जानकारी

64-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत में वित्तीय वर्ष 2011-12 में कौन-कौन से मार्ग स्वीकृत हुए हैं ? क्या उनका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद पीलीभीत में वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल 50 मार्ग स्वीकृत हुये हैं, जिसके सापेक्ष 19 मार्गों पर निर्माण कार्य पूर्ण हैं तथा शेष 31 मार्गों पर निर्माण कार्य प्रगति में हैं। इनको पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के कतिपय ग्रामों के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत करवाये जाने की मांग

65-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पर्क मार्गों की मरम्मत एवं गड्ढ़ों को भरे जाने की क्या नीति है ? क्या मा0 मंत्री जी को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम अहमदपुर नियाजपुर (मेजवान होटल) के पास से रेती रोड तक जाने वाले मार्ग तथा ग्राम हथौड़िया, कुरसंडा, टिकरा, ददिउरा, तिउलक को जाने वाला मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उनकी मरम्मत करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सामान्य मरम्मत के अन्तर्गत पैच मरम्मत कर गड्ढ़ामुक्त करने का प्राविधान है।

उक्त मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

उक्त मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ में उपभोक्ता का ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने पर उपभोक्ता को विद्युत बिल में छूट दिये जाने का प्राविधान

66-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक कितने ट्रांसफार्मर फुंकने के आठ दिन बाद बदले गये ? क्या विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत उपभोक्ता को विद्युत लाइन एवं ट्रांसफार्मर की खराबी पर बिल में छूट का प्राविधान है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012 की अवधि में कुल 36 नग ट्रांसफार्मर आठ दिन बाद बदले गये।

जी हां।

उपभोक्ता का ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने की तिथि तक यदि उपभोक्ता पर कोई विद्युत बिल बकाया नहीं, तो एक माह से अधिक अवधि होने पर निम्नानुसार बिल में छूट दिये जाने का प्राविधान हैः-

(अ) निजी नलकूप उपभोक्ताओं के प्रकरण में एक माह से अधिक की अवधि के बिलों को माफ किया जाता है।

(ब) औद्योगिक उपभोक्ताओं के प्रकरणों में उपरोक्तानुसार मिनिमम कन्जम्प्सन गारण्टी (एम0सी0जी0) में छूट दिये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ स्थित शेखा झील को राष्ट्रीय आर्द्र संरक्षण कार्यक्रम में शामिल कर क्षेत्र में संरक्षण एवं प्राकृतवास प्रबन्धन का कार्य

67-श्री दलवीर सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद स्थित शेखा झील में प्रत्येक वर्ष हजारों विदेशी पक्षी आते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे बर्ड लाइफ सेंचुरी बनाने व इसके विकास पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

पक्षियों एवं जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत जनपद-अलीगढ़ स्थित शेखा झील को वन्य जीव विहार की परिधि में लाये बिना इसका विकास किया जा रहा है। इसलिए शेखा झील को राष्ट्रीय आर्द्र संरक्षण कार्यक्रम में शामिल कर क्षेत्र में संरक्षण एवं प्राकृतवास प्रबन्धन का कार्य किया जा रहा है।

जनपद अलीगढ़ के टप्पल टाउनशीप के लिये अधिग्रहीत भूमि कर लगे विद्युत उपकरणों के हटाने के उपरान्त सामान स्टोर में जमा न करने वालों के विरुद्ध जांच

68-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में टप्पल टाउनशीप के लिये अधिग्रहीत भूमि पर लगे विद्युत की लाइन तथा उपकरणों को हटाया गया था ? क्या हटाया गया पूर्ण सामान स्टोर में सही समय पर नहीं जमा किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

टप्पल टाउनशीप के लिए जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गई थी उनके तीव्र विरोध के कारण जिला प्रशासन के सहयोग से आंशिक सामग्री ही हटायी जा सकी।

जी हां।

आंशिक रूप से हटाया गया सामान स्टोर (भंडार) में माह जुलाई, 2012 से अगस्त, 2012 के मध्य जमा किया गया था। कुछ सामान विभागीय कार्यों में उपयोग किया गया है।

उक्त प्रकरण की जाँच हेतु कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8533 दिनांक 31-08-2012 द्वारा जाँच समिति गठित की गई है तथा जाँच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

अन्य राज्यों के इंजीनियरिंग कालेजों में उत्तर प्रदेश के छात्रों को सीटें आवंटित करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध

69-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई में स्टेट कोटा ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य राज्यों की तरह प्रदेश में भी स्टेट कोटे को पुनः बहाल करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री आलोक कुमार शाक्य)-

प्रदेश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा पाठ्यक्रमों में जो सीटें स्वीकृत की जाती हैं उसमें किसी प्रकार का स्टेट कोटा निर्धारित नहीं होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से वर्ष 2009 तक अन्य प्रदेशों के कतिपय इंजीनियरिंग कालेजों में प्रदेश के छात्रों के लिए बी0टेक0 पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु सीटें आवंटित की जाती थीं किन्तु वर्ष 2010 से प्रदेश के छात्रों हेतु अन्य प्रदेशों के कालेजों में कोई सीट भारत सरकार द्वारा आवंटित नहीं की जा रही है।

अन्य राज्यों के इंजीनियरिंग कालेजों में राज्य के छात्रों हेतु सीटें भारत सरकार द्वारा आवंटित की जाती है। पूर्व की भांति अन्य राज्यों के इंजीनियरिंग कालेजों में उत्तर प्रदेश के छात्रों को सीटें आवंटित करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में तथा उद्योग को विद्युत आपूर्ति किये जाने वाले समय की जानकारी

70-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों तथा उद्योगों को कितने घण्टों की विद्युत आपूर्ति दी जा रही है एवं कौन-कौन से जिलों

को विद्युत कटौती से मुक्त रखा गया है ? क्या सरकार जनपदवार विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों को 10 घण्टे (साप्ताहिक अदल-बदलकर) विद्युत आपूर्ति की जा रही है। जनपद स्तरीय शहरी क्षेत्रों को 17 घण्टे से 22 घण्टे तथा उद्योगों को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश मे रायबरेली नगर, अमेठी नगर, लोक सभा क्षेत्र लखनऊ, जनपद आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, रामपुर नगर एवं संभल नगर विद्युत कटौती से मुक्त है। जी हाँ। विवरण उपरोक्तानुसार है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के भाउराव देवरस अस्पताल, महानगर में ई0एन0टी0 विशेषज्ञ की तैनाती किये जाने की मांग

71-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भाऊराव देवरस अस्पताल, महानगर, लखनऊ में ई0एन0टी0 विशेषज्ञ डाक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है ? यदि हां, तो उक्त पद पर विशेषज्ञ डाक्टर की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हाँ। भाऊराव देवरस संयुक्त चिकित्सालय, महानगर लखनऊ में ई0एन0टी0 विशेषज्ञ का पद स्वीकृत न होने के कारण उक्त विशेषज्ञ की तैनाती नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र में स्थित बुढ़ाबाबू का तालाब के सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि

72-श्री सुरेश राणा-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि पौराणिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तालाबों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र में स्थित बुढ़ाबाबू का तालाब जो पौराणिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, का जीर्णोद्धार कराकर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

ऐसे पौराणिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तालाबों को, जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाता है।

बुढ़ाबाबू तालाब के सौन्दर्यीकरण हेतु जिला योजना समिति द्वारा रु0 10.00 लाख की योजना को चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुमोदित किया गया है।

जिला योजना समिति द्वारा इस योजना हेतु अनुमोदित धनराशि रु0 10.00 लाख की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि/नये निर्माण का विवरण

73-श्री सुरेश राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा प्रदेश में अधिभारित (ओवर लोडेड) बिजलीघरों की क्षमता वृद्धि की कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा स्थित बिजलीघरों लुहारी, मालेण्डी, पल्ठेडी, थानाभवन नगर की क्षमता वृद्धि कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ, आवश्यकतानुसार 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि किया जाना प्रचलित है।

जनपद शामली के थाना विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि/नये निर्माण का विवरण इस प्रकार हैः-

1. 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र हसनपुर लुहारी की क्षमता वृद्धि हेतु परिवर्तक आंवटित हो चुका है जो माह फरवरी, 2013 के अंत तक कार्य पूरा हो जायेगा।

2. 33/11 के0वी0 मालेण्डी (8+10 एमवीए) विद्युत उपकेन्द्र अतिभारित नहीं है।

3. 33/11 के0वी0 (2X10 एमवीए) पल्ठेड़ी/गढ़ी अब्दुल्ला विद्युत उपकेन्द्र अतिभारित है इसकी अतिभारिता को कम करने के लिए एक नया 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मुण्डेट खादर आर0जी0जी0वाई0 योजना-द्वितीय में प्रस्तावित किया गया है।

4. थाना भवन नगर में एक 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन में वित्तीय वर्ष में जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने की योजना में शामिल किये जाने की जानकारी

74-श्री सुरेश राणा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2012-13 में जर्जर सड़कों की मरम्मत एवं विशेष मरम्मत की कोई योजना है ? यदि हां, तो जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन की किन-किन सड़कों को इसमें शामिल किया गया है और उनका जीर्णोद्वार कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन की 26 सड़कों को इसमें शामिल किया गया है, जिनमें से एक मार्ग ऊन थाना भवन मार्ग पापड़ी रजवाहे की पटरी की विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत प्रदान की जा चुकी है। शेष 25 मार्गों के पुनः निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद गंगोह मार्ग पर टूटे पुल (पुलिया) की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने की जानकारी

75-श्री सुरेश राणा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में टूटे पुलों की मरम्मत एवं चौड़ीकरण की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो जनपद शामली के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र में जलालाबाद गंगोह मार्ग पीर स्थित टूटे पुल की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

टूटे पुलों की सामान्य मरम्मत का कार्य सतत प्रक्रिया है। पुलों के चौड़ीकरण का कार्य नवनिर्माण/ पुनः निर्माण के अन्तर्गत आता है, जो मार्ग के यातायात घनत्व एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

जनपद शामली के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र में जलालाबाद गंगोह मार्ग पर टूटे पुल (पुलिया) की मरम्मत एवं चौड़ीकरण का कार्य चालू वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद से दुलखा मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

76-श्री सुरेश राणा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में क्षतिग्रस्त एवं जर्जर सड़कों की मरम्मत की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो जनपद शामली के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र में जलालाबाद दुलखा मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में ऊर्जा विभाग टी0जी0 2 (लाइन) कुशल श्रमिक टी0जी0 2 (विद्युत) श्रमिक के स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण तथा नियुक्ति किये जाने की जानकारी

77-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऊर्जा विभाग में इस समय आपरेटिंग स्टाफ लाइनमैन, पेट्रोल मैन, मीटर रीडर एवं श्रमिकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति करेगी यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान में पूर्ववर्ती पद लाइनमैन, पेट्रोल मैन, मीटर रीडर का पद परिवर्तित होकर क्रमश टी0जी0 2 (लाइन), कुशल श्रमिक एवं टी0जी0 2 (विद्युत) हो गया है। स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है:-

पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
टी0जी0-2 (लाइन)	5997	2864
कुशल श्रमिक	12313	9247
टी0जी0-2 (विद्युत)	9510	2149
श्रमिक	11462	4444

सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति द्वारा रिक्त पदों पर कार्मिकों का चयन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत नियुक्तियाँ की जाती हैं। जिसके क्रम में विगत वर्षों में नियुक्तियाँ की गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधान सभा के क्षेत्र दो ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

78-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र के दो ग्रामीण सम्पर्क मार्गों पथरा से विशुनपुरवा सुमहा तिगोड़ना, जोगिया बुजुर्ग होते हुए बांसी बस्ती मार्ग के करही चौराहा तक एवं तिगोड़वा से वनगवां बन गड़ोरी, मसिना होते हुए बस्ती बांसी मार्ग के डिढ़ाई चौराहे तक मरम्मत का कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5 जून, 2012 को फैक्स सन्देश द्वारा अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, बांसी सिद्धार्थनगर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मार्गों के मरम्मत/पुननिर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ कें विकास खण्ड दोहरी घाट की ग्राम सभा अमिला दरगाह मार्ग पर हनुमत गेट से सूरजपुर मार्ग आदि की मरम्मत कराये जाने की मांग

79-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विकास खण्ड दोहरी घाट के अन्तर्गत ग्राम सभा अमिला दरगाह मार्ग पर हनुमत गेट से सूरजपुर मार्ग तक सड़क नई बाजार से तारनपुर होते हुए सियरही तक सड़क तथा कुस्महाँ से बरजला तक सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

हनुमत गेट से सूरजपुर मार्ग खड़न्जा स्तर का मार्ग है जिस पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

नई बाजार से तारनपुर होते हुए सियरही तक तथा कुस्महाँ से बरजला तक मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व है। यह मार्ग कहा-कही क्षतिग्रस्त है।

मार्गों के मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ ब्लाक दोहरी घाट के ग्राम सभा रेवली नरहरपुर के अन्तर्गत मौजा महावल चक आदि ग्रामों के विद्युतीकरण करके कनेक्शन दिये जाने की जानकारी

80-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के ब्लाक दोहरी घाट के ग्राम सभा रेवली नरहरपुर के अन्तर्गत मौजा महावल चक, पटेल बस्ती एवं चौहान बस्ती, ग्राम सभा अपड़िया हरिपरा, ग्राम टेसूपार का विद्युतीकरण नही हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मऊ के ब्लाक दोहरी घाट के ग्राम सभा रेवली नरहरपुर के अन्तर्गत मौजा महावल चक, पटेल बस्ती का विद्युतीकरण 63 के0वी0ए0 के परिवर्तक द्वारा किया गया है जिस पर 15 कनेक्शन (भार24 कि0वा0) दिये गये हैं एवं चौहान बस्ती का भी विद्युतीकरण 63 के0वी0ए0 का परिवर्तक से किया गया है। जिस पर 35 कनेक्शन (भार40 कि0वा0) दिये गये है। हरिपरा, ग्राम टेसूपार 63 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर से विद्युतीकृत है जिस पर 40 कनेक्शन (भार40 कि0वा0) दिया गये है। नये कनेक्शनों के आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के ब्लाक घोसी के मौजा जैतपुर, कैथोली की अनुसूचित जाति की बस्ती का विद्युतीकरण करवाये जाने की जानकारी

81-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के ब्लाक घोसी की ग्राम सभा मुरारपुर के अन्तर्गत मौजा अनुसूचित बस्ती ग्राम सभा धर्मपुर कसायर (कैथोली) अनुसूचित बस्ती में सरकार विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

जनपद मऊ के ब्लाक घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा मुरारपुर के अन्तर्गत मौजा जैतपुर अनुसूचित बस्ती ग्राम सभा धर्मपुर कसायर (कैथोली) अनुसूचित बस्ती के विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण में सम्मिलित कर लिया गया है। योजना की स्वीकृति एवं धन प्राप्ति के उपरान्त कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ ब्लाक फतेहपुर मण्डान के ग्राम सभा सुआह अनुसूचित बस्ती के ग्रामों का राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण

82-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के ब्लाक फतेहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम सुआह अनुसूचित बस्ती ग्राम गंगऊपुर, ग्राम सभा हदय पट्टी अनुसूचित बस्ती में सरकार विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मऊ के ब्लाक फतेहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम सभा सुआह अनुसूचित बस्ती ग्राम गंगऊपुर, ग्राम सभा हदय पट्टी अनुसूचित बस्ती का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में कराया जा चुका हैं। उपरोक्त बस्तियों में ग्राम सभा सुआह एवं ग्राम गंगऊपुर में क्रमश 35 एवं 40 विद्युत कनेक्शन हैं। ग्राम सभा हदय पट्टी पूर्व से ही विद्युतीकृत हैं तथा नये कनेक्शन के आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के चौरी-चौरा क्षेत्र के विकास खण्ड सरदार नगर में मां तर्कूलही देवी पर्यटक स्थल का विकास व सौन्दर्यीकरण कराये जाने की जानकारी

83-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र के विकास खण्ड सरदार नगर में मां तर्कूलही देवी एक ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उसका सौन्दर्यीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

गोरखपुर में विकास खण्ड सरदार नगर में मां तर्कूलही देवी के सौन्दर्यीकरण की योजना सम्प्रति विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त स्थल राजस्व ग्राम बेबीपुर उर्फ तरकुलहा वर्तमान समय में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत हैं अतः स्थल पर ग्राम सभा/सरकारी भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने की दशा में विकास कार्य कराया जाना सम्भव है।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के आगरा रजवा नहर के अन्तर्गत आने वाली माइनर एवं गूल की सफाई करवाये जाने की जानकारी

84-श्री काली चरन सुमन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्रमीण विधान सभा क्षेत्र के आगरा रजवा नहर के अन्तर्गत आने वाली माईनर एवं गूल की सफाई सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

रजवाहा आगरा के अन्तर्गत आने वाली माइनरों की सफाई के कार्य मनरेगा के अन्तर्गत करा दिये गये हैं तथा गूलों का रख-रखाव कृषकों द्वारा स्वयं किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिल्डर्स/कोलोनाईजर्स चमरौली आदि गावों के आम रास्ते गूल व सार्वजनिक स्थलों को अपनी कालोनियों में सम्मिलित किये जाने की जानकारी

85-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्रमीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिल्डर्स/कोलोनाईजर्स ने चमरौली, रजरई, सैमरी पचगाई खेड़ा, नगला काली आदि गांवों के आम रास्ते गूल व सार्वजनिक स्थलों को अनाधिकृत रूप से अपनी कालोनियों मे सम्मिलित कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड कुरारा में सिटी फारेस्ट से चन्दूपुर आदि रोड के निर्माण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

86-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड कुरारा में सिटी फारेस्ट से चन्दूपुर तक एवं सिरोड़ी से भटपुरा तक रोड निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-5/009407 दिनांक 19-06-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड कुरारा में सिटी फारेस्ट से चन्दूपुर तक मार्ग निर्माण का प्रस्ताव सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं पाया गया। ग्राम सिकरोढ़ी एवं ग्राम भटपुरा शासन की सिंगिल कनेक्टीविटी नीति के अन्तर्गत पक्के मार्ग से जुड़े हैं।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मौदहा के ग्राम मैदहा तथा छिमौली रोड निर्माण विषयक पत्र पर कार्यवाही

87-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मौदहा में, मौदहा से छिमौली तक रोड व रपटा निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-5/009407 दिनांक 19.06.2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

ग्राम मौदहा तथा छिमौली दोनों ग्राम पूर्व से लेपित एकल मार्ग से जुड़े हुये हैं।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद हमीरपुर सदर के विकास खण्ड कुरारा के बिलौटा के छक्की का डेरा आदि ग्रामों का विद्युतीकरण करने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

88-साध्वी निरंजन ज्योति

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर सदर के विकास खण्ड कुरारा के बिलौटा के मजरे से छक्की का डेरा, टेकचन्द्र का डेरा, धनीराम का डेरा तक का

विद्युतीकरण कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-5/009410 दिनांक 19-06-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

जनपद हमीरपुर सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड कुरारा के ग्राम बिलौटा के मजरे छक्की का डेरा एवं धनीराम का डेरा को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत चयनित करते हुए डीपीआर भारत सरकार को स्वीकृत हेतु प्रेषित कर दी गई है। डीपीआर की स्वीकृति एवं धन प्राप्त होने पर विद्युतीकरण की कार्यवाही सम्भव होगी। टेक चन्द्र का डेरा की आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार मानक 300 से कम है। अतः इस मजरे को योजना में शामिल नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर के विकास खण्ड सुजानगंज के सखवट माइनर पर कदम पुलिया तथा दोनों डौले को पक्का करवाने की मांग

89-श्रीमती सीमा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर के विकास खण्ड सुजानगंज में सखवट माइनर पर कदम पुलिया तथा दोनों डौले को सरकार पक्का करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभागीय मानकों के अनुरूप साध्य नहीं पाया गया है।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के ग्राम मुंडाव व रामपुर का विद्युतीकरण कराये जाने की जानकारी

90-श्रीमती सीमा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के मुँडाव, तरसाँव बारा सरोखनपुर, रामपुर में विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद जौनपुर के विधान सभा मुंगराबादशाहपुर के ग्राम तरसाव, बारा एवं सरोखनपुर का विद्युतीकरण पूर्व में निर्धारित मानक के अनुसार कराया जा चुका है। ग्राम मुंडाव व रामपुर का विद्युतीकरण नहीं हुआ है।

जी हाँ।

ग्राम-मुंडाव व रामपुर के विद्युतीकरण कार्य को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित कर लिया गया है। धन की उपलब्धता होने पर कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा में खैरी से तिनबरदहा पानमती स्थान होते हुए डोमन पट्टी तक पिच मार्ग के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव

91-श्री विजय कुमार दुबे-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा के डोमन पट्टी से पानमती होते हुए तिनबरदहा भटपुरवा तक के लगभग 04 किमी0 तक मार्ग कच्चा होने के कारण आवागमन में समस्या होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका पिच स्तर तक निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

जनपद-कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा में खैरी से तिनबरदहा पानमती स्थान होते हुए डोमन पट्टी तक पिच मार्ग के निर्माण कार्य से संबंधित प्रस्ताव आयुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर के पत्र दिनांक 4-2-2013 के माध्यम से शासन में दिनांक 12-2-2013 को प्राप्त हुआ है। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य की स्वीकृति पर वर्तमान वर्ष में विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र के पनियहवा शुगर मिल तक के प्रमुख क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

92- श्री विजय कुमार दुबे-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र के पनियहवा से छितौनी शुगर मिल तक के प्रमुख मार्ग कई वर्षों से क्षतिग्रस्त हैं ?

यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

उक्त मार्ग का स्वामित्व गन्ना विभाग का है। क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। गन्ना विभाग द्वारा चीनी मिल क्षेत्रों में अंशदायी आधार पर संबधित गन्ना विकास परिषदों से प्राप्त 40 प्रतिशत अंशदान में 60 प्रतिशत शासकीय अंशदान सम्मिलित करते हुए उपलब्ध धनराशि से सड़कों का निर्माण कराया जाता है। गन्ना विकास परिषद, छितौनी की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण गन्ना विभाग द्वारा पुनर्निर्माण नहीं कराया जा पा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

93-श्री कालीचरन सुमन-

[1ले गुरूवार के अता0 प्र0 सं0-56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में विकास प्राधिकरणों द्वारा नये भवनों के मानचित्र पास करने में रूफ टाप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग-के मानकों का प्रयोग न करने वालों के विरुद्व कार्यवाही

94-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकास प्राधिकरण द्वारा नये भवनों के मानचित्र प्राप्त करने के रूफ टाप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग-के प्राविधान हेतु शासनादेश संख्या-1730 दिनांक 12-04-2001, शासनादेश संख्या-यू0ओ0 35, दिनांक 25-04-2006 एवं शासनादेश सं0-3982, दिनांक 01-07-2008 में मानक निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या शासनादेश जारी किये जाने के बावजूद अधिकांशतः भवन निर्माण में इन मानकों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करा कर ऐसे सभी प्राधिकरणों एवं भवनों को मानक के अनुसार ''रेन रूफ हार्वस्टिंग'' एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्राविधान सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

भवन निर्माण में निर्धारित मानकों के उल्लघंन का मामला कतिपय विकास प्राधिकरणों के संज्ञान में आये हैं, जिसके संबंध में संबंधित विकास प्राधिकरण स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मऊ में विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक दोहरीघाट के अन्तर्गत जिला सहकारी फेडरेशन लि0 के शीतगृह को चालू कराये जाने की मांग

95-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ में विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक दोहरीघाट के अन्तर्गत जिला सहकारी फेडरेशन लि0, आजमगढ़ द्वारा संचालित शीत गृह बीस वर्षों से अधिक समय से बन्द पड़ा है, जिससे क्षेत्रीय जनता को आलू भण्डारा करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बन्द पड़े सहकारी फेडरेशन लि0 के शीतगृह को चालू करोयगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद मऊ के विधान सभा मधुबन के ब्लाक दोहरीघाट के अन्तर्गत जिला सहकारी फेडरेश्न लि0, आजमगढ़ द्वारा वर्ष 1977 से उक्त शीतगृह संचालित किया गया था। उक्त शीतगृह से संस्था को हानि होने के कारण वर्ष 1997 से बन्द करना पड़ा। वर्ष 1997 लगभग 15 वर्षों से बन्द होने के कारण प्लान्ट/मशीनरी सब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है और किसी प्रकार से मरम्मत योग्य नहीं रह गयी है। वर्तमान में संस्था रू0 29 लाख की हानि में है और उक्त शीतगृह नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत है। अतः उसको पुनः चालू करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाँव के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने की जानकारी

96-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाँव के अन्तर्गत ग्राम सभा रसूलपुर उर्फ रामपुर के मजरा चांदपुर के पूर्व मोहल्ला में स्थित छोटी मस्जिद तक विद्युतीकरण एवं ट्रांसफार्मर लगाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के विकास खण्ड फतहपुर मण्डांव के अन्तर्गत ग्राम सभा रसूलपुर आदमपुर उर्फ रामपुर के मजरा चाँदपुर के पूर्वी मोहल्ला में स्थित

छोटी मस्जिद तक विद्युतीकरण पूर्व में 63 के0वी0ए0 का परिवर्तक लगाकर कराया जा चुका है। यह परिवर्तक अतिभारित नहीं है अतः दूसरा परिवर्तक लगाना तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है।

जनपद वाराणसी में गंगाघाट से दो सौ मीटर के दायरे में स्थित पुराने एवं जर्जर भवनों की मरम्मत कराये जाने की अनुमति की मांग

97-श्री श्यामदेव राय चौधरी-(दादा)

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में गंगाघाट से दो सौ मीटर के दायरे में स्थित पुराने एवं जर्जर भवनों के परिवर्तन-परिवर्द्धन एवं मरम्मत का कोई प्रतिबन्ध लागू है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुरातन नगरी काशी से प्रभावित भवनों की मरम्मत करने की अनुमति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

जनहित याचिका सं0-31229/2005 कौटिल्या सोसाइटी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 27.07.2012 द्वारा गंगा तट से दो सौ मीटर क्षेत्र में निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है। मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश के उपरान्त ही नियमानुसार कार्यवाही सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ शहर में एटा चुंगी चौराहे को जाम से निजात दिलाये जाने हेतु 4-लेन बाईपास बनाये जाने की जानकारी

98-श्री दलवीर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ शहर में एटा चुंगी चौराहे को जाम से निजात दिलाने हेतु सरकार उसके चौड़ीकरण एवं सुन्दरीकरण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अलीगढ़ शहर के मध्य से जी0टी0रोड एन0एच0-91 पास होने के कारण शहर के मध्य से भारी-वाहनों का आवगमन रहता है। मार्ग पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लगभग 20 कि0मी0 लम्बा 4-लेन बाईपास बनाया जा रहा है, कार्य प्रगति पर है। बाईपास बन जाने के उपरान्त शहर के मध्य से भारी वाहनों का आवागमन बन्द हो जायेगा और जाम से निजात मिल जायेगी

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

अब निधन के निर्देश।

अतांराकित प्रश्न सं0-65 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद। मान्यवर, आज नत्थी 'ख' के अतारांकित प्रश्न संख्या-65 पर यह मान्यवर, हमारा प्रश्न था। क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पर्क मार्गों की मरम्मत एवं गड्ढों को भरे जाने की क्या नीति है, इसका उत्तर मान्यवर, आया कि सामान्य मरम्मत के अन्तर्गत पैच मरम्मत कर गड्ढामुक्त करने का प्राविधान है। मान्यवर, मैंने 3-4 सड़कें इसमें दी थीं और केवल गड्ढामुक्त करने का उद्देश्य मेरा था। मान्यवर, हजारों करोड़ रुपये का बजट है और बड़े-बड़े इश्तहार दिये गये कि गड्ढामुक्त सड़क करा देंगे और नीचे लिख दिया गया कि उक्त मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलबधता पर निर्भर है। जब गड्ढामुक्त सड़क नहीं होगी तो मान्यवर, हम लोग यहाँ पर किसलिए आते हैं। एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि हम गड्ढामुक्त सड़क करायेंगे और दूसरी तरफ मान्यवर, जवाब यह आता है कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ मान्यवर, छोटे-छोटे दो-दो किलोमीटर के मार्ग हैं उसमें गड्ढे हैं ज्यादा से ज्यादा चारों मार्गों पर 10 से 20 हजार रुपया गड्ढामुक्त होने में खर्च आयेगा। मान्यवर, 7 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट कल प्रस्तावित हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि बड़े-बड़े इश्तहार, इलेक्ट्रानिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक में कहा जाता है कि सड़कों को गड्ढामुक्त करायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आप अपनी बात कहिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम यह चाहते हैं कि इन मार्गों को गड्ढामुक्त करा दिया जाए, हम आपका संरक्षण चाहते हैं कि आप कोई व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष-

आपने मंत्री जी से कह दिया और मा0 मंत्री जी ने सुन लिया ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मंत्री जी यह कह दें कि दिखवा लेंगे।

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन तथा परती भूमि विकास विभाग मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, लिख करके दे देंगे, हम दिखवा लेंगे।

(मा0 सदस्य श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, कृपया बैठ जाएं अब निधन के निर्देश ले रहे हैं।

प्रश्नों के वार निर्धारण के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं आप हम सबका संरक्षण करते हैं। मान्यवर, प्रश्नों के सन्दर्भ में पिछली बार मैंने एक व्यवस्था उठाई थी और आपने उस पर अपना निर्देश दिया था। मान्यवर, नत्थी-ग देख लें, इसमें कार्य-मंत्रणा की सिफारिशें हैं, 14 तारीख से सदन शुरू हुआ और 22 तारीख तक सदन चलेगा। मान्यवर, आप भी छठी बार जीत कर आये हैं और सौभाग्य से मैं भी छठी बार जीत करके आया हूँ लेकिन आप हमसे वरिष्ठ हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना सवाल कीजिए।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, पिछली बार मैंने पूछा था कि क्या कभी आठवाँ, नवाँ और दसवां बुधवार आपने देखा है। मान्यवर, मैं पिछले 6 टर्म में मैंने तो यह बुघवार देखा नहीं है। मान्यवर, जो मेरे पास स्वीकृत हो करके प्रश्न आये हैं वह नवें बुधवार के लिए हैं। आठवें, सातवें बुधवार का आया है। मान्यवर, यदि ऐसे प्रश्न स्वीकार करके औपचारिकता पूरी की जानी है तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। मान्यवर, पिछली बार आपने व्यवस्था दी थी कि उसको देख लिया करें। एक-दो आगे पीछे तो हो सकता है लेकिन मान्यवर, नवाँ बुधवार नहीं आयेगा। मेरा आपसे निवेदन है प्रश्नों से सम्बन्धित यह विषय है, महत्वपूर्ण होते हैं और यह विपक्ष का अधिकार होते हैं। आप हमारे अधिकारों का संरक्षण करें और जो छठे, सातवें, आठवें और नवें बुधवार के लिए जो हमारे प्रश्न स्वीकार किये गये हैं उस पर पुनर्विचार करके पहले किसी तारीख में लगवा दें, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय महाना जी, प्रश्न जब किया जाता है तो उसकी डेट के हिसाब से, जैसे प्रश्न आता है उसके हिसाब से वह क्रम में लगता है। अब आपसे पहले किसी सदस्य ने ज्यादा सवाल पूछ लिए तो उनके सवाल क्रम में लग गये, आपका सवाल बाद में पहुँचा होगा तो बाद का क्रम मिला लेकिन यदि महत्वपूर्ण सवाल है तो उसे हम दिखवा लेंगे।

विधान सभा के पूर्व सदस्यों सर्वश्री धनीराम वर्मा (पूर्व अध्यक्ष, विधान सभा), श्री रामबाबू मिश्र, श्री ख्याली राम शास्त्री, श्री शिवलाल मित्तल, श्री नित्यानन्द स्वामी, श्री बृजलाल, श्री राम दयाल, श्री मुन्शी लाल, श्री जगदम्बा सिंह, श्री राम हर्ष मिश्र, श्री सईदुल हसन, श्री किशोरी लाल यादव, श्री मान सिंह आजाद, श्री प्रभु दयाल प्रधान तथा श्री श्याम बिहारी सिंह के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा का 12 दिसम्बर, 2012 कों निधन हो गया। वे लगभग 82 वर्ष के थे।

श्री धनीराम वर्मा का जन्म 7 अक्टूबर, 1930 को ग्राम पुर्वासुजान, जिला औरैया में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल0टी0 की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री धनीराम वर्मा वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र औरैया, जिला इटावा से जनता (एस) चरण सिंह के टिकट पर, वर्ष 1989 में निर्वाचन क्षेत्र विधुना, जिला इटावा से जनता दल के टिकट पर, वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र विधूना, जिला इटावा से जनता पार्टी के टिकट पर वर्ष वर्ष 1993 एवं 1996 में निर्वाचन क्षेत्र विधूना, जिला इटावा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर तथा वर्ष 2007 में निर्वाचन क्षेत्र विधूना, जिला औरैया से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री धनीराम वर्मा 15 दिसम्बर, 1993 से 20 जून, 1995 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष पद पर रहे। वे 21 अप्रैल, 1997 से 15 सितम्बर, 2001 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा में नेता विरोधी दल भी रहे थे। श्री धनीराम वर्मा विभिन्न आन्दोलनों में वर्ष 1978, 1980 तथा 1983 में धारा 144 एवं 188 के अन्तर्गत सेण्ट्रल जेल, फतेहगढ़ तथा जिला जेल, इटावा में बन्दी रहे थे। वे भगवान दास इण्टर कालेज, हरचन्दपुर के प्रधानाचार्य, श्री शिव इण्टर कालेज के संस्थापक एवं प्रबन्धक जनता इण्टर कालेज पुर्वासुजान, इटावा के प्रबन्धक एवं संरक्षक तथा कई शैक्षिक संस्थाओं से भी सम्बद्ध रहे थे। वे जिला सहकारी बैंक, इटावा के उपाध्यक्ष एवं संचालक, बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के कार्यकारी उपाध्यक्ष तथा यू0पी0 एग्रो के चेयरमैन भी रहे थे। जनसेवा, राजनीति, अध्ययन एवं अध्यापन में उनकी विशेष रुचि थी तथा शैक्षिक कार्य एवं खेलकूद उन्हें प्रिय था।

श्री धनीराम वर्मा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रामबाबू मिश्र का 29 नवम्बर, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 77 वर्ष के थे।

श्री रामबाबू मिश्र का जन्म 2 अगस्त, 1934 को मथुरा में हुआ था। उन्होने बी0 काम0 एवं एल0 टी0 की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री रामबाबू मिश्र वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र मथुरा, जिला मथुरा से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री रामबाबू मिश्र ने पत्रकार एवं छात्र नेता के रूप में विदेशों का भ्रमण किया था। खेलकूद में उनकी विशेष रुचि थी तथा गृह, सूचना, शिक्षा आदि विषय भी उनको प्रिय थे।

श्री रामबाबू मिश्र के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री ख्याली राम शास्त्री का 14 नवम्बर, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 91 वर्ष के थे।

श्री ख्याली राम शास्त्री का जन्म अक्टूबर, 1921 में हुआ था। उन्होंने व्याकरण शास्त्री एवं वैद्यराज की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री ख्याली राम शास्त्री वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र अमरोहा (पूर्व) जिला मुरादाबाद से कांग्रेस के टिकट पर, वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र मुरादाबाद (पश्चिम), जिला मुरादाबाद से कांग्रेस के टिकट पर तथा वर्ष 1977 में इसी निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री ख्याली राम शास्त्री वर्ष 1942 के स्वतंत्रता आंदोलनों में अनेक बार जेल गये थे। वे जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री, पी0सी0सी0 के सदस्य तथा जिला कांग्रेस परिषद् के सदस्य रहे थे। वे केन डेवलपमेन्ट कौंसिल तथा आई0टी0आई0, चन्दौसी के अध्यक्ष एवं अनेक शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष भी रहे थे। श्री ख्याली राम शास्त्री श्री बनारसी दास मंत्रि-मण्डल में मंत्री रहे थे। उन्हें 25 अगस्त, 2006 को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा प्रथम विधान सभा के सदस्य होने का सम्मान प्रदान किया गया था। कृषि तथा लघु उद्योग में उनकी रुचि थी।

श्री ख्याली राम शास्त्री के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शिव लाल मित्तल का 10 दिसम्बर, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 81 वर्ष के थे।

श्री शिव लाल मित्तल का जन्म मई, 1931 में ग्राम नौरंग बास (भवानी, हरियाणा) में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री शिव लाल मित्तल वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र शोहरतगढ़, जिला बस्ती से जनता पार्टी के टिकट पर तथा वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र शोहरतगढ़, जिला सिद्धार्थनगर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री शिव लाल मित्तल पार्टी द्वारा चलाये गये सत्याग्रहों और आंदोलनों में अनेक बार जेल गये थे तथा वर्ष 1975-76 में डी0 आई0 आर0, मीसा आदि के अन्तर्गत जिला कारागार बस्ती, देवरिया, गोरखपुर एवं दिल्ली जेल में बन्दी रहे थे। वे क्षेत्र समिति नौगढ़ तथा जिला सहकारी संघ, बस्ती के सदस्य, सहकारी क्रय-विक्रय समिति के उपाध्यक्ष और सहकारी संघ, तेतरी बाजार के अध्यक्ष रहे थे। श्री शिव लाल मित्तल कई शिक्षण संस्थाओं से भी सम्बद्ध रहे थे। समाज तथा गरीबों की सेवा में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री शिव लाल मित्तल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य तथा विधान परिषद् के भूतपूर्व सभापति श्री नित्यानन्द स्वामी का 12 दिसम्बर, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 84 वर्ष के थे।

श्री नित्यानन्द स्वामी का जन्म 27 दिसम्बर, 1928 को नारनौल, हरियाणा में हुआ था। उन्होंने एम0 ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री नित्यानन्द स्वामी वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र देहरादून नगर से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे वर्ष 1984, 1990 तथा 1996 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री नित्यानन्द स्वामी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभायी थी । वे वर्ष 1950 से 1951 तक कालेज छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे । वे 13 अगस्त, 1991 को विधान परिषद् के उप सभापति के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। श्री नित्यानन्द स्वामी जुलाई, 1992 से 9 मई, 1996 तक कार्यकारी सभापति विधान परिषद् रहे तथा पुनः 23 मई, 1996 से 8 नवम्बर, 2000 तक लगातार सभापति रहे थे। वे 9 नवम्बर, 2000 से 29 अक्टूबर, 2001 तक नवगठित उत्तराखण्ड राज्य के प्रथम मुख्य मंत्री भी रहे थे। वे विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक तथा धार्मिक संगठनों से भी सम्बद्ध रहे। आपातकाल में तथा विभिन्न जन समस्याओं को लेकर वे अनेक बार जेल गये थे। अध्ययन एवं खेलकूद में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री नित्यानन्द स्वामी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बृज लाल का 12 दिसम्बर, 2012 को निधन हो गया।

श्री बृज लाल वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र कादीपुर (अ0जा0) जिला सुल्तानपुर से जनता पार्टी के टिकट पर तथा वर्ष 1984 के उप चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र मलिहाबाद, जिला लखनऊ से निर्दलीय सदस्य के रूप में विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री बृज लाल एक कर्मठ सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी रुचि थी ।

श्री बृज लाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम दयाल का 15 दिसम्बर, 2012 को निधन हो गया।

श्री राम दयाल का जन्म ग्राम धनपुरा, जिला मेरठ में हुआ था। उन्होंने विशारद की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री राम दयाल वर्ष 1974 तथा 1977 में निर्वाचन क्षेत्र किठौर, जिला मेरठ से क्रमशः भारतीय क्रान्ति दल तथा जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री राम दयाल नवजीवन इण्टर कालेज के मैनेजर तथा बैजल मेमोरियल इण्टर कालेज, लोधीपुर, जिला मेरठ के अध्यक्ष रहे थे। कृषि से उन्हें विशेष प्रेम था।

श्री राम दयाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मुंशी लाल का 23 दिसम्बर, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थे।

श्री मुंशी लाल का जन्म वर्ष 1933 में ग्राम बरनाहल, जिला मैनपुरी में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री मुंशी लाल वर्ष 1967 तथा 1969 में निर्वाचन क्षेत्र करहल (अ0जा0), जिला मैनपुरी से स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर, वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र किशनी (अ0जा0), जिला मैनपुरी से कांग्रेस के टिकट पर तथा इसी निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980 में काग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री मुंशी लाल वर्ष 1977 तथा 1978 में धारा 188 के अन्तर्गत राजनीतिक बन्दी रहे थे। वे उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ के महामंत्री तथा जिला कांग्रेस कमेटी, मैनपुरी के उपाध्यक्ष रहे थे। वे वर्ष 1970-71 में श्री त्रिभुवन नारायण सिंह मंत्रि-मण्डल में राज्य मंत्री भी रहे थे। श्री मुंशी लाल कई शिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध रहे थे। शिक्षा संबंधी कार्यों तथा कृषि में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री मुंशी लाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जगदम्बा सिंह का 30 दिसम्बर, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 70 वर्ष के थे।

श्री जगदम्बा सिंह का जन्म 1 नवम्बर, 1942 को ग्राम छतौना, जिला बस्ती में हुआ था। उन्होंने बी0 ए0, जे0टी0सी0 एवं बी0एड0 की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री जगदम्बा सिंह वर्ष 1991 के उप चुनाव में तथा 1993 में निर्वाचन क्षेत्र हरैया, जिला बस्ती से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री जगदम्बा सिंह वर्ष 1990 में श्री राम जन्म भूमि आंदोलन में अस्थायी कारागार, बस्ती रहे थे। वे वर्ष 1983 से 1988 तक भारतीय जनता पार्टी के मण्डल अध्यक्ष तथा वर्ष 1988 से 1991 तक क्षेत्र समिति, विक्रमजोत, बस्ती के ब्लाक प्रमुख रहे थे। वे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी रहे थे। अध्यापन एवं समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा खेल-कूद प्रिय था।

श्री जगदम्बा सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम हर्ष मिश्र का 5 जनवरी, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 87 वर्ष के थे।

श्री राम हर्ष मिश्र का जन्म 25 मई, 1926 को ग्राम महसी, जिला बहराइच में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री राम हर्ष मिश्र वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र महसी, जिला बहराइच से कांग्रेस के टिकट पर तथा वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र फखरपुर, जिला बहराइच से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री राम हर्ष मिश्र राजनीतिक आन्दोलनों के संबंध में वर्ष 1979-80 के मध्य 15 दिन केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में बन्दी रहे थे। वे ग्राम सभा, महसी के प्रधान तथा ब्लाक प्रमुख रहे थे। वे स्वामी विवेकानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महसी के संस्थापक एवं प्रबन्धक भी थे। कृषि विकास एवं शिक्षा संबंधी कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री राम हर्ष मिश्र के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सैयद सईदुल हसन का 6 जनवरी, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 88 वर्ष के थे।

श्री सैयद सईदुल हसन का जन्म 25 जनवरी, 1925 को हुआ था।

श्री सैयद सईदुल हसन वर्ष 1980 तथा 1985 में निर्वाचन क्षेत्र बुलन्दशहर, जिला बुलन्दशहर से कांग्रेस(आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य भी रहे थे।

श्री सैयद सईदुल हसन श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रि-मंडल तथा वीर बहादुर सिंह मंत्रि-मंडल में मंत्री रहे थे। वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव, उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे थे। वे वर्ष 1993 से 1999 तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे थे।

श्री सैयद सईदुल हसन के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री किशोरी लाल यादव का 8 जनवरी, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 71 वर्ष के थे।

श्री किशोरी लाल यादव का जन्म 1 नवम्बर, 1942 को ग्राम तुलसीपुर, जिला जौनपुर मे हुआ था। उन्होंने एम0 एससी0, एम0ए0 एवं बी0एड0 की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री किशोरी लाल यादव वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र मडियाहूँ, जिला जौनपुर से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री किशोरी लाल यादव वर्ष 1987 में माध्यमिक शिक्षक संघ तथा दहेज उन्मूलन एवं पुलिस अत्याचार विरोधी आंदोलनों में अनेक बार जेल में बन्दी रहे थे। वे श्री कृष्ण गोपाल गोशाला, मडियाहूँ, जौनपुर के महामंत्री रहे थे। सामाजिक, राजनैतिक एवं गरीबों के उद्धार हेतु कार्य करने में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री किशोरी लाल यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मान सिंह आजाद का 9 जनवरी, 2013 को निधन हो गया । वे लगभग 93 वर्ष के थे। श्री मान सिंह आजाद का जन्म 14 नवम्बर, 1920 को हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल स्तर तक शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री मान सिंह आजाद वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र मलिहाबाद (अ0जा0), जिला लखनऊ से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री मान सिंह आजाद ने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था जिसके फस्वरूप वे एक वर्ष कठोर कारावास में रहे थे। स्वतंत्रता के पश्चात् शरणार्थी कैम्पों में उन्होंने सेवा कार्य भी किया था। उन्होंने विभिन्न आन्दोलनों में भाग लिया था तथा डी0आई0आर0 एवं मीसा में भी बन्दी रहे थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस (संगठन) के सदस्य के रूप में उन्होंने अनेक पदों पर कार्य किया था। वे लखनऊ जिला परिषद् के सदस्य भी रहे थे।

श्री मान सिंह आजाद के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री प्रभू दयाल प्रधान का 20 जनवरी, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 85 वर्ष के थे।

श्री प्रभू दयाल प्रधान का जन्म 11 फरवरी, 1928 को ग्राम धनपुरा, जिला मेरठ में हुआ था।

श्री प्रभू दयाल प्रधान वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र किठोर, जिला मेरठ से लोकदल के टिकट पर तथा वर्ष 1989 में निर्वाचन क्षेत्र खरखौदा, जिला मेरठ से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य भी रहे थे।

श्री प्रभू दयाल प्रधान विभिन्न आन्दोलनों में धारा 144 का उल्लंघन करने के कारण जिला कारागार, मेरठ में बन्दी रहे थे। वे नवजीवन किसान इण्टर कालेज, लोधीपुर तथा कृषक इण्टर कालेज, परीक्षित गढ़ की कार्यकारिणी के सदस्य रहे थे। समाज सेवा, संगीत तथा टेक्निकल कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री प्रभू दयाल प्रधान के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री श्याम बिहारी सिंह का 11/12 फरवरी, 2013 की रात्रि में निधन हो गया। वे लगभग 75 वर्ष के थे।

श्री श्याम बिहारी सिंह का जन्म 11 नवम्बर, 1938 को ग्राम बड़ागांव, जिला बरेली में हुआ था।

श्री श्याम बिहारी सिंह निर्वाचन क्षेत्र आंवला, जिला बरेली से वर्ष 1974 में जनसंघ के टिकट पर, वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर तथा वर्ष 1985, 1989 एवं 1991 में जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री श्याम बिहारी सिंह पार्टी आन्दोलनों में डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत अनेक बार जेल गये तथा जिला जेल और केन्द्रीय जेल, बरेली में बन्दी रहे थे। वे को-आपरेटिव सोसाइटी, राजपुरकला, बरेली के सदस्य रहे थे। शिक्षा और सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र में उनका रचनात्मक सहयोग रहा था। सार्वजनिक, धार्मिक और समाजोत्थान के कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री श्याम बिहारी सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

माननीय भूतपूर्व सदस्यों के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे एवं उनके शोक संतप्त परिवारों को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाओं को मृतकों के परिवारों तक पहुँचा दूँगा। अब हम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये दो मिनट का मौन रखेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए)

अब स्थान ग्रहण करें।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20-02-2013 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 36 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गईं :-

1-श्री कलराज मिश्र	की	जनपद लखनऊ की बादशाहनगर कालोनी में स्थित एल टाइप पार्क में हो रहे आवासीय निर्माण को तत्काल रोके जाने के सम्बन्ध में है।
2-श्री ललितेशपति त्रिपाठी	की	जनपद मिर्जापुर की कतिपय अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में है।
3-श्री अजय कुमार 'लल्लू'	की	जनपद कुशीनगर के पड़रौना स्थित तहसील मुख्यालय तमकुहीराज को सीधा जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है।
4-श्रीमती रूबी प्रसाद	की	जनपद सोनभद्र की दुद्धी विधान सभा के अन्तर्गत राजस्व विभाग की मिलीभगत से गरीब व्यक्तियों की जमीनों पर दबंगो द्वारा कब्जा किये जाने तथा सर्वे कराकर पैमाइश कराये जाने के सम्बन्ध में है।
5-श्री केशव प्रसाद मौर्य	की	जनपद कौशाम्बी में व्याप्त पेयजल संकट को दूर किये जाने के सम्बन्ध में है।
6-श्री रविन्द्र भड़ाना	की	जनपद मेरठ के प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों का कर्ज माफ किये जाने के सम्बन्ध में है।
7-श्री राधेश्याम जायसवाल	की	जनपद सीतापुर के 12 विकास खण्डों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है।
8-श्री जियाउद्दीन रिजवी	की	जनपद बलिया के सिकन्दरपुर अन्तर्गत घाघरा नदी के पीपे के पुल को तत्काल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है।
9-डा0 धर्म सिंह सैनी	की	जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त जू0 हाई स्कूल में कार्यरत कर्मियों को मकान किराया भत्ता की सुविधा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है।

10-श्री भगवान सिंह कुशवाहा	की	जनपद आगरा के क्षेत्र खैरागढ़ में जगनेर से बसेडी राजस्थान जाने वाले मार्ग की जर्जर हालत होने के सम्बन्ध में है।
11-श्री बब्बन सिंह चौहान	की	जनपद चन्दौली अन्तर्गत मुगलसराय के शहरी क्षेत्र में सीवर की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है।
12-श्री दीपक पटेल	की	जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना में इरादतगंज हवाई पट्टी मार्ग एवं उस पर निर्मित पुलिया की जर्जर हालत होने के सम्बन्ध में है।
13-श्री रामलाल अकेला	की	विधान सभा क्षेत्र बछरावां रायबरेली के अन्तर्गत कतिपय ड्रेनों की खुदाई एवं पटरी सड़कों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है।
14-श्री आलमबदी	की	जनपद आजमगढ़ के तहबरपुर ब्लाक के खास बेगपुर इंटर कालेज के समीप सहलनी नदी पद बने पुराने पुल के ध्वस्त होने के सम्बन्ध में है तथा
15-डा0 पूर्णमासी देहाती	की	जनपद कुशीनगर और गोरखपुर के बीच कप्तानगंज से पिपराइच मार्ग को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैः-

1-श्री सतीश महाना,

2-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल,

3-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल,

4-श्री दलजीत सिंह,

5-श्री अजय मिश्र 'टेनी',

6-श्री मुकुट बिहारी वर्मा,

7-श्री सुरेश बंसल,

8-श्री प्रदीप चौधरी,

9-श्री पूरन प्रकाश,

10-डा0 दलवीर सिंह,

11-श्री भीम प्रसाद सोनकर,

12-श्री सुधाकर सिंह,

13-श्री जय प्रकाश अंचल,

14-श्री राकेश बाबू,

15-मो0 आसिफ जाफरी,

16-श्री रोशन लाल वर्मा,

17-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,

18-श्री बृजेश कुमार,

19-श्री पंकज कुमार मलिक,

20-डा0 रमेश चन्द्र बिन्द तथा

21-श्री बेचई सरोज।

जनपद लखनऊ की बादशाहनगर कालोनी में स्थित एल टाइप पार्क में हो रहे आवासीय निर्माण को तत्काल रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कलराज मिश्र-

[मान्यवर, जनपद लखनऊ-फैजाबाद रोड पर स्थित बादशाहनगर राजकीय कालोनी में स्थित पार्क (एल टाइप) में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय भवन बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त कालोनी में एल टाइप आवासों के मध्य अवस्थित पार्क का निर्माण बच्चों के खेलने-कूदने एवं खुली हवा के उद्देश्य से किया गया था। उक्त (पार्क) कालोनी के निर्माण से पूर्व ही उक्त स्थान पर एक भव्य मन्दिर है जो कि कालोनी वासियों की आस्था का केन्द्र बिन्दु है।

उल्लेखनीय है कि उक्त कालोनी के न्यू ब्लॉक परिसर में मजार के सामने खाली पड़ी राज्य सम्पत्ति विभाग की भूमि पर कर्मचारियों के अध्यासन हेतु राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा बहुमंजिला आवास बनाये जाने की स्वीकृति की गयी थी। लेकिन कतिपय कारणों से मजार के सामने खाली पड़ी राज्य सम्पत्ति की भूमि पर न बनाकर उक्त कालोनी को एल टाइप आवासी परिसर के मध्य स्थित पार्क में बनाया जा रहा है। जबकि मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर योजित जनहित याचिकाओं/रिट याचिकाओं में पारित आदेशों द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल/पार्क मार्ग आदि में किसी भी प्रकार के निर्माण किये जाने को प्रतिबन्धित किया गया है। परन्तु राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा मा0 न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करके पार्क में निर्माण कराया जा रहा है। इस पर अविलम्ब कार्यवाही करके तत्काल निर्माण कार्य रोका जाना जनहित में आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बादशाहनगर कालोनी लखनऊ में स्थित एल टाइप पार्क एवं सार्वजनिक स्थान पर कराये जा रहे आवासीय निर्माण को तत्काल रोके जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद मिर्जापुर की कतिपय अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ललितेशपति त्रिपाठी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मड़िहान, जनपद-मिर्जापुर में निवासरत निम्न जातियों/कोल, मुसहर, बहेलिया, बांसफोर, धरकार, मझवार, माझी, घसिया, कंजड़, मजहबी नट जो आदिवासी जनजातीय संस्कृति में आज भी अपना पहचान कायम रखते हुए विभिन्न व्यवसायों द्वारा जीविकोपार्जन कर रही हैं, जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में वर्गीकृत हैं, परन्तु उन्हें अनुसूचित जाति के अन्तर्गत कुछ विशेष जातियों के वर्चस्व के कारण इन जातियों को आज भी विकास की हवा तक नहीं लग पायी है, जिसके परिणामस्वरूप ये जातियां खानाबदोश जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र-मड़िहान के साथ पूरे जनपद-मिर्जापुर एवं सोनभद्र में इस जाति के लोगों की बहुलता है। साथ ही साथ प्रदेश के हर कोने में इस जाति के कमोवेश लोग हैं जिनके जीविका का साधन एवं आर्थिक स्तर निम्न कोटि का है, इसलिए इन जातियों को अनुसूचित जाति की सूची से निकाल कर अनुसूचित जनजाति की सूची में रखे जाने तथा विशेष अभियान चलाकर इनका सर्वांगीण विकास करने की आवश्यकता है। इससे इस जाति के लोग भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

अतः जनहित एवं लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय, तात्कालिक विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर के पड़रौना स्थित तहसील मुख्यालय तमकुहीराज को सीधा जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

[मान्यवर, जनपद कुशीनगर से तहसील मुख्यालय तमकुहीराज को सीधा जोड़ने वाले मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य चल रहा था, और लगभग आधे से अधिक मार्ग का कार्य पूर्ण भी हो गया है। किन्तु धनाभाव के कारण उपरोक्त मार्ग का कार्य विगत लगभग एक वर्ष से बन्द पड़ा हुआ है। जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक है क्योंकि मार्ग के अधूरे होने के कारण जहां आवागमन बाधित हो रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है वहीं लागत में भी वृद्धि होती जा रही है। यह मार्ग पूरी तरह से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके कारण विभिन्न प्रकार की परेशानी हो रही है, चूँकि यह मुख्य मार्ग है और जनपद मुख्यालय को जोड़ता है ऐसी स्थिति में छोटे से लेकर बड़े वाहनों तक का आवागमन बाधित हो रहा है और जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं मार्ग के अधूरे होने के कारण एवं कार्य बन्द होने के कारण लोगों में चिन्ता व्याप्त है। जनहित में उक्त मार्ग का समयबद्ध ढंग से कार्य कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अवलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद सोनभद्र की दुद्धी विधान सभा के अन्तर्गत राजस्व विभाग की मिलीभगत से गरीब व्यक्तियों की जमीनों पर दंबगों द्वारा कब्जा किये जाने तथा सर्वे कराकर पैमाइश कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती रूबी प्रसाद-

[मान्यवर मेरे विधान सभा क्षेत्र दुद्धी, जनपद सोनभद्र में बहुत सारे गांव में गरीबों की जमीन को सर्वे किये जाने के दौरान दूसरे के नाम कर दिया गया है जिससे फसली सीजन में जब वे खेतों में जोतने-बोने के लिए जाते हैं तो उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, गलत ढंग से दबंगयी करके तथा राजस्व विभाग से मिलीभगत करके गरीब व्यक्तियों के नाम जमीनों को कुछ लोगों ने अपने नाम करा लिया गया है। ऐसी स्थिति में पूरे विधान सभा क्षेत्र दुद्धी, जनपद सोनभद्र का पुनः सर्वे कराकर पैमाइश किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। गरीब किसानों में काफी असंतोष व्याप्त है उन्हें न्याय दिलाने की आवश्यकता है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद कौशाम्बी में व्याप्त पेयजल संकट को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

[महोदय, जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में दो विकास खंड है और दोनों विकास खण्ड वर्क जोन घोषित हो गया हैं। भूजल स्तर नीचे जाने से पीपे के पानी का एकमात्र साधन है। हैण्डपम्प रिबोर नहीं कराने से पेयजल का गम्भीर संकट व्याप्त है। सिराथू विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा निधियावां, रमसहाईपुर थोन, विदनपुर ककोडा, मलाक पिंजरी सिंधिया, केसारी, नासिरपुर, फरीदगंज, कोरियों, कोखराज, कादीपुर, ख्वाजा खड़क शाह उर्फ

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भानीपुर, रामपुर धमावां, मो0 पुर पद्रन्सा गम्भीरा पूर्व, समसाबाद नारा, देवखरपुर, शहजादपुर कशिया पश्चिम, गनपा, रामपुर बढनावॉ, खोचकी माई, सैनी, औरेनी, अफजलपुर सातों, कन्थुआ, उदिहिन खुर्द एवं वुजुर्ग जवई पड़री, कुण्डावल, मो0 पुर अनेठा, हिसामपुर बहरेमऊ, धुमाई, सॉखा, अफजलपुरवारी, जियापुर खनवारी, दारानगर, म्योहरा सौरई बुजुर्ग सहित सैकड़ों ग्राम सभाओं में पीने का पानी का संकट पिछले कई वर्षों से व्याप्त हैं जिसका समाधान बार-बार अनुरोध के बावजूद नहीं हो रहा है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर तत्काल कार्यवाही एवं वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद मेरठ के प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों का कर्ज माफ किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविन्द्र भड़ाना-

[महोदय, जनपद मेरठ में माह फरवरी, 2013 में भयंकर ओलावृष्टि आंधी तूफान एवं भारी बरसात के कारण किसानों के आलू एवं सरसों आदि अनेक प्रमुख फसलों को भारी क्षति हुई है। इस दैवीय आपदा के कारण किसानों की फसल बरबाद हो जाने के कारण किसानों के सामने विकट आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। उनकी सारी लागत फसलों के बरबाद होने से चौपट हो गयी है। इस अतिवृष्टि से जनपद मेरठ को आपदा ग्रस्त जिला घोषित कर किसानों की फसलों का मुआवजा/आर्थिक सहायता फसल बीमा योजना द्वारा अथवा सरकार सीधे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है और साथ ही बैंकों तथा सहकारी समितियों के फसली ऋण माफ किया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए किसानों के समस्त ऋण माफ करने एवं किसानों के फसलों के नुकसान की भरपाई फसल बीमा योजनाओं के द्वारा अथवा सीधे सरकार द्वारा किये जाने हेतु कार्यवाही करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के 12 विकास खण्डों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम जायसवाल-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद सीतापुर के 12 विकास खण्डों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के वर्ष 2010-11 का विकास कार्यो का धन जिला पंचायत सीतापुर में एक वर्ष से अधिक से खातों में जमा है जो निदेशक पंचायती राज के स्तर पर आगणन की स्वीकृति न किये जाने के कारण खर्च नहीं हो पा रहा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। मैं तत्काल स्वीकृत जारी करने एवं विकास कार्यों को प्रारम्भ कराये जाने की मांग करता हूँ।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये तत्काल निराकरण कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया के सिकन्दरपुर अन्तर्गत घाघरा नदी के पीपे के पुल को तत्काल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से गम्भीर विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जनपद बलिया के मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर अन्तर्गत घाघरा नदी पर खरीद दरौली घाट पर पीपा का पुल मा0 मुलायम सिंह यादव की सरकार में वर्ष 2004-05 में स्वीकृत हुआ था। बिहार एवं उ0प्र0 के जोड़ने के लिए यह पीपा का पुल बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार में सिवान गोपालगंज जनपद बलिया से जुड़ गया है। इस खरीद दरौली घाट पर 105 पीपा स्वीकृत है यह पीपा का पुल 2004-05 में पिछले 2012 में चला है। इस वर्ष 2013 माह जनवरी में 63 पीपा लगाकर पीपा का पुल लोक निर्माण विभाग ने लगाकर चालू किया, परन्तु विभागीय लापरवाही के कारण पर्याप्त पीपा नहीं लगाया गया है। इस सप्ताह हुई बारिश में पानी बढ़ने के कारण पीपा का पुल बह गया है। जिससे उ0प्र0 एवं बिहार की जनता का आवागमन बन्द हो गया है। जनता परेशान है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल निर्देशित किया जाय कि जनता की कठिनाइयों को देखते हुए बलिया जनपद के सिकन्दरपुर तहसील पर घाघरा नदी पर खरीद-दरौली घाट पर पीपा लाकर तत्काल पीपा पुल को चालू किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त जू0 हाई स्कूल में कार्यरत कर्मियों को मकान किराया भत्ता की सुविधा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 धर्मसिंह सैनी-

[महोदय, कृपया संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत दिनांक 2-10-2009 के द्वारा नगर निगम का दर्जा दिया गया था, जिनके उपरान्त शासनादेश संख्या जी-1-701/10-2011-226/2008टी0सी0 वित्त (सामान्य) अनुभाग, लखनऊ दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 के द्वारा सहारनपुर नगर को बी-2 श्रेणी में वर्गीकृत होने के पश्चात् राजकीय कार्यालयों में कार्यरत तथा निगमों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को बी-2 श्रेणी का

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मकान किराया भत्ता भुगतान किया जा रहा है। किन्तु अशासकीय सहायता प्राप्त जू0हा0 स्कूलों में नगर सहारनपुर में कार्यरत कर्मचारियों को उक्त लाभ नहीं दिये जाने के कारण कर्मचारियों में जनाक्रोश व्याप्त किया जा रहा है।]

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अशासकीय सहायता प्राप्त जू0हा0 स्कूलों में नगर सहारनपुर में कार्यरत कर्मचारियों को उक्त मकान किराया भत्ता भुगतान किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद आगरा के क्षेत्र खैरागढ़ में जगनेर से बसेड़ी राजस्थान जाने वाले मार्ग की जर्जर हालत होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान दीन कुशवाहा-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद आगरा के मेरे विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के अन्तर्गत विकास-खण्ड जगनेर से बसेडी राजस्थान जाने वाले अन्तर्राज्जीय राजमार्ग अत्यन्त ही जर्जर हालत में जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अनेक दुर्घटनायें आये दिन होती रहती हैं, क्षेत्रीय लोग 15 फरवरी, 2013 से अनिश्चित कालीन अनशन पर बैठे हैं, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अतिशीघ्र उक्त सड़क निर्माण की कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद चन्दौली अन्तर्गत मुगलसराय के शहरी क्षेत्र में सीवर की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन सिंह चौहान-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद चन्दौली विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में अभी तक सीवर का कार्य नहीं कराया गया हैं जिसमें मिनी महानगर मुगलसराय में बरसात के दिनों में गन्दे नालियों का पानी घरों में प्रवेश कर जाता है। गन्दगी के कारण इस मिनी महानगर में अनेक प्रकार की बीमारी फैल रही है। जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना में इरादतगंज हवाई पट्टी मार्ग एवं उस पर निर्मित पुलिया की जर्जर हालत होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपक पटेल-

[मान्यवर, जनपद-इलाहाबाद के अन्तर्गत मेरी विधान सभा क्षेत्र-करछना में इरादतगंज हवाई पट्टी मार्ग एवं उस पर निर्मित पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है, जिसके कारण उपरोक्त सड़क पर चलने वाले आम नागरिकों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञातव्य है कि उपरोक्त मार्ग मेरी विधान सभा का मुख्य मार्ग है तथा हजारों लोगों का आवागमन प्रतिदिन उक्त मार्ग पर होता है। उक्त मार्ग के पुलिया के जिरिया बाग यूकों बैंक के सामने तथा अन्य तीन पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जिसके कारण चार पहिया वाहन का आवागमन ठप हो चुका है। आवागमन बाधित होने के कारण क्षेत्रीय जनता में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त मार्ग एवं पुलिया के निर्माण कराने की भी मांग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र बछरावां रायबरेली के अन्तर्गत कतिपय ड्रेनों की खुदाई एवं पटरी सड़कों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामलाल अकेला-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद रायबरेली में मेरे विधान सभा क्षेत्र बछरांवा के अन्तर्गत महराजगंज, शिवगढ़, हसवां एवं फिरोजाबाद ड्रेन सर्वाधिक प्रभावित करती है। इस क्षेत्र की हजारों बीघे जमीन जल भराव के कारण बेकार पड़ी रहती है। जिसके कारण यहाँ के किसानों के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। क्षेत्रीय किसानों ने सपा सरकार से काफी उम्मीद लगा रखी है। किन्तु अब तक इन ड्रेनों पर कोई कार्य न होने से किसान निराश हैं।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मेरा सरकार से उक्त ड्रेनों की खुदाई एवं पटरी की मरम्मत कराये जाने की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के तहबरपुर ब्लाक के खास बेगपुर इंटर कालेज के समीप सहलनी नदी पर बने पुराने पुल के ध्वस्त होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलम बदी-

[श्रीमन्, मैं उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मा0 पंचायती राज मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आजमगढ़ के कप्तानगंज बाजार से कोइनहा बाजार जाने वाली पिच रोड से ग्राम-गौरा के पश्चिम बड़सरा खालसा को जोड़ने वाली खड़न्जा मार्ग लगभग 500 मीटर की दूरी पर खास बेगपुर इण्टर कालेज के समीप सीलनी नदी पे एक प्राचीन पुल था, जो ध्वस्त हो गया इसके कारण ऊपर से गाड़ियों का यातायात प्रभावित है। बच्चों के स्कूल ले जाने वाली बसों को लम्बी दूरी तय करनी पड़ रही है।

जनहित में इस पुल का निर्माण अति आवश्यक है। मुझे आशा है कि उपरोक्त पुल का निर्माण कराने का कष्ट करेंगे।

जिसके लिए मैं और मेरे क्षेत्र की जनता आपकी आभारी रहेंगे।]

जनपद कुशीनगर और गोरखपुर के बीच कप्तानगंज से पिपराइच मार्ग को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी देहाती-

[मैं आपके माध्यम से गम्भीर विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जनपद कुशीनगर और गोरखपुर के बीच कप्तानगंज से पिपराइच होकर गोरखपुर तक सड़क अत्यन्त जर्जर स्थिति में है जिसका चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण किया जाना जनहित में आवश्यक है। बिहार, नेपाल तक यात्री छितौनी पनिहवां से कप्तानगंज-पिपराइच होकर गोरखपुर तक की यात्रा करते हैं। जोकि महत्वपूर्ण सड़क है। सड़क जर्जर होने के कारण आवागमन बहुत ही बाधित रहता है। यह लोक महत्व प्रश्न है जोकि जनहित से जुड़ा हुआ है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त सड़क का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।

नियम-311 की सूचना को सर्व प्रथम लिये जाने की मांग

श्री प्रदीप कुमार-

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं।

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20 फरवरी, 2013 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 04 सूचनायें प्राप्त हुयीं, जिनमें पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहाँपुर में वित्तीय वर्ष 2012-2013 की जिला योजना समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुसार शासन द्वारा धन अवमुक्त न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। दूसरी सूचना श्री प्रदीप माथुर की वित्तीय वर्ष 2012-2013 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु संचालित

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

योजनाओं के लिए धनावंटन में किये जा रहे भेद भाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। तीसरी सूचना श्री राकेश बाबू की नगर पालिका परिषद, टूण्डला के कतिपय मोहल्लों का विकास विभिन्न निधियों से कराये जाने के सम्बन्ध में। चौथी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की उत्तर प्रदेश सचिवालय में एक विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को एक ही जगह स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

जनपद शाहजहांपुर में वित्तीय वर्ष 2012-2013 की जिला योजना समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के अनुसार शासन द्वारा धन अवमुक्त न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

इसमें एक है जो जिला योजना समिति से संबंधित है उसके बारे में सुरेश कुमार खन्ना जी आप एक मिनट में अपनी बात कह लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूँ कि नियम 300 की सूचना पर आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। मान्यवर, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार जिला योजना समितियों का गठन हुआ। एक मंत्री सरकार के प्रभारी मंत्री के रूप में हमारे जिले में गए, उनकी अध्यक्षता में मान्यवर, मीटिंग होती है 30-8-2012 को, जिले की हाइएस्ट रिकमन्ड्रेटरी बॉडी जिसमें सभी जिले के विधायकगण, ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष समेत बहुत से मेम्बर उसमें शामिल होते हैं। मान्यवर, 6 महीने बीत गए है, उसमें बहुत सी इम्पारटेंट संस्तुतियाँ शासन के विभिन्न विभागों में पहुँच गयी है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में हर जगह पर जाम लगता है, शाहजहाँपुर में भी जाम लगता है, उसमें एक बहुत इम्पारटेंट मामला था, रिंग रोड का, उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इसके बारे में भी कार्यवाही की जायेगी लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी किसी भी विभाग के लिए पैसा नहीं भेजा गया है। मान्यवर, कल 2013-14 का बजट भी पेश हो गया, आगे की सारी कार्यवाही शुरू हो गयी है। मान्यवर, होता क्या है, जो पुराना तजुर्बा है, देर से बजट जाता है तो हमेशा यह है कि बजट को जल्दी जल्दी खर्च करने में कार्य की क्वालिटी प्रभावित होती है और उससे जितने भी प्रकार के दुष्परिणाम हो सकते हैं, वह सब सामने आते हैं और उससे जितने भी प्रकार के दुष्परिणाम हो सकते हैं, वह सब सामने आते हैं और अन्ततोगत्वा उसका दुष्परिणाम जनता को भुगतान पड़ता है। बाद में जाँच कराते रहें, उससे कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं और आपके माध्यम से यह जरूर चाहते हैं कि आप सरकार को निर्देशित करें, 11 महीने इस सरकार को सत्ता में आए हो गए हैं, अगर इस प्रकार से जो पुरानी लीक चली आ रही है, उसी को पीटा

जायेगा और हर बजट बाद में, देर से रिलीज किया जायेगा तो इसका फायदा क्या है ? मान्यवर, मेरा आपसे विशेष रूप से विनम्र आग्रह है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि जिले की योजना समिति के द्वारा जो संस्तुतियाँ आई हैं, उसमें बजट तत्काल आवंटित किया जाए ताकि विकास कार्य तत्काल शुरू हो सके। मान्यवर, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-300 में जो स्पष्ट प्रावधान है कि संविधान के उन्हीं अनुच्छेदों का उल्लेख किया जायेगा जिससे सदन की कार्यवाही तत्काल संचालित होती है। मान्यवर, 73वें और 74वें संविधान संशोधन की जो बात माननीय खन्ना जी ने उठाई है, वह पंचायतों को अधिकार दिए जाने के सम्बन्ध में संविधान में जो संशोधन किया गया था, उससे सम्बन्धित है, सदन की कार्यवाही के संचालन से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिए यह नियम-300 में नहीं आता है। लेकिन मान्यवर, जो विषय इन्होंने उठाया है, जिसकी आपने कृपापूर्वक अनुमति दी है, वह विषय गंभीर है और हम इस सम्बन्ध में दिखवा लेंगे और तत्काल कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(श्री प्रदीप कुमार माथुर के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे, आपका वह बजट आवंटन का है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका इसमें नहीं आता है। माननीय माथुर जी, आप नेता हैं, आप इसको पढ़िए, इसमें आपका नहीं आता है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 फरवरी, 2013 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 20 फरवरी, 2013 से दिनांक 22 मार्च, 2013 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं:-

1-दिनांक 20 फरवरी, 2013 को निधन के निर्देश लिये जायं।

2-दिनांक 22 फरवरी, 2013 को नियम 103 के अन्तर्गत डा0 धर्मपाल सिंह के पूर्व लम्बित 03 (तीन) प्रस्तावों पर अग्रतर चर्चा सम्बन्धी मद ले ली जायं।

3-दिनांक 25 फरवरी तथा 01 मार्च, 2013 को सदन के उपवेशन न हों।

4-तद्नुसार 20 फरवरी, 2013 से 22 मार्च, 2013 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जायः-

<u>फरवरी, 2013</u>

20 बुधवार 1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।

2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

21 गुरुवार श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

22 शुक्रवार 1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। (अन्तिम दिन)।

2-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

3-डा0 धर्मपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 15 जून, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्तावों पर अग्रतर चर्चाः-

(1) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर में यातायात की सुगमता हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाय।''

(2) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।''

(3) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर के ऐतिहासिक महत्ता के दृष्टिगत आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाय।''

23 शनिवार
24 रविवार } बैठक नहीं होगी।
25 सोमवार

26 मंगलवार
27 बुधवार } वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय व्ययक पर साधारण चर्चा।
28 गुरुवार

मार्च, 2013

01 शुक्रवार 02 शनिवार 03 रविवार	बैठक नहीं होगी।
04 सोमवार 05 मंगलवार 06 बुधवार 07 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
08 शुक्रवार	असरकारी दिवस (आधा दिन)।
09 शनिवार 10 रविवार	बैठक नहीं होगी।
11 सोमवार 12 मंगलवार 13 बुधवार 14 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
15 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन)। 2-विधायी कार्य (आधा दिन)।
16 शनिवार 17 रविवार	बैठक नहीं होगी।
18 सोमवार 19 मंगलवार 20 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
21 गुरुवार	1-वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एव मतदान। 2-3.00 बजे अपराह्न। उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2013 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण।
22 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन)। 2-विधायी कार्य (आधा दिन)।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसमें जो सूचना मिली है इसमें 08 तारीख को असरकरी दिवस (आधा दिन) दिया है लेकिन बाकी का आधा दिन का नहीं दिया है। क्या बाकी का आधा आपके यहाँ भोजन की व्यवस्था है। अगर है तो मैं वहाँ पहुंचूं।

श्री अध्यक्ष-

अरे आइये मैं आपको प्यार से भोजन कराऊंगा। 08 तारीख को बाकी का आधा दिन औपचारिक काम के लिए है।

श्री सतीश महाना-

औपचारिक काम के लिए हैं, लेकिन लिखना भूल गये हैं।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-07 में कुछ नहीं है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20-12-013 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें श्लाका के आधार पर निम्नलिखित चयनित की गई है। प्रथम 2 सूचनायें को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राजबली जैसल, श्री दीपक पटेल, श्री राजनारायण बुधौलिया, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री अमरपाल शर्मा, श्री लोकेश दीक्षित, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया तथा श्री रोशन लाल वर्मा, श्री हुकुम सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री केशव प्रसाद मौर्य, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री सतीश महाना, श्री अजय मिश्र 'टेनी', श्री सुरेश राणा, श्रीमती विमला सिंह सोलंकी तथा श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की दिनांक 10-2-2013

को कुम्भ मेले में श्रृद्धालुओं के साथ हुयी घटना के दृष्टिगत आने वाले पर्वो पर उचित प्रबन्ध व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में,

दूसरी सूचना डा0 धर्मपाल सिंह, श्री ममतेश शाक्य, ठा0 सूरजपाल सिंह, श्री राजकुमार रावत, श्री कालीचरन सुमन, श्री छोटेलाल वर्मा तथा श्री भगवान सिंह कुशवाहा की प्रदेश भर में हुई बेमौसम भयंकर बारिश, पाला, ओलावृष्टि एवं तूफान के कारण किसानों की बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में,

तीसरी सूचना श्रीमती सीमा द्विवेदी की जनपद जौनपुर में थाना मुंगरा बादशाहपुर में तैनात थानाध्यक्ष के कार्य व्यवहार से जनमानस में उत्पन्न आक्रोश के संबंध में,

चौथी सूचना डा0 अरूण कुमार की बरेली अन्तर्गत बिशप कान्डेरेट सीनियर सेकेन्डरी स्कूल का छात्र आयूष का अपहरण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं :-

1. श्री सुरेश कुमार खन्ना,
2. श्री सन्त प्रसाद,
3. श्री राकेश बाबू,
4. श्री पूरन प्रकाश,
5. श्री मुकेश श्रीवास्तव,
6. श्री संजय कपूर,
7. श्री रोशन लाल वर्मा,
8. श्री अगयश राम सरन वर्मा,
9. श्री राजेश अग्रवाल तथा
10. श्री रामचन्द्र यादव।

पहली सूचना दिनांक 10-02-2013 को कुम्भ मेले में श्रद्धालुओं के साथ हुये घटना के दृष्टिगत आने वाले पर्वो पर उचित प्रबन्ध सुनिश्चित कराये जाने के सम्बंध में है। इसमें नेता विरोधी दल ने भी दिया है, माननीय श्री हुकुम सिंह जी ने भी दिया है और कांग्रेस पार्टी ने भी दिया है तो मैं निवेदन करूंगा कि इस पर जैसा तय हुआ है जिसकी सहमति बनी थी कि इसकी ग्राहयता पर दो दो मिनट बोल लें इसके बाद हम अपना निर्णय दे दें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 के अंतर्गत हमने इलाहाबाद महाकुम्भ हादसे के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है। जैसाकि मान्यवर, हजारों करोड़ रूपये व्यवस्था की बिना पर आयोजित

महाकुम्भ मेले में 44-44 लोगों की जान जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा और मान्यवर, एक ही दिन में दो हादसा, एक हादसे का जिक्र तो रोज होता रहा लेकिन एक हादसा छिपा लिया गया। जिस दिन रेलवे स्टेशन पर 39 लोग मौत के शिकार हुए उसी दिन माघ मेला प्रांगण में वहां पर जहां पर कल्पवासी और साधु-सन्यासी लोग रहते है, वहां पर भी चार लोगों की मौत हुई दुर्व्यवस्था से और जिस प्रकरण को उस दिन सभी अखबार, रेडियों, मीडिया, प्रेस मीडिया के लोगों ने भी प्रस्तुत किया था, लेकिन लाश गायब करके जिस प्रकार से शासन ने उस पर पर्दा डालने की कोशिश की हम समझते हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यद्यपि की महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मैने यह बात रखी थी, आज इसको हम रखना नहीं चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने वहां तमाम ऐसे श्रद्धालुओं, साधुओं और कल्पवासियों की मौत को छुपाने का कुकृत्य किया है, उस पर भी सरकार का संज्ञान जाना चाहिए। रेल हादसे में मरे हुए लोगों के परिवारीजनों को अगर आर्थिक सहायता दी जाती है तो जो वहां पर कुम्भ मेला प्रांगण के अन्दर चार लोगों की मौत हुई है, उसको भी वह सुविधा मुहैया कराया जाना चाहिए, और साथ ही साथ हजारों करोड़ रुपये, ...

श्री अध्यक्ष-

यह सब आगे कहियेगा, इस समय यह सब कहने का मौका नहीं है। आप केवल इसकी ग्राह्यता पर बोलिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आयोजन पर खर्च हुए, लेकिन एक दो दिन पानी बरसने से जिस तरीके से वहां अव्यवस्था हुई, लाखों की तादात में कल्पवासी वहां से भागने के लिए मजबूर हुए। मान्यवर, यह भी चिन्तनीय विषय है, गम्भीर प्रकरण है, अविलम्बनीय है, पूरे देशवासी इससे प्रभावित हुए है, इसलिए लोकमहत्व का भी है, इसलिए मान्यवर, इसकी गम्भीरता, ग्राह्यता को संज्ञान में लेते हुए इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है, केशव मौर्या, उसी जनपद से विधायक हैं, घटना के समय वहां पर मौजूद थे, मैं केवल एक मिनट में अपनी बात कहूंगा, लेकिन मेरे बाद उनको अपनी बात कहने का अवसर जरूर दे दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी, आप ग्राह्यता पर बोल दीजिए, अगर इस पर आप न भी बोलते तब भी मैं इस पर डेढ़ घण्टे की चर्चा स्वीकार करता, जब चर्चा होगी, तब यह बोल लेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह-

ठीक है, मान्यवर, ग्राह्यता पर मैं बोल देता हूँ चर्चा में यह हिस्सा ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह चर्चा में हिस्सा ले लेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इस पर्व के दो भाग है, जहां पर मेला की व्यवस्था थी, जहां संगम है वहां पर एक व्यवस्था थी, लोगों के आने की, इकट्ठा होने की, भोजन करने की और रहने की। उसके बाद दूसरा भाग है मान्यवर, स्नान करने के बाद में जाने की। तो दूसरे भाग की व्यवस्था करना शायद यह भूल गये या इनके संज्ञान में नहीं आई या इनको इस बात का एहसास नहीं हुआ। मान्यवर, स्नान करने के बाद में अगर उस भीड़ को नियंत्रित किया होता, तो सम्भवतः यह घटना या दुर्घटना न हुई होती, वह नहीं किया गया और क्या प्रमाण उसके है, स्टेशन पर सीमित स्थान है, लाखों आदमी क्यों पहुँच पाये वहां पर। क्यों नहीं उनको नियंत्रित किया गया और दूसरा भाग मान्यवर, यह है, कहा गया कि भागने से दुर्घटना हुई, भागने की नौबत क्यों आई। यह जानकारी है मान्यवर, कि भागने की नौबत क्यों आई ? न भागे होते तो शायद यह दुर्घटना न होती। निश्चितरूप से पब्लिक ने जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने कहा, लाठी चार्ज किया गया, किसी कारण से भी किया गया हो और लाठी चार्ज का परिणाम यह हुआ कि लोग भागे वहां से। तीसरी बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूँ, मान्यवर दुःखदायी बात यह है, राजनीति उस मेले में भी शामिल रही, जो व्यवस्था ट्रान्सपोर्ट की थी, जो यात्रियों के लिए की गई थी, श्रृद्धालुओं के लिए की गई थी, जो एम्बुलेन्स वहां पर लगाई गई श्री मान्यवर, वह भी उपलब्ध नहीं हुई, उसमें भी एक राजनीतिक दल के लोग घूमते रहे, वी0आई0पी0 बने रहे, एम्बुलेन्स तक उनको उपलब्ध नहीं कराई। इसका कोई उत्तर किसी सरकार के पास में कैसे हो सकता है कि घण्टों-घण्टों लाशें वहां पर पड़ी रहीं, घण्टों-घण्टों तक जख्मी वहां पड़े रहे न डाक्टर आया, न कोई व्यवस्था हुई मान्वयर, यह चार पाँच बिन्दु है। आप कृपा करके विस्तार से इस पर चर्चा करायें, केवल स्टेटमेण्ट की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपकी बात आ गई।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 अनुग्रह नारायण सिंह बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

केवल इसकी ग्राह्यता पर बोलें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, कुम्भ मेला पूरे विश्व में धार्मिक ऐतिहासिक, बौद्धिक और आध्यामिक, सांस्कृतिक रूप से बहुत ही प्रसिद्ध मेला है और इसके संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के विभाग की संयुक्त रूप में है। जैसे लोक निर्माण विभाग नगर विकास, जल निगम बिजली विभाग पुलिस आदि का है और केन्द्र सरकार में रक्षा, रेलवे और टेलीकम्युनिकेशन आदि विभाग का है। इन सब के द्वारा साथ मिल करके इसको संचालित किया जा रहा था। 14 जनवरी को मकर संक्रान्ति थी, 10 फरवरी को मौनी अमावस्या थी और मान्यवर, इस बीच आपस में तालमेल न होने की वजह से एक बहुत हीं दुर्भाग्यपूर्ण दर्दनाक घटना हुयी जिससे मेले पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है और चूँकि अभी आप इस पर चर्चा कराने की बात कह रहे है। हम लोग इस पर विस्तार से आगे बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप इसमें केवल ग्राह्यता पर बोल दो बस।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि जैसे ही यह घटना रेलवे स्टेशन पर हुयी और हम लोग इस घटना के दर्द को दूर करने का प्रयास कर रहे थे कि इसके बजाए इस पर सियासत शुरू हो गयी। टेलीविजन मीडिया पर आने लगा कि रेलिंग टूट गयी, हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने कहा कि रेलिंग टूटने से घटना हो गयी। किसी ने कहा कि लाठी चल गयी इसीलिये घटना हो गयी। मान्यवर, इन सारी चीजों का आज बुरा प्रभाव यह है कि जो मेला है, जहाँ लाखों लोग अभी भी मेले के मैदान स्थान पर हैं, वे लोग वहाँ से भागने लगे हैं। अभी जो सबसे ज्यादा जरूरत है कि 1195 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया है 90 प्रतिशत केन्द्र और 10 प्रतिशत पैसा इसमें राज्य सरकार का लगा हुआ है। अभी आज भी अखबारों में खबर है कि वहाँ हेतापट्टी के पास नहर का बाँध टूट गया। सेक्टर नम्बर 10 में पूरा पानी भर गया है, लोग भागने लगे हैं। वही टापू बन गया है।

श्री अध्यक्ष-

आप ग्राह्यता पर बोलो न।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, ग्राह्यता यही है और यह तात्कालिक है। अभी भी उस पर सचेत रहने की जरूरत है। मेला 10 मार्च तक महाशिवरात्रि तक है इसलिये महाशिवरात्रि तक वहाँ की व्यवस्था चाक चौबन्द रहे। वहाँ की पुलिस व्यवस्था ठीक रहे, सिंचाई विभाग की व्यवस्था ठीक रहे, सड़क की व्यवस्था ठीक रहे, नहीं तो वहाँ अभी दुर्घटना की सम्भावना है इसलिये मामला तात्कालिक है और गम्भीर भी है क्योंकि एक तरफ तो जुडिशियल इनक्वारी की बात हो रही

है और दूसरी तरफ हमारे लोग अधिकारियों को क्लीन चिट भी देते जा रहे हैं। ये सारी बातें आगे के चर्चा में आयेंगी कि किसका दोष रहा है, क्या रहा है इसलिये मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर चर्चा स्वीकार करें।

*राजस्व, अभाव सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, ये कुम्भ का मेला जो इस बार इलाहाबाद में चल रहा है जिस पर मा0 सदस्य ने नोटिस दी है। इसकी व्यवस्था इस बार सरकार ने जैसी की है उसकी सराहना प्रदेश में, देश में और उसके बाहर भी सभी लोगों ने समवेत रूप से की। हादसा हुआ और उस हादसे के पूर्व तक सबकी एक स्वर से एक राय थी कि इतनी अच्छी व्यवस्था मेले की इससे पूर्व कभी नहीं हो पायी थी। तीन करोड़ से ज्यादा लोग एक दिन में आये। दुनिया में अब तक इतने ज्यादा लोग किसी एक क्षेत्र में विश्व में कही इकटठा नहीं हुये हैं। इसकी व्यवस्था थी किन्तु यह हादसा हुआ। मान्यवर, मा0 सदस्यगण ने जो बात कही है, उसमें मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार की ओर से जो प्रबन्ध किये जाने थे, वे सर्वोत्तम प्रबन्ध थे लेकिन इसके बावजूद भी हादसा हुआ है। इस हादसे को इतना ही गम्भीर मानते हुये मा0 मुख्य मंत्री जी ने उसके कारणों पर जाँच के लिये और अन्य बिन्दुओं पर जाँच के लिये प्रदेश के वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी को उसका जाँच अधिकारी बनाया किन्तु इसके बाद भी उसमें कहीं किसी कोने से कोई कमी न रह जाये, इस कारण उसकी न्यायिक जाँच के आदेश भी दे दिये गये। स्वयं लोक निर्माण मंत्री जी ने इसकी न्यायिक जाँच के आदेश के बाद वहाँ की बारिश की स्थिति के निरीक्षण के लिये स्वयं गये और उन्होंने निर्देशित किया है। इसलिये इन सभी बिन्दुओं पर सरकार की ओर से जितनी गम्भीरता से इस विषय को लिया जाना चाहिये, हमने लिया है। हम एक बात स्वीकार करते हैं इस सूचना में कि श्रीमन्, आपका निर्णय भी आ गया है पहले ही और उस निर्णय के आने के अतिरिक्त हम ये बात स्वीकार करते हैं कि यह तात्कालिक भी है, लोक महत्व का भी है और गम्भीर भी है। श्रीमन्, अगर आपका आदेश होगा तो सरकार पूरी तरह तैयार है। जो समय आप तय करेंगे उस समय चर्चा में, अगर आप सरकार को कहेंगे तो हम विस्तृत उत्तर लेकर आयेंगे लेकिन मैं आज इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को अवगत कराना चाहता हूँ कि इस मेले की सर्वोत्तम व्यवस्था जो सम्भव थी, वह सरकार ने की है और इसकी सराहना भी हुयी है। हादसा हुआ है इसलिये हम इसको स्वीकार करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 नेता विराधी दल, मा0 नेता भा0ज0पा0, मा0 नेता कांग्रेस तथा राजस्व मंत्री को सुना। इसे नियम-56 में न लेते हुये, नियम-52 में परिवर्तित करते हुये डेढ़ घण्टे की चर्चा पर मैं स्वीकार करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, 52 की चर्चा तो सबसे बाद में आती है। आप चर्चा स्वीकार कर लें, इसमें आप नियम की बात न करें कि मैंने नियम-52 में स्वीकार की है। आज न करायें, जब भी आपको समय हो तब करा लीजियेगा। मान्यवर, आप 52 में रखेंगे तो इससे क्रम बदल जायेगा। अगर आप 52 में रखेंगे तो फिर एजेण्डे के बाद में आयेगा। नियम-52 में न रखें। आप केवल चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

इस पर हम कार्य मंत्रणा समिति में बात कर लेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

ठीक है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

दूसरी डा0 धर्मपाल सिंह जी की है। आप ग्राह्यता पर एक लाइन बोल दें मैं वैसे ही इसका जवाब दे दे रहा हूँ, क्योंकि 1.20 तक इसे खत्म हो जाना है। यह विषय प्रदेश भर में हुई बेमौसम भयंकर बारिश, पाला एवं तूफान से किसानों की बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में है।

*डॉ0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद क्योंकि आपने किसानों का दर्द सरकार के सामने लाने का मुझे मौका दिया। मा0 अध्यक्ष जी, इसी महीने की 16 व 17 तारीख को पूरे प्रदेश में बहुत भयंकर बारिश हुई, ओला पड़ा, तूफान आया। पूरे प्रदेश के किसानों की चाहे वह गेहूँ की फसल हो, चाहे वह आलू की फसल हो, चाहे मा0 अध्यक्ष जी वह सरसों की फसल हो पूरी तरह से वह फसल नष्ट हो गई। मा0 अध्यक्ष जी, जब किसान सवेरे अपने खेतों पर पहुँचा तो किसानों ने देखा कि उसके पूरे खेत भरे हुए है। मा0 अध्यक्ष जी, इस बार किसान आलू और सरसों की बम्पर फसल की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जब वह 18 फरवरी को अपने खेतों पर पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई है। खेतों में पानी भरा हुआ है। मा0 अध्यक्ष जी, जो किसान खुशी मना रहा था, वह किसान आलू और बरसात देखकर बिल्कुल जैसे मरघटी में सन्नाटा छा जाता है, वहाँ किसानों के खेतों में बिल्कुल वैसा ही सन्नाटा छा गया। मा0 अध्यक्ष जी, आगरा, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फरूर्खाबाद और कन्नौज जिलों में आलू किसान बहुत हैं। वहाँ पर बहुत बड़ी फसल आलू की होता है। मा0 अध्यक्ष जी, केवल आगरा में ही 66 हजार हेक्टेयर आलू की फसल हैं,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और करीब इतनी ही सरसों की फसल है। मा0 अध्यक्ष जी, 16 व 17 फरवरी को आगरा के सभी 15 ब्लॉकों में चाहे वह एत्मादपुर हो, चाहे वह खदौली हो, चाहे वह बिछपुरी हो, चाहे वह अकोला हो, चाहे खैरागढ़ हो, चाहे जगनेर हो, चाहे शम्शाबाद और फतेहाबाद हो, चाहे बहा, चाहे पिनहट और जैतपुर हो सभी ब्लॉकों के किसानों की आलू और सरसों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। मा0 अध्यक्ष जी, हमें ध्यान है जब मुख्य मंत्री जी ने पहला बजट पढ़ा था, तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि देश की तरक्की तभी सम्भव है जब किसानों की तरक्की हो।

श्री अध्यक्ष-

अब आप इसमें चर्चा मत करिए। एक आदमी कह लिया इसलिए आपको मौका मिला है। अब बैठ जाइए।

डॉ धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मै समाप्त ही कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि इस सरकार का लक्ष्य किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाना है। मा0 अध्यक्ष जी, आज प्रदेश के किसानों में हाहाकर मचा हुआ है। किसान प्रकृति की मार से विचलित हो गया है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करूँगा कि पूरे प्रदेश में किसानों की फसलों के नुकसान का आंकलन करके उन्हें तुरन्त मुआवजा देने का इंतजाम सरकार करे। मा0 अध्यक्ष जी, यह विषय तात्कालिक है क्योंकि अभी 16, 17 फरवरी को बरसात और ओले पड़े हैं और पूरे प्रदेश का किसान इस बरसात और ओले की मार से प्रभावित हुआ है। इसलिए मा0 अध्यक्ष जी यह बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो सूचना दी है इस सम्बन्ध में मैं पूरे सदन को अवगत चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में ओला नहीं पड़ा है और न पूरे प्रदेश में ओले से किसान कहीं तबाह हुआ है।

(बसपा के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग सुनिये। मा0 मंत्री जी कह रहे हैं, पूरे प्रदेश के विषय में। कुछ जनपदों में ओला पड़ा है, ये वह कह रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी मैं अवगत कराना चाहता हूं, पूरे प्रदेश में ओला नहीं पड़ा है, यह बात मैं तीसरी बार कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में ओला नहीं पड़ा है और पूरे प्रदेश का किसान तबाह भी नहीं हुआ है। मेरा यह कहना है कि जिन जगहों पर मान्यवर, ओलावृष्टि के

कारण किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट मान्यवर, मंगवाई गई और उसी के आधार पर उनको दैवीय आपदा में राहत दिये जाने का प्रबन्ध भी है। संवेदनशील तरीके से उस मामले को दिखवा रहे हैं और उस रिपोर्ट के आने पर उसका आंकलन करके इस आधार पर समुचित कार्यवाही की जायेगी। यह नियम-56 में नहीं आता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसमें मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि क्योंकि यह दैवीय आपदा से सम्बन्धित है और इस सूचना में आगरा, फिरोजाबाद मथुरा, मैनपुरी, एटा, कासगंज यानि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ बुन्देलखण्ड क्षेत्र भी बुरी तरह इससे प्रभावित है। हम केवल इतना आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि साथ ही साथ बुन्देलखण्ड को भी इसमें शामिल करते हुये सारे जिलों की रिपोर्ट लेकर जो भी अधिक से अधिक किसानों को आर्थिक सहायता दी जाए और हम ज्यादा अच्छा तो यह समझेंगे कि लेकिन उसके बावजूद इसकी गम्भीरता को देखते हुये इस पर सरकार का वक्तव्य आ जाये तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपकी बात सुनी और माननीय राजस्व मंत्री जी की भी बात सुनी। इसे नियम-56 में अग्राह्य करते हुये यह निदेश देता हूं कि इस पर सरकार का वक्तव्य आ जायेगा और उसमें जो आपको सवाल करने होंगे वह कर लेंगे।

माननीय सीमा द्विवेदी जी आपका प्रकरण बहुत लम्बा है। आपने 56 में भी दिया है और विशेषाधिकार की नोटिस भी दी है। आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्रीमती सीमा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं तीसरी बार इस सदन की विधायक हुई हूं। हमारे यहां थाना, मुंगरा बादशाहपुर में श्री राघवेन्द्र थानाध्यक्ष चौथी बार तैनात हुये हैं मान्यवर, इनका इतिहास बहुत ही गड़बड़ रहा है। वह जिस जिले में तैनात रहे हैं वहाँ से पनिश्मेन्ट लेकर गये हैं। उनकी चौथी बार पोस्टिंग पर मैंने अपने यहां जौनपुर के एस0पी0 साहब को लिखा मैने यह भी लिखा कि इनका तबादला यहां से हो चुका है इनकी पोस्टिंग यहां पर न की जाए। मैंने इसकी शिकायत डी0जी0पी0 साहब से भी की और उन्होंने पुलिस अधीक्षक से आख्या मांगी। वह आख्या उस थानाध्यक्ष के अगेन्स्ट में गयीं। उनका स्थानान्तरण जनपद जौनपुर से गोरखपुर जोन के लिये कर दिया गया लेकिन अपने धन और बल के प्रभाव के कारण वे अपना स्थानान्तरण निरस्त करा लिये और वहां पर वापस आ गये। मान्यवर जब उनका स्थानान्तरण निरस्त हो गया तो वहां थाना मुगरा बादशाहपुर के सामने रात नौ बजे से लेकर रात दो बजे तक जबरदस्त आतिशबाजी होती रही। लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि

इस क्षेत्र के किसी महानुभाव को लालबत्ती कार की सुविधा मिल गयी है। मान्यवर मैं उस क्षेत्र से विधायक हूँ। महिला हूँ। यदि मेरे विरुद्ध कोई अशोभनीय टिप्पणी करता है तो आप सब भी उससे सहमत नहीं होंगे और आपको अच्छा नहीं लगेगा। मान्यवर मेरा कार्य और व्यवहार सबको पता है मैं पन्द्रह साल से राजनीतिक जीवन में काम कर रही हूँ मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति के ऊपर 151 का मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ है। मैं उस परिवार से बिलांग करती हूँ। मान्यवर एक थानाध्यक्ष मेरे प्रति गलत टिप्पणी करे यह उचित नहीं है। मैंने विशेषाधिकार की नोटिस दी थी अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर राजस्व मंत्री अम्बिका चौधरी जी यहां पर बैठे हुए हैं मैं आप सबका संरक्षण चाहूँगी। मान्यवर मुझे अगर विधान सभा में न्याय नहीं मिला तो फिर विधान सभा से बाहर न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आप इसकी जांच करा लें माननीय राजस्व मंत्री जी जांच करा लें। माननीय अध्यक्ष जी आप जांच करा लें या प्रतिपक्ष के कोई माननीय नेता जांच कर लें। मुझे अन्य किसी अधिकारी पर विश्वास नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अम्बिका चौधरी जी से करा लेंगे।

श्रीमती सीमा-

मान्यवर, हम चाहते हैं कि उनका वहां से तबादला हो जाए।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय सीमा द्विवेदी जी इस सदन में बहुत ही मर्यादित ढ़ग से अपनी बात करती हैं। इस सदन में पहले से आती रही हैं। हम लोग इनको काफी अर्से से जानते हैं। जो बात कही है वह नियम-56 में तो किसी प्रकार से नहीं आती है। लेकिन जो बात उन्होंने सदन में कही है। यदि कोई माननीय सदस्य किसी बात से क्षुब्ध है और उसने सदन में उस बात को कहा है तो वह गम्भीर है। मान्यवर उन्होंने किसी बल के प्रभाव से स्थानान्तरण रुकवाने की बात कही और दूसरी बातें भी कहीं। माननीय अध्यक्ष जी इस पर जो आपके निर्देश होंगे सरकार उसका पालन करेगी। मान्यवर हम इस विषय को अगम्भीर हो कर नहीं ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राजस्व मंत्री जी इनका प्रकरण बहुत दिनों से हमारे पास है उस विशेषाधिकार नोटिस पर दरोगा का भी जबाब आया है। जब एक बार दरोगा का वहां से स्थानान्तरण हो गया तो फिर किन कारणों से उसको फिर से वहां पर लाने की बात है। वहां से कहीं अन्यत्र दूसरी जगह पर उसे करा दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन् आपके निर्देशों का पालन होगा और आज ही होगा।

श्री अध्यक्ष-

राजेश अग्रवाल जी हैं हमारे पूर्व डिप्टी स्पीकर साहब हैं, यह एक और इसी तरह का है डा0 अरूण कुमार का बरेली अन्तर्गत विषप कन्डोरेट सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल का छात्र वही है जो आप कह रहे है, वही है दोनों लोग एक ही बात कह रहे हैं तो आप दो मिनट कह लें।

(डा0 अरूण कुमार द्वारा बोलने हेतु आग्रह करने पर)

वह इस सदन के वरिष्ठ हैं, डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं उनको कह लेने दीजिए वही बात आपकी भी है उनको कह लेने दीजिए दो मिनट।

*श्री राजेश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अवसर दिया, मै धन्यवाद देता हूँ। कानून व्यवस्था कैसी है इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हुई लेकिन इसके ऊपर बरेली के अखबार जो विगत 3 माह से लिख रहे हैं, 8 दिन में 18 वारदातें, सोते रहे रखवाले जाग गयी जनता, अपराधों से दहले शहरी, शहर पुलिस का न इकबाल है न उसका भरोसा, खर्राटों में डूबी है खाकी, चोरों का है राज्य, दरोगा के घर चोरी, एस0पी0 ट्राफिक के आफिस में चोरी। मान्यवर, बहुत बुरी स्थिति बरेली जनपद की है अभी 18 फरवरी, 2013 को परसों बरेली का सुभाषनगर का रहने वाला गंगा कालोनी का निवासी श्री ज्ञानेन्द्र यादव का 8 वर्षीय बच्चा आयुष स्कूल जा रहा था अपने बहन और भाइयों के साथ जबरदस्ती तमंचे की नोक के ऊपर उसको किडनैप कर लिया। और अभी 2 घन्टे पहले का मुझे पता है कि किसी प्रकार की कोई कार्यवाही उसके बारे में अभी तक नहीं हुई है। बहुत बड़ा दहशत है बरेली के अन्दर और यह मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी पिछले 2-3 वर्षों से बरेली का माहौल कुछ अलग प्रकार का है कई बार दंगे हुए। धीरे-धीरे बरेली की गति अपने रास्ते पर आ रही है शांति है, इस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है लापरवाही से अब सरकार इसको देखें कि पुलिस की लापरवाही है या प्रशासन की लापरवाही है लेकिन इससे जो बरेली की शांति वातावरण है वह फिर से खराब होने की आशंका हो रही है। यह मेरी चिन्ता का विषय है। तत्कालिक विषय है उस बच्चे के बारे में जिसका किडनैप हुआ है, बरेली में अभी तक किडनैप कभी नहीं हुआ इसलिए मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ और निर्देश चाहता हूँ।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राजेश अग्रवाल जी के बारे में जानते हैं वह हमारे उपाध्यक्ष रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनवीर्क्षण नहीं किया।

(डा0 अरूण कुमार द्वारा बोलने की अनुज्ञा मांगने पर)

श्री अध्यक्ष-

वही बात तो आप भी दोहरायेंगे। एक सेकेण्ड इनको भी सुन लीजिए।

*डा0 अरूण कुमार-

मान्यवर, पिछले डेढ़ महीने के अन्दर करीब 50 चोरियां ऐसी हैं जिनका कोई राज नहीं खुला है, लूट की वारदात बहुत हो रही है इसके साथ ही साथ जाने कितने लोगों ने थाने जाना छोड़ दिया है रिपोर्ट लिखाने के लिए कि वहाँ जाकर क्या करेंगे लिख कौन रहा है और बहुतों से तहरीर ले ली जाती है चक्कर वह लगाते रहते हैं फिर वह अपने आप जाना बन्द कर देते हैं। चोरी, डकैती राहजनी और यह अपहरण की जो घटनाएं हैं इनको साधारण नहीं लिया जाना चाहिए। इसके अलावा यह वह जगह हैं जहाँ एक साल में दो बार कर्फ्यू लग चुका है एक महीने का। इसके अलावा जरा भी कोई बात होती है तो तुरन्त अघोषित कर्फ्यू लग जाता है। मैं चाहता हूँ वहाँ की स्थित के बारे में आप के संरक्षण में सरकार तुरन्त उचित कार्यवाही करे।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अखबार की कतरनों को अग्रवाल साहब नायात्मक कविता की तरह पढ़ रहे थे बहुत रोचक था, इसके लिए उनकी शैली के लिए उनकी सराहना करता हूँ। यह कानून व्यवस्था पर चर्चा हो और उस पर सभी तरह की घटनाओं की चर्चा हो यह तो ठीक है। लेकिन नियम 56 के लिए किसी घटना पर घटना सुनिश्चित होनी चाहिए यह अनिवार्यता है। तो स्वयं उन्होंने अपनी तरफ से खारिज कर दिया कि घटना सुनिश्चित नहीं है इसलिए नियम 56 में नहीं आना चाहिए। तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है लेकिन उन्होंने विशेष तौर पर एक घटना का उल्लेख किया है कि बाकी सारी चीजे आगे पीछे लेकिन उन्होंने इंगित किया है कि वह जो अपहरण की घटना है वह बरेली में पहली बार हुई है और गम्भीर घटना है तो मान्यवर, इसको दिखवायेंगे और इसपर समुचित कार्यवाही निश्चित रूप से करायेंगे और कोई भी माननीय सदस्य जो इस तरह की सूचना दे रहे हैं उनकी सूचना नियमों में आती हो न आती हो लेकिन सरकार को उस सम्बन्ध में जो कार्यवाही करनी है निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही कराई जायेगी। नियम 56 में इनकी सूचना नहीं आती है।

श्री अध्यक्ष-

मैने अग्रवाल जी को और डाक्टर साहब को सुना, मंत्री जी को सुना, मंत्री जी ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया इसलिए इसको अग्राह्य करते हुए अब माननीय कल जो बोल रहे थे, वह राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनवीर्क्षण नहीं किया।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, मेरी सूचना का क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष-

मैनें आपको समझा दिया था अभी बहुत टाइम है। अभी सदन बहुत लम्बा चलेगा, कुछ विषय बचाये रखो आगे के लिये। आपका एक नियम-51 भी स्वीकार है अब माननीय सदस्य को बोलने दीजिये।

(बीच में श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य द्वारा खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

(1.22 बजे) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष-

अब आप छोड़ो वह सब बातें, वह खत्म हो गयी। आपके नेता जी ने तय किया है, उसी के अनुसार चर्चा होगी।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कल बोलने के बाद आज पुनः हमें राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा में बोलने का अवसर दिया उसके लिये हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की चर्चा कल कर रहा था। हमने क्षेत्र में बहुत सी जगह पर जलभराव को लेकर नियम 301 में सूचना दिया था वह आपने ली है इसके अलावा भी हमारे क्षेत्र में दसों साल पहले जो मकान बने हुये है श्याम नगर में ए0बी0सी0डी0ई0 ब्लाक में तथा शिवकटरा में, आनन्द नगर में कृष्ण नगर में कर्मचारीनगर में वहाँ चलने के लिये रास्ता नहीं है। मान्यवर, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इन क्षेत्रों में जो सड़कें पहले से बनी हैं, अगर इन सड़कों को सही करा दिया जाये तो वही बहुत कम पैसे में सड़के बनेंगी, वह सड़के खराब हैं और कम पैसे में चलने योग्य रास्ता बन जायेगा। चूँकि वहाँ पर साइकिल से भी चलला दूभर है इसलिये अगर सरकार इस पर ध्यान देगी तो निश्चित रूप से जनता को उसका लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे बाबूपुरवा में जो कालोनी है, वह श्रमिक कालोनी है और श्रमिक कालोनी के पीछे 3-3 फुट तक कीचड़ भरा हुआ है और अगर वह कीचड़ नहीं निकलवाया गया तो अभी तो बीमारी है और आगे चलकर महामारी शुरू हो जायेगी। इसी तरह से शिवकटरा में, आनन्द नगर आदि क्षेत्रों में सीवर बह रहा है, वहाँ पहले छोटी सीवर लाइन पड़ी थी, जनसंख्या बढ़ जाने की

† दिनांक 19 फरवरी, 2103 की कार्यवाही से।

वजह से यह समस्यायें बनी हुयी हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री के रूप में आज हमें सौभाग्य मिला है कि बड़े भाई अम्बिका चौधरी जी बैठे है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे सदस्य हाथी वाले कह रहे थे कि बिजली पानी दे न सके, वह सरकार निकम्मी है। इसके पहले भी इन्होंने बिजली पानी नहीं दिया है और आज यह माँग रहे हैं निश्चित यह बिजली पानी एक अहम समस्या है और इस सरकार को सोचना चाहिये कि जिन्होने नहीं किया वह माँग रहे हैं। मतलब यह अहम समस्या है। आज जनता रोटी कपड़ा मकान भूल गई है, आज जनता को बिजली पानी और सड़क की समस्या दिखाई पड़ने लगी है। अगर सरकार इस काम को करायेगी तो निश्चित रूप से हम सबको इसका लाभ मिलेगा।

मान्यवर, मै एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो बलात्कार हुये हैं अभी तक उन बलात्कारियों को आरोप-पत्र देकर जेल नहीं भेजा गया है, गौ हत्यायें हुयी हैं, इन हत्याओं को भी आज तक सही ढ़ग से नहीं लिया गया है। इसमें शासन प्रशासन दुरूस्त करने की जरूरत है। मै आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ। कल मैं कह रहा था कि डी0एम0, एस0एस0पी0, कमिश्नर फोन नहीं उठाते हैं, सौभाग्य है कि आज मैनें डी0एम0 को फोन मिलाया और उन्होने फोन उठा लिया, यह सरकार का दबाव है या सदन में मैं जो बोला हूँ उसका दबाव है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मै नया विधायक इस सदन में आया और मैंनें बात रखी वह हो गयी। जो दर्जनों बार फोन न उठाया हो, आज उस डी0एम0 ने हमारा फोन उठाया।

मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जिस तरह से खनन् में खदानों में लूट चल रही है जो खदान चला रहे हैं, वह यह कहते हैं कि ऊपर पैसा जा रहा है। इसका माल सब ऊपर जा रहा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि पोंटी चढ्ढा तो चला गया जो पैसा लेकर सरकार में ऊपर पहुँचाता था, अब ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया है, कुछ चर्चाओं में आया है कि चिकारा नाम का व्यक्ति आपके प्रदेश में घुस गया जो हरियाणा का रहने वाला है।

(इस समय 1 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए)

और वह पूरी तरह से सरकार को डील कर रहा है। क्या सरकार पूर्ववर्ती हाथी की सरकार की तरह काम करेगी, एक पोन्टी चड्ढ़ा ऊपर चला गया जो पैसा अपने पास नहीं रख पाया है अब चिकारा सारे पैसों की डील कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि एक गाड़ी से 10 से 15 हजार रुपए तक लिया जाता है अगर यह रुपया सीधे सरकार को मिले तो इतना रेवेन्यू मिल जायेगा कि सरकार जो पैसे को परेशान है वह परेशान नहीं रहेगी। मैं तो कहता हूँ कि इसका निगम बना दिया जाए और सरकार स्वयं इसका काम करे और जितना माल लदे, जितनी रायल्टी का आप सामान दें उतनी ही रायल्टी दें और अगर इससे ज्यादा

कोई आता है तो सबसे पहले खादान बन्द होना चाहिए, खादान का मालिक चेन्ज होना चाहिए और इसके बाद गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को जेल जाना चाहिए। अगर इनके साथ आप कुछ न कुछ कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि घटतौली खत्म हो जायेगी, यह रोज रोज सड़क की आँख मिचौली खत्म हो जायेगी, होमगार्ड से लेकर सिपाही, दारोगा से लेकर कप्तान, सी0ओ0 से लेकर वरिष्ठ अधिकारी बहुत लोग इसमें शामिल हैं कि जगह-जगह पर करोड़ों रुपया गलत ढ़ंग से आज वसूला जा रहा है। मान्यवर, मैं आपकी पीठ से चाहता हूँ कि सरकार इस पर कार्यवाही करे क्योंकि इससे पहले हाथी की सरकार ने लूटा था और जिसकी वजह से सड़क पर हाथी की सरकार पीछे हो गई और साइकिल की सरकार आगे हो गई कहीं साइकिल की सरकार जो 2014 में आप सोच रहे हैं मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा करते रहे तो 2014 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में बनेगी और 2017 में क्या होगा यह ईश्वर जाने। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अभी भी सीख लें और अगर सीख नहीं लेंगे तो तो जनता परेशान है जिसे आज सड़क पर लूटा जा रहा है, मैं कानपुर से लखनऊ आता हूँ एक घण्टे की रास्ता थी, टोलटैक्स वाले पैसा ले रहे है सड़कें नहीं बना रहे है आाखिर टोलटैक्स के रूप में जो पैसा लिया जाता है वह किसलिए लिया जाता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर इस विषय में विशेष प्रयास न किये गये तो हम सभी का नुकसान होगा। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं कहना चाहता हूँ कि मैने अपने क्षेत्र की जो भी समस्याएं सदन में रखी है उन्हें अभिभाषण में जोड़ दिया जाए, धन्यवाद।

*श्री लोकेश दीक्षित-

मान्यवर, मैं आभार प्रकट करता हूँ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज किसान को बड़ी मजबूती के साथ लूटा जा रहा है। यदि उसके ट्यूबबेल का ट्रांसफार्मर फुंक जाता है तो उसका तीन तीन महीने बाद बनने का नम्बर आता है और तीन महीने में नम्बर तब आता है जब वह पाँच हजार से लेकर दस हजार रुपए तक स्टोरकीपर को देता है और वह स्टोरकीपर उस पैसे को ऊपर तक पहुँचाता है। किसान के पास कोई ऐसा स्रोत नहीं होता कि वह अलग कहीं से पैसा लाये, वह ब्याज का पैसा और मेहनत मजदूरी का पैसा ला करके स्टोरकीपर को देता है तब जाकर उसका ट्रांसफार्मर बदला जाता है। मै आपसे कहना चाहता हूँ कि भारत देश 65 प्रतिशत कृषि प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश 80 प्रतिशत कृषि प्रधान प्रदेश है। हम किसान की बात करते हैं, किसान के बेटे कहलाते है, सी0एम0 भी किसान के बेटे कहलाते है परन्तु किसान को रात में नहीं बल्कि दिन-दहाड़े लूटा जाता है। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ हमारा बागपत जिला है बड़ौत से मैं चुनाव जीत कर आया हूँ, हमारा जिला 90 प्रतिशत गन्ना उगाता है और गन्ने में इतनी घटतौली होती है कि किसान की

* वक्ता ने भाषण का पुनवीर्क्षण नहीं किया।

तो वैसे ही कमर टूट जाती है इसका संज्ञान हम कई बार थानों में, कई जगहों पर देते हैं, डी0एम0 के यहाँ भी देते है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे माननीय मंत्री, पी0डब्ल्यू0डी0 ने कहा था, पिछली बार भी कहा था कि सभी विधान सभाओं में 20-20 किलोमीटर तक गड्ढामुक्त सड़क हो जायेगी। आज सड़कों के हालात यह है कि जो पशु है जो भैसाबुग्गी चलती है और जब किसान भैसाबुग्गी में गन्ना लेकर मील पर आता है तो उस भैसे के पैर भी लहुलुहान हो जाते है। क्योंकि सड़क गड्ढ़ामुक्त नहीं हो पायी, सड़के जर्जर हो चुकी है। एक साल के अन्दर, मैं तो यह कहता हूं कि हमारा जिला तो है ही, पूरे प्रदेश में कही भी रोलर चलता हुआ नहीं दिखाई दिया। माननीय अधिष्ठाता जी, सड़कों की हालत बहुत खराब है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि तालाब ओवर फ्लो हो गये, कुछ तालाबों पर कब्जे तो हो ही रहे हैं, वह हम सब जानते है। ओवर फ्लो होने के कारण गंदा पानी गाँवों की गलियों में बह रहा है। बरसात मे हमारे यहाँ 50 प्रतिशत गाँव ऐसे हैं जो बहुत त्रस्त है जिसकी वजह से पीलिया व अन्य बीमारियाँ हो जाती हैं। आपसे मेरा विशेष तौर पर निवेदन और प्रार्थना है कि उन तालाबों की खुदाई नरेगा से नहीं हो पाती है, नरेगा से अगर होती है तो जो गाँव के प्रधान जी होते हैं, सभी को कसूरवार मैं नहीं कहता, लेकिन तकरीबन कसूरवार पाये जाते हैं। अभी मैं अपने गाँव की ही बात कहूँ, एक कालेज है उसके सामने एक बहुत बड़ा तालाब है। उस पर 25 प्रतिशत कब्जा हो गया है और मुझे लगता है कि साल दो साल में 25 प्रतिशत और हो जायेगा। तालाबों की हालात खराब हो गयी है, मेरा आपसे निवेदन है कि ट्यूबवेल या इंजन लगाकर तालाबों को खाली किया जाए, यह हो सकता है। हर गाँव के साथ खेत-खलियान है वह पानी खेतों में चला जायेगा। उसकी खुदाई हो जाए और रेत निकल जाए, अगर रेत निकल जाएगा तो जो गाँव का पानी उसमें जाता है वह पानी जमीन में जायेगा, उससे वाटर लेबल भी बढ़ेगा।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ गायें या बैल, साथ में हरियाणा है। अभी हमारे कुछ किसान भाई नागौर जिले से बैल लेकर के आ रहे थे वह गौरीपुर मोड़ पर पकड़े गये कि आप बैल लेकर के आ रहे हो, यह बड़ा अपराध है। किसान बैल लेकर के आता है तो उसको पुलिस पकड़ लेती है, जेल में डालती है और उससे रिश्वत लेती है। असलियत में जो काटने के लिए लाता है वह रात के अँधरे में अपनी गाड़ियों से ले करके आता हे उनको नहीं पकड़ा जाता। भोले भोले किसानों को मुल्जिम बनाकर खड़ा किया जाता है। मान्यवर, हमारे यहाँ हरियाणा नजदीक में है, लोग गायें लेकर के आते हैं, किसान एक गाय लेकर के आ रहे हैं, बैल ले करके आ रहा है तो उसको तो जरूर पकड़ेंगे अन्यथा वैसे तो छोड़ देते हैं। माननीय अधिष्ठता जी, एक सबसे बड़ा मामला सड़कों का जरूर है कि हमारे यहाँ कम से कम 5-6 मिल है उस शुगर मिल तक आने वाली सड़कों

की हालत बिल्कुल एकदम जर्जर हो गयी है। ट्रैक्टर ट्रॉली वाले तो बैठकर के ट्रैक्टर ले आते हैं। असलियत में जो छोटा किसान है वह पिस जाता है। उसका जो भैंसा होता है उसके पैर अक्सर लहुलुहान हो जाते है। इसलिए उस पशु पर दया करके कम से कम उन सड़कों को जरूर, किसी न किसी समिति से जो मिल पर छोटा किसान गन्ना ले करके आता है, उसको आप अवश्य ठीक करायें। यह मेरा आपसे निवेदन और प्रार्थना है। इसी के साथ आपने मुझे मौका दिया मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री मदन चौहान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो माननीय प्रो0 शिवाकांत ओझा ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा था उसके सम्बन्ध में मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। मान्यवर, जो अभिभाषण महामहिम राज्यपाल महोदय ने दिया, विपक्षी दलों ने उसमें विपरीत प्रतिक्रियायें की है। लेकिन यह सत्य है कि जब तक प्रदेश का या देश का किसान, छात्र, गरीब, कमजोर आदमी की तरक्की नहीं होगी तो प्रदेश की विकास दर नहीं बढ़ सकती और जब तक विकास दर नहीं बढ़ सकती तो विकास या सम्पन्नता का द्योतक हम लोग नहीं हो सकते। मान्यवर, इन सबको प्रभावित करते है चिकित्सा, शिक्षा, किसान, सड़क का निर्माण, विद्युत आपूर्ति आदि। अब जिस तरह से हम सब लोगों ने महसूस किया है कि पूर्व सरकार में व्यवस्था कहाँ तक बिगड़ी थी उसको सही रूप में लाने के लिए कुछ समय की आवश्यकता जरूर होती है। लेकिन फिर भी सात आठ महीने में जिस तरह से सरकार ने और हमारे युवा मुख्य मंत्री जी ने अपनी नीति के तहत, क्योंकि कल मैं सुन रहा था तीन बातें मैंने सुनी नेता, नीति और नीयत अब पहले कैसे नेता थे आज के युवा मुख्यमंत्री कैसे नेता हैं मैं तो यहाँ पर देखता हूँ कि विपक्ष के लोग भी ऐसे मिलते हैं जैसे कोई बहुत परिचित और बहुत लगाव हो। और पूर्व में तो सत्ता पक्ष के लोगों का ही मिलना मुश्किल हो जाया करता था तो विपक्ष की तो कोई औकात ही नहीं थी। तो मान्यवर, मैं यह नेता के गुण की बात कर रहा हूँ। अब नीयत कैसी थी यह हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कितने पूर्व मंत्री जेल में है उनकी नीयत कितनी बढ़िया थी। आज क्या स्थिति है और यह भी बिल्कुल सही बात है कि नीयत साफ नहीं होगी तो हम लोग किसी किसान को छात्र को छात्राओं को गरीब को मदद करने वाली नीति नहीं बना सकते हैं। आज साफ नजरिया है सरकार हमारी पार्टी की सरकार का साफ नजरिया है कि वह गरीब की मदद करें किसान की मदद करें किसान के लिए ऐसी नीतियां बनाए ताकि उसकी विकास दर बढ़ जाय और उसके भी बच्चे पढ़ लिख लें और उसकी भी बेटियों की शादी हो सके। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो हमारी सरकार ने नीति बनाई कि कर्ज से मुक्ति। मुक्ति किसे चाहिए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनवीर्क्षण नहीं किया।

जो किसान बेचारा कर्ज के बोझ में दब गया हो अब उस दबे हुए को किस तरह से निकाला जाय वह हमारी सरकार ने हमारी सरकार के मुखिया ने इसमें 50 हजार तक का कर्ज जो माफ करने की घोषणा की थी उसको क्रियान्वयन करने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है और उस पर अमल हो रहा है। किसानों को लाभकारी मूल्य मिले आज गन्ना किसान की हालत देखिए पहले भी आपने देखी होगी और आज हम पाते हैं कि किस तरह से रेट बढ़ा और रेट बढ़ने से गन्ना किसान ने अपने को संतुष्ट महसूस किया प्रसन्नता जाहिर की तो इसमें गन्ना किसान की तरक्की होगी। मान्यवर, क्योंकि किसान बहुत कमजोर व्यक्ति है और किसान की माली हालत पर पूरे देश के और प्रदेश के हालात निर्भर करते है। तमाम घटनाओं का शिकार कभी कभी किसान हो जाता है। गरीब किसान जिसको रोटी मिलना भी मुश्किल हो जाता है उसकी किसान दुर्घटना बीमा जिसको समाजवादी सरकार ने एक लाख से शुरू की थी आज अपनी सरकार में उसको पाँच लाख तक कर दिया। यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी तरह से ग्रामीण किसानों को क्योंकि ऋण की आवश्यकता होती है फसल में खाद बीज डालने के लिए और कई कारणों से उसको फसल में ऋण की आवश्यकता होती है उसको अगर कम रेट पर ऋण मिले तो वह उसके लिए फायदेमन्द होगा। ग्रामीण किसानों के लिए जो तीन प्रतिशत ऋण देने की सरकार ने घोषणा की है वह वास्तव में किसान के हितकारी हैं। मान्यवर, दूसरी चीजें दैवी आपदा से आर्थिक मदद मिलना सिंचाई मुफ्त होना यह बहुत बड़ा कदम है सरकार का जिसमें सिंचाई अगर किसानों के लिए मुफ्त होगी तो एक बोझ उनके ऊपर से हट जाएगा। एक उसको राहत मिलेगी इस बार जिस तरह से सिल्ट सफाई हुई है तो आपने देखा होगा कि नीयत में अन्तर है। आज की सरकार काम करना चाहती है किसान के फेवर में। सरकार किसान को राहत देना चाहती है। इसी तरह से महिलाओं के लिए छात्र-छात्राओं के लिए क्योंकि छात्र-छात्राओं के पास अपना कोई रोजगार नहीं होता है उनको मदद करना बेहद जरूरी है। आज जिस तरह से ईन्फार्मेशन टेक्नालाजी बढ़ती जा रही है उसके लिए जरूरी है कि बच्चे बच्चे के पास कम्प्यूटर जो शहर में हम देखते हैं वह गाँवों में नहीं है तो छात्र-छात्राओं के लिए कम्प्यूटर टैबलेट और लैपटाप की व्यवस्था की गई है वह वास्तव में सरकार का नजरिया बहुत साफ है और सरकार चाहती है कि हमारे प्रदेश का छात्र आगे बढ़े क्योंकि जब भी परिवर्तन होता है तो छात्र छात्राओं का बड़ा योगदान होता है उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो सरकार ने की है इसको सराहना चाहिए। मान्यवर, कन्या विद्या धन क्योंकि कन्या को बहुत नीचे की दृष्टि से देखते हैं हमारे समाज में लेकिन जब उसको विद्याधन मिलता है तो उसका स्तर बढ़ जाता है। गरीब लड़कियों के लिए 30-30 हजार रुपए देना उसका मनोबल बढ़ाना है इसी तरह से महिलाओं के लिए जब गाँव में हम जाते हैं, क्षेत्र में हम जाते हैं, आप भी जीते होंगे और तमाम जन प्रतिनिधियों को भी जाने का मौका मिलता है, तो वह देखते हैं कि गरीब महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं जिनके पास कोई

सहारा नहीं होता, जिनको कहीं से कोई सहारा नहीं मिलता है। बी0पी0एल0 परिवार की महिलाओं को सरकार ने अगर साड़ी देने का और वृद्धजनों को कम्बल देने का काम किया है तो वह एक सराहनीय कार्य है, उसकी सराहना करनी चाहिए। मान्यवर, उसी तरह से गरीब आदमी है। मान्यवर, रिक्शा कौन चलाता है ?

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री मदन चौहान-

रिक्शा वह गरीब आदमी चलाता है जिसके पास रोजगार को कोई और साधन नहीं होता है। रिक्शा चालक को बहुत गरीब, कमजोर, आर्थिक कमजोर माना जाता है। जब वह आर्थिक कमजोर है तो मान्यवर, उसके रिक्शे में हम लोग बैठ जायं। मान्यवर, कभी कभी 4 लोग उसके रिक्शें में बैठ जाते हैं और एक छोटा सा कमजोर आदमी उस रिक्शा को चलाता है तो मान्यवर, क्या हालत होती है, जरा इस पर सोचिये। इस पर हमारी सरकार ने चिन्तन किया है, और सरकारों ने तो नहीं किया है। इसलिये यह यह उपलब्धि है। और उसके लिये एक बैटरी की व्यवस्था, सौर ऊर्जा से चलने वाली एक मोटर बैटरी जिससे वह रिक्शा चला सके।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त करें।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, रानी लक्ष्मीबाई योजना, एक ऐसी योजना, जिसमें जो कहीं किसी और योजना से कवर नहीं होता, किसी को कहीं से एक पैसे की मदद नहीं मिलती। बहुत सारे वृद्ध हैं जो बी0पी0एल0 की श्रेणी कवर नहीं हो पा रहे उनका नाम नहीं आ पा रहा है उस सूची में, उसकी पात्रता की श्रेणी में उसका नाम नहीं आ पा रहा है। मान्यवर, जिसका कोई सहारा नहीं है। मान्यवर, अगर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के गरीब कमजोर लोगों की बात नहीं करता वह दोबारा चुनना मुश्किल हो जाता है, तिबारा चुनना मुश्किल हो जाता है। इसलिये गरीब की बात करना, निर्धन की बात करना यह बहुत जरूरी है। मान्यवर, इसके लिये इस प्रकार से निर्धन व्यक्तियों के लिये, मेहनतकशों के लिये आवास की व्यवस्था, बेरोजगारी भत्ता, जो पढ़ लिखकर।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा माननीय सदस्या श्रीमती रूबी प्रसाद का नाम पुकारा गया)

श्रीमती रूबी प्रसाद-

धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने को मौका दिया।

श्री मदन चौहान-

यह योजनाएं ऐसी हैं जो गरीब को बढ़ायेंगी, किसान को आगे बढ़ायेंगी। किसानों की तरक्की होगी तो देश की तरक्की होगी।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। रूबी जी आप अपनी बात कहिये।

श्री मदन चौहान-

अगर किसान आज पैदा नहीं करेगें तो हम आप रोटी भी नहीं खा पायेगें। तो मान्यवर, सरकार की इस बात को सराहना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

चौहान साहब सुन तो लें। माननीय अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी है उसके अनुसार दो मिनट ज्यादा ही हो गये हैं।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन तो लें। अभी दो मिनट ही हुए हैं। अधिष्ठाता जी, मौका नहीं मिलेगा, अभी तो खाली सा ही है। हमको ऐसे में मौका मिल जाना चाहिए। दो मिनट और बोल रहा हूँ। मान्यवर, गढ़मुक्तेश्वर है। आपका उत्तराखंड में जाने बाद वहाँ की पवित्र नदी जो गंगा नदी है। गढ़मुक्तेश्वर में जो इतना पौराणिक और पवित्र स्थल है मान्यवर, उसको पर्यटन की दृष्टि से सरकार का अपना एक मनसूबा है कि उसका विकास किया जाय। और जो वहाँ बड़ी बड़ी झील हैं मान्यवर, भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर उसका सौन्दर्यीकरण कर दें तो पर्यटन की दृष्टि बहुत दूर दूर का यात्री और श्रृद्धालु वहाँ पर गंगा स्नान करने को आयेगा और वहाँ के सौन्दर्यीकरण को देखने को आयेगा। दूसरी बात मेरी यह है मान्यवर, कि गढ़मुक्तेश्वर कई जगह पर हाई वे पर स्थित है वहाँ पर रोज कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि अगर वहाँ पर ट्रामा सेन्टर की स्थापना हो जाय तो बहुत बड़ी उपलब्धि वहाँ सभी के लिये होगी। बहुत से लोग वहाँ बहुत दूर से आते हैं और एक्सीडेंट में कई बार घायल हो जाते हैं, उनको दूर तक जाने में समय लग जाता है इसलिये वहाँ पर एक आधुनिक ट्रामा सेन्टर की स्थापना बहुत जरूरी है।

कृपया समाप्त करें।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर,आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आभारी हूँ और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव का भरपूर समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्रीमती रूबी प्रसाद-

धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं जनपद सोनभद्र जो अति गरीब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र

है, का प्रतिनिधित्व करती हूँ मैंने राज्यपाल के अभिभाषण को बड़े गौर से पढ़ा उसमें कहीं भी आदिवासियों के लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है जिससे उसकी शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारा जा सके। चूकि जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के बाद सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला है हमारे जनपद सोनभद्र जहां पर बड़े-बड़े उद्योग लगे हैं, बड़े-बड़े थर्मल पावर हैं और आज भी सोनभद्र अंधेरे में जीने को विवश हैं। वहां के आदिवासियों का शैक्षिणिक स्तर और सामाजिक स्तर काफी पिछड़ा हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आजादी के बाद से सिर्फ एक डिग्री कालेज है और वहां से छात्र छात्रायें 80 किलोमीटर की दूरी तय करके उस डिग्री कालेज में पढ़ने आते हैं और युवा मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, पढ़े-लिखे और सूझबूझ वाले मंत्री जी है उनसे उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीदें थी। बड़ी उम्मीद के साथ जनता ने उनको प्रचंड बहुमत देकर उनकी सरकार बनवाई लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र ऐसा है जहां आदिवासी, वनवासी और गिरिवासी जंगलों में रहते हैं आदि मानव की तरह रहते है सामां कोदों का भात खाते हैं उनका शैक्षिणिक स्तर ऐसा है कि आप सोच लें आजादी के बाद हमारा विधान सभा जो छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड, बिहार से घिरा हुआ है और नक्सली क्षेत्र है नक्सलियों के लिए भारत सरकार ने, जिससे नक्सलियों में सुधार हो सके और वहां के आदिवासी लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। इसके लिए बड़े-बड़े पैकेज देते हैं, लेकिन आज भी वहां की जनता नदी नालियों से पानी पीने के लिए विवश है। मजबूर है वहां के आदिवासी सामां कोदों का भात खाते हैं। उनका शैक्षिणिक स्तर इतना नीचा है कि उन्हें पता भी नहीं कि जब आदिवासी अस्पतालों में बीमार होकर जाते है तो वहां जो उनका इलाज होता है तो आदिवासी जो जंगल में निवास करते हैं अस्पतालों के कर्मचारी और अधिकारी उनका बहुत उत्पीड़न करते हैं, शोषण करते हैं। क्योंकि वह पढ़े लिखे नहीं होते है। वह लोग बहुत सीधे होते हैं। उनका बहुत शोषण किया जाता है।

हमारा जनपद सोनभद्र जो कि पूरे पूर्वाचल में नम्बर एक पर खनन में है। हमारे सोनभद्र में एक चिकारा नाम का आदमी खनन माफिया बनकर बैठा हुआ है। पूरे जनपद सोनभद्र के जो छोटे छोटे उद्योग के मालिक है वह परेशान है। आए दिन हम लोगों से शिकायत करते रहते है। अगर कहीं एक ट्रक मिट्टी जाती है तो वहां पर चिकारा नाम का आदमी परमिट के नाम पर बी0आई0पी0 टैक्स और गुण्डा टैक्स के नाम पर 4100/- रुपये प्रति ट्रक वसूली करता है इससे आम किसान, गरीब आदिवासी और दलित वर्ग के लोग प्रभावित हैं। क्योंकि घर बनाने के लिए उन्हें गिट्टी और बालू की जरूरत पड़ती है। और इस तरह का काम जो हो रहा है, पता नहीं इस तरह की बातें मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में है या नहीं, लेकिन उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। चिकारा नाम का व्यक्ति जो है उसके लोग मिट्टी और गिट्टी पर वसूली करते हैं। मैं मंत्री जी से आग्रह करूँगी कि इस

तरह के धन्धे करने वाले लोगों पर रोक लगाई जाए। ताकि लोगों को यह विश्वास हो कि हमारे युवा मुख्य मंत्री जो इतनी अच्छी सोच रखते हैं कम से कम किसानों के हितैषी कहलाने वाले, आदिवासियों और दलितों के हितैषी कहलाने वाले, इनकी बातों का संज्ञान गम्भीरता पूर्वक लें। और अवैध खनन और इस चिकारा पर रोक लगाने का काम करें। साथ ही साथ एक अति लोक महत्व की बात है जिसको मैं कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों में एक गोंड़ जाति है जिसको पिछड़ी जाति कहा गया है और उत्तर प्रदेश सरकार के गजट में और भारत सरकार के गजट में, गोंड़ जाति पहले से ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में है तो फिर इसे पिछड़ी जाति से अनुसूचित जाति में करने का क्या मतलब है यदि यह वही गोंड़ जाति है तो पूरे भारतवर्ष में गोंड़ जाति सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में है। 57 जिलों में गोंड़ जाति को अनुसूचित जाति में रखा गया है और 13 जिलों में अनुसूचित में रखा गया है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ है कि जिन जिलों में अनुसूचित जनजाति में रखा गया है उनको सार्टिफिकेट इश्यू नहीं होता है। इससे जो हमारे आदिवासी भाई दर-दर की ठोकरें खाते हैं। उनके बच्चे उच्च शिक्षा, प्राइमरी स्कूल में एडमीशन पाने में, वजीफा पाने में उनको काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। मेडिकल इंजीनियरिंग में भी उनको नामांकन दाखिल करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए जो 13 जनपदों में इनको अनुसूचित जनजाति में रखा गया है, उनको सर्टीफिकेट प्रदान करने की कृपा की जाए। साथ ही साथ जब भारत सरकार के गजट में और उत्तर प्रदेश सरकार के गजट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में गोंड़ जाति को रखा गया है, फिर यह क्यों कहा जा रहा है कि गोंड़ जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। यह सिर्फ जनता को ठगने का काम किया गया है उनको गुमराह करने का काम किया गया है ताकि इनको सर्टीफिकेट न मिल सके, इनको मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज में दाखिला न मिल सके और जो यह वजीफा या छात्रवृत्ति पाते है, वह न मिले, यही कारण इसमें नजर आता है। मान्यवर, मैं एक महिला जनप्रतिनिधि हूँ, इसलिए मैं महिलाओं के बारे में बोले बिना नहीं रह सकती। हमारी विधान सभा में ही एक महीने के अन्दर 2 बच्चियों और 1 महिला के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी गयी। 7 साल की एक बच्ची जो अनुसूचित जनजाति की थी, उसके साथ बलात्कार करके, उसकी हत्या करके उसकी लाश फेंक दी गयी थी। उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी तो मजबूरन मुझे थाने का घेराव करना पड़ा। दुद्धी थाना जहाँ तहसील भी है, मैंने थाने का घेराव किया जब जाकर उस बच्ची की रिपोर्ट लिखी गयी और आनन-फानन में 1 लाख 86 हजार रूपये प्रशासन ने दिया। साथ ही साथ और लड़की के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गयी और उसकी डेड बाडी को 24 घण्टे के अन्दर बिना पोस्टमार्टम किए ही जला दिया गया। मान्यवर, इस तरह की घटनाएँ हमारे क्षेत्र में होती रहती है।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी पूरी बात आ गयी है, अब आप बैठिए।

श्रीमती रूबी प्रसाद-

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक महिला सदस्य हूँ तो महिलाओं के बारे में बोलने का हमें मौका दीजिए। हम चाहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा यह सरकार प्रदान करे। महिलाओं को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, पूरे देश का यह मामला है, धन्यवाद।

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अधिष्ठाता जी, रूबी प्रसाद जी ने अभी एक बात कही है, वह स्पष्ट हो जानी उचित है, किसी स्तर पर उसमें भ्रम नहीं रहना चाहिए। वह जाति स्पष्टतया 13 जनपदों में अनुसूचित जनजाति में है। और बाकी जनपदों में न्यायालय के आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति में है। यह कहीं पिछड़ी जाति में नहीं है और यह भ्रम जिस किसी कारण से भी हो गया है, कहीं किसी अखबारी रिपोर्ट से या किसी पर्चे से, किसी प्रचार से, किसी बैनर से तो उससे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट है कि गौड़ जाति 13 जनपदों में अनुसूचित जनजाति में है और बाकी जनपदों में अनुसूचित जाति में है और यह पिछड़ी जाति में नही है, इसलिए इसको अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने के सम्बन्ध में जो भी सूचनाएँ है, वह भ्रामक है, आप उस भ्रम में न रहिए। सरकार का स्पष्ट निर्णय है और उनके प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश भी दे दिए गए है और आज की तारीख में एक और शासनादेश जारी करके कि जो लोग रिपोर्ट करने में आनाकानी करेंगे या कोताही करेंगे, जानबूझकर परेशान करेंगे, उनको दण्डित करने का प्रावधान किया जायेगा। इस बारे में आज ही शासनादेश जारी किया जायेगा। इसमें कोई भ्रम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

चलिए, आपकी बात का उत्तर भी आ गया।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मुझे अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, मैं केवल विरोध में नहीं बोलूँगा, कल जब धन्यवाद प्रस्ताव किया जा रहा था, जिन माननीय सदस्य को धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना था, वह सदन से गायब हो गये। उन्होंने सोचा होगा कि इसमें धन्यवाद देने लायक कुछ है ही नहीं। जिन माननीय सदस्य को उसका समर्थन करना चाहिए था, वह हाउस में बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम समर्थन नहीं करेंगे। फिर माननीय अम्बिका चौधरी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी, हमारे मित्र हैं इन्होंने एक माननीय सदस्य को इशारा किया कि तुम बोलो। आदरणीय श्री शिवाकान्त ओझा जी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। उन्होंने दबाव में प्रस्ताव रख तो दिया लेकिन उस पर चर्चा हो, पक्ष और विपक्ष क्या बोल रहे है। मान्यवर, जो धन्यवाद प्रस्ताव रखता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह पूरी चर्चा को सुने और अंत में उसका जवाब देना होता है। लेकिन माननीय श्री शिवाकान्त ओझा जी कल से बोलने के बाद गायब है। वह कल से ही नहीं हैं। इसका मतलब कि वह खुद के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं।

श्री पूर्णमासी देहाती-

वह आये हैं। अभी बैठे थे।

श्री सतीश महाना-

जब मैं बोल रहा हूँ तो वह उस समय नहीं हैं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल को किस बात के लिए धन्यवाद दिया जाये। उन्होंने पहले पेज से कुम्भ मेला से प्रारम्भ किया और कुम्भ में 42 लोग मर जाते है क्या इस बात के लिए उनको धन्यवाद दिया जाये। इसके लिए तो उनको संवेदनायें व्यक्त करनी चाहिए थी कि बड़ा अफसोस है। लोग मर गये और हम उनको धन्यवाद दे दें। कल आदरणीय शिवाकान्त ओझा जी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ कि वह यहाँ पर क्यों नहीं हैं। कार्यवाही में है। कल उन्होंने कहा कि हम महामहिम राज्यपाल को इसलिए धन्यवाद देना चाहते है कि जो कालेजेस में वर्षों से इलेक्शन नहीं हुए थे, वह उन्होंने समय से कराये है। मान्यवर, मैने इसका एक-एक पेज पढ़ा इसमें इलेक्शन का जिक्र ही नहीं हैं। उन्होंने धन्यवाद दे दिया कि उन्होंने यूनिवर्सिटीज के इलेक्शन समय से कराये। जो काम नहीं कहा गया है उसके लिए भी धन्यवाद दे रहे हैं। मान्यवर, धन्यवाद किस लिए दे रहे हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में लॉ आर्डर की स्थिति ध्वस्त है। महिलाओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं वह हमारे सामने है। अभी माननीय सदस्य ने विस्तार से बताया कि किस किस पर अत्याचार हो रहे है। किस बात के लिए इनको धन्यवाद देना चाहिए। इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि गरीब बस्ती में रहने वाले आदमी के पास पीने के लिए पानी नहीं है। हैण्डपम्प आपने एक भी नहीं दिया, धन्यवाद हम दे दें। बिजली के बारे मे चर्चा में माननीय मंत्री जी ने कहा कि 31 परियोजनाओं में एक पर भी काम समय से नहीं हो रहा है। बिजली परियोजनाएँ कहाँ है कहाँ नहीं है यह सरकार को भी नहीं पता। इनको किस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए। सरकार की कोई इंडस्ट्रियल पालिसी नहीं है। एक आगरा समिट आपने की।

श्री अम्बिका चौधरी-

पालिसी है।

श्री सतीश महाना-

चलिए, पालिसी होगी लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। मान्यवर, एक आगरा समिट करने से उत्तर प्रदेश में उद्योग बढ़ जाएगा। पिछली बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो देश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों को बिठाकर सजाया गया था। और कोई एक औद्योगिक विकास परिषद नाम दिया गया था। उनमें एक श्रीमान् जी थे, क्या हुआ क्या नहीं, मैं उनके बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता। लेकिन क्या एक भी उद्योग लगा। उस औद्योगिक विकास परिषद में जो सबसे बड़े देश के आदमी थे जिनका नाम अम्बानीज था उन्होंने उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी जमीन लेकर कहा कि हम इस पर पावर प्लांट लगायेंगे। और वह गायब हो गये, क्या इसलिए औद्योगिक विकास निगम की स्थापना नहीं की जा सकी। औद्योगिक विकास निगम की स्थापना करने के लिए आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा औद्योगिक घरानों को कि आप आइये यहां पर, हम आपको इन्फ्रास्ट्रेक्चर देगें, आप आइये यहां पर, यहां पर ला एण्ड आर्डर हम कण्ट्रोल करेंगे, आप आइये यहां पर, सिंगल विण्डों के ऊपर आपको, आपकी सारी की सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। मेरे मन में है, मैने पिछली बार भी जब विधान सभा सत्र प्रारम्भ हुआ था, मैने कहा था कि मुझे मा0 मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है, आज भी है, लेकिन इस विश्वास को बनाये रखने का काम सरकार करे। वह विश्वास डामाडोल न हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है और इस मामले में सरकार हमें कहीं गम्भीर दिखाई नहीं दे रही है।

मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी, जिलों में जाकर यहां लखनऊ में किया होगा, जिलों में किया होगा, मुझे नहीं मालूम कि कितनी सौ परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन कर दिया, शिलान्यास कर दिया। मेरा मा0 मंत्री जी से, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी की कुर्सी पर बैठे हैं, विनम्र निवेदन है, क्योंकि मुख्य मंत्री है, तो वह हमारे, आपके, सबके मुख्यमंत्री हैं और सबके मन में उनके प्रति आदर होना चाहिए, संवैधानिक पद है, लेकिन मुख्य मंत्री जी के नाम की शिलापट अगर किसी गली में लिख जाती है। और वह टूट कर गिर जाती है, उस पर कोई काम नहीं होता है, तो आपको तकलीफ होती है कि नहीं होती है, लेकिन मुझे तकलीफ होती है कि मेरे प्रदेश के हमारे मुख्य मंत्री की शिलापट टूट कर गिरी क्यों। उसकी फोटो छपती है तो समाजवादी पार्टी के लोग जाकर उसकी फोटो खिंचा कर पूरे शहर को बता देते हैं कि शिलापट गिर हुआ हमने देखा है। शिलापट मत लगवाइये, लगवाइये तो उसके ऊपर काम करवाइये। मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा को हल्के में लेने में किसी भी अधिकारी को माफ नहीं किया जा सकता। हम सोचते हैं कि अगर उस पद के साथ यह पत्थर अगर वहां लगाने के बाद लावारिस पड़ा रहता है तो हमें खुद अपनी हैसियत के बारे में सोचने के लिए विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह गम्भीर बात है, आपके लिए है कि नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन यह बात मेरे लिये गम्भीर है। मैं आपको स्थान बता सकता हूँ, अखबारों में

छपा हुआ है, मत लगवाइये, शहर में अगर किसी भी विधान सभा क्षेत्र में किसी भी माननीय सदस्य के क्षेत्र में मैं पूरे 403 मा0 सदस्यों की बात कर रहा हूँ, किसी भी मा0 सदस्य के क्षेत्र में अगर मा0 मुख्य मंत्री जी का पट पर नाम लिखता है, तो मुख्य मंत्री जी तो इस पूरे प्रदेश को संचाचित करते ही करते हैं, इसमें कौन सी शक की बात है। उनकी कलम से पूरे प्रदेश का बजट जाता ही जाता है, इसमें कहने की क्या जरूरत है। उस क्षेत्र के विधायक को भी अगर उसमें सम्मान दे दें तो वह कुछ करे न करे, कम से कम उस पत्थर की रक्षा तो करेगा ही, वह भी नहीं कर सकते। राजनीतिक कारणों के चलते हम वह भी नहीं कर सकते और आप पूरे प्रदेश की विकास की बात करते हैं, इसलिए धन्यवाद नहीं देता, मुख्यमंत्री जी के पत्थर लगे हुए है, वह टूट गये हैं और उस पर कोई काम नहीं हुआ।

मान्यवर, हैण्डपम्प की बात हुई, मैने आपको बताया हैण्डपम्प नहीं है, शहर में, बस्ती में रहने वाले गरीब के पास, जिसके पास पैसा नहीं हे, 15-20 हजार रूपया पूरा मुहल्ला इक्ट्ठा नहीं कर सकता, वह भी पीने के पानी के लिए प्यासा है। हैण्डपम्प आपने कहा था देंगे, सौ-दो सौ आपने नहीं दिये। आप यहां से कहते थे कि देने चाहिए, भेद-भाव से हट कर देने चाहिए, वहां जाकर भूल जाते हैं। जो आपने यहां कहा था, उसकी कार्यवाही निकाल कर देख लीजिए, जो आपने यहां कहा था, उसकी कार्यवाही निकाल कर देख लीजिए, जो आपने कहा था, उसको करवा दीजिए। यह नहीं कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं उसको करवा दीजिए, जो आपने कहा उसको करवा दीजिए। अस्पतालों में दवायें नहीं है। एन0एच0आर0एम0 घोटाला हुआ, घोटाले की जांच हो रही है, घोटाला करने वाले जेल जायेंगे, जायें। जिन्होंने गड़बड़ किया, उनको जेल जाना ही चाहिए, लेकिन जनता का, सरकार का पैसा जो लग गया करोड़ों रूपया, उसको लगने के बाद ठूँठ की तरीके से खड़े हुए उन अस्पतालों की चिन्ता कौन करेगा। वह पैसा जनता का है, किसी राजनैतिक दल का नहीं है। मान्यवर, आज यह परिस्थितियां है, पिछले दिनों मान्यवर, बीमारी फैली थी, अस्पतालों में जगह नहीं बची थी, बेड के बगल में स्ट्रेचर, स्ट्रेचर के बगल में कुर्सी और कुर्सी के बाद में फिर आदमी, क्योंकि कोई जगह नहीं। अस्पतालों का मान्यवर यह हाल है। इण्डस्ट्री के बारे में मैंने आपको अभी बताया। एक बात और माननीय आदरणीय अम्बिका जी, मुझे यह जानकारी मिली थी, सही है या गलत उसको ठीक कर देंगे कि लखनऊ में एक दुग्ध उत्पादन फैक्ट्री खोलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया था। कानपुर में भी पराग दुग्ध डेरी चालू कराने की बात की थी मा0 मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की, उस घोषणा की कापी मेरे पास है। जो घोषण की, उसको तो कम से कम पूरा करवा देते और लखनऊ में जिस फैक्ट्री को चलाने की स्थिति में यह नहीं है। आपको अन्ततोगत्वा शरण लेनी पड़ी गुजरात के अमूल की और उनसे कहा आप यहां पर दूध की फैक्ट्री खोलो। अगर अमूल को ही खोलनी है तो आपका, हमारे प्रदेश का पराग क्या कर रहा है। आप उसको कितना संरक्षण दे रहे हैं ? उसकी

कितनी सहायता कर रहे हैं ? जो दूध की फैक्टरियाँ बन्द पड़ी है उनको चलाने के लिये हमारा क्या प्रयास हो रहा है ? वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम कितना पैसा, कितनी तनख्वाह देने के लिये तैयार हैं?

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, बस समाप्त। आपने कह दिया, आपकी बात मान्यवर काट नहीं सकते, काटने की हिम्मत भी नहीं है। मैं वाइण्ड अप कर देता हूँ। मान्यवर, ये सारी की सारी बातें चाहे वह कुम्भ की हो, विकास की हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर की हो, लॉ ऐण्ड ऑर्डर की हो। मान्यवर, किसी भी विषय में सरकार खरी नहीं उतरी। बजट आयेगा तो बजट में विस्तार से अलग अलग मदों पर चर्चा करेंगे। अन्त में बस एक बात कहकर कि मैंने पिछली बार कहा था कि एक साल बाद आप एक काम ऐसा बता देना जो स्वागत योग्य हो, जब आप वो बात बतायेंगे तो शायद हम समर्थन कर सकेंगे नहीं तो संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, धन्यवाद आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद प्रस्ताव मा0 ओझा जी ने इस सदन के समक्ष रखा। महामहिम जी का जो अभिभाषण होता है वह सरकार के विकास का एक आईना होता है। जो सरकार की उपलब्धियाँ होती हैं, उनका इसमें उल्लेख किया जाता है। सरकार की तमाम उपलब्धियाँ हैं जिनका तमाम वक्ताओं ने यहाँ पर जिक्र किया है। उन सभी उपलब्धियों का मैं भी समर्थन करते हुए कुछ अपने जनपद, मण्डल और प्रदेश से सम्बन्धित बात रखना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के अन्दर जो माध्यमिक विद्यालय यू0पी0 बोर्ड के संचालित हैं, उनमें से 25 से 30 हजार की संख्या नौजवानों की है जो उसमें तदर्थ रूप से अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं और सरकार के खजाने से वेतन भी पा रहे हैं, परन्तु वे नियमित नहीं हैं, 18-18, 20-20 साल से सेवा कर रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि उस प्रस्ताव में उनके नियमितीकरण की बात को शामिल किया जाये। हम गोंण्डा के रहने वाले लोग हैं। जरवल से गोण्डा और बलरामपुर एक मार्ग है उसे फोरलेन मार्ग बनाये जाने की बात को भी इसमें शामिल करने का काम किया जाये। देवी पाटन मण्डल मुख्यालय है वहां पर कोई इंजीनियरिंग कालेज और मेडिकल कालेज की सुविधा अभी तक नहीं है हमारी पूर्ववर्ती सरकर ने वहाँ पर एक इंजीनियरिंग कालेज का उद्घाटन क्या शिलान्यास भी किया था। तत्कालीन मंत्री भाई योगेश प्रताप सिंह जी सदन में बैठे हैं। वे उस शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद भी थे। हमारी यह अपेक्षा है कि उस इंजीनियरिंग कालेज को

प्रारम्भ किया जाये और एक मेडिकल कालेज की भी स्थापना की जाये। करनैलगंज, बेल्सर,नवाबगंज मार्ग मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा का मार्ग है। अयोध्या और फैजाबाद को जोड़ने का काम करता है। इस मार्ग को भी टू लेन में परिवर्तित करने का काम किया जाये। हमारी सरकार की योजना है कि हर तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालयों से जोड़ जाये। तरबगंज तहसील को जिला मुख्यालय से जोड़ती है वह सड़क बहुत ही पतली सड़क है उसके चौड़ीकरण करने का काम भी किया जाये। परसपुर धौरहरा बाँध जिसे पी0डी0 डैम के नाम से हम लोग जानते हैं, ये भी मुख्यमंत्री जी की घोषणा का कार्य है। इसको पक्का करने का काम, सड़क बनाने का काम इस पर किया जाये। जनपद गोण्डा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तरबगंज तहसील के तमाम गाँव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित है। इन गाँवों को बचाने के लिए ऐली परसौली से लोलपुर तक एक बाँध के निर्माण के प्रस्ताव की बात चल रही है और यह भी मुख्यमंत्री जी की घोषणा का कार्य है। इसे भी पूरा कराया जाये। हमारी विधान सभा में तमाम नदी नाले हैं। हमारा क्षेत्र सरजू, घाघरा, टेढ़ी, ढ़ेकिया, ढ़ोकरा आदि तमाम नदी नालों से प्रभावित है। यहाँ आवागमन में साधन बहुत कम हैं और पुलों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिसमें दुर्जनपुर से चौबेपुर के बीच टेढ़ी नदी पर एक पुल, गोण्डा बेलसर मार्ग पर गोड़वाघाट का पुल, जो बहुत पुराना पुल है और ट्रैफिक के बढ़ने के कारण वह कभी भी टूट सकता है। उसका नया निर्माण कराया जाये। सम्मयमाता और भिखारीपुर गाँव के बीच टेढ़ी नदी पर एक पुल की आवश्यकता है। इसी प्रकार सेमरा शेखपुर और विश्नोहर के बीच टेढ़ी नदी के ऊपर एक पुल की आवश्यकता है। इन पुलों के साथ साथ जनपद गोण्डा और फैजाबाद को जोड़ने के लिए घाघरा नदी पर टेमुवाघाट और जनपद गोण्डा तथा बाराबंकी को जोड़ने के लिए घाघरा नदी पर कैथीघाट पर भी पुल के निर्माण की बात इसमें शामिल की जाए। ग्रमीण विद्युतीकरण योजना में 300 आबादी के मजरों को शामिल करने की बात की गयी है, लेकिन इसमें किसी भी मा0 जनप्रतिनिधि से उन मजरों की सूची न माँग करके एक ए0जी0ओ0 के माध्यम से जो सूची बनायी गयी है, उस सूची का पुनरीक्षण कराने के बाद ही उन मजरों के विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ कराया जाय। इसी प्रकार विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए 33 के0वी0ए0 के 3 केन्द्रों की बात आदमपुर, उमरी, अमदही, दुर्जनपुर घाट पर 33 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र स्थापना कराने का काम भी किया जाय और स्वास्थ्य सेवा के लिए बहादुरपुर, दत्तनगर, साखीपुर, नौबस्ता तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का काम भी किया जाए।

हमारे क्षेत्र में बाराही देवी का एक बहुत बड़ा मंदिर है, जिसके प्रति लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। लाखों लोग वहाँ प्रतिवर्ष आते-जाते हैं, लेकिन वहाँ सुविधाओं की कमी है। मा0 मंत्री जी, से मैंने अभी अनुरोध भी किया है उनसे आग्रह है कि इस मंदिर को सुविधा देने के लिए कुछ कार्य वहाँ पर कराया जाना बहुत ही आवश्यक है। मा0 राजस्व मंत्री जी,

हमारे बीच बैठे हैं। हमारे जिले की भी एक समस्या है कसौधन जाति है, जिसे पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र जनपद गोण्डा में नहीं दिया जाता है, कुछ जनपदों में कसौधन जाति को पिछड़ी जाति माना जाता है लेकिन हमारे यहाँ बहुत दिनों से कसौधन जाति के लोग इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे है कि उन्हें पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र दिया जाए। मैं मा0 राजस्व मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि जनपद गोण्डा में कसौधन जाति के लोगों को पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के लिए निर्देश देने का कष्ट करें। मैं पुनः एक बार धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन को बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिन्द।

श्री राजबली जैसल-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन पर बल देने के लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मा0 अधिष्ठाता महोदय कल महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद। प्रस्ताव पर सम्मानित ओझा जी जब अपनी बात कह रहे थे, उस समय मा0 ओझा जी ने कहा था कि कुंभ मेले का आयोजन हमने किया था।

मान्यवर, कल भी यहां पर बात आ रही थी कुंभ मेले के आयोजन के बारे में। मान्यवर, यह कुंभ मेले का आयोजन एक निश्चित आयोजन था। उसकी आपने व्यवस्था की है यह बात तो मानी जा सकती है। लेकिन उस व्यवस्थ में भी आपने ऐसी व्यवस्था की कि वह अव्यवस्थित हो गया और उस मेले में कई लोगों की जानें गयी हैं।

मान्यवर, प्रो0 शिवाकान्त ओझा जी कह रहे थे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो वायदें करते हैं उन वायदों को पूरा करते हैं। लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत दूर की बात नहीं है, सत्ता पक्ष के ही माननीय अवधेश कुमार सिंह जी ने आज अपनी बात रखते हुए कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी घोषणाओं के बारे में मैं आपको याद दिलाया कि वायदों की बात तो छोड़ दीजिये जो घोषणायें करते हैं उनको पूरा करने का काम नहीं करते हैं। यह बात इसी से साबित हो जाती है। माननीय ओझा जी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण की बात को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इस बात के विरोध में है कि किसी एक जाति को प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाये। इस समय चूंकि यहां पर माननीय ओझा जी नहीं हैं इसलिए आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि आप वास्तव में यदि लोहियावादी है मानवतावादी हैं, समाजवादी हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम प्रमोशन में आरक्षण तभी नहीं चाहेंगे जब आप जाति प्रमाण पत्र जारी कराने का काम वर्ण व्यवस्था के आधार पर तब करायेंगे हम प्रमोशन में आरक्षण की मांग नहीं करेंगे। अगर आपकी सरकार में दम है तो आप केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजिये कि अन्य स्वर्ण जातियों की भांति अनुसूचित जाति के लोगों को भी वर्ण व्यवस्था के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने चाहिए। फिर हम प्रमोशन में आरक्षण की मांग नहीं करेंगे।

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका लक्ष्य है 2014 का लोक सभा चुनाव। श्रीमान् उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कार्य योजनायें बना रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस सरकार के जो कार्यकलाप हैं आपके जो लोग विधान सभा में यहां बैठे हुए हैं उसमें से आधे से ज्यादा लोग अपने क्षेत्रों में उस समय घुसने लायक नहीं रहेंगे। जनता उनको अपने यहाँ घुसने नहीं देगी। मान्यवर, इस बात को भी कहा गया कि डा0 अम्बेडकर समग्र ग्राम्य विकास योजना बनायी गयी थी वह एक जाति के लिए बनायी गयी थी। मान्यवर, मैं माननीय ओझा जी से कहना चाहता हूँ कि आप किसी जिले में जाकर जांच करा लें उस योजना की प्रगति की जांच करा लीजिये कि क्या एक ही जाति के लोगों की सुविधा के लिए सड़क बनी है एक ही जाति के लोगों के यहां केवल बिजली पहुंची है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि डा0 अम्बेडकर समग्र ग्राम्य विकास योजना से ठाकुर, बाह्मण, कुर्मी, सभी वर्ग के लोग लाभांवित हुए हैं जो उस ग्राम सभा के अन्तर्गत निवासी हैं। किसी भी जाति का आदमी रहा हो उसके यहां सड़क बनी है, बिजली पहुंची है। आप ओझा जी चाहे तो इसकी जांच करा लें अगर आपकी बात सही निकली तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूँगा और अगर हमारी बात सही निकले तो फिर आप विधान सभा से इस्तीफा दे देंगे।

श्री अधिष्ठाता-

आप माननीय सदस्य सम्मानित साथी नहीं कहेंगे इस चेयर को एड्रेस करेंगे।

श्री राजबली जैसल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी अपनी बात कह रहे थे कि आपकी सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल बीतने को हो रहा है। पिछली बार आपने अपना बजट पेश किया था उसका एक तिहाई भी धनराशि आप प्रयोग नहीं कर पाये हैं अब तक। आपने कहा था कि गरीब परिवारों की महिलाओं को दो साड़ी देंगे तो जब यह पूरा वित्तीय वर्ष बीतने का हो रहा है एक महीना बाकी है तो फिर किस तरह से आप यह साड़ियां देंगे। किसी भी महिला को अभी तक एक भी साड़ी नहीं मिली है।

एक महीने में आप कितनी साड़ी दे लेंगे, कितनों को कम्प्यूटर दे लेंगे, कितनों का कर्जा माफ कर लेंगे यह मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हैण्डपम्प की जहां तक बात है कई साथी माननीय विधायकगण इस बात को कह देते हैं कि हैण्डपम्प मांग रहे है हमें तो पता है के पूरे उत्तर प्रदेश में हैण्डपम्प जब से यह समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है नये हैण्डपम्प के अधिष्ठापन और पुराने हैण्डपम्प के रि-बोर पर भी रोक लगादी गयी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अब अपने विधान सभा क्षेत्र में भी जाना चाहूँगा कि माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहीं भी इस तरह से चर्चा नहीं है जिससे एक आम किसान, एक आम नागरिक खुशहाली की जिन्दगी जी सके। हमारे

क्षेत्र में मेजा तहसील जो हमारे विधान सभा क्षेत्र और हमारे सम्मानित विधायक उस तरफ बैठे हुए हैं श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय जी उनके क्षेत्र से सटा हुआ एक मेजा कताई मिल है जो काफी दिनों से बन्द पड़ी है हम आपके माध्यम से मांग करते हैं जो उस कताई मिल को या तो चालू करा दिया जाय क्योंकि वह राज्य कताई मिल के नाम से थी, आज वह बन्द पड़ी है हो सकती तो उसमें किसी भी प्रकार का उसमें भंडारण कर दिया जाय गेहूँ का, धान का तमाम किसानों को उसमें दिक्कत होती है तो उसको एक भंडारण के रूप में कर दिया जाय ताकि किसानों का हित हो सके। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ हमारे क्षेत्र में एक रतयोरा से सुभाष तक सड़क है उसकी लम्बाई 8 किमी0 है माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना थी माननीय लोक निर्माण मंत्री जी की भी घोषणा थी कि हम गडढ़ामुक्त करने का काम करेंगे लेकिन उस सड़क पर आज भी लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है लोग चल नहीं पाते हैं मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि उस सड़क की विशेष मरम्मत करा दिया जाय।

हमारे इलाहाबाद मुख्यालय से तहसील मुख्यालय को जोड़ने की बात है। हमारे इलाहाबाद मुख्यालय से कोरांव तक पहुँचनें के लिए एक करछना तहसील का मुख्यालय पड़ता है दूसरा कोरांव तहसील का मुख्यालय पड़ता है बीच में एक करछना रेलवे स्टेशन पड़ता है उसकी एक क्रासिंग है जहां आज भी उस क्रासिंग का उपरिगामी सेतु न बनने की वजह से लोगों को घन्टों उस जाम में फंसे रहना पड़ता है। इसलिए हम चाहेंगे उस उपरिगामी सेतु का निर्माण कर दिया जाय। इसके साथ ही हमारे नेता जी द्वारा जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था उस पर बल देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।

*श्री मनीष असीजा-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, कल से और पूर्व से हुई इस चर्चा में यह मुझे देखने में आया है कि जो भी सरकार की नीतियों को महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसके लिए धन्यवाद एक जैसे पक्ष का कर्तव्य होता है। इस प्रकार यह एक फार्मेलिटी की तरह दिखता है। अनेक सुझाव जो पक्ष से भी अच्छे आये हैं। विपक्ष के माध्यम से भी रखे गये हैं। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि यह ऐसी तीव्र ध्रुवीकरण की रेखा है कि मानो यह ठान लिया गया है कि हमारा कहा आप न सुनेंगे और आपका कहा हम न सुनेंगे। मैं इसमें आपके माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूँ कि स्वस्थ लोकतांत्रिक पद्धति में, परम्पराओं में जो भी सही सुझाव है, जिसके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये अंततोगत्वा हम सब विधायक इस सदन में आते हैं, जो जनहित के हैं, न केवल उनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिये अपितु उनके ऊपर काम भी कराना चाहिये।

माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं अपने नगर फिरोजाबाद की एक प्रमुख समस्या को सदन के सामने रखना चाहता हूँ। नगर फिरोजाबाद पिछले 6-7 वर्षों से भौगोलिक कारणों से पीने के पानी की समस्या से बहुत अधिक ग्रसित है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में पेयजल की समस्या है इसको भी नकारा नहीं जा सकता लेकिन फिरोजाबाद की कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं जो मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ। मान्यवर, हमारे फिरोजाबाद में जो पानी पीने का वर्तमान में प्राप्त किया जा रहा है, वह ग्राउन्ड वाटर से किया जा रहा है, बोरिंग के माध्यम से ट्यूबवेल के माध्यम से लिया जा रहा है। भूगर्भ जल विभाग की यह रिपोर्ट है कि प्रदेश के सबसे अतिदोहित ब्लाक्स में फिरोजाबाद है। भूगर्भ जल विभाग की यह भी रिपोर्ट है कि फिरोजाबाद नगर में पौने चार सौ फीट नीचे की बोरिंग कराने पर हाईफ्लोराइड और आर्सेनिकयुक्त पानी है, जो पीने के मानको के सर्वथा विपरीत है। भूगर्भ जल सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार जो प्रदेश के 67 इलाके जिनमें सबसे जलस्तर की गिरावट दर्ज की गयी है, उन ब्लाक्स, उन विकास खण्ड़ में फिरोजाबाद आता है। महोदय, वर्तमान में यह परिस्थिति इस प्रकार से हो गयी है कि नीचे गहराई में पानी अशुद्ध है तो हम लोग उसको ले नहीं सकते और जल स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि जो पहले से कार्यरत ट्यूबवेल हैं, उनका जलस्राव, उनका पानी उगलना, उनके पानी देने की क्षमता इतनी कम हो गयी है कि सर्दी के दिनों में भी आये दिन धरना-प्रदर्शन ऐसे अनेक घटनाचक्र घटते हैं, जिससे कि नगर की शान्ति व्यवस्था और कानून व्यवस्था दोनों के बिगड़ने की आशंका लगातार बनी रहती है। महोदय, समस्या के समाधान के लिये मैं आपके माध्यम से एक सुझाव भी देना चाहता हूँ।

नगर फिरोजाबाद से 45 से 50 कि0मी0 दूर झेड़ाजाल रेगुलेटर है, जो निचली गंगा प्रणाली के अन्तर्गत जिसमें भोगनीपुर ब्रांच निकलती है, और जिसके हेड पर 1800 क्यूसेक पानी उपलब्ध रहता है, वहाँ से यदि कच्चा जल, सतही जल लेकर आया जाये, जिस प्रकार से ट्रांस गोमती की योजना में लिया गया है, जैसे आगरा में कलरा से पानी लेकर आया जा रहा है, अगर इस प्रकार से हमारे नगर को पानी मिल जाये तो हमारे शहर के प्राण बच सकते हैं। इसमें हमारे पास एडवान्टेज है, वह यह है कि जिस प्रकार से एक समय में गंगा जी जब पृथ्वी पर अवतरित हो रही थीं तो शिव जी की जटायें इसलिए संभालने के लिये फैलाई गयी थी नहीं तो पृथ्वी पाताल पर चली जाती। आने वाले पानी को संभालने का क्या साधन हो, कहना आसान है कि हमें किसी नहर से या किसी नदी से पानी दिलवा दिया जाये। पिछले 10 वर्षों से यू0आई0डी0 एस0एल0पी0 स्कीम और नगर विकास विभाग के सहयोग से नगरपालिका के माध्यम से नगर फिरोजाबाद में 18 ओवरहेड टैंक तथा 14 सी0डब्लू0आर0 और लगभग 80 से 90 प्रतिशत पीने के पानी की लाइन का वितरण का जो जाल है...वह

बिछ चुका है, मान्यवर, यदि हमें अच्छा जल मिल जाता है, सतही जल मिल जाता है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन की प्रणाली विकसित करने के लिए यदि अरबों में भी जाना पड़े तो उसमें कोई गुरेज न होगा। मान्यवर, लम्बा समय क्योंकि 18 टैंक है, सी0डब्लू0आर0 हैं, केवल पैसे भर से नहीं बनेंगे इसके लिए जमीनें भी लेनी पड़ती हैं इसमें निर्माण भी कराना पड़ता है तो मान्यवर, समय और श्रम के बचाव का उपाय भी फिरोजाबाद में उपलब्ध है। मान्यवर, अगर यह बात माननीय नगर विकास मंत्री जी के सामने आ जाती अवश्य वह उस पर ध्यान देंगे मैं उसी को संशोधित करते हुए कहता हूँ कि माननीय नगर विकास मंत्री जी का जो ईमानदारी और जिम्मेदारी भरा व्यवहार है उसी को संज्ञान में लेते हुए आप मेरे नगर की समस्या को उन तक पहुँचाने का काम करेंगे। मान्यवर, मैं शहर के अतिरिक्त कुछ छोटी सी बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

मान्यवर, चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ अच्छी बातें भी कही गई हैं। मुझे यह विश्वास है कि जो अच्छी बाते हैं उन्हें मुझे बोलना ही चाहिए मैं इधर खड़ा हूँ या उधर खड़ा हूँ। बहुत सारा बजट है, एन0आर0एच0एम0 से पैसा आ रहा है वह अलग चीज है। एक जगह प्रस्ताव दिया गया है कि गरीब रोगियों के जो तीमारदार हैं उनके ठहरने के लिए जो व्यवस्था आपने बनायी है वह प्रशंसा के योग्य है। मान्यवर, दिल्ली के बड़े अस्पतालों के सामने लोगों ने फ्लैट खोल रखें हैं क्योंकि मरीज अकेले नहीं होता है उसके साथ उसके घर वाले उसके चाहने वाले होते हैं। लेकिन मान्यवर, मैं एक बात का अनुरोध करना चाहता हूँ आरोग्य निधि जो एक योजना है उसको अधिकारियों ने तो अच्छा ही सोचकर किया होगा लेकिन उसका प्रैक्टिकल लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरे पास ऐसे रोगी लगातार आते हैं, लगभग 10 हास्पिटल है जिनका स्पेसिफिक रूप से जी0ओ0 में उल्लेख है। इसमें एस0जी0पी0जी0आई0 हैं, जी0एस0वी0एम0 है, एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज है, प्रदेश के सभी मेडिकल कालेज हैं, वाराणसी एवं लखनऊ के विश्वविद्यालय हैं, इसके द्वारा मरीज का इस्टीमेट बनाया जायेगा और यहीं पर इलाज होगा तो पैसा सरकार ट्रांसफर कर देगी। अब समस्या यह आती है कि ज्यादातर गम्भीर बीमारियों का मरीज विषय विशेषज्ञों की दरकार रखता है। मैं आलोचना की भावना से नहीं कह रहा हूँ लेकिन मान्यवर यह जो 10 के 10 हास्पिटल हैं, मैं दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ, आप पता कर लीजिएगा कि विषय विशेषज्ञों की कमी है और वहाँ पर पहले से लोड ज्यादा है। इन दस अस्पतालों में गम्भीर रोगी बहुत हैं। मैंने यह सुझाव देना चाहा है संशोधन का प्रस्ताव देना चाहा है कि आप प्राईवेट हास्पिटल और मरीजों की सांठ-गांठ से बचाव की भावना को रखिये यह तो ठीक है लेकिन इसे रखते हुए इन्हीं हास्पिटल से उस मरीज का स्टीमेट बनवा दें और फिर उसे किसी और अस्पताल में इलाज कराने की सुविधा दे दें जैसे ग्वालियर में भी एक कैंसर का हास्पिटल है जो अर्द्धसरकारी है। मान्यवर, अगर यह हो जाता है तो कम से कम इतना तो हो जाएगा कि मरीज के प्राण बच जायेंगे। अभी यह है

कि संजय गांधी हास्पिटल में हमने इस्टीमेट बनवा दिया लेकिन वहाँ बेड नहीं हैं डाक्टर नहीं है तो इस्टीमेट यहाँ से बन जाए और इलाज कहीं और भी हो सके, यह मेरा निवेदन है। मान्यवर, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि राशनकार्ड दोबारा बनने वाले हैं सन् 2005 में बने थे और उनकी 2010 तक की अवधि थी, 6-6 महीने का एक्सटेंशन हुआ अब इसकी सीमा मई, 2013 तक की है। पूरे प्रदेश का मामला है , हर विधायक के क्षेत्र का मामला है। इसमें मेरा निवेदन है कि आपने निर्देश दिया है अपने विभाग को कि दो रूपये के अन्दर यह कार्ड छपे और इसमें ए0पी0एल0 वाले से 10 रुपये चार्ज किया जाए और बी0पी0एल0 वाले से 5 रुपये चार्ज किया जाए। शासन की कहीं से भी मंशा लगती नहीं, इसको व्यंग न लीजिएगा लेकिन शासन अनेक लोक कल्याणकारी भावनाओं से ओत प्रोत होकर, अनेक मुआवजे दे रहा है या जिसे कहना चाहिए कि वजीफे दे रहा है, भत्ते दे रहा है तो यह राशनकार्ड के लिए क्यों व्यापार ? यह दो रूपये और आठ रूपये का गैप। बी0पी0एल0 वाले से पाँच रुपये है तो मेरा अनुरोध है कि दो रुपये का कार्ड छपना है और दस रुपये वसूला जाना है तो उसको दो का दो रुपये में कर दें और बी0पी0एल वाले को अन्त्योदय की तरह फ्री कर दें। उन्त्योदय को फ्री किया गया है। दूसरी बात यह है कि इसमें पाँच साल का उल्लेख होता है, पाँच पन्ने जुड़ेंगे जैसे 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010, 6 पन्ने जबकि इसमें केवन तीन पन्ने जुड़वाये जा रहे हैं- 2013, 2014 और 2015 जबकि कार्ड बनने वाला है 2013 से 2018 तक। तो यह फिर कवायद होगी और आप जानते हैं कि हमारा आपका मन साफ होने के बावजूद कई बार इस प्रकार की जो कवायद होती है।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त करें, मा0 राम करन आर्य जी अपनी बात रखें।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अधिष्ठाता जी, अन्तिम लाइन कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। बात तो बहुत कहना चाहता था। बिजली के संबंध में एक निवेदन है कि दोबारा से आप ओ0टी0एस0 (वन टाइम सेटलमेण्ट) की स्कीम लागू करा दें तो जो गरीब लोग हैं, बिल जितने का है उससे तिगुनी और चौगुनी ब्याज है तो शरत चन्द्र और प्रेमचन्द्र के उपन्यास की तरह मैं समझता हूँ कि कोई शासन पद्धति ऐसी साहूकार का स्वरूप न रखेगी कि छोटे से मूलधन के बदले उसके घर-मकान को ब्याज में कब्जा लिया जाए। ओ0टी0एस0 से ब्याज माफ हो जाए, पैसा जमा होने लग जायेगा और वह बिल का पैसा देकर और अधिक रेवेन्यु बढ़ाने का काम करेगा। माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे सदन में अपनी बात रखने का और महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेलकूद व युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे पक्ष में बोलने अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारे लायक विपक्ष के साथियों ने और खासकर के ब0स0पा0 के नेता ने कहा कि यह जो दस्तावेज है, यह समाजवादी पार्टी का दस्तावेज है, यह महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण नहीं है। सच तो यह है कि कोई भी राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वह सरकारी पार्टी के कार्यक्रमों को उसके सिद्धान्तों का एक दस्तावेज ही होता है और उसको राज्यपाल महोदय अभिभाषण के रूप में रखते हैं। मान्यवर, यह भी कहा कि यह हमसे चोरी कर लिया गया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, कोई किसी का चोरी नहीं करता है, सबकी अपनी नीति और सिद्धान्त होते हैं। जब भा0जा0पा0 रहती है तो अपना रखती है, काँग्रेस थी अपना रखती थी, हम लोग अपना रख रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो उसने अपना रखा था। लेकिन यह हमारा विकास का दस्तावेज है और बहुजन समाज पार्टी ने जो 2007 में रखा था उनका एक लूट का दस्तावेज था। पूरे 05 साल लूट के अलावा उनके पास कोई सैद्धान्तिक काम ही नहीं था। अगर मैं यह कह दूँ तो अभी सब लोग आलोचना करने लगेंगे। मैं केवल एक ही बानगी बता रहा हूँ कि एक करोड़, पाँच लाख में इनकी एक हाथी तैयार हुई थी। एक करोड़ रुपये में कम से कम अगर एक लाख रुपये का कोई आवास बनता तो 100 दलितो के, गरीब जातियों के, जो अति निर्धन लोग थे उनके 100 आवास बन जाते। वह जिन्दा हाथी तो नहीं था, मुर्दा हाथी था और अगर जिन्दा हाथी होता तो मैं सोचता कि वैसी हाथी मर जाए तो बेहतर है। क्योंकि जिस प्रदेश की जनता इतनी गरीब हो, जिनके पास छप्पर के मकान हों, एक कमरे में उनका भोजन बनता हो, उसी में बकरी बाँधी जाती हो, उसी में बेटा पढ़ता हो और उसी छप्पर में पूरा परिवार रहता हो तो ऐसे प्रदेश का मुखिया कोई भी हो, अगर एक करोड़ रुपये में अपनी हाथी बनवाता हो या अपना निशान बनाता है तो उस मुखिया को मर जाना चाहिए। यह मैंने नहीं कहा यह महात्मा गाँधी जी ने कहा था बनारस के अपने भाषण में जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि आप गवर्नर के जलसे में अपनी बात रखिए तो माननीय बापू जी ने कहा था कि हमारे गवर्नर जनरल पर एक दिन में 10 हजार रुपया खर्च होता है और हिन्दुस्तान की जनता पर एक दिन में 10 नया पैसा खर्च होता है ऐसा लाट गवर्नर मर जाय तो बेहतर है। क्योंकि हिन्दुस्तान की जनता इसे बर्दाश्त करने लायक नहीं है।

अभी हमारे साथियों ने हम बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि 125 वर्ष का हमारी विधान सभा का इतिहास है उसके सम्बंध में जो उत्तरशती समारोह हुआ हम उसमें शिरकत किए यह

जितने पक्ष विपक्ष के हमारे साथी हैं सभी सौभाग्यशाली हैं जो लोग उसमें आए हैं 403 लोग अपने को अति महत्वपूर्ण समझें मैं कहता हूँ कि वह भगवान के स्पेशल बनाए हुए लोग है आम लोग तो नहीं आ सकेंगे। उसमें तीन लोग हमारे सम्मानित भी हुए उनकी लम्बी उम्र हो जाय अभी उनमें से एक के बारे में तो शोक संवेदना व्यक्त की गई है दो अभी जिन्दा हैं। मान्यवर, महाकुम्भ के बारे में बहुत लोगों ने चर्चाएं की प्रेस के लोगों ने मुझसे भी पूछा कि जो यह घटना घटी है इस पर क्या कहना है मैंने कहा कि यह बहुत दुखद है फिर उन्होंने कहा कि इस पर आपकी सरकार क्या करेगी हमने कहा कि मृतक के परिवारों की ज्यादा से ज्यादा मदद करेगी और कहा कि दोषी कौन है तो हमने कहा कि यह तो जाँच की बात है जाँच में जो आएगा वह दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी तो प्रेस के लोगों ने कहा कि खेल मंत्री ने शर्मनाक बयान दिया है। मान्यवर, यह कौन सा शर्मनाक बयान है जो भी हमारे कुछ साथियों ने केन्द्र पर कुछ ने प्रान्त पर आलोचना किया मैं कहना चाहता हूँ कि वक्त से बड़ा दुनियाँ में कोई नहीं होता है ''बली बली नहि होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वहि अर्जुन वहि बान।'' हमारा कितना बढ़िया इंतजाम था लेकिन पानी बरस गया तो तम्बू में पानी चला गया और लोगों ने कहा कि बदइंतजामी। भगवान से कोई बड़ा हो जाएगा ? हम पानी रोक पाएंगे ? कोई आज तक रोक पाया समाजवादी पार्टी ने जितना बेहतर व्यवस्था किया था आज तक हिन्दुस्तान के जितने भी महाकुम्भ हुए कभी भी इतनी बेहतर व्यवस्था नहीं की गई। इसको मैं नहीं कह रहा हूँ जो महाकुंभ के यात्री थे जो स्वर्ग जाने के लिए मां गंगा और जमुना के संगम पर स्नान करने गए थे उन लोगों ने कहा। हमने सात सात लाख रुपया मृतक के परिवारों को दिया। घायलों को भी पैसा दिया गया मगर लोगों ने उसकी बड़ी आलोचना किया आलोचना करना तो आसान है लेकिन इंतजाम करना कितना कठिन है।

मैं माननीय आजम खाँ साहब को बधाई देना चाहता हूँ उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि मेरे समय में यह हुआ है। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की तरह काम किया उन्होने बड़प्पन का काम किया लेकिन व्यवस्था तो करनी है हमारे साथियों ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ अभी तक हम पाँच लाख किसानों की दुर्घटना बीमा के लिए दे रहे हैं, पिछली सरकार में हम एक लाख देते थे हमारे लायक दोस्त किसानों के रहबर जो आज यहाँ पर हाउस को डिस्टर्ब कर रहे थे उन्होंने एक नया पैसा पाँच साल के अन्दर नहीं दिया। यह लायक लोग हैं यह विपक्ष में बैठे लोग हैं मान्यवर, कानून-व्यवस्था की जो बात है तो कानून व्यवस्था में एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती है सबकी होती है। बहुजन समाज पाटी के कार्यकाल में मैंने देख था हाथ काट दिया गया था लड़के का सरे चौराहे पर और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम नहीं करेंगे हमारे राज्य में जो गलती करेगा उसके साथ सख्ती से हम निपटेंगे चाहे वह सत्तापक्ष का हो या विपक्ष का किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की हम छूट नहीं दे

सकते हैं और हम 30 हजार रुपये जो कन्याओं को कन्या विद्या धन में दे रहे हैं चाहे मुस्लिम लड़कियां हो, चाहे हिन्दू लड़कियां हों सबको दे रहें हैं। यह एक अच्छा काम है। हमारे देश हिन्दुस्तान में पुरुष प्रधान समाज है। यह नारी प्रधान नहीं, पुरुष प्रधान समाज है। यह इंगलैंड की तरह नहीं है कि वहाँ पर 55 प्रतिशत औरतों के पास दौलत है। यहाँ तो मोहताज रहती हैं बेंचारी, कभी भी तलाक दे दो, कभी भी घर से निकाल दो। यह 30 हजार रुपये देने का मतलब है कि वो अपने जीवन के लिये, पढ़ने लिखने के बाद कभी तलाक भी हो जाय तो वह अपना जीवन खुद निर्वाह कर सके यह मान्यवर, हमारा इसमें मकसद है। इसके साथ ही साथ अनुसूचित जतियों के लिये बहुजन समाज पार्टी के लोगों 10 लाख रुपया हम उनके व्यापार के लिये बिना व्याज के दे रहे हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि अनुसूचित जाति के लोगों को 10 लाख रुपया बिना ब्याज के दिया जा रहा है। यह हमारे बजट में भी आयेगा और इसमें भी दिया हुआ है। हम 3 प्रतिशत पर किसानों को कर्ज दे रहे हैं। और क्या लीजियेगा हमसे ? यह छोटी मोटी जीजों, नहीं कोई यह बड़ी बात है। हम खादी ग्रामाद्योग के लिये नौजवानों को दे रहे हैं और तीन वर्षों में मान्यवर, हम 3 हजार नये नलकूप लगा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त करें।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, 10 हजार गांवों को हम विद्युत से, सड़क से, आवास से आच्छादित कर रहे हैं यह हमारी व्यवस्था है। मान्यवर, हम पाँच साल के अन्दर गाँव-गाँव में खेल मैदान बना रहे हैं, वह मेरी सरकार की व्यवस्था है मान्यवर, इससे ज्यादा हमसे यह लोग क्या ले सकते हैं, क्या चाहते हैं। मान्यवर, 500 एकड़ का पार्क हम माननीय जनेश्वर मिश्र के नाम से बना रहे हैं। हम हाथी पार्क नहीं हैं, हमारे पार्को में बूढ़े लोग घूमने जायेंगें, हमारे लोग अपनी सेहत के लिये जायेंगे। हमारी यह जो व्यवस्था है यह आम लोगों के लिये है और हम बैटरी संचालित रिक्शा दे रहे हैं। हमारे साथियों ने बात रखा है कि हम रिक्शावालों दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री राम करन आर्य-

बस मान्यवर, हम ज्यादा बोलेंगे नहीं। मान्यवर, इसी के साथ-साथ हम रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत 400 रुपये पेंशन दे रहे हैं। इतना ही नहीं मान्यवर, हम 262 छात्रावास अनुसूचित जातियों के लिये बना रहे हैं जिसमें मान्यवर, 252 बन चुके हैं और

शेष इसी साल में मान्यवर, हमारा बनकर तैयार हो जायेगा। मान्यवर, हमारी बेटियाँ पढ़े बेटियाँ, बढ़ें बेटियाँ यह हमारी योजना है। मान्यवर, पिछड़ी जातियों के लिये 100 बेड का 14 छात्रावास बना रहे हैं और 2000 हम मछुवा आवास बना रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

राम करन जी अब आप समाप्त करें। रजनी तिवारी जी, आप अपनी बात कहें।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। मान्यवर, मैं स्वयं राम करन आर्य जब ग्यारहवीं में पढ़ते थे तो मैं मीसाबंदी रहा हूँ। हो सकता है मान्यवर, आप भी रहे हों। कितना तकलीफ था, हमारे प्रदेश के लोगों को। जार्ज फर्नाडीस का आँख निकाल लेते काँग्रेज की पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आदेश दिया था लेकिन वो बेचारे बच गये दुनिया के बन्दरगाहों ने हिस्दुस्तान का सामान उतारने या चढ़ाने के लिये बंद कर दिया था। यह काली रात, यह आपात काल ऐसी थी। मान्यवर, हमारे नेता ने पिछली बार 1 हजार रुपया किया था। लायक दोस्त, बहुजन समाज पार्टी के लोगों आप लोगों ने वह काट दिया। एक हजार रुपया मिलता था अबकी बार 3 हजार रुपया किया है। मान्यवर, मेरी जनप्रिय सरकार है, हम प्रदेश की उन्नति चाहते हैं, सभी जातियों का विकास चाहते हैं। दलित से लेकर सवर्ण तक अमीर से लेकर गरीब तक हम सबकी इज्जत आबरू की व्यवस्था चाहते हैं, समानता चाहते हैं। मान्यवर, हम सबको दवा देना चाहते हैं। मुफ्त पढ़ाई देना चाहते हैं, मुफ्त दवाई देना चाहते हैं। मेरे राज्य में और मेरी सरकार में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यगण आपके दल से जो सूची आई है उसी क्रम में मैं आपको बुला रहा हूँ।

श्रीमती रजनी तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर प्रस्तुत संशोधन पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी अभारी हूँ। मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पाँच नदियाँ रामगंगा, गर्रा, गम्भीरी, नीलम यह पाँच नदियाँ मेरे निर्वाचन क्षेत्र से गुजरती है। प्रतिवर्ष बरसात के मौसम में हमारे क्षेत्र में भयानक बाढ़ आ जाती है और समस्त जनमानस को बाढ़ की बार-बार भयंकर त्रासदी झेलनी पड़ती है। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में अर्जुनपुर बड़ागाँव के मध्य रामगंगा

नदी पर पुल का निर्माण होना अति आवश्यक है। मान्यवर, इस पुल के निर्माण से एक लाख क्षेत्र के नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का हरपालपुर कटियारी क्षेत्र रामगंगा नदी पर उपरोक्त पुल न होने के कारण दो भागों में बंटा हुआ है। लोक निर्माण विभाग द्वारा 25 वर्ष पूर्व से उपरोक्त स्थान पर आवागमन हेतु पैन्टून पुल का निर्माण किया जाता है। परन्तु बरसात के मौसम में लगभग 4 माह तक सम्पूर्ण क्षेत्र दो भागों में बँटकर अव्यवस्थित हो जाता है। रामगंगा नदी के पार बसे हुए क्षेत्रवासियों को जनपद मुख्यालय हरदोई तक लगभग 100 कि0मी0 का सफर वाया फर्रुखाबाद सड़क मार्ग से तय करना पड़ता है अथवा नाव से नदी पार करनी पड़ती है। पुल के निर्माण के पश्चात् अर्जुनपुर से जनपद मुख्यालय हरदोई की दूरी लगभग 52 कि0मी0 रह जाएगी। मान्यवर, लोक निर्माण विभाग एवं सेतु निगम द्वारा पुल के निर्माण स्थल का सर्वेक्षण कर आगणन तैयार कर लिया गया है तथा समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् पुल निर्माण की पत्रावली धन आवंटन हेतु शासन में लम्बित है। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में सवायजपुर तहसील का सम्पूर्ण भाग आता है। तहसील मुख्यालय सवायजपुर की विडम्बना यह है कि सवायजपुर में तहसील मुख्यालय को छोड़कर अन्य कोई सार्वजनिक सुविधाएं नहीं है। कोतवाली है ही नहीं, तीस किलामीटर दूर फायर स्टेशन है जबकि इस क्षेत्र की आधाी आबादी बाढ़ के कारण छप्परों में निवास करती है, सी0 ओ0 पुलिस की सर्किल तो है परन्तु सी0ओ0 का कार्यालय नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है परन्तु डाक्टर नहीं। तहसील मुख्यालय को इस दुर्दशा के कारण कभी-कभी तहसील दिवस पर फरियादियों की संख्या शून्य तक हो जाती है। मान्यवर क्षेत्रवासी वर्ष भर बाढ़ की त्रासदी से उबरने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं परन्तु बार-बार बाढ़ आने से क्षेत्र का विकास अवरुद्ध रहता है। यह सच है कि यह दैवी आपदा है परन्तु इस दैवी आपदा से निपटने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं अच्छे सम्पर्क मार्ग चिन्हित स्थानों पर पुल पुलिया आदि बनवाकर काफी हद तक हम बाढ़ की त्रासदी से बच सकते हैं। मान्यवर, पिछले समय, पिछली सरकार में विधान सभा सवायजपुर में विद्युत समस्या के निराकरण के लिए 132 के0वी0 पावर सब-स्टेशन स्वीकृत हुआ था लेकिन इस सरकार के बनने के बाद वहां पर कार्य अभी भी शुरू नहीं हुआ और वहाँ पर विद्युतीकरण के लिए जो गाँव स्वीकृत हुए थे उसके लिए धन भी आवंटित हो गया था लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके लिए पिछले सत्र में नियम-51 में सूचना दी थी। उसमें मा0 मुख्य मंत्री जी का पत्र भी हमको प्राप्त हुआ था। उसमें उन्होंने हमें जवाब दिया कि वहां पर बिजली की कठिन समस्या है। मान्यवर, उपरोक्त कार्यों के लम्बित होने के कारण वहां की क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रहा है। इन समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है। विधान सभा 2012 की आचार संहिता लागू होने के कारण कार्य नहीं हो सके थे। यह प्रकरण वर्तमान में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में विचाराधीन है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूँ कि इस कार्यों को अविलम्ब शुरू न कराया जाए। मान्यवर, मेरी विधान सभा की भौगोलिक

स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन महत्वपूर्ण विषयों को उठाना हमारा परम कर्तव्य है और इसका समाधान करना सरकार का दायित्व है। महामहिम राज्यपाल अभिभाषण पर प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

अब श्री सुदेश जी।

(कई सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री अधिष्ठाता-

श्री सुदेश जी के बाद, गामा जी, फिर संजय कपूर जी बोलेंगे। मेरे पास जो सूची है, उसके अनुसार हम आप लोगों को बुला लेंगे।

*श्री सुदेश शर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध और संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका अभारी हूँ। मुझसे पूर्व सभी विद्वान सदस्यों ने, नेताओं ने अपने विचार रखे है। अभी मेरे एक साथी सदस्य जो प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए सरकार का धन्यवाद कर रहे थे और बड़ी लम्बी-चौड़ी बाते कहीं जाती है कि सरकार किसानों की रहबर है और महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में भी जो आपने ने कहा, उसको हमने पढ़ा लेकिन में आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना करना चाहूँगा कि मेरी विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के अन्दर चाहे वह पिछली सरकार की रही हो, चाहे यह समाजवादी पार्टी की सरकार हो, आज भी वहां पर किसानों का 100 करोड़ रुपये से ऊपर बकाया हो चुका है और जो पिछला बकाया था, वह अब तक बाँट रहा है और जो अब भुगतान लम्बित हो रहा है, वह न जाने किस दशा में कब हो पायेगा। मैं कहना चाहूंगा कि जिस किसान को खेत-खलिहान के अन्दर काम करना चाहिए, वही किसान हर बार अपनी फसल का मूल्य पान के लिए सड़कों पर उतर करके संघर्ष करता है और उसके बाद उसके भुगतान की जो एक परम्परा सी हो गयी है, तब उसका भुगतान किया जाता है। मैं आपके माध्यम से, आपका संरक्षण चाहते हुए सरकार से कहना चाहूंगा कि इस बारे में ध्यान दे करके कोई न कोई ठोस नीति बनायी जाए जिससे किसानों के बकाये का भुगतान सुनिश्चित किसा जा सके। मैं आपकी कृपा से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरठ में जा करके घोषणा की थी। हमारे साथियों ने गिरफ्तारी दी थी। महीउद्दीनपुर शुगर मिल को चलाने की माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी थी लेकिन आज तक माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के बाद भी महीउद्दीनपुर शुगर मिल को नहीं चलाया जा सका है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहूँगा कि यदि मुख्य मंत्री जी की घोषणाएँ इस प्रकार से हवा हवाई होगी तो उन घोषणाओं का कोई लाभ नहीं होगा और इससे सरकार की छवि जनता के अन्दर घोषणाओं का कोई लाभ नहीं होगा और इससे सरकार की छवि जनता के अन्दर धूमिल हो रही है। आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और महीउद्दीनपुर शुगर मिल को शीघ्र चलाने का कष्ट करें।

मान्यवर, बहुत लम्बे समय से मेरे विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर की एक समस्या है, मोदीनगर में मोदी कपड़ा मिल के नाम से एक मिल था जिसमें 20 हजार वर्कर काम करता था। लेकिन पिछले 20 वर्षो से उन मजदूरों के बच्चे बेघर हो गए, उनकी महिलाएँ लिपिस्टिक और बिंदी बना करके अपने बच्चों को पालने का काम कर रही है। वहाँ के मजदूर रिक्शा चलाने के लिए मजबूर हैं, फल और सब्जी बेंचकर अपना गुजारा कर रहे हैं लेकिन न तो उस मिल को चलाया गया, न ही मजदूरों का हिसाब कराया गया है। चुनाव के दौरान माननीय मुख्य मंत्री, श्री अखिलेश यादव जी ने मोदीनगर शहर में एक रैली के अन्दर घोषणा की थी कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो मोदीनगर के इन मजदूरों की समस्या का समाधान किया जायेगा। मैं आपकी कृपा से, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस ओर विशेष ध्यान दे करके मोदीनगर की इस मिल की समस्या का निस्तारण बहुत शीघ्र से शीघ्र कराने का कष्ट करें। साथ ही साथ 40-50 वर्षों से मजदूर वहाँ के मकानों में रह रहे हैं, उन मजदूरों को उन मकानों का मालिकाना हक दिलाने का भी कष्ट करें। मान्यवर, एक बड़ी गहन समस्या है, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर अंग्रजों के समय में पाँच गाँव सुहाना, भनैड़ा, खिंदौड़ा, कुम्हैड़ा, ग्यासपुर को बागी करार दिया गया था लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गये लेकिन वह गाँव आज भी बागी गाँव के नाम से जाने जाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि कम से कम आज उन गाँवों को बागी गाँवों को दर्जा न देकर उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का दर्जा देकर उन गाँवों का डॉ लोहिया ग्राम्य विकास योजना का तर्ज पर विकास किया जाये। माननीय अम्बिका चौधरी जी हमारे बीच में आ गये हैं मैं विशेष रूप से आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि उन पाँचों गाँवों को जिनको बागी गाँव कहा जाता है उन गाँवों को सम्मानजनक नाम देते हुए आप घोषणा करने का कष्ट करें। इससे उन गाँवों को लगेगा कि कम से कम हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के समय में जो बलिदान दिया था आज उसका कर्जा वसूल हो गया है। मान्यवर, यह मामला भी माननीय राजस्व मंत्री जी से जुड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ी मुश्किल से आपकी कृपा प्राप्त हुयी है। मैं कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में हर तहसील में मुंसिफी न्यायालय है। लेकिन मोदी नगर में मुंसिफी न्यायालय नहीं है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस बात की घोषणा करें कि वहाँ पर मुंफिसी न्यायालय की स्थापना की जाएगी। वहाँ पर सर्वे भी हो चुका है, जमीन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। हाई

वे पर बसे हुए मोदी नगर शहर में मुंसिफी न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मोदी नगर से यू0पी0, उत्तरांचल, दिल्ली और हरिद्वार को जोड़ने वाला हाईवे है। आज मोदी नगर शहर को जाम नगर के नाम से जाना जाता है। आज वहाँ पर कई-कई घण्टे जाम लगता है। माननीय मुख्य मंत्री जी वहाँ पर अपनी चिंता कर चुके हैं लेकिन उसके बाद भी आज तक वहाँ पर जाम की समस्या का कोई निराकरण नहीं कराया गया है। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वहाँ पर कम से कम कोई एलिवेटेट पुल या किसी बाईपास निर्माण कराने का कष्ट करें। जिससे लोगों को जाम से निजात मिल सके। यह बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है। मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 अम्बिका चौधरी जी से अनुरोध करना चाहता हूँ वह इस ओर ध्यान दें और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी अवगत करायें। इसी के साथ मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि महीउद्दीनपुर से खरखौदा मार्ग वाया चुड़ियाला सैदपुर मार्ग पर किसानों का भारी आवागमन रहता है, वहाँ पर मिल भी है लेकिन वहाँ की सड़क की हालत इतनी जर्जर है कि वहाँ पर पैदल आदमी नहीं निकल सकता तो ट्रैक्टर और बुग्गी निकालने की बात तो बहुत दूर है। बहुत वर्षों से सुन रहे हैं कि सड़क बनेगी लेकिन आज तक उस पर कोई कार्य चालू नहीं हुआ है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि उस सड़क पर कार्य शीघ्र शुरू हो जाये। एक अनुरोध यह भी करना चाहूँगा कि हमारे माननीय सदस्यों ने समर्थन में बहुत लम्बी चौड़ी बात कही कि आप अमीर, गरीब, पिछड़े, सवर्ण सभी का विकास करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम किसी में भेदभाव नहीं रखेंगे लेकिन मैं बड़े साफ दिल से कहना चाहता हूँ। तमाम माननीय सदस्यों की तरफ से जो भी विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लिया जाय कि एक भी लोहिया ग्राम या कोई भी हैण्डपम्प उनके कहने से लग पाया है क्या। यह पक्ष-पात नहीं तो और क्या है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कम से कम जब लोहिया ग्रामों को चिन्हित किया जाय या जनेश्वर मिश्र ग्रामों को चिहिन्त किया जाय तो कम से कम मा0 विधायकों की भी उसमें सलाह ले ली जाय और उनके अनुरोध को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। मान्यवर, मोदी नगर से निवाडी धोलड़ी मार्ग का चौड़ीकरण और हिंदौला से महमदपुर मार्ग जो कि अति क्षतिपूर्ण है उसको भी इस कार्यवाही में शामिल कर के मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वह इसको भी ठीक कराने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब समाप्त करें। मा0 गामा पाण्डेय जी आप अपनी बात कहें।

श्री सुदेश शर्मा-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया और मा0 अम्बिका चौधरी जी ने, राजस्व मंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया है कि वह मुझे लिख कर के दें, तो निश्चितरूप से वह समस्या का समाधान करेंगे। मा0 अधिष्ठाता जी, यदि आपकी कृपा से मा0 अम्बिका चौधरी जी इतनी

सी बात कम से कम खड़े होकर कह दें, उन बागी ग्रामों के बारे में जो अंग्रेजों के समय में थे तो उनकी बड़ी कृपा होगी।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 अम्बिका चौधरी जी ने आपकी बातों का संज्ञान ले लिया, मौनम् स्वीकृत लक्ष्णम्। अब आप कृपया बैठ जायं।

श्री सुदेश शर्मा-

मान्यवर, मा0 अम्बिका चौधरी जी उनका संज्ञान ले लेंगे तो उन बागी गाँवों के लिए बड़ी खुशी होगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अधिष्ठाता जी, जो लोग पक्ष पात की परम्परा के वारिस हैं, जिन लोगों ने इस लोकतंत्र में विपक्ष के लोगों को विपक्षी नहीं शत्रु समझा, उन लोगों के मन में कोई शंका पैदा होती हो, तो उनके मन में शंका पैदा होने दीजिए, लेकिन जो लोग इस परम्परा के वारिस नहीं हैं उनको पक्ष पात की किसी आशंका से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब सबके साथ होगा, तो आपके साथ भी होगा, कोई चिन्ता करने की बात नहीं है।

श्री सुदेश शर्मा-

मान्यवर, जो अंग्रेजों के समय के बागी गाँव हैं, उनके बारे में भी कुछ कह दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

जैसा मैंने कहा, आप उन पाँच गाँवों को लिख कर के दें दीजिए, उनको संचित करेंगे।

श्री दलवीर सिंह-

मा0 अधिष्ठाता जी, जो हमारे मा0 सदस्य ने पाँच गाँवों के बारे में बताया कि उनको आज भी स्वतंत्रत भारत में बागी का दर्जा दिया जा रहा है, जो उनके लिए कलंक है, उन्हें क्रान्तिकारी का दर्जा दिया जाय और उन्हें लोहिया ग्रामों में चयनित किया जाय।

(विपक्ष के कई मा0 सदस्य एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप लोग शान्त रहें।

श्री दलवीर सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, जिन पाँच गाँवों का मा0 सदस्य ने जिक्र किया है, उनके सम्बन्ध में मैं चाहूँगा कि मा0 अम्बिका चौधरी जी एक शब्द कह दें कि इनके नाम के साथ

जो कलंक लगा है, इसको हटा दिया जायेगा और उनके नाम का अच्छा नामकरण किया जायेगा और उन गांवों को सारी सुविधायें दी जायेंगी।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 नेता लोकदल जी, आप बहुत सीनियर सदस्य हैं और एक दल के नेता भी हैं, आपकी बात का संज्ञान मा0 मंत्री जी ने ले लिया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 मुख्यमंत्री जी स्वयं आपका बहुत आदर करते है।

श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मै मा0 शिवाकान्त ओझा जी के रखे हुए प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे तमाम नेताओं के विचार आये, महामहिम राज्यपाल महोदय का जा हमारा एजेण्डा है, उस एजेण्डा से हट कर के, जो विपक्षी नेताओं ने विषय उठाया है उस पर मैं आपकी अनुमति से मा0 सदन में चर्चा करना चाहता हूँ। हमने नेता विरोधी दल को भाषण सुना, उन्होंने कहा कि यह बजट हमको घुनघना लगता है नेता विरोधी दल का घुनघुना लड़कई में बड़ा पसन्द रहा होगा। पता नहीं क्या वो घुनघुना बजा करके पैदा हुये थे, अगर घुनघना देना होता तो जिनके पैरों में ताकत नहीं उन विकलांगों को रिक्श नहीं देते। अगर घुनघना देना होता तो इलाहाबाद को इलाहाबाद विश्वविद्यालय न देते। अगर घुनघुना देना होता तो एक लाख बीस हजार विकालांग इलाहाबाद जनपद में हैं, उन विकलांगों के लिये विकलांग विद्यालय न देते। कौन सा घुनघुना? घुनघुना यही है न कि हम कन्या विद्या धन दे रहे हैं। हमारी सरकार कन्या विद्या धन दे रहीं है। इस घुनघुने से आप बहुत परेशान हैं। आप अम्बेडकर पार्क में मायावती का फोटो लगाने को घुनघुना नहीं मानते और जब हम अपनी बेरोजगार बहनों, बेटियों एवं नवजवानों को बेरोजगारी भत्ता देते हैं तो आप घुनघुना मानते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि व्यवस्थायें, सरकारें बदला करती है यह सदन गवाह है कि कभी इस पार, कभी उस पार हुआ करता है। मैं इसके पहले इस सदन में विधायक नहीं था। मैंने ये सुनता था कि जब आपकी मुख्य मंत्री आया करती थीं तो पुलिस वालों का मुँह दीवार की तरफ कर दिया करती थी। सचिवालय का कोई आदमी उनको देख नहीं पाता था। अरे, उनकों घुनघुना दीजिये जिनका चेहरा देखने के लिये जनता तरसती हो। हमारे मुख्यमंत्री को क्या आप घुनघुना देंगे। जो बेचारा, आपने बबुआ कहा, मैं बेचारा कह रहा हूँ इसलिये कि अब जब नहरों में पानी चलता है तो टेल तक पहुँचता है इतनी बढ़िया सफाई 5 सालों में कभी हुयी। रोड बन रही है परन्तु आपने जिन लोगों को काम दे दिया 5 साल पहले आज के वे छात्रशक्ति कौन है ? विधायक राजबली जैसल बैठे हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे गाँव के हैं, हमारा इनका क्षेत्र मिला हुआ है। 5 साल

से सड़क उखड़ गयी, पैसा लेकर गायब, छात्रशक्ति महोदय कौन है, मैंने देखा हीं नहीं, जानता ही नहीं। पूरे क्षेत्र में कम से कम सैकड़ों आदमी मर गये, उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिये। स्वामी प्रसाद मौर्य नेता विरोधी दल को लेनी चाहिये, उसका आरोप मेरे ऊपर क्यों लगा रहे हैं। मैं तो अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ अधिष्ठाता महोदय। हमारा क्षेत्र मिर्जापुर से जुड़ा हुआ है, रीवा से जुड़ा हुआ है। हमारे क्षेत्र की हालत अच्छी नहीं है। एक लाख बीस हजार विकलांग में 80 हजार विकलांग हमारे मेजा, कोराँव और शंकरगढ़ में हैं उनके लिये मा0 मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में घोषणा की, मैं इसलिये उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ अपने राजस्व मंत्री जी से कि इलाहाबाद से हमारे क्षेत्र की दूरी 70-80 किलोमीटर है, वहाँ न्यायालय नहीं है, मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय नहीं है। जगह उपलब्ध है एक मुसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय वहाँ बनवा दीजिये।

हमारे यहाँ 100 किलोमीटर दूर आपके यहाँ कोराँव में कोई बस का डिपों नहीं है, वहाँ के नागरिकों को इलाहाबाद आने में कठिनाई होती है, जब बस खराब हो जाती है तो सात-सात, आठ-आठ दिन बनती नहीं, कोराँव में एक डिपो बनवा दीजिये। हमारी जो बेलन नहर है, बेलन नदी निकलती है, उस पर एक बाँध की इच्छा है मैं एक बाँध चाहता हूँ। ये बाँध अगर बन जाये तो हमारे पूरे विकास खण्ड कोराँव ग्राम ढुड़ियार में कोराँव और मेजा तहसील की समस्यायें अपने आप हल हो जायेंगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इलाहाबाद मिर्जापुर के बीच में कोई पुल नहीं है, नया पक्का पुल हो जाये। मिर्जापुर (बाया सिरसा-सैदाबाद) और इलाहाबाद के बीच की दूरी 102 किलोमीटर है, कोई नया पक्का पुल नहीं है। अगर गंगा नदी पर सिरसा में एक नया पक्का पुल बन जाता तो इलाहाबाद की दूरी और इलाहाबाद पर दबाव कम हो जाता और रीवा, जबलपुर, सतना जाने वालों को एक अच्छा मार्ग मिल जाता। मेरा एक और निवेदन है और अपनी सरकार से विनती इसलिये कर रहा हूँ क्योंकि आशा है। हमको यूनिवर्सिटी मिल गयी, विकलांगों का विद्यालय मिल गया, सड़कों का जाल बिछ गया। इसीलिये आशा है, हमने यूनिवर्सिटी के लिये जमीन पहले से खोज रखी है, मुख्यमंत्री जी से बता भी दिया है कि हमने 300 एकड़ जमीन की व्यवस्था उसके लिये, आपके लिये कर दी है। हम चाहते है जो नैनी इण्डस्ट्रियल बेल्ट है जिस पर दबाव ज्यादा है, शहर के अन्दर है, उस इण्डस्ट्रियल बेल्ट को हटाकर हमारे कोंड़हार से मेजा तहसील के बीच में स्थानान्तरित कर दिया जाये। अपने आप पूरी समस्या हल हो जायेगी। हमारे यहाँ कोड़हार में एन0टी0पी0सी0 चालू है, राजबली जैसल जी विधायक है, इन्हीं के क्षेत्र में एक हमारा पारा में एन0टी0पी0सी0 चल रहा है। तीसरा करछना का एन0टी0पी0सी0 बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने नहीं बनने दिया, लेन देन का झगड़ा हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। पहले तो मैं सुना करता था कि मायावती के राज्य में नोट गिनने की मशीन थी, और पी0डब्ल्यू0डी0 का इंजीनियर बोरे में नोट लेकर आता था, गिनवाता था और उनका

भाई कहता था कि रूक नोट गिनाकर जा, कम हो जाएगी तो कौन देगा ? यह मैं विधान सभा में कह रहा हूँ ठेकेदारों ने मुझसे कहा, इंजीनियरों ने मुझसे कहा कि अरे मैं तो लेकर गया था 1 करोड़ 20 लाख उसमें जब 20 लाख कम हो गया तो उसने कहा कि रुक 1 करोड़ लेकर जा। क्या ऐसा हमारी सरकार में हो रहा है? मा0 अधिष्ठाता महोदय, मै अपनी बात यही इसलिए समाप्त करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जिस तरह से अच्छा काम कर रही है, जिस तरह से हमारी सरकार गरीब, किसान, मजदूरों की बात कर रहीं है, वह अच्छी पहल है। इन्हीं शब्दों के साथ मै अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री संजय कपूर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लगभग एक वर्ष होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश मे सरकार बदली पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है। लोगों ने बड़ी उम्मीद की निगाह से मा0 मुख्य मंत्री जी को देखा। यह उम्मीद जरूर थी कि कुछ-न-कुछ बदलाव जरूर आएगा। हमारे क्षेत्र का विकास होगा। हमारे क्षेत्र में रोजगार लगेंगे। हमारे क्षेत्र में बिजली, सड़क और पानी की समास्याओं का समाधान होगा। मगर लगभग एक वर्ष होने के बाद भी आज भी जो हम उम्मीद करते थे, आप उस पर खरा नहीं उतर पाए हैं। जो घोषणाएँ मा0 मुख्य मंत्री जी ने की थी, उसमें सुधार लाने की जरूरत है। सबसे बड़ी समस्या मेरे क्षेत्र के किसान लोग आते है, कर्जा माफी के लिए। मा0 अंबिका चौधरी जी, यहाँ बैठे है, इसलिए मै यह बात पहले रखना चाह रहा हूँ। जब यह सरकार बनी तो कहा गया कि 50 हजार तक का कर्जा माफ हो जायगा, तो गरीब किसानों ने, छोटे मजदूरों ने अपना कर्ज देना बन्द कर दिया वह भी इस उम्मीद से कि हमारा कर्जा माफ हो जाएगा। एक वर्ष होने जा रहा है, मैं समझता हूँ कि मेरी जानकारी में मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी तक 10 लोग भी ऐसे नहीं आए, जो मुझसे यह कहते हो कि हमारा कर्जा माफ हो गया। सब परेशान है। जिन्होंने बिजली का पैसा नहीं दिया, उनपर पैनाल्टी लगकर आ रही है, जो किसानों का कर्जा लिए थे, उन पर भी पैनाल्टी लग गई है। कुछ लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो रही ही है, वे लोग बहुत परेशान है। जो भी निर्णय हो, एक निर्णय हो ताकि आम किसान, गरीब किसान को उसका फायदा मिल सके। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। वह किसानों का प्रदेश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकारी नलकूप तो मिल नहीं रहे है, निजी नलकूपों का हाल यह है कि मेरी अपनी तहसील में 500 से ज्यादा निजी नलकूपों के आवेदन-पत्र पेण्डिंग हैं। पिछले समय में तो लगभग 700-800 हो गए थे, अब भी 500 से ऊपर पेण्डिेन्सी है। जब किसान को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिजली नहीं मिलेगी, किसान को निजी ट्यूबवेल का साधन नहीं मिल पायेगा, तो किसान तरक्की कैसे करेगी ? इसलिए यह जरूरी है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है, जैसे हमारे यहाँ राजकीय इण्टर कालेज की स्थिति है। आठवीं तक की तो शिक्षा मिल जा रही है, प्राइमरी शिक्षा मिल जा रही है, बेसिक शिक्षा मिल जा रही है। जूनियर हाईस्कूल से आगे जो हाई सेकेण्डरी की शिक्षा है, उसमें बहुत बड़ी समस्या आ रही है। मेरे क्षेत्र में पिछली बार जब मैं विधायक था तब भी यह बात विधान सभा में उठाता रहा कि लगभग 10 जगहें ऐसी हैं, जहाँ पर बच्चों को 9-10 की शिक्षा के लिए 10-10, 15-15 तथा 20-20 किलोमीटर दूर पढ़ने जाना पड़ता है, कोई शिक्षा का साधन नहीं है। मेरे क्षेत्र में महिलाओं के लिए डिग्री कालेज नहीं है। बहुत लंबे समय से माँग चली आ रही है, मगर उसका समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसमें सुधार की बहुत जरूरत है। मेरे क्षेत्र में एक शुगर फैक्ट्री है। कोओपरेटिव की शुगर मिल है, उसका नाम रूद विलास चीनी मिल पिछली सरकार जो आज अपोजीशिन में है , वह इसे बेचना चाह रहे थे। उस समय भी मैंने यह विषय विधान सभा में उठाया था कि यह कोओपरेटिव की चीनी मिल है, सहकारिता की चीनी मिल है, इसे न बेचा जाए, फिर हाईकोर्ट ने समर्थन दिया और वह रूक गई। मैं चाहूँगा कि रामपुर जनपद में सिर्फ एक चीनी मिल कोओपरेटिव की रह गई, अगर उसमें नया प्लान्ट लगा दिया जाएगा तो उससे किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। किसानों के बगैर कुछ चलने वाला नहीं है, किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा, नौजवानों के बारे में सोचना पड़ेगा। नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, नौजवानों को शिक्षा मिलनी चाहिए। हम जब कहीं बाहर प्रदेश में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि कहाँ से आये हैं बताते हैं तेा कहते हैं कि वह तो बहुत पिछड़ा प्रदेश है। मेरा बच्चा मुम्बई पढ़ रहा है, बेटी मेरा पूना पढ़ रही है। जब उत्तर प्रदेश का नाम आता है तो वह हमें बहुत नीचे वाले स्तर पर रखते है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश का कोई बच्चा पढ़कर जाता है तो उसे तुरंत नौकरी मिलती है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम लोगों को मिल-जुलकर उत्तर प्रदेश की जगह इस देश में बनानी होगी और उसके लिए बहुत संघर्ष की बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मान्यवर हम लोग कटाक्ष जो एक-दूसरे पर करते हैं वह न करें और बदलाव की तरक्की की बात करें। मान्यवर, पहले के मुकाबले कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट लेकिन हमें उसके और आगे देखने की जरूरत है। मान्यवर, आज किसानों को निजी नलकूप नहीं मिल पा रहे है उसमें बिजली कनेक्शन नही मिल पा रहा है। सरकारी नलकूप पूरे जिले में हमारे मुश्किल से पांच-छः है। इस तरह से एक ब्लाक में एक का भी नम्बर नहीं आ पाता है। सरकारी ट्यूबबेलों को बिजली नहीं मिलेगी निजी नलकूपों को बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा तो किसान कैसे आगे बढ़ेगा। इस पर सरकार को सोचना होगा। मान्यवर पिछली सरकार में पूरे पांच साल मैं प्रयास करता रहा बहुत विभागों में

मेरे मामले गये लेकिन अधिकारियों के मुंह से यही निकलता था कि फला व्यक्ति कांग्रेस का विधायक है इसलिए काम नहीं होना चाहिए। इस मानसिकता को आज बदलने की जरूरत है। अगर हमारे क्षेत्र में कोई सड़क बनेगी तो केवल उस पर कांग्रेस का ही व्यक्ति ही नहीं चलेगा सभी जाति और वर्ग के लोग चलते हैं और सभी को सुविधा होती है। मैने माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव जी से अनुरोध किया था उन्होंने हमारे यहां की एक सड़क स्वीकृत कर दी है। सत्ता पक्ष की ओर से मेंजों की थपथपाहट। इसलिए मैं कह रहा हूँ चाहे किसी भी दल का विधायक हो आज सभी के क्षेत्रों में समान रूप से विकास की जरूरत है। मानसिकता मे बदलाव की जरूरत है। मान्यवर पिछली बार मेरे यहां के विकास से सम्बन्धित कई फाइलों में शासन के अधिकारियों ने यह लिख दिया कि प्रतिक्षा करे। आखिर यह काहे की प्रतिक्षा थी। मैं सदन में प्रश्न लगाता रहा और मेरे मामले शासन में जाते रहे लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। हम लोगेां को उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना है और हम सब चाहतें हैं कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े तो सोच-समझकर सरकार को काम करना होगा। बराबर रूप से सबको विकास का अधिकार देना होगा। मान्यवर चाहे लोहिया समग्र विकास योजना हो, जनेश्वर मिश्र जी के नाम से योजना हो या किसी आबादी के बीच हैण्डपम्प लगने की बात हो तो लोग विधायकों से अपेक्षा करते है कि उनके गांवो में भी इन योजनाओं का लाभ पहुंचे लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इन योजनाओं के अन्तर्गत किसी गांव का चयन नहीं हुआ हैं। इसको देखने की जरूरत है और मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है।

मान्यवर इस सरकार ने कन्या विद्या धन योजना और बेरोजगारी भत्ता बांटने की बात कही है हमारे जनपद में इसको लेकर अभ्यर्थियों में शिकायते हैं कि अपात्र लोगों को मिल गया और पात्र लोग रह गये। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और जो शिकायतें हैं इसमें वह दूर होनी चाहिए। हमें अगर प्रदेश को आगे ले जाना है तो सभी पात्र अभ्यर्थियों को लाभ देना होगा। मान्यवर आज पब्लिक बहुत जागरूक हो गयी है। टी0वी0 रेडियो से उसको सब जानकारी हो जाती है। हम से पहले हो जाती हैं। गांवों मे जो किसान फावड़ा चला रहे होते है वह बताते हैं कि विधायक जी सरकार ने यह घोषणा की है, उसे आप लागू करायें। इसलिए हम सबको भी जागरूक बनना पडेगा और प्रदेश को आगे ले जाना पड़ेगा। मान्यवर, हम देखते हैं कि दूसरे प्रदेशों में उद्योग लग रहे हैं लेकिन हमारे प्रदेश में उद्योग नहीं आ रहे हैं। मान्यवर उद्योगों की स्थापना के लिए तीन-चार चीजों की बहुत जरूरत होती है जैसे बिजली, सड़कें, शिक्षा, और कानून-व्यवस्था की अच्छी स्थिति। मान्यवर हमारे प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ाने की बहुत जरूरत है। हर राज्य में आप देखें 17 से 18 घण्टा बिजली लोगों को मिल जाती है यही व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए। मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश में सरकारी चिकित्सालयों में डाक्टरों की , नर्सों की, और दूसरे स्टाफ की बहुत कमी है।

इस कमी को दूर किया जाना चाहिए, जो पशु चिकित्सालय है वहां पर भी डाक्टरों की और दूसरे स्टाफ की बहुत कमी है। उसको दूर किया जाय। इस सम्बन्ध में हमने विधान सभा में हमने प्रश्न भी लगाया था। उस प्रश्न के जवाब के आधार पर हमारे यहां पोस्टिंग हो गयी, परन्तु तीन महीने बाद ही वह स्टाफ वापस चला गया। विद्यालयों में टीचर की कमी है। विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर की कमी है और दूसरे स्टाफ की बहुत कमी है। इस कमी को दूर कराया जाय। मान्यवर, मेरे क्षेत्र की कुछ समस्या है वह बताकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। 1-जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में मुंसिफ कोर्ट का निर्माण, रोडवेज बस अड्डे का निर्माण, जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में महिला महाविद्यालय का निर्माण टाउन एरिया केमरी में सी0एच0सी0 का निर्माण, जनपद रामपुर की तहसील मिल्क के ग्राम तिराह में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण तहसील मिलक के ग्राम भवरकी के पास नदी पर पुल निर्माण, जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में एहरो शीशगढ़ मार्ग का निर्माण जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के ग्राम खेड़िया के पास भाखड़ा नदी पर पुल का निर्माण, जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण, जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में ट्रांसपोर्ट का निर्माण, जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में उपमण्डी का निर्माण, जनपद रामपुर की विलासपुर विधान सभा क्षेत्र में पांच पशु चिकित्सालयों का निर्माण, जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के ग्राम एडरो में पी0एच0सी0 का निर्माण जनपद रामपुर की विलासपुर विधान सभा क्षेत्र में पाँच इण्टर कालेजों का निर्माण जनपद रामपुर की तहसील मिलक में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण। धन्यवाद

*श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जो ओझा जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा था उसमें संशोधन रखते हुए हमारे नेता माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है मैं उसी से अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ मान्यवर, राज्यपाल जी की जो यह अभिभाषण की पुस्तिका मिली है इसमें दुसरे पन्ने में लिखा हुआ है कि मेरी सरकार ने चुनाव में जो वायदे किये थे उनको मूर्त रूप करने का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। मान्यवर, भारत कृषि प्रधान देश है। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है यहाँ पर 80-90 प्रतिशत किसान है। मैं पेशे से किसान हूँ इसलिए किसान की पीड़ा को यहाँ पर कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पहली बार सदन में चुनकर आया हूँ इसलिए अगर कोई त्रुटि हो जाय, कोई गलती हो जाय तो कृपया उसका संज्ञान न ले। मैं यह कह रहा हूँ कि हमारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, लखीमपुर जिला बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, घाधरा, शारदा नदियां वहां से निकलती है। बाढ़ में बेघर लोग हो जाते है उन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विस्थापितों को बसाने के लिए सरकार ने योजना चलाई है लेकिन वहां पर ऐसा मूर्तरूप में नहीं हो सका।

मेरी अधिकारियों से बात हुई थी उन्होंने बताया कि पैसा पड़ा हुआ है लेकिन किन कारणोवश उस जमीन को खरीदकर क्यों नहीं उन लोगों को बसाया जा रहा है, जरूर इसमें कही उन अधिकारियों या कर्मचारियों की शिथिलता रही होगी। मैं कृषि के संबंध में यह कहना चाहता हूँ कि जो लोग माल में जाकर आटा, चावल, गेहूँ, तिलहन, दलहन सब्जियाँ खरीदते है उनको क्या मालुम किसान किस तरह से अपनी फसल को उगाता हैं उनको कया मालूम है कि किसान के पैर में जो बिवाइयां फटती है वह जब ठड़ पड़ रहीं थी जो कि बताते है कि 10-20 सालों में इतनी ठंड नहीं पड़ी, कोहरा गिरा, ओले पड़े उस भीषणतम ठंड में वह नंगे पैर अपने खेतों में जाता है वहा जाकर वह अपनी खेती किसानी का काम करता है, मजबूरी का काम करता है और उससे वह जो मेहनत करने के बाद फसल तैयार करता है उस फसल पर अगर बिचौलिये उसका दोहन करते हैं, उसको उसका मूल्य नहीं मिल पाता है तो वह किसान बहुत दुःखी होता है और बहुत परेशान होता है और आत्महत्या तक करने को विवश होता है। हमारे विधायक साथियों ने हमे यहाँ पर बताया और बात भी सच थी कि राज्यपाल महोदय का भी दौरा लगा था लखीमपुर में और मुख्य मंत्री जी पहली बार शपथ लेने के बाद लखीमपुर गये और वहां पर उन्होंने कुछ वायदे किये वहाँ पर उन्होंने कुछ बाते करी लेकिन एक साल बीत गया है तकरीबन 11 माह ही रहे है वहाँ पर उन चीजों को बाढ़ के बंधों का न निर्माण हो पाया है न कटान से प्रभावित जो लोग है, उनको बसाने का काम किया गया है। मान्यवर, वहाँ पर बंधों पर सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। नहरों की सफाई की बात अगर करें तो मान्यवर, 30 हजार कि0मी0 नहर की सफाई के सापेक्ष 8500 कि0मी0 सिर्फ नहरों की सफाई हो पाई है। सरकारी आंकड़े बता रहे है कि सिर्फ 7000 नलकूप खराब पड़े है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि कृषि का साढ़े 5 हजार करोड़ का बजट आया था जिसमें आधा खर्च नहीं हो पाया। जो चीज सत्य है वह मैं कहता हूँ किसानों को खाद अबकी बार मिली है खाद में दिक्कत नहीं हुई है लेकिन बीज का जो बजट था, बीज जो बोना था वह बीज नहीं मिला। हमारे जनपद में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मुझे जानकारी है कि किसी भी किसान को बीज नहीं दिया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केन्द्र से मिले आठ करोड़ रुपये में से मात्र 40 परसेन्ट ही खर्च हो पाया है नही बन पाई है नयी कृषि नीति, किसानों की भूमि अधिग्रहण के लिए नीति बननी थी, मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजटीय भाषण में कहा था आश्वासन दिया था लेकिन नहीं पूरा हो पाया। किसानों की आय बढ़ाने में तीन प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हो पाया। आलू उत्पादक को लाभ पहुंचाने के लिए कन्नौज क्षेत्र में फर्रुखाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र में आलू से ओतका बनाने का संयत्र लगाने की बात हुई थी।

(इस समय 03 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

लेकिन निवेशकों द्वारा रुचि नहीं लेने से वह बात आगे नहीं बढ़ पाई है। कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना एवं भंडारण करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुयी। मान्यवर, जैसा कि हमारे महाना जी बता रहे थे कि दुग्ध संघो को पुर्नजीवित करने की कार्य योजना का लाभ दुग्ध उत्पादको को नहीं पहुँच पाया है, लखनऊ में 5 लाख लीटर दुग्ध प्रतिदिन हैण्डलिंग क्षमता वाले डेरी प्लान्ट के लिये बजट में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान था, लेकिन इस दिशा में डेरी के शिलान्यास से आगे बात नहीं बढ़ पाई है। भूमि सेना में मान्यवर, 48 करोड़ रूपये देने के बाद भूमि सेना अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई है। बुन्देलखण्ड की सूखा समस्या के लिये कहा गया था कि इजरायल माडल लागू होगा, इजरायल की तर्ज पर यहाँ पर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी और सूखा दूर किया जायेगा लेकिन योजना फाइलों से बाहर नहीं निकल पाई। यहाँ पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने ग्रामवासियों के लिये विद्युत फीडर अलग करने की योजना बनाई थी, जो कि नहीं लागू हो पायी। बजट पेश करते समय मुख्य मंत्री जी ने अलग से विद्युत फीडर की स्थापना की बात कही थी, अलग से राज्यांश की व्यवस्था का आश्वासन दिया था, लेकिन मान्यवर, यह भी नहीं हो पाया।

गन्ना जो किसान अपनी गाढ़ी कमाई, मेहनत के बाद पैदा करता है, आज की स्थिति क्या है, उसे चीनी मिलों पर निर्भर कर दिया गया है, पर्चियां निर्गत करने का काम चीनी मिलें कर रही है। पेमेन्ट करने का काम चीनी मिलें कर रही है, जबकि सहाकारी गन्ना समिति आज वजूद मे है, 60-60, 70-70 उसमें काम करने वाले कर्मी लोग हैं, लेकिन पर्ची निर्गत करने का काम मनमाने तरीके से मिल वाले कर रहे है। गन्ना रेट आपने बढ़ाया लेकिन दबाव पेमेन्ट के लिये नहीं बन पा रहा है। दिसम्बर के बाद माह जनवरी और आज फरवरी की 20 तारीख हो गयी है, इतने दिनों में गन्ने के भुगतान का काम मिल वाले बिल्कुल निरंकुशता से कर रहे हैं, यह बात सत्य है कि छापे डाले जा रहे है और उनकी घटतौलियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उनका तंत्र और वह इस चीज का फायदा उठा रहे है कि प्रदेश में उद्योग नहीं लग रहे है, मुख्य मंत्री जी उद्योगपतियों को आमंत्रित करने की बात करते है, उद्योगपतियों के लिये माहौल बनाने का काम करते है लेकिन इसका बेजा फायदा गन्ना चीनी मिल मालिक उठा रहे हैं। आज शादियों का एक महीना हो गया, हम सभी लोग शादियों में गये है, गरीबों के यहाँ भी शादियाँ हुयी है, अमीरों के यहाँ भी शादियां हुयी है। कोई बीमार हुआ है लेकिन भुगतान के लिये हम उन चीनी मिल मालिकों के सामने जाते है और गिड़गिड़ाते है, जैसे वह हमें कर्ज के रूप में रुपये दें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस कठोरता से आप फैसले ले रहे है, जब तक उन चीनी मिल वालों पर कठोरता नहीं दिखायेगें, तब तक बात बनने वाली नहीं है। कठोरता की बात हमारी नेता ने दिखाया था और पाँच

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

वर्षों में गन्ने का रेट 140 रुपये तक बढ़ाया, 15 प्रतिशत ब्याज उत्तर प्रदेश में पहली बार किसानों को उनके बकाये पर दिलाने का काम हमारी नेता ने किया था। हमारे बैठे सदस्य, हमारे पड़ोसी क्षेत्र के सदस्य कह रहे थे कि इस सरकार में बढ़ा है, 40 रुपये, इतना कभी नहीं बढ़ा। मैं बताना चाहता हूँ कि उससे पहले हमारी सरकार में 40 रुपये बढ़ा। हमारी सरकार ने डेढ़ सौ रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाने का काम किया है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन किसानों की दुर्दशा को, किसानों के भुगतान को अगर अविलम्ब न दिलाया गया, चूँकि माँगे उठी हैं, आज यहाँ लखनऊ में धरना-प्रदर्शन करने के लिये कमिश्नरी को लोग घेरे है, मेरठ में कमिश्नरी को घेरा जा रहा है। आदमी परेशान है, इसलिये परेशान है कि जो उसने अपनी गाढ़ी कमाई, जेवर-गहने बेचकर जो भी पैसा रखा, उसमें किसान को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, मैं मान्यवर, आपसे यह कहना चाहता हूँ कि विकास के नाम पर जो बातें हो रही हैं, लोहिया ग्राम नहीं दिया गया। अम्बेदकर ग्राम का यह हुआ, मैं इनमें नहीं पड़ना चाहता। मैं कहना चाहता हूँ कि रचनात्मक काम करिये, अच्छा काम करिये। आप लोहिया ग्राम को अम्बेदकर ग्राम से अच्छा बनाकर दिखा देंगे तो जनता उत्तर प्रदेश की स्वतः कहने लगेगी कि आज लोहिया ग्राम अम्बेदकर ग्राम से अच्छे है। वरना जितने अम्बेदकर ग्रामों का चयन किया है, हम लोगों ने कभी उसमे ंभेद नहीं किया, हर बस्ती के बीच में हमने आर0सी0सी0 रोडे बनवाई है। हमने नाली बनवाई है।

मान्यवर, कांशीराम शहरी आवास योजना ऐसी है कि किसी नगर पंचायत में हम घुसते हैं, किसी बड़े शहर में घुसते हैं, चाहे लखनऊ हो, लखीमपुर हो, सीतापुर हो, आगरा हो, शहर में घुसते ही 4 मंजिल, 5 मंजिला कांशीराम आवास योजना दिखाई देने लगती है। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप भी ऐसी शहरी योजना बनाकर दिखाये और लोगों को मकान दिलाये, उसमें कोई भी रहेगा, रहेगा इस प्रदेश का वासी ही। आप पार्क बनाये, आपने मान्यवर, जनेश्वर मिश्र पार्क बनाने का काम किया है, हालांकि उससे पहले हमारे दल ने उसको चिन्हित किया था। आपने बनाया है। आप बात करते है कहते है कि पत्थरों पर, मूर्तियों पर पैसा खर्च किया गया अरे ! अगर आज लखनऊ आन-बान-शान बना है तो बहन कुमारी मायावती जी के विकास के कारण बना है। एक हमारे मित्र का विद्यालय है वहाँ मास्को से एक टीम आई थी, वह जैसे ही अम्बेडकर पार्क चौराहे के पास पहुँची तो वह उतर गयी उसने कहा कि इतना विकास कार्य भारत में नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूँ अपने साथियों से कि अगर पहचान देनी है तो कानपुर को दीजिए, पहचान देनी है तो इलाहाबाद को दीजिए, पुराने लखनऊ का सुन्दरीकरण कीजिए, किसने रोका है आपको। आप विकास कीजिए, विकास कार्य कीजिए, स्वस्थ स्पर्धा मान्यवर, होनी चाहिए, स्वस्थ तरीके से अपना काम करें। यह काम होता है अधिकारियों का, अधिकारियों के द्वारा लड़ाई लगाई जाती है कहा जाता है

कि वह उनके पीछे पड़े, वह उनके पीछे पड़ें। मैं तो कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम करते हैं, हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते है लेकिन यदि एक अधिकारी एक जिले में तैनात रहा है और उसका तबादला हो गया वह चला गया तो दूसरा अधिकारी उसके प्रति मित्रवत व्यवहार रखता है और उनके बकाये काम को पूरा करने का काम करता है। आज जितने भी छापे पड़ रहे है, चाहे जेल भेजे जा रहे है, चाहे फर्जी मुकदमें लिखे जा रहे है, सब नेताओं पर लिखे जा रहे हैं। समाज आज हमें दूसरी दृष्टि से देख रहा है वहा कहता है कि यह आपस में लड़ने वाले लोग हैं, यह आपस में एक दूसरे का कुर्ता खींचने वाले लोग हैं। अगर आज आप माल एवेन्यू में बहन मायावती जी के घर के ऊपर से उपरिगामी पुल निकालेंगे तो दूसरी तरफ रेलवे लाइन है जो विक्रमादित्य मार्ग होते हुए जाती है, समय किसी का गुलाम नहीं रहा, क्या मालूम अगली बार हमारी सरकार बने और उसके ऊपर से भी उपरिगामी सेतु बने। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग रचानात्मक कार्य करें और रचनात्मक तरीके से अपनी बातों को कहें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री शमशेर बहादुर शेरू भैय्या-

मान्यवर, मै अपने क्षेत्र धौरहरा के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अभी तक आप इंटरनेशनल विषय पर बोल रहे थे अब आप धौरहरा में आये हैं। आपका समय समाप्त हो गया, कृपया बैठ जाएं।

श्री शमशेर बहादुर शेरू भैय्या-

मान्यवर, हमारे धौरहरा तहसील में महिला डिग्री कालेज नही है, सरकारी कालेज नहीं है, आई0टी0आई नहीं है, मुंसिफ न्यायालय नहीं है, मण्डी परिषद् की जमीन खरीदी हुई पड़ी है, शारदा नदी में जो बन्धा शारदा खण्ड-1 में बना हुआ है उस पर राजमार्ग नहीं बना है। हमारे मंत्री जी ने यहाँ बताया कि ईसानगर से सुरजनपुर जगदीशपुर तक जाने वाली सड़क नहीं बनी हुई है। टेड़िया सरैया से पक्की रोड खराब हो गई, उसके पुनर्निर्माण का कार्य कराया जाए। ग्राम सेमरिया चौराहे से मुखलिसपुर होते हुए बरारी नानकार तक बनी पक्की सड़क की मरम्मत की जाए। मान्यवर, राम बाटिका और हनुमान गढ़ी को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

अब नहीं, अब आप बैठ जाएं।

श्री शमशेर बहादुर शेरू भैय्या-

मान्यवर, दो मिनट में कह दूँगा। ग्राम खमरिया खुर्द से गैसापुर होते हुए सुरजनपुर तक बनी पक्की सड़क के मरम्मत का कार्य कराया जाए। ईसानगर से मूड़ी होते हुए त्रिकौलिया सिंगावर तक पक्की सड़क के मरम्मत का कार्य कराया जाए। ग्राम नौरंगपुर पुल के पास से बेल्तुआ-मूड़ी व बेल्तुआ से रायपुर तक पक्की सड़क के मरम्मत का कार्य कराया जाए। खमरिया मिल से महम्मदापुर जसवन्तनगर मिठौली तक पक्की सड़क की मरम्मत का कार्य कराया जाए। ग्राम समरदा से बेहटा होते हुए सुसावल पुर तक पक्की सड़क के मरम्मत का कार्य कराया जाए। ग्राम सरसवॉ चौराहे से ग्राम महराजनगर होते हुए जुगनूपुर धौरहरा तक पक्की सड़क के मरम्मत का कार्य कराया जाए। ग्राम बम्भौरी से रासापुर मज्जा तक पक्की सड़क के मरम्मत का कार्य कराया जाए।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका नहीं लिखा जाएगा।

श्री शमशेर बहादुर शेरू भैय्या-

मान्यवर, ग्राम बसन्तापुर से खरवाहिया होते हुए पहड़ियापुर तक पक्की सड़क की मरम्मत का कार्य कराया जाए। ग्राम अमेठी होते हुए धौरहरा से डिहुआ पहड़ियापुर तक पक्की सड़क की मरम्मत का कार्य कराया जाए। ग्राम लालजी पुरवा से राम नगर लहबड़ी होते हुए हौकना मटेरा तक पक्की सड़क के मरम्मत का कार्य कराया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर विपक्ष द्वारा लाये गये संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरी इन बातों को भी उसमें जोड़ लिया जाए।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं व्यवधान नहीं पैदा करना चाह रहा था लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूँ कि गौतमबुद्ध नोएडा में भारी हिंसा भड़क उठी है, वहाँ पर दर्जनों वाहन जला दिये गये है, यहाँ तक कि दमकल की जो गाड़ी आग बुझाने के लिए गई उसमें भी आग लगा दी गई। वहाँ का पुलिस प्रशासन नागरिकों की कोई सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। हालाँकि बाहर के थानों से पुलिस बुलायी जा रही है। यह जो भारत बंद हुआ, दो दिन पहले इसकी घोषणा हुई थी। अच्छा होता प्रदेश सरकार इसकी आशंका को देखते हुए इसकी व्यवस्था कर लेती। मान्यवर, आज हजारों छात्र बिना गाड़ी के खड़े हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री अध्यक्ष-

सूचना आपकी आ गयी, अब इसे नियमों में दीजिएगा।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सूचना मैंने दे दी। मैं कल चाहूँगा कि इस पर सुना जाए।

(श्री सतीश कुमार ममाना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, बात आ गयी। हुकुम सिंह जी ने सूचना दे दी, अब बैठिये।

*श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, कल सूचना देंगे, आपने आदेश दिया है तो कल सूचना देंगे। मान्यवर, जब हिंसा भड़क जाती है तो उसका दुष्प्रभाव पूरे प्रदेश में, दूसरे जिलों में भी पड़ने की आशंका रहती है। इसीलिए मान्यवर, मै आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सरकार को निर्देशित करें कि इस मामले में सरकार संवेदनशीलता बरतते हुए, आजा जो आग फैला है वह कल अन्य जिलों मे न फैले। आगे सावधानी बरतें, सावधानी नहीं बरती गयी इसलिए यह हुआ। इसके लिए जो सख्त से सख्त कदम हो सकता है वह सरकार उठाये। मान्यवर, बाकी आपने जो निर्देश दिया है वह हम कल उठा लेंगे। यह मान्यवर, बहुत जरूरी बात है।

*डा0 अरूण कुमार-

अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने गर्वनर एड्ड्रेस पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मै बरेली का प्रतिनिधत्व करता हूँ और पहली बार इस सदन में आया हूँ इसलिए अगर कुछ कमी रह जाए तो आप उसे नजरंदाज करें। हमारे क्षेत्र बरेली में जिसे काउण्टर मैग्नेट सिटी डिक्लेयर किये हुए काफी समय हो गया लेकिन अभी तक उस स्तर कोई विकास कार्य नहीं शुरू हुआ। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री सम्मानीय श्री अम्बिका चौधरी जी यहाँ मौजूद है। मैं चाहूँगा कि इसका संज्ञान ले कि काउण्टर मैग्नेट सिटी डिक्लेयर होने के बाद अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। मै यह भी चाहूँगा कि थाना बारादरी से बरेली कालेज तक एक ओवरब्रिज बनाया जाए ताकि वहाँ पर यातायात की स्थिति सही हो सके। वहाँ पर यातायात की स्थिति बहुत खराब है और यह शहर के नार्थ और साउथ हिस्से को जोड़ने वाली प्रमुख रोड़ है, इसके ऊपर ओवरब्रिज बनना बहुत जरूरी है। आई0वी0आर0आई0 गेट पर रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाए। बरेली से बहेड़ी तक रोड़ बनना अब शुरू हुई है साल भर के बाद, लेकिन धन्यवाद की शुरू हो गयी परन्तु बहुत धीमी गति से कार्य हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि उसकी गति बढ़ाई जाए। आई0वी0आर0आई0 फाटक से डेलापीर तक मण्डी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

समिति के नजदीक पीलीभीत रोड तक फोर-लेन बनायी जाए। यह भी हमारी जिला समिति से पास हो चुका है लेकिन इसके बाद भी अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। एअरपोर्ट गेट नैनीताल रोड से पीर बहोड़े तक एक रोड बनाये जाने का प्रस्ताव है लेकिन अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। बरेली में एक समय था कि उद्योगों की स्थिति काफी अच्छी थी लेकिन आज उद्योगों की हालत बहुत खराब है जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। मैं चाहूँगा कि उद्योगों का सहयोग कर उनका विस्तारीकरण कराया जाए ताकि वहाँ पर रोजगार सृजित हो सकें। उद्योगों को जो बिजली मिलती है उसकी दरों के बार में भी मैं चाहूँगा कि हमारी प्रदेश सरकार सोचे कि विद्युत के जो रेट्स बहुत ज्यादा बढ़े हैं उस पर पुनर्विचार किया जाए। औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थापना सुविधायें मुहैया करायी जाँए। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे बी0पी0एल0 कार्ड की जो आय की सीमा रेखा थी वह काफी पुरानी थी, अब आज समय बदल गया, हर चीज के दाम बहुत बढ़ गए। मैं समझता हूँ कि बी0पी0एल0 की जो लिमिट है वह कम से कम 60 हजार रुपये सालाना की जानी चाहिए और सभी लोगों को जिनके अभी तक बी0पी0एल0 कार्ड व हेल्थ कार्ड नहीं बन सके हैं उनके भी बनवाए जांए। वृद्धावस्था, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना अभी तक लोगों को मिलना नहीं शुरू हुई है, तुरन्त दिलवायी जाए और इस बात को देखा जाए कि इन सबको प्राप्त करने के लिए उसे चाहिए होता है लेखपाल का सार्टिफकेट, और हम यहाँ राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे हैं [XXX] लेखपाल कोई का बिना पैसे लिए हुए किसी जिले में नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे बरेली के नार्थ हिस्से में कोई भी फायर ब्रिगेड स्टेशन नहीं है, वहाँ पर फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाया जाए क्योंकि अक्सर जब आग लगती है तो एक-एक मिनट मैटर करता है। भीड़-भाड़ में फायर ब्रिगेड का आना बड़ा मुश्किल होता है। बरेली में एक सिवियलन हवाई पट्टी की डिमांड बहुत दिनों से चलती आ रही है लेकिन अभी तक इसमें कार्यवाही नहीं हो पा रही है, यह नहीं बन पा रही है मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सिविलयन हवाई पट्टी बने ताकि वहाँ का विकास हो सके हमारे क्षेत्र में बहुत सी गलियाँ विशेषकर जो नई कालोनियाँ बनी है उनमें सड़क नाम की चीज नहीं है नाली बनी हुई नहीं है। जो मुख्य सड़क है वहीं एक नाला बनी हुई है लोगों का निकलना बहुत मुश्किल होता है हल्की सी बूँदे पड़ जाएं तो बच्चों का स्कूल जाना नामुमकिन हो जाता है इसके साथ ही साथ मैं यह भी चाहूँगा कि नेशनल रिवर गंगा बेसिन एथारिटी के सहयोग से हमारे यहाँ जल निकासी में जो भी मदद हो सकती है वह ली जाय और यह योजना लागू की जाय जवाहर लाल नेशनल अरबन डेवलपमेंट स्कीम के तहत सीवर लाइन जो

नोटः-[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

लगभग ध्वस्त हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है उसका भी नवीनीकरण किया जाय। आपने जो 108 नम्बर की एम्बुलेस दी वह बहुत अच्छा काम है लेकिन उनका असली इस्तेमाल तभी होगा जब वह एम्बुलेंस जहाँ मरीज लेकर जायं वहाँ पर उनको पूरी सहूलियत मिले अगर डिस्ट्रिक हास्पिटल में आई0सी0यू0 नहीं है डिस्ट्रिक हास्पिटल में ट्रामा सेन्टर नहीं है तो एम्बुलेंस ले जाकर वहाँ क्या करेगी वह मरीज का एक घंटा खराब करेगी जो सीरियस मरीज किसी अच्छे अस्पताल में पहुँच जाता उसको वहाँ पहुँचने में दिक्कत होगी। मैं चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में एक अच्छा आई0सी0यू0 और ट्रामा सेंटर बनाया जाय और एक बड़ा अस्पताल बनाया जाय इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूँगा कि बरेली महानगर में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो पहले देहाती क्षेत्र थे अब शहरी क्षेत्र हो गए हैं और 20 साल से जुड़े हैं लेकिल उनको बिजली वही रूरल फीडर से मिल रही है जिसकी वजह से उनको बिजली बहुत कम देर मिलती है मैं इस सदन के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि इस रूरल फीडर को अरबन फीडर में बदलवाने के आर्डर दें ताकि जल्दी से जल्दी यह काम हो जाय। हमारे बहुत से क्षेत्रों में खम्भे नहीं हैं तार नहीं हैं वहाँ पर लोगों ने बिजली बल्लियों से केबिल डालकर ली हुई है जिससे वहाँ दुर्घटना होने के चांसेज रहते हैं मैं चाहता हूँ कि उन तारों को बदलवाकर बल्लियों की जगह खम्भे लगवाकर लोगों को बिजली मुहैया कराने में मदद करें। मै यह भी कहना चाहूँगा कि आज बहुत सी जगहों पर बिजली विभाग वालों ने आफत जोत रखी है मीटर रीडर के साथ चार-छह लड़के प्राइवेट रख रखे हैं जो मीटर चेकिंग के नाम पर कभी कहते हैं कि आपका मीटर तेज चल रहा है कभी कहते हैं कि स्लो चल रहा है आपके मीटर में शंट लगा हुआ है और बिना वजह लोगों को डरा धमका कर पैसे तय करते हैं और कहते हैं कि आपके ऊपर इतना जुर्माना हो जाएगा हम मीटर उखाड़कर ले जाएंगे बिजली काट देंगे। इन सबसे डराकर वह सौदेबाजी करके लोगों से पैसे वसूलते हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार इस बात को देखे कि बिजली विभाग के लोग इस तरह के कार्य न करें। मीटर की चेकिंग होनी चाहिए लेकिन जो पैसा लिया जाय वह सरकारी खजाने में जाना चाहिए लोगों को बिना वजह तंग करके जो लोगों से पैसा वसूला जाता है मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी अभी डाक्टर साहब, सदस्य बरेली ने बहुत अच्छे सुझाव और बहुत अच्छी बातें कहीं एक वाक्य थोड़ा खतरनाक है उसको कार्यवाही के समय जरूर दिखवा लीजिएगा। उन्होंने लेखपाल की चर्चा करते समय राज्यपाल से उसकी तुलना कर दी और यह

कहा कि [xxx] और लेखपाल बिना पैसे लिये काम नहीं करता तो यह सेंटेंस ठीक से दिखवाइएगा वरना उनका अनर्थ हो जाएगा।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसको भी देख लें कि अम्बिका चौधरी अम्बिका सोनी न बनने पाएं।

श्री अध्यक्ष-

जो राज्यपाल से तुलना की गई है उसमें बीच वाला वाक्य निकाल दीजिए। अम्बिका सोनी का तो उन्होंने सुधार कर लिया था इसलिए उसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री गुलाम मोहम्मद-

इस सदन में महामहिम राज्यपाल जी द्वारा दिये गये अभिभाषण और उसके समर्थन में माननीय ओझा साहब ने जो अपने विचार दिए थे उसके समर्थन में मैं अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूँ सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। मान्यवर, जो अभिभाषण माननीय राज्यपाल जी ने यहाँ दिया। वह हमारी सरकार का एक अक्स था, प्रतिबिम्ब था और सच्चाई उसमें हर पहलू में दिखाई दे रही है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो कार्यक्रम हैं और जो माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में सदन के सामने रखा है वह गरीबों के दिलों को छूता हुआ उनके उत्थान के हर पहलू को अग्रसर करते हुए, आगे बढ़ाते हुए चाहे बच्चियों के लिये कन्या विद्या धन का मामला हो। हमारी बेटी और उसका कल, छात्रवृत्ति, किसानों के मामलात, गन्ने का मूल्य, गन्ने का भुगतान, हर पहलू पर गरीबों को सेन्ट्रलाइज करके, उनको केन्द्रित करके, उनको फोकस करके नीतियाँ बनाई गई हैं और सरकार चल रही है। एक ऐसी सरकार जिसका अगर कम्पेरिजन करें कल की सरकार से और आज की सरकार से तो ऐसा लग रहा है कि कितना फर्क है। अभी एक साहब बोल रहे थे वह पार्को और मूर्तियों की तारीफ कर रहे थे जैसे वह साम्राज्यवादी युग में चले गये हों और इस प्रदेश का सब पैसा जो गरीबों से टैक्स के रूप में आता है वह उनका अपना पैसा बन गया हो और उसको वह जहाँ चाहें और जिस तरह से खर्च करें। आज की सरकार सम्वेदनशील सरकार है, यह गरीबों के हितों का ख्याल रखने वाली सरकार है और एक-एक पॉलिसी, एक-एक नीति गरीबों के उत्थान के लिये, उनकी तरक्की के लिये, उनके रहन सहन को ऊपर उठाने के लिये बनाई जा रही है। इसमें कोई भी प्वाइंट, एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको क्रिटिसाइज किया जा सकता हो, जिसकी आलोचना की जा सकती हो। और सिर्फ आलोचना के लिये आलोचना करना उसी मकसद से आलोचना करना, वह तो विपक्ष का काम है, वह करे लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें एक भी प्वाइंट

नोटः- [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

ऐसा नहीं है जिसकी आलोचना की जाय। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे संविधान की आत्मा, अनेकता में एकता और खास तौर से धर्म निरपेक्षता उसकी रूह है। उस रूह का ख्याल रखते हुए यहाँ चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, बसपा के लोग हों, चाहे राष्ट्रीय लोकदल और काग्रेस के लोग हों, हमेशा इन लोगों ने जब भी इनकी सरकार आयी है दोनों हाथों में लड्डू रखने का काम किया है। लेकिन यह पहली सरकार है, मुलायम सिंह यादव जी जब-जब सत्ता में आये हैं, समाजवादी पार्टी जब-जब सत्ता में आई हैं, इसने खुलकर के अपनी धर्मनिरपेक्षता का सबूत दिया है। और सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्र कमेटी ने साफ जाहिर कर दिया है, यह साबित कर दिया है कि आज मुस्लिम वर्ग इस देश में सबसे पिछड़ा हुआ है। उन लोगों की सहायता करके, उन लोगों को प्रोत्साहन दे करके, उन लोगों को थोड़ा विशेष अवसर देकर के अगर बात की जा रही है तो हमारे कई साथी लोग उसको तुष्टिकरण की राजनीति कहते हैं । इस देश में लगभग एक चौथाई मुस्लिम वर्ग के लोग रहते हैं जो शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरह से पिछड़े हुए हैं। अगर यह इतना बड़ा वर्ग कमजोर रहेगा, वंचित रहेगा, शिक्षा से पीछे रहेगा तो यह देश तरक्की नहीं कर सकता है इसलिए मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करता हूँ और माननीय ओझा जी ने जो उसके समर्थन में अपना भाषण दिया है, उसका पूरा-पूरा समर्थन करता हूँ। इसके साथ-साथ कुछ मेरे क्षेत्र की बात है। मेरा क्षेत्र, सिवाल खास क्षेत्र है जो चौधरी अजीत सिंह जी और उनसे पहले बड़े चौधरी चरण साहब सिंह का पार्लियामेंट क्षेत्र रहा है। संसदीय क्षेत्र रहा है लेकिन विकास के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं हो पाया । पहली बार समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीता है। मैं चाहता हूँ उस क्षेत्र की कुछ समस्यायें आपके समक्ष रखूँ और आपके जरिए से सरकार के पास पहुँचाऊ। मान्यवर, सिवाल खास में दूर-दूर तक कोई महिला डिग्री कालेज नहीं है। एक महिला डिग्री कालेज सिवाल खास में स्थापित होना चाहिए। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी हमारे यहाँ एक अपर गंगा नहर है, वहाँ पर एक हाइडिल का पावर प्रोजेक्ट है, उसके सौन्दर्यीकरण का प्रबन्ध होना चाहिए, क्योंकि उधर कोई भी ऐसा पर्यटक स्थल नहीं है ताकि पर्यटक वहाँ आ सकें जा सके। और अगर वहाँ से लेकर सरधना तक नौकायन का कोई इन्तजाम करा दिया, कोई काम करा दिया जाय तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह अपने आपमें अनूठा कार्य होगा और बड़ी तादाद में पर्यटक आएंगे। इसके अलावा पांचवी बुजुर्ग के सामने जो सरूरपुर ब्लाक का ग्राम है उसके सामने हिंडन नदी पर एक पुल की बेहद जरूरत है हम चाहते कि उस पुल का निर्माण हमारी सरकार के द्वारा हो जाए। मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूँ कि 'हमारी बेटी और उसका कल' या इस तरह की जो और भी योजनायें हैं इसमें कुछ चयन में गलती हुई है उसको सुधारा जाना चाहिए। पहले आओ और पहले पाओ, के आधार पर, हमने उन बच्चियों का चयन किया और उसमें खासतौर से जो देहात की बेटियां थी वह रह गई और जो शहरी लोग थे उन्होंने तैयारी की उन बच्चियों

को मिल गया और देहात की बच्चियां बहुत बड़ी तादाद में रह गई। इसका कोई न कोई फार्मूला तय होना चाहिए, कोई न कोई नियम बनना चाहिए, या तो यह हो कि जो गरीब हैं, इन्कम में सबसे नीचे हैं उसको लेकर चलें या फिर ऊपर से लेकर चलें, जिसने सबसे ज्यादा अच्छें अंक प्राप्त किये है वहाँ से नीचे की ओर लेकर चलें। इस तरह का कोई न कोई फार्मूला हमे तय करना पडेगा। बहुत से कालेजेज यह भी कर रहे हैं कि वह लिस्ट टाइम से नहीं भिजवाते हैं उन कालेजों को मजबूर किया जाना चाहिए और उनकी बाकायादा लिस्ट आनी चाहिए टाइमली लिस्ट आनी चाहिए क्योंकि कोई अगर एक बार महरूम रह गया हैं तो तीस हजार रुपये एक गरीब परिवार को मिलने थे उससे वह वंचित रह जाता है। उसको फिर मौका नही मिल पाता है। मेरे इस सुझाव को शामिल कर लिया जाय आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद।

*श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और हम कमी बाढ़ की विभीषिका का शिकार होते है तो कभी अग्नि पीड़ा का शिकार होता है। अभी स्थिति यह है कि ए0पी0 तटबंध की हालत बहुत नाजुक स्थिति में है। ए0पी0 तटबंध में अभी से कटान शुरू है और कटान की स्थिति यह है कि नदी से बंधे की दूरी मात्र एक मीटर रह गई है और बंधा आज की डेट में कट रहा है। लगातार धरना प्रदर्शन के बाद भी एक रुपया भी धन अवमुक्त नहीं हो सका है और न ही वहाँ किसी प्रकार का काम शुरू हो पाया है। होता क्या है अक्सर कि धन तो तब आंवटित होता है जब बाढ़ शुरू हो जाती हैं नदियां उफान पर आ जाती हैं बंधे टूटने की स्थित में आ जाते हैं तब धन आवंटित होता हैं और काम केवल नाम का होता है और सरकारी धन का खुलेआम लूट होता है। ऐसे में मैं मांग करना चाहूँगा। कि अमुवा तटबंध और ए0पी0 तटबंध और ए0पी0 तटबंध का एक्सटेंशन नरवा जोत बंधे पर तत्काल धन अवमुक्त कराकर उन तटबंधों का मरम्मतीकरण कराया जा सके ताकि वह बंधा सुरक्षित रह सके। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि पिछली बार मैंने आपको एक पत्र दिया था, तमकुहीराज तहसील में ट्रेजरी कार्यालय खोलने के लिए आपने मुझे आश्वासन भी दिया था कि इस वर्ष तो नहीं लेकिन अगले वर्ष वहाँ पर पर ट्रेजरी कार्यालय खोलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करूंगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ ट्रेजरी कार्यालय खुलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। खासकर हमारा जो क्षेत्र है, दुदही और तमकुहीराज तो तहसील है, काफी पुराना तहसील है, राजा इन्द्र जीत प्रताप बहादुर शाही जिन्होने अंग्रेजी हुकुमत के खिलाफ लड़ने के काम किए थे, वहाँ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तहसील होने के साथ-साथ नगर पंचायत का दर्जा नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि तमकुहीराज और दुदही को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया जाए, जिससे वह भी शहरी क्षेत्र घोषित हो सके। मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर जो नहर किसानों की फसलों को सिंचित करने के लिए निकलती है, उन नहरों की हालत यह है, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि नहरों में हेड से टेल तक पानी जा रहा है। लेकिन आलम यह है कि हेड से टेल तक पानी आने के लिए उनकी सफाई की आवश्यकता होती है और नहरो की सफाई के नाम पर उसी नहर को मनरेगा से भी हर वर्ष साफ कराया जाता है, उसी माइनर में विभाग से भी पैसा जाता है और उन नहरों में फाटक न होने के कारण किसानों की फसलों को सही ढंग से पानी नही मिल पा रहा है। इसके कारण उन लोगों को इसका लाभ नही मिल पा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि तमाम नहरों, माइनरों में अगर फाटक लग जायें तो शायद उस इलाके में किसानों को सही ढंग से पानी मिल पायेगा। मान्यवर, पडरौना से तमकुहीराज तक एक सड़क बन रही थी, देवरिया से आगे तक सड़क के चौड़ीकरण का प्रस्ताव था, लेकिन पता नही किन स्थितियों में जब आपकी सरकार आयी तो काम और विकास की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वह वहीं रोक दिया गया और सड़क वैसे की वैसे बनी पड़ी है। मैं आपके माध्यम से माँग करना चाहूँगा कि इस सड़क को तत्काल बनाने का काम शुरू किया जाए। 1984 में बाढ़ आयी थी, बाढ़ की विभीषिका से हजारों परिवार बेघर हुए थे । अमुवा तटबंध और ए0पी0 तटबंध पर 84 से लेकर अब तक, मान्यवर, इस साल भी बाढ़ आई और हजारों परिवार उससें प्रभावित हुए, बेघर हुए वह लोग आज तक बंधे पर जीवनयापन कर रहे हैं। अभी हमारे एक साथी ने बताया कि कई जगह जमीनें खरीद कर रखी गयी हैं, लेकिन उनपर उनको नही बसाया गया है। हमारे यहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने पर मजबूर है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि जो लोग बंधे पर बसें है, यदि सरकारी जमीन नही है तो आप क्रय करके उन लोगों को जमीन देकर करके बसाने कामा करें जिससे उन लोगो काा जीवनयापन ठीक ढंग से हो सके।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवधान के लिए क्षमा। आवश्यकता थी इस बात की, इसी बहाने हमने सोचा कि बाकी लोगों से भी बात कर लू । हमने पहली बार 10 करोड़ के बजट का प्राविधान टोकेन तौर पर किया था कि जो लोग कटान के कारण विस्थापित हो गये है उनको अगर सरकारी भूमि उपलब्ध नही है, मान्यवर, मुश्किल से हमारा 10 प्रतिशत वह बजट यूटीलाइज हो पा रहा है। मान्यवर, मुश्किल से हमारा 10 प्रतिशत वह बजट यूटीलाइज हो पा रहा है। मान्यवर, प्रस्ताव कही से नही आये हैं और जो माननीय जनप्रतिनिधि है, उनसे हमारा

अनुरोध है। अपने क्षेत्र की दिलचस्पी आप रखेंगे, उतनी दिलचस्पी अधिकारी नही रखेंगे, इसलिए जिन गांवों की विशेष तौर पर ऐसी स्थिति है, आप उसकी सूची मुझे भी अगर दे दीजिए तो मै कलेक्टर से उसकी तुरन्त रिपोर्ट मांग मांगूँगा। धन हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन हम उस मद में खर्च नही कर पा रहे है। इसलिए आप लोगों से मैं अपनी ओर से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से कटान के कारण विस्थापित हुए लोग हैं तो उन लोगों की अनुमानित संख्या के आधार पर गाँव चिन्हित करके दीजिए ताकि उसकी रिपोर्ट बनाकर धन दिया जा सके, धन की कमी नही है। हमने पहली बार प्रस्तावित किया था और पिछली बार उसे आपने बजट में परित किया। इस साल भी हमने इसका प्रावधान रखा है। धन है लेकिन आप लोगों के प्रस्ताव आने चाहिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मैं राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप कुशीनगर डी0एम0 से रिपोर्ट मँगा लें, मैंने उन्हे एक पत्र भी दिया था और मै भी एक पत्र आपको सौप दूंगा जिसके माध्यम से आप वह पत्र मंगा सकें। मान्यवर, 1984 में जब बाढ़ की विभीषिका हुयी थी तो तमाम सड़के नदी के दबाव के कारण कट गयी थी। उन सड़को में आज तक पानी चल रहा है। और कोई इस पार हो गया कोई उस पार हो गया। सम्पर्क मार्ग टूटा हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि गौरीघाट पर गौरी घाट का पुल, टी0बी0 रोड पर टी0बी0 रोड का पुल और गोलाघाट पर गोलाघाट का पुल जो 1984 में बाढ़ के कारण आज तक नही जुड़ पाया है और तमकुही रोड से बरवा पट्टी जाने के लिए या गौरी जगदीश से अमुआ जाने के लिए या सेवरही से पिपराघाट जाने के लिए इन मार्गों का चालू होना बहुत आवश्यक है। चूँकि हमारा क्षेत्र गन्ना उत्पादन पर आधारित क्षेत्र है। लोग गन्ना उस पार से इस पार लाते है। इसके लिए उनके पास यातायात की कोई व्यवस्था नही है। नदी में नाव से गन्ना लाकर इस पार देते है और बैलगाड़ी या गाड़ियों से फैक्ट्री में ले जाने का काम करते है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हमने लिखकर भी दिया था, नियम-301 में भी लगाया था रिपोर्ट आ गयी है बडी कृपा होगी अगर उस पर धन आवंटन हो जायेगा। तो लाखों लोगों के आने जाने का एक रास्ता सुगम हो जायेगा। मान्यवर, हमारे यहाँ एशिया स्तर का एक गन्ना अनुसंधान केन्द्र हुआ करता था। आज की स्थिति में वहां पर अपर निदेशक तक नही है। वहाँ पर मात्र दो वैज्ञानिक बचे हुए उसको शाहजहाँपुर से अटैच कर दिया गया है। जहाँ किसी जमाने में निदेशक बैठा करते थे। उस गन्ना अनुसंधान में अच्छी प्रजातियाँ उत्पन्न करने के लिए उनको अवार्ड से सम्मानित किया है। ऐसी दशा में उसको उपेक्षित रखा गया है। मैंने तमाम पत्र मा0 मुख्य मंत्री जी को, प्रमुख सचिव जी को दिया था प्रमुख सचिव जी ने कहा था कि मैं वहाँ चलूँगा, चूँकि मैने उसको देखा है और देखकर उस गन्ना

अनुसंधान केन्द्र को विकसित करूँगा। वह बाबू गेंदा सिंह जी के नाम पर बना अुनसंधान केंन्द्र है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि उस बाबू गेंदा सिंह अनुसंधान केन्द्र को विकसित किया जाये। हमारा सेवरही अस्पताल जो नगर पंचायत में है उस अस्पताल का आलम यह है कि वहाँ लिखा तो है कि सी0एच0सी0 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र। लेकिन उसको एडिशनल पी0एच0सी0 का दर्जा प्राप्त है। वहाँ अधीक्षक नाम की कोई पोस्ट नहीं है। कभी आपने पी0एच0सी0 से सी0एच0सी का संचालन सुना है। यह हमारे क्षेत्र में होता है। उसे सी0एच0सी0 का दर्जा देते हुए अधीक्षक पोस्ट करते हुए 100 बेड का अस्पताल उसको बनाया जाये। एक नदी के उसपार खानगी बाजार है और एक सलेमगढ़ जो बिहार जो बिहार यू0पी के बार्डर पर है अगर वहाँ भी पी0एच0सी0 का निर्माण करा देंगे तो मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आराम से उनको अपने गाँव के सुदूर क्षेत्रों में विकास की किरण दिखायी देगी। और स्वास्थ्य का लाभ मिल पायेगा। एन0आर0एच0एम0 में डी0एम0, कुशीनगर ने एन0आर0एच0एम0 के माध्यम से एक पत्र आपके यहाँ संस्तुत करके भेजा है कि गरीब लाचार लोगों के लिए एक बस की सुविधा हो जाएगी और वह बस पडरौना या जनपद कुशीनगर जनपद मुख्यालय से चलेगी और गरीब लोगों को पी0जी0आई0 में दिखाएगी और फिर पी0जी0आई0 से ले जाकर वहाँ गन्तव्य स्थान पर छोड़ देगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा अगर सरकार एक बस वहाँ गरीब लोगों को देने का काम करेगी तो गरीब लोग पी0जी0आई0 में अपना इलाज करा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, हमारे यहाँ एक बांसगाँव टोला खैरवा हुआ करता है। जो दुदही ब्लाक में है। आजादी की लडाई में उसका बड़ा योगदान है। अंग्रेजी हुकुमत के खिलाफ जब खिलाफ जब नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने आह्वान किया, उन लोगों ने रेलवे लाइन उखाड़ना और सहकारी गोदामों को लूटने का काम किया। माननीय स्वर्गीय श्री फिरंगी गोसाई जी हुआ करते थे उनको ताम्र पत्र से भी सम्मानित किया गया और हालत यह है कि वह पूरी जमीन जब आजादी के बाद सीलिंग एक्ट लागू हुआ तो उस जमीन को अधीग्रहीत करके वन विभाग में दे दिया गया। लोगों को पता नहीं था। जब लोगों को इंदिरा आवास मिला, जब लोग घर बनाना शुरू किये तो स्थिति यह हुयी कि उन लोगों को उजाड़ने का काम वन विभाग द्वारा करना शुरू कर दिया गया। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से भी निवेदन कर चुका हूँ, मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन कर चुका हूँ।

आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन में लड़ने का काम किया, जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया, ऐसे लोगों को आज घर से बेघर करने की मंशा वन विभाग के द्वारा की जा रही है। आपसे मैं मांग करना चाहूँगा कि उन लोगों को वहाँ मालिकाना हक देने का काम किया जाय और उन लोगों को वहां बसाये रहने का काम किया जाय। मान्यवर, एक सुझाव और देना चाहता हूँ, मैं, मा0 राजस्व मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि अग्नि पीड़ित जो लोग है, वह सबके क्षेत्र में हुआ करते है, अग्नि पीड़ा से सब लोग प्रभावित होते है। मैं कहना चाहूँगा कि इन्दिरा आवास न सही, आपने एक योजना शुरू की है, लोहिया आवास, आप एक आदेश/सर्कुलर जारी करिये सरकार की तरफ से कि जिन लोगों का घर अग्नि पीड़ा में या बाढ़ की विभीषिका में खत्म हो जायेगा, उन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जायेगा। मान्यवर, गन्ना की स्थिति यह है कि हमारा सेवरई शुगर फैक्ट्री मिल जो पहले हर साल, पिछली समय तक आज तक बकाये की स्थिति में नहीं रहा, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, यह मैं नहीं जानता, इस साल मात्र गन्ना का भुगतान दिसम्बर,29 तक हुआ है। जबकि आपका एक सरकारी आदेश है कि कोई भी चीनी मिल अगर 15 दिन तक गन्ना का भुगतान नहीं देता है, तो उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से मांग करना चाहूँगा कि तत्काल उन लोगों पर एफ0आई0आर0 कराना चाहिए जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाएं, अब आपका भाषण लिखा नहीं जायेगा, चाहे जितना आप बोलें। मा0 राम लाल अकेला जी, आप अपनी बात शुरू करें। (मा0 अध्यक्ष महोदय के मना करने के बाद भी मा0 सदस्य श्री अजय कुमार लल्लू अपनी बात कहते रहे, लेकिन माइक ऑफ होने के कारण उनकी कोई भी बात सुनाई नहीं दी।

श्री राम लाल अकेला-

माननीय अध्यक्ष जी, महामहीम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मा0 ओझा साहब ने जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन में रखा है, उसके समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय का अभिभाषण मैंने पूरी तरह से पढ़ने का काम किया है और जो महामहिम ने यहां अपना भाषण दिया है, मान्यवर, 2012 के पहले सदन से लेकर सड़क तक लोकतंत्र की हत्या करने का काम पूर्ववर्ती सरकारों ने किया था और मा0 श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में सरकार का गठन हुआ तो सदन से लेकर सड़क तक जो लोकतंत्र की हत्या लोगों ने कर दी थी, हमारी सरकार ने उस लोकतन्त्र को सदन के अन्दर भी जिन्दा करने का काम किया और सड़क पर भी जिन्दा करने का काम किया। उसका जीता

जागता उदाहरण है कि हमारे मुख्य मंत्री जी जब आते हैं, अपने आसन पर जब बैठते हैं तो चाहे पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हो, उनके पास आकर के उनसे अपनी पीड़ा बताने का काम करते है। और हमारे मुख्य मंत्री जी सहृदयता से उनकी पीड़ा को सुनने का काम करते हैं। हमने देखा है इसके पहले भी सदन में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, नेता सदन जब सदन के अन्दर आती थी, हिम्मत नहीं थी विपक्ष की तो बात छोड़ दो, सत्ता पक्ष का कोई भी विधायक, नेता सदन से अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं करता था। यह लोकतंत्र स्थापित किया है हमारे मा0 नेता सदन ने और इससे पहले याद होगा जब कोई राज्य का कर्मचारी आन्दोलित हो, किसान आन्दोलित हो, नौजवान आन्दोलित हो, तो विधान सभा के सामने उसके अधिकार छीन लिये गये थे कि तुमको यहां विधान सभा के सामने धरना-प्रदर्शन करने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस की लाठी चलाकर, घोड़ों की टापों से उनकी आवाज को कुचल दिया जाता था, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाती थी, लेकिन हमारे नेता मा0 अखिलेश यादव जी ने कहा कि नहीं, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और उन्होंने लोकतंत्र को आजादी देने का काम किया है। आज अभी हमारे बहुजन समाज पार्टी के मित्र बोल रहे थे कि मास्को से कोई टीम आई थी, लखनऊ के विकास को देखकर, पत्थरों को देख कर उसने कहा कि भारत में ऐसा विकास नहीं हो सकता। मैं तो सुन रहा था, उसके बाद में उन्होंने बोलना शुरू किया कि हमारे क्षेत्र में सड़क नहीं है, हमारे क्षेत्र में अस्पताल नहीं है, हमारे क्षेत्र में मण्डी नहीं है। आप जब पत्थरों को शान समझते हो, तो मण्डी और सड़क की बात क्यों करते हो। हमारे नेता ने जो प्रदेश के किसानों की आवश्यकता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और बिजली उसको प्राथमिकता देते हुये जो काम शुरू किया है, आज चारों तरफ चाहे नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हों, जिनके चेहरे मुरझा गये थे, अखिलेश यादव जी ने ऐसी योजनायें चलाकार उन सब के चेहरे पर मुस्कान पैदा करने का काम किया है इसलिए महामहिम राज्यपाल ने चाहे कन्या विद्या धन योजना हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो और सबसे बड़ी बात है कि आपने पत्थर लगाने का काम किया लेकिन हमने क्या किया, जो रिक्शा चालक आपको ढ़ोता था उसको टी0बी0 हो जाती थी। हमने उसको बैटरी चलित रिक्शा देने का काम किया ताकि उसका परिवार स्वास्थ्य हो सके और टी0बी0 से बचने का काम कर सके। आपने पत्थरों में पैसा लगाया, हमने गरीब मजदूर को स्वचालित रिक्शा देने का काम किया। हमने कन्या विद्या धन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया। आप सड़कों की बात करते हो। पूरे 5 बरस उत्तर प्रदेश में किसी सड़क पर गड्ढ़े पाटने का काम शुरू नहीं हुआ। धन्यवाद दीजिये, मा0 शिवपाल सिंह यादव जी को, मा0 अखिलेश यादव जी को कि सरकार बनने के बाद पहली बार पूरे उत्तर प्रदेश में एक फरमान जारी किया लोक निर्माण मंत्री जी ने कि खबरदार अगर किसी सड़क पर गड्ढ़ा मिल गया तो उस अधिकारी की खैर नहीं, उसका परिणाम हुआ है कि पूरे उत्तर प्रदेशों में सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हुआ। तहसीलों में

लेखपालों द्वारा जो भ्रष्टाचार कायम था, जो आप बात कर रहे थे, हमारे साथी बात कर रहे थे लेखपालों की, वे पहले की सरकार की बात कार रहे थे। मा0 अम्बिका चौधरी जी ने पूरी तहसीलों का नक्शा बदलने का काम किया है और आज पूरी तरीके से अच्छी तरीके से हमारे गरीब जो जाते है उनके काम किये जा रहे है। इसीलिये मा0 ओझा साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसको पुरजोर समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अपने रायबरेली, अपने क्षेत्र का भी तो नाम लो न। अपने जिले की बात ही नहीं बता रहे हो।

श्री रामलाल अकेला-

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारे रायबरेली जनपद में स्पिनिंग मिल है। हमारे बड़े भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी इनका भी ताल्लुक है, रायबरेली से। मैं इनसे भी कहना चाहता चाहूँगा कि रायबरेली की स्पिनिंग मिल बन्द हो गयी। मान्यवर, आज मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राजस्व मंत्री जी बैठे है। जौनपुर की मिल बन्द हो गयी थी, हमने सुना है कि उसे आपने चालू कराने के लिये आदेश देने का काम किया है। हमारा अनुरोध है कि रायबरेली की स्पिनिंग मिल को भी चालू कराने का काम किया जाये। वहाँ दसियों हजार मजदूर एक-एक रोटी के लिये मोहताज हो रहा है। मजदूर रो रहा है, परिवार रो रहा है क्योंकि पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया है तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, उन मजदूरों को सहारा देने का काम किया जाये। उस मिल को फिर से प्रारम्भ करने का काम किया जाये। दूसरी बात मैं अपने विधान सभा क्षेत्र बछरावाँ के लिए कहना चाहता हूँ। हमारे बछरावाँ में लालगंज रोड पर फूलाई ओवर बनने से पूरे कस्बे का विनाश हो रहा है। मैं चाहूँगा राजस्व मंत्री जी के माध्यम से सरकार से कि हमारे बछरावाँ को बचाने के लिये एक रिंग रोड की स्थापना करने का काम किया जाये। वरना हमारा कस्बा बछरावाँ पूरी तरह से बरबाद हो जायेगा। तीसरी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में हसवा ड्रेन, महाराजगंज ड्रेन, शिवगढ़ ड्रेन इन सारी ड्रेनों की वजह से क्षेत्र का दो तिहाई हिस्सा जलभराव से परेशान रहता है। हजारों बीघा जमीन होने के बाद भी किसान भुखमरी के कगार पर पहुँच रहा है। मैं आपके माध्यम से मा0 अम्बिका चौधरी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी ड्रेनों का सुधार करके शताब्दी ड्रेन से उसको जोड़ करके और राष्ट्रीय परियोजना से उनको जोड़ने का काम अगर कर दिया जायेगा तो हमारे क्षेत्र के किसानों को उनकी समस्याओं से निपटारा मिल जायेगा। एक बार फिर जो शानदार काम हमारे नेता मा0 अखिलेश यादव जी ने शुरू किया है। चाहे लोकतंत्र की स्थापना हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। आप लोग दवा की बात करते हो कि 5 साल पहले कहीं एक भी

मरीज को दवा देखने को नहीं मिलती थी लेकिन जब से मा0 अखिलेश यादव जी ने व्यवस्था संभाली है और कोई भी गरीब जाता है अस्पताल में तो उसे दवा के लिये लाइन नहीं लगानी पड़ती। डॉक्टर आता है, कम्पाउण्डर आता है और मरीज को जो सुविधा देनी होती है, वो सुविधा देने का काम किया जाता है। मान्यवर, इन्ही शब्दों के साथ डॉक्टर साहब ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ और आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया है इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

मा0 अध्यक्ष महोदय, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, प्रदेश में जितनी भी योजनायें बन कर जाती है, वो जनता के लिये बनती है। मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे जिले चन्दौली में जिला पंचायत के माध्यम से नरेगा में हजारों-हजार मजदूरों ने काम किया था, लेकिन मान्यवर, आज तक उनको भुगतान/पेमेन्ट नहीं कराया गया और मैं आपसे निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि वे हजारों-हजार मजदूर जो आज पैसे के लिये दर-बदर घूम रहे है, उनका भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। मान्यवर, जो भी सरकार की योजनाएं जाती है, जिला पंचायत के द्वारा, जिले के अधिकारी के द्वारा, ब्लाकों के द्वारा और शहर में नगर पालिका के द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे विधान सभा मुगलसराय में जो भी ब्लॉक, नगरपालिका या जिला पंचायत के द्वारा योजनाएँ चलाई जा रही है, उसमें घोर अनियमितताएँ बरती जा रही है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उस पर एक उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए, जिससे गरीबों को उनका हक मिल सके। उनको उसका लाभ मिल सके। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे विधान सभा में रामनगर औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ पर हजारों हजार मजदूर काम करते है और वहाँ पर उनको आज भी 12 घंटे काम कराया जाता है और मजदूरी उनको तीन हजार से साढ़े तीन हजार दी जाती है। मैं आपसे इसके लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि उसकी भी जाँच कराई जाए। वहाँ पर लेबर आफिसर एवं अन्य अधिकारी सब निष्क्रिय पड़े हुए है। इसकी जाँच कराकर उनकी पूरी मजदूरी उनको दिलाई जाए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुगलसराय विधान सभा में नगर पालिका मुगलसराय उ0प्र0 की सबसे बड़ी नगर पालिका परिषद का दर्जा प्राप्त है और वहाँ पर नाली की व्यवस्था आज भी नहीं हो पाई है। दर्जनों गाँव ऐसे है, मुगलसराय से सटे हुए कि उनमें आज भी पानी का निकास नहीं हो पाता है और गर्मी के महीने में भी वहाँ पर पानी भरा रहता है, जिसकी निकासी के लिए वहाँ पर कोई सुनिश्चित व्यवस्था करायी जाए। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में बिजली की स्थिति यह है कि हमारा जो मुगलसराय चन्दौली का जो शहरी क्षेत्र है, वहां पर बिजली का 21 घंटे का शेड्यूल बना है लेकिन 11-12 घन्टे ही बिजली मिलती है। शेड्यूल के हिसाब से वहां पर बिजली दी जाय। गांव के क्षेत्रों में

भी शेड्यूड के हिसाब से बिजली का प्रबन्ध करा दिया जाए, मान्यवर, मैं इसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगा। मान्यवर, वहां पर सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या यह है कि आज 6 महीने हो गये हैं, हमने गांव की निधि से बिजली के लिये पैसा देने का जो प्रस्ताव भेजा था, आज भी वहां के अधिशासी अभियन्ता प्रथम चन्दौली के द्वारा बिजली के सम्बन्ध में कोई भी आगणन/इस्टीमेट बनाकर नहीं पेश किया गया, जिससे कि धन अवमुक्त नहीं किया जा सका है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी योजनायें बिजली के नाम पर चन्दौली में गई हैं, उसमें घोर अनियमिततायें हुई है। जमीन पर काम नहीं हुआ है, जिसको मैंने लिखित रूप में मा0 मुख्यमंत्री जी को भी दिया है और जिलाधिकारी को भी दिया है, लेकिन आज तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ है। मान्यवर, मैं उसकी जांच चाहता हूं, उसकी जांच कराकर जो भी दोषी हैं उसको दण्डित किया जाय। मान्यवर, मगुलसराय से सटा हुआ बाईपास है, हाई-वे है, हाई-वे से लगा होने के कारण बहुत सारा ट्रैफिक वहां जाता है। बिहार से सटा हुआ हमारा बार्डर का एरिया है, वहां पर बहुत ज्यादा ट्रकों का आवागमन है। मान्यवर, वहां पर आर0टी0ओ0 द्वारा प्रतिदिन जिस तरह से जांच हो रही है। वहां पर 6 महीने में दर्जन पर लोगों को ट्रकों से कुचले जा चुके हैं। वे आते हुये ट्रक को किसी भी रास्ते से किसी भी तरीके से रोकते हैं, जिसके डर से ट्रक वाले गाड़ी को भगाते हैं और दर्जनों वहां पर मौतें हो चुकी है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि इसकी भी जांच कराई जाये और इसका भी ब्यौरा मंगवाया जाये कि किन-किन लोगों को वहां पर किस तरह से कुचला गया है। मान्यवर, उनका जो भी मुआवजा बन पड़े, उसको दिलाने का काम सरकार के द्वारा करायें। मान्यवर, वहां पर जो हमारा शहरी इलाका है, मुगलसराय में वहां पर बहुत लोग आते हैं। मान्यवर, वहां पर जर्जर तार है और ट्रान्सफार्मर की भी व्यवस्था नहीं। ऐसा है कि वहां आये दिन ब्रेकडाउन में 4 से 5 घन्टे शहर में जो बिजली मिलती है उसमें भी कटौती होती है। मान्यवर, उसको सही तरीके से कराया जाय, हमारे यहां दर्जन भर गांव ऐसे हैं जो शहर से लगे हुये हैं, वहां नाली की व्यवस्था नहीं है, मैं चाहता हूं कि वहां पर पानी के निकास की व्यवस्था हो जाय, क्योंकि पानी के निकासी के उचित प्रबन्ध के अभाव में तमाम बीमारियों के होने के सम्भावना है। मान्यवर, हमारे यहां हैण्डपम्प के लिये जिला योजना से प्रस्ताव गया था लेकिन मान्यवर अभी तक कोई भी हैण्डपम्प नहीं लगाया गया है। अधिशासी अभियन्ता से सूची मांगी हैं लेकिन सूची भी उपलब्ध नहीं करायी गयी है कि किस वर्ष में कौन-कौन सी जगहों पर हैण्डपम्प लगाये गये हैं। मान्यवर जो अधिकारियों द्वारा लापरवाही की जा रही है इसको संज्ञान में लेते हुये कार्यवाही करायी जाय। मान्यवर हमारे क्षेत्र चन्दौली में विज्ञान स्तर की कालेज की स्थापना होनी बहुत जरूरी है। वहां एक मिनी स्टेडियम बनवाया जाय। बबूरी में हास्पिटल बनवाया जाय। खराब सड़कों को बनवाया जाय। धन्यवाद।

श्री सत्यवीर मुन्ना-

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, इधर दो दिन से पक्ष-विपक्ष की तरफ से कई बाते आ रही हैं। हमारे विपक्ष के साथी खासतौर से बी0एस0सी0 के साथियों ने जिस तरह से आरोप लगाये वह बहुत ही निन्दनीय है। अभी हमारे साथी राम लाल अकेला जी ने बहुत अच्छी बाते कहीं मान्यवर हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार जिस तरह से विकास के कार्य और जनहित के कार्य शुरू कर रही है वह अत्यन्त ही सराहनीय है। हमारी सरकार में जो विकास कार्य शुरू हुये हैं उनमें कुछ का उल्लेख करना चाहूंगा। मान्यवर, हमारी सरकार में सैटलाइट इमेजरी सिस्टम की स्थापना की जा रही है। इससे हमारा प्रदेश हाईटेक बनेगा और मान्यवर, जो तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं उनकी मानीटरिंग की व्यवस्था हो सकेगी। मान्यवर, मनरेगा स्कीम में देखा गया है कि काम हुआ या परन्तु नहीं उसकी कोई मानीटरिंग ठीक से नहीं हो पाती है। थ्री-डी सेट लाइट इमेजरी सिस्टम से भू-स्थलीय निरीक्षण का कार्य हो सकेगा और वास्तविकता सामने आयेगी। मान्यवर, हमारे प्रदेश में महिला हेल्प लाइन स्कीम प्रारम्भ की गयी है वह बहुत ही सराहनीय है। मान्यवर, मैं यह इसलिये बता रहा हूं क्योंकि जो पिछली बार यहां पर बी0एस0पी0 की सरकार थी उससे कुछ अलग हटाकर हमारी सरकार में काम हो रहे हैं। मान्यवर, इलाहाबाद में राज्यस्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात हमारी सरकार ने कही है उसके लिये मा0 मुख्य मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं मेजों की थपथपाहट। मान्यवर, इलाहाबाद को बेहतर (के चौराहों पर) ट्रैफिक सिस्टम के लिये चुना गया है और वहां सी0 सी0 टी0 वी0 लगेगें यह बहुत सराहनीय काम हो रहा है। मान्यवर, वेहिकल ट्रैफिंग रिस्पांस सिस्टम इलाहाबाद में बेहतर पुलिसिंग हेतु लागू किया जा रहा है वह सराहनीय है मान्यवर, हमारे सोरांव विधान सभा क्षेत्र में 108 एम्बूलेंस सेवा चालू हुई है, अभी वहां पर एक बच्चा बोर बेल में गिर गया और घायल हो गया था, मैं उस समय अपने क्षेत्र में था मैने देखा कि मेरे पहुंचने से पहले ही वहां एम्बुलेंस सेवा पहुंच गयी थी। मान्यवर, मेरा क्षेत्र इलाहाबाद-प्रतापगढ़ हाई-वे से लगा हुआ है इसलिये वहां पर एम्बुलेंस सेवा के विस्तार की जरूरत है। मान्यवर, बेसिक शिक्षकों को कोषागार से पेंशन देने की नीति बनाई गयी है वह सराहनीय है इसी तरह से सरकार जो कर्मचारियों को ई-पेमेण्ट के द्वारा सेलरी देने की व्यवस्था कर रही है वह भी बहुत, सराहनीय कदम है उससे पारदर्शिता बढ़ेगी। मान्यवर, हमारे सोरांव विधान सभा क्षेत्र के तहसील हेतु 33/11 के0वीए0 विद्युत उप केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति जो हमारे सरकार ने उपहार स्वरूप दी है उसके लिये हमारे सोरांव विधान सभा क्षेत्र की पूरी जनता इस सरकार के प्रति आभार प्रकट करती है। मान्यवर, इलाहाबाद के गंगापार में कोई भी पर्यटन क्षेत्र नहीं हैं पर्यटन स्थल का अभाव है मान्यवर हमारे विधान सभा क्षेत्र से मनसईता नदी प्रवाहित होती है। किराव से लेकर सिकन्दरा

तक उसका बहुत अच्छा प्रवाह है और उसके अगल बगल अगर उसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाय, बहुत ही अच्छे पर्यटन के क्षेत्र में के वे रूप में उसका विकास हो सकता है। साथ ही मऊआइमा कताई मिल हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी कताई मिल थी और 70 के दशक से यहां पर हजारों कर्मचारी अपना रोजगार प्राप्त करते थे लेकिन बहुत ही दुख का विषय है कि वह कताई मिल बन्द हो गयी वहां के कर्मचारियों का लाखों करोड़ों का बकाया है उसको भी दिलाया जाय और इस मऊआइमा कताई मिल को फिर से शुरू करने का काम किया जाय। यह आग्रह करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र उमरन ताल ड्रेन है जो बहरिया ब्लाक में है। वहां पर वाटर लागिंग की बहुत बड़ी समस्या होती है और हजारों एकड़ जमीन किसानों की जलमग्न हो जाती है उसकी भी सफाई और खुदाई की जाय इसका मैं आग्रह करता हूं। इसके साथ ही मऊआइमा एक बड़ी टाउन एरिया है वहां पर 100 शैय्या के अस्पताल की मांग करते हुये आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राघव लखनपाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर मैं बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, पिछले 3-4 दिनों से जिस गुम्बज के नीचे हम बैठे हैं, बाहर से मैं देख रहा था कि इस गुम्बज की छत पर बहुत सारे काले कौए आकर जमे हुये थे और जब मैं अन्दर दाखिल होने लगा तो एक सज्जन मुझे दिखे तो मैंने पूछा कि भाई इतने कौए क्यों आये हैं तो वह बोले कि एक फिल्म थी राजकपूर साहब की और उसका एक गाना था झूठ बोले कौआ काटे। तो शायद वह इस कारण से पिछले 3-4 दिनों से यहां इकट्ठे हो रखें हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप कोई भी विभाग उठा लीजिये यह जो अभिभाषण है, कोई भी विभाग उठा लीजिये और मैं अपने गृह जनपद से उसकी तुलना कर लूं। आप बात करिये नगर विकास की आप आइये मेरे गृह जनपद में, आप आइये मेरी विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर में देखिये। चाहे कोई पाश कालोनी हो, चाहे कोई बस्ती हो और चाहे कोई नई बसी हुई कालोनी हो, सब जगह समस्याओं का अम्बार लगा हुआ है। जिस प्रकार से जलभराव है, जल आपूर्ति नहीं है, सीवरेज नहीं है, सड़के नहीं है, पथप्रकाश नहीं है और सुरक्षा तो किसी रूप में ही ही नहीं चाहे आप गृह विभाग की बात कर लें चाहे आप ऊर्जा विभाग की बात कर लें यह कहना कि हमने 17 से 22 घन्टे बिजली शहरी क्षेत्रों को दिया है सहारनपुर जनपद में 8 से 10 घन्टे से ज्यादा बिजली नहीं आई है। सहारनपुर नगर की मैं बात कर रहा हूं। यह कहना कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों को 10 से 12 घन्टे बिजली दी है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सहारनपुर जनपद क्षेत्र के जो गांव हैं वहां 5 से 6 घन्टे बिजली आई है इससे ज्यादा बिजली वहां है नहीं आई है यही सत्य

है यह कटु सत्य है और जब तक असत्य पर हम बैठे रहेंगे तक तक प्रदेश का उद्धार होने वाला नहीं है। मान्यवर, चिकित्सा शिक्षा की बात हो रही है पिछली सरकार द्वारा सहारनपुर को एक मेडिकल कालेज दिया गया था हम बहुत खुश हुये और सोचा कि अब शायद सहारनपुर किसी गिनती में आयेगा और सहारनपुर की तरक्की होगी वह बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और उसमें अभी तक कालेज प्रारम्भ नहीं हुआ है और वह धीरे-धीरे खंडहर बनती जा रही है। न जाने क्यों सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। मान्यवर, बात करें किसानों की तो एक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं चौतिसवे राष्ट्रपति थे डुवाइट डी आइज़न हॉवर उन्होंने एक बात कहीं थी मैं उसको अंग्रेजी में कहकर फिर उसका अर्थ हिन्दी में भी बताऊंगा। फार्मिंग लुक्स माइटी ईजी व्हेन योर प्लावो इज ए पेन्सिल एण्ड योर ए थाउजेण्ड माइल्स फ्राम दी कार्न फील्डस यानी कि जब आपके हाथ में हल की जगह कलम हो और जब आप खेतों से हजारों मील दूर बैठे हों तो खेती बहुत आसान नजर आती है लेकिन वास्तविकता क्या है उस किसान से जाकर पूछिये जो अपने खून और पसीने से धरती को सींचता है, अपने खून और पसीने से उस फसल को तैयार करता है और जब उस फसल को बेचने जाता है तो उसे उस फसल का सही मूल्य नहीं मिलता और यदि कहीं मूल्य कोई घोषित होता है तो उसका भुगतान नहीं होता। मान्यवर, पश्चिम क्षेत्र में विशेष रूप से सहारनपुर में गन्ना किसान अधिक मात्रा में हैं, वहां प्रमुखता से गन्ने की खेती होती है और इतनी ज्यादा समस्यायें वहां पर हैं, समय इतना कम है इसलिये मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगा। गन्ना मिलों द्वारा किसानों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। डेढ़ से दो और तीन महीने तक का भुगतान सहारनपुर में चीनी मिलों द्वारा नहीं किया गया है और मेरे साथी सदस्य ने कहा था कि कोर्ट द्वारा जो आर्डर है कि 14 दिन के अन्दर भुगतान न हो तो मिल के खिलाफ आर0सी0 जारी कर देनी चाहिये, लेकिन आर0सी0 जारी नहीं होती है। गन्ना क्रय केन्द्रों का जो किराया है, पिछली सरकार में शायद 5 रुपये 75 पैसे था अब 8 रुपये 75 पैसे कर दिया गया है और यह सब जानते हैं कि उसके पीछे क्या षड़यंत्र है। यहां क्योंकि संसदीय भाषा का प्रयोग करना है, इसलिये मैं बहुत कुछ बात नहीं कह पा रहा हूं लेकिन आप भी जानते हैं और यह लोग भी जानते हैं और प्रदेश की जनता भी जानती है कि सच्चाई क्या है और किस प्रकार से चीनी मिलों के साथ सॉठगांठ की गयी है। मान्यवर, घटतौली की समस्या होती है, चीनी मिलों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। यह कह देना कि हमने गन्ने को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है, मेरी सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के किसानों का व्यापक हित समर्थन है तो मुझे तो इस सबसे यह कहीं नजर नहीं आता। एक माननीय सदस्य ने बात कही, इजराइली माडल की। इजराइली माडल का बेसिस क्या है, उसका आधार क्या है। उसका आधार है, एक को-आपरेशन, एक कोलेबरेशन, और तीन पहलुओं का मर्जर। यानि सरकार का, कृषि वैज्ञानिकों का, जो उस पर रिसर्च करते हैं और किसान का, लेकिन यहां किसी

प्रकार का कोई कोलेबरेशन नहीं है। यहां कोलेबरेशन है तो गुन्डों का, बदमाशों का और कही न कहीं उनसे मिले हुये नेताओं का। माननीय अध्यक्ष जी, एक कहावत है, दो पंक्तियां है कि-

''नदी के तट पर यदि भ्रष्ट नेता बस जायें
तो प्यासे लोग पानी को तरस जायें
नहीं चलती मौसम पर इनकी हुकूमत
वरना सारे बादल इनके खेतों में ही बरस जायें''।

और यह वास्तव में स्थिति है कि शायद वह ईश्वर ही है जो इनके बहकावे में नहीं आते और ईश्वर है इसलिये उन्हें प्रदेश की और देश की जनता की चिन्ता है। तो मैं आपसे यही करना चाहूंगा कि इजराइली माडल जो है, हम इजराइली माडल को छोड़ दें एक सेकेंड के लिये, हम इतना दूर क्यों जा रहे हैं। हम गुजरात क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाकर देखते कि गुजरात में किस प्रकार से 10 प्रतिशत कृषि विकास दर पिछले 10 वर्षों से मेन्टेन है और यह 10 प्रतिशत से भी ऊपर गई है बीच के वर्षों में। क्यों गई है, क्योंकि सार्थक कदम उठाये गये हैं। क्यों, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी है, प्रशासनिक स्पष्टता है और जब तक प्रशासनिक स्पष्टता नहीं होगी तब तक आप कोई योजना ले आइये, आप कोई नीति बना लीजिये, वह कारगर नहीं हो सकती। वहां जिस प्रकार से हर वर्ष कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाता है, कृषि रथ निकाले जाते हैं, किसान के द्वार तक वह रथ पहुंचता है और वह रथ किसी पार्टी का लिट्रेचर बांटने वहां नहीं जाता, बल्कि उस रथ में कृषि वैज्ञानिक होते हैं, रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वह जाते हैं और बात करते हैं किसान से ओर पूछते हैं उसकी समस्या। स्वायॅल हेल्थ चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि वह जो भूमि है उसका स्वास्थ्य कैसा है और उसको सुधारने के लिये क्या-क्या करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, गुजरात में पिछले कुछ वर्षों में 15 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है और एक लाख से ज्यादा चेक डैम्स वहां बनाये गये हैं। बहुत सी बाते हैं बताने को, जैसे ज्योति ग्राम योजना, हमारे अभिभाषण में भी लिखा है कि 15 जनपदों में जो किसानों के लिये बिजली फीडर है, उन्हें अलग कर दिया जायेगा, जबकि पूरे गुजरात में किसानों के लिये अलग फीडर पहले से है और उसके कई बेनिफिट्स हैु, कई फायदे उसके हैं। एक तो उससे स्थिर वोल्टेज मिलती है, किसान फसलों की सिंचाई कर पाता है और उसके साथ-साथ उसके जो पम्प हैं, उसके जो उपकरण हैं, वह फुंकते नहीं हैं, जलते नहीं है, उसे नुकसान हानि नहीं होती। इससे वहां का किसान खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। जब हम अपने भारतवर्ष में एक क्षेत्र में 10 प्रतिशत विकास दर कृषि में पा सकते हैं तो यहां पर हम 5 प्रतिशत विकास दर पाने के लिये इतना तरस रहे हैं आखिर क्यों ? आखिर कहीं न कहीं किसी न किसी की कमी तो है, मैं यह नहीं कह रहा कि सारी कमी अब बैठी हुयी

सरकार की है, कमी पिछली सरकार की भी है और शायद उससे पहले भी रही हो, मैं नहीं जानता यह बात। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि यदि सही मायने में जिसके हाथ में ताकत हो, अगर वह कुछ करना चाहे तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है...मेरा तो बस यही आपसे निवेदन है कि आप सरकार को यह सुझाव दें कि एक सपोर्ट सिस्टम एक ऐसी समर्थन प्रणाली हमें किसानों के लिये स्थापित करनी पड़ेगी जिसके तहत् उन्हें सही मूल्य, लाभकारी मूल्य प्राप्त हो। चूंकि आपके ही माननीय नेताओं ने चुनाव के दौरान यह कहा था कि कम से कम तीन सौ रुपये गन्ना मूल्य घोषित होगा और जो भी केन्द्र सरकार का गेहूं मूल्य होगा उस पर हम दो सौ रुपये बढ़ाकर देंगे लेकिन इस प्रकार की अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई। जो गन्ना मूल्य घोषित किया है, किसान की लागत साढ़े तीन सौ रुपया प्रति क्विंटल है बताइये वह क्या करेगा दो सौ सत्तर, दो सौ अस्सी रुपये में। मान्यवर, कम से कम चार साढ़े चार सौ रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य घोषित होना चाहिये था। मेरा एक और सुझाव है सरकार के लिये कि यदि कृषि विकास दर बढ़ानी है तो कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा। इससे मेरा मतलब है कि ऐसे इस्टीट्यूट्स एडाप्ट करने पड़ेंगे, ऐसे प्राईवेट पार्टनरशिप के लोगों को इसमें लाना पड़ेगा जो कृषि निर्यात को बढ़ावा दे सकें, एग्रो प्रोसेसिंग की यूनिट लगा सकें और ऐसी कम्पनियों को लाया जाय जो रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर यानि कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुनियादी ढाँचा है उसको मजबूत करने का काम करें, जब तक हम इस ओर कदम नहीं उठायेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आज गुजरात में 99 प्रतिशत गांव, 99 प्रतिशत लिखिये यह बहुत बड़ा फीगर है छोटा नहीं है, मान्यवर, 99 प्रतिशत गांव आपस में पक्की सड़कों से जुड़े हैं, इसलिये गुजरात तरक्की पर है, इसीलिये गुजरात खुशहाल है। माननीय अध्यक्ष जी, कहने को बहुत सी बातें हैं, बहुत से सुझाव हैं, यहां किसानों के लिये मार्केटिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है कि वह किस प्रकार से अपना प्रोड्यूस बाजार तक ले जाएं या मिलों तक ले जाएं। यहां जो गुणवत्ता वाले उन्नत बीज हैं उनको लेकर यहां लिख दिया गया कि भाई यहां पर शोध चल रहा है लेकिन मैं जानता हूं कि अर्ली ब्राइटी का गन्ना जो पहले हमारे क्षेत्र में भरपूर मात्रा होता था आज वह न के बराबर रह गया है। वहां पर जो गन्ना उत्पाद भी है, उसका यदि आप पिछले दो-तीन वर्षों तक लगभग 25 से 30 प्रतिशत गिर गया है। तो यह आंकड़े मुझे नहीं पता कि किस प्रकार से ऐसी विकास दर की ओर ले जाने वाले हैं मान्यवर, 10 प्रतिशत तो बहुत दूर है, हम 5 प्रतिशत कब अचीव करेंगे, 6 प्रतिशत कब अचीव करेंगे, यह सोचने का विषय है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि हर चीज को पक्ष और विपक्ष के रूप में न लेकर कुछ हेल्दी डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं एक स्वस्थ लोकतंत्र को अपनाइये और जो अच्छे सुझाव हैं उन्हें लीजिये। मैंने पिछले अपने अगस्त के भाषण में औद्योगिकीकरण पर बात रखी थी और मैंने गुजरात का उदाहरण देते हुये कहा था कि वहां पर वाइब्रेन्ट गुजरात समिट होता है हर साल और मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपने

आगरा समिट कराया, मुझे नहीं पता कि उसका परिणाम क्या निकला। लेकिन मेरा आग्रह है कि आप लखनऊ, सैफई और न जाने कहाँ-कहाँ महोत्सव तो करा ही रहे हैं दो महोत्सव आप हर वर्ष करायें, ऐसा महोत्सव जिसमें आप हर बार अलग जनपद में जाएं और वहाँ किसानों को इक्टठा करें, यह कोई राजनैतिक कार्यक्रम न हो, किसी झण्डे के तले न हो, केवल मंत्रियों के भाषण देने की जगह न हो बल्कि वहाँ वास्तव में कृषि वैज्ञानिक आयें, ऐसे एक्सपर्ट आयें जो किसानों को सही राय दे सकें। और उनकी मदद कर सकें इस प्रकार से वह सपना साकार हो सकता है जिसे साकार करने के लिए हम सब यहां पर बैठे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर रखें गये संसोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

(कई मा0 सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

एक माननीय सदस्य सत्ता पक्ष से और एक मा0 सदस्य विपक्ष से इसी प्रकार से सभा को बोलने का मौका मिलेगा।

श्री हेमराज वर्मा-

मान्यवर मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है। उस सरकार की नीतियों के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो बताया, मै अपने आपको उससे सम्बद्ध करता हूँ। जिस तरह से आज हमारा यू0पी0 आगे बढ़ रहा है यदि पहले भी इसी तरह से काम हुआ होता तो शायद आज हमारा उत्तर प्रदेश कहीं आगे होता। अभी भाजपा के माननीय सदस्य जी ने अपने भाषण में गुजरात का जिक्र किया, बड़ी तारीफ उन्होंने गुजरात की। मैं उनसे जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से आपका कार्यकाल भी यू0पी0 में रहा है, उत्तर प्रदेश में आपकी भी सरकार रही हैं क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को कितना आगे बढ़ाया है। सिवाय हमारे उत्तर प्रदेश में जाति धर्म के नाम पर धर्म सम्प्रदाय के नाम पर लड़ाने के अलावा, जनता से झूठे वादे के अलावा कोई भी दूसरा काम नहीं किया है और आज उदाहरण दे रहे हैं गुजरात का। जिस तरह से भाजपा के माननीय सदस्य ने अपना पूरा भाषण गुजरात पर उतारा है, काश उन्होंने जो भाजपा का कार्यकाल उ0प्र0 में रहा है उसकी चर्चा भी की होती । आज हमारी सरकार ने जिस तरह से उन बहुत से गांवों को जो 250 की आबादी के ऊपर के हैं जिनको अभी तक सड़क मुहैया नहीं हो पायी है। हमारी सरकार की योजना में उन गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया है, इसका उदाहरण और कहीं नहीं मिलता। आज 108 एम्बुलेन्स सेवा (समाजवादी स्वास्थ्य सेवा) की शुरूआत हुई है जबसे यह सेवा शुरू हुई है उससे पीछे का समय देखना चाहें । ऐसी बहुत

सी महिलाएं, ऐसे बहुत से एक्सीडेण्टल लोग जो रास्ते में अपना दम तोड़ दिया करते थे। आज 108 एम्बुलेन्स सेवा (समाजवादी स्वास्थ्य सेवा) का लाभ उनको तुरन्त मिलता है और वह नजदीकी अस्पताल तक उसके द्वारा पहुँच रहे हैं। आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह से 36,000 रूपये की सालाना आय पर गरीबों को आवास मुहैया कराने की बात कही है। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे परिवार जो आग से पीड़ित होते हैं उनके घर जल जाते हैं लेकिन बी0पी0एल0 सूची में नाम न होने की वजह से उनको आवास नही दे पाते, हमारी सरकार ने ऐसे परिवारों को आवास देने की बात कही है वास्तव में उसका लाभ लोगों को मिलेगा, इससे बहुत सारे परिवार लाभाविन्त होंगे। आज जिस तरह से सिंचाई के लिए, मै अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से इस बार नहरों की सफाई हुई है जीवन में कभी भी इस तरह से नहरों की सफाई नहीं हुई है। हमारे क्षेत्र के लोग कहते हैं कि दूसरी सरकारों ने भी काम किया है। लेकिन जब से नहरे खुदी है। तब से इतनी अच्छी सफाई आज तक कभी नहीं हुई है, आज नहरों को बिल्कुल नया रूप दिया गया है। जिस तरह से हमारे नेता मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, निश्चित रूप से उनकी सोच इस प्रदेश को आगे ले जाने की है और जनता का सहयोग उन्हें निरन्तर प्राप्त हो रहा है। बहुत जल्दी ही हमारा उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों के मुकाबले कहीं आगे होगा। मैं अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में पीलीभीत जनपद, लखीमपुर और जनपद बरेली के बहेड़ी क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे बंगाली परिवार हैं जो बंगलादेश से यहाँ पर आये हुए हैं। उन्हें डी0आर0आर0ओ0 की जमीनें उपलब्ध करायी गयी हैं और वह तब से उन पर रह रहे हैं। बंगाली समाज की जो नमो शुद्र पौंड माझी जातिया है, उन जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए हम लोगों का प्रयास रहा है, हमारी सरकार का प्रयास रहा है। मेरा यह अनुरोध है कि जिस तरह से 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने की बात हमारी सरकार द्वारा की जा रही है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में पीलीभीत, लखीमपुर, बरेली के साथ-साथ पूरे प्रदेश में जहाँ-जहाँ बंगाली समाज के नमो शुद्र पौंड माझी परिवार के लोग रह रहे हैं उनको भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाए और उन परिवारों के पास जो उस वक्त डी0आर0आर0ओ0 की जमीनें दी गयीं, उन जमीनों का उन्हें संक्रमणीय भूमिधारी का अधिकार नहीं मिल पाया मेरा आपसे निवेदन है कि उन परिवारों को संक्रमणीय भूमिधरी अधिकार मिलना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है आज जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में एक युवा मुख्य मंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम निरन्तर हो रहा है बहुत ही कम समय में हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी

आगे बढ़ेगा। ज्यादा न कहकर मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे तीन दिन बाद बोलने का मौका दिया मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के खिलाफ और संशोधन के समर्थन में बल देता हूँ अध्यक्ष जी सरकार के समर्थन में जो एक घण्टे से दो घण्टे से दो दिन से सत्ता पक्ष के लोग जो कब्बाली कर रहे हैं और बसपा को बुरा बता रहे हैं बसपा वाले इन्हे बुरा बता रहे हैं अभी हमारे सहारनपुर के सदस्य ने जो बात कही वह व्यवहारिक बात यह है कि यदि सरकार की मंशा ठीक हो और बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार कदम उठाए हम बिजली चोरी के खिलाफ है लेकिन अध्यक्ष जी बिजली कनेक्शन देने की प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया जाय और उस प्रक्रिया में कनेक्शन को जरूरी कर दिया जाय तो बिजली चोरी ही नहीं रुकेगा बल्कि राजस्व भी बढ़ेगा। बिजली की लाइने बिछाने का काम भी होगा। माननीय अध्यक्ष जी विधायकों के साथ हो रहे भेदभावपूर्ण रवैये के बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्रों में कोई विकास का काम नहीं हो रहा है और जाति विशेष की बात कभी यह लोग कहते थे इनके लिए कभी यह लोग कहते हैं इनके लिए। सच्चाई यह है कि जाति विशेष की और व्यक्ति विशेष की जो दूरी थी वह कतई खत्म नहीं हुई है आज एक थाने का सिपाही चाहे वह डेड बाडियों का ट्रक भरकर जा रहा हो उसको हाथ नहीं देगा। लेकिन एक गरीब किसान वैशाख के महीने में या कार्तिक के महीने में दो पैसे बचाकर एक कोठरा बनाना चाहता है तो खनन के नाम पर उसका उत्पीड़न होता है अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी बैठे हैं बड़े अदब से यह बात कहना चाहता हूँ जो व्यवहारिक बात है पक्ष विपक्ष की बात नहीं है एक सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूँ खनन के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में विशेष कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थानाध्यक्षों द्वारा भूमाफियाओं और खनन माफियाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। और एस0डी0एम0 और ए0डीएम0 स्तर के अधिकारियों द्वारा उन ट्रालियों और ट्रैक्टरों को पकड़ कर रिश्वतखोरी का काम किया जा रहा है। यह किसी से छिपा नहीं है सत्तापक्ष के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। यह सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते लेकिन अच्छी बातें सरकार को घर बैठकर बता सकते हैं। अध्यक्ष जी एम0एल0ए0 और एम0पी0 की निधि का काम भी बाधित हुआ है मैं सोनभद्र के पहाडों से आने वाले सामान की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन एस0डी0एम0 व ए0डीएम0 जो हमारे विधान सभा क्षेत्र में ठेकेदार काम कर रहे हैं आपकी सरकार द्वारा रखें गये है उनको भी काम नहीं करने दिया जा रहा है प्रभारी मंत्रियों की परम्परा इंदिरा गाँधी के टाइम में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से मंत्रियों को प्रभारी बनाकर भेजने की परम्परा पड़ी।

आज उन प्रभारी मंत्रियों ने सारे नियम और कानून की धज्जियाँ उड़ा दी है। मुंह देखकर बात करते हैं। पार्टी के हिसाब से बात करते हैं विधायिका का कोई महत्व उन लोगों ने नहीं छोड़ा है। अध्यक्ष जी यह लोग कितनी अच्छी बातें करते हैं अध्यक्ष जी सत्ता पक्ष में अगर दम हो तो एक सर्वदलीय कमेटी बना दीजिए और गन्ना किसानों की घटतौली गन्ना किसानों के साथ हो रहा धोखा गेहूँ क्रय केन्दों का मामला धान खरीद का मामला यदि यह सरकार झूठा [XXX] हो तो नैतिकता के नाम पर बहुमत की सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। अध्यक्ष जी यदि मै झूठ बोल रहा हूँ तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूँगा आज चीनी मिलों पर गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है।

यह [XXX] बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी, आज घटतौली हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

[XXX] शब्द असंसदीय हैं। इसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

अध्यक्ष जी, मेरा अधिकार है बोलने का। आज यहाँ ओझा जी ने बात कही। कुम्भ मेले की बात कही। अध्यक्ष जी यदि यहाँ का बैंक लुटता है तो क्या वित्त मंत्री उसे बचाने आयेगा ? यदि रेल की पटरी उखाड़ी जायेगी तो क्या रेल मंत्री आयेंगे ? उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश के अन्दर सारी जिम्मेदारियाँ हैं। (शोर) ढाई सौ करोड़ का बजट इन्होंने प्रस्तावित किया। माननीय अध्यक्ष जी, 8 हजार रुपये करोड़ रुपये कुम्भ मेले में इस सरकार को देने का काम किया। अध्यक्ष जी, अच्छी बात सुनना इनको पसन्द नहीं है। (शोर) अध्यक्ष जी, यह बसपा को गाली दे सकते हैं और बसपा वाले इन्हें। लेकिन अध्यक्ष जी, हम सच्चाई की बातें कहना चाहते हैं आज पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़कों को काली करने के लिये बाजार में काला रंग खत्म हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पहाड़िया जी कुम्भ पर चर्चा लग गई है उसी दिन चर्चा करना।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

अध्यक्ष जी उनकी लिपाई पुताई करने का काम यह सरकार करे। माननीय अध्यक्ष जी, आज हास्पिटलों में दवा नहीं है। डाक्टर दवा बाजार से खरीद के ला रहे हैं। आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने बीमारी के बारे में कहा। कितना कम बजट का प्राविजन किया। इन्हें किसने रोका ? आज 10-10 हजार रुपये बीमार आदमियों के लाखों रुपये के खर्चे में

नोट-[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

क्या हैं। मैं मुख्य मंत्री के कार्यालय गया, मैंने देखा 10 हजार, 12 हजार, 8 हजार, 15 हजार। अध्यक्ष जी, आज यह जो....

श्री अध्यक्ष-

पहाड़िया जी, सुनो ना। आप सुन लो। आपके यह जो नियम बना है आपके विधायक निधि से आपको भी अब मरीजों को देने का अधिकार मिल गया है। तो आप उससे जो डेढ़ करोड़ है उससे दे सकते हैं।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

अध्यक्ष जी, उससे एक तरफ वाह वाही लूटते हैं कि विधायकों की क्षेत्र निधि बढ़ा दी और उसी में प्रोविजन करते हैं फायर सर्विस का, उसी में प्रोविजन करते हैं हेल्थ का। अध्यक्ष जी, यह विधायकों के साथ घोर अन्याय है। अध्यक्ष जी, आज इन्टर कालेजों में टीचर नहीं हैं, डिग्री कालेजों में टीचर नहीं हैं। आज अध्यक्ष जी गुन्डा, भू माफिया। अध्यक्ष जी, इनको बड़ा बुरा लगेगा, शोर मचायेंगे। जो बात यह कहते थे, कि मायावती जी के कार्यकाल में गुन्डागर्दी हो रही है। जिस यमुना एक्सप्रेस वे को आपने भी देखा है इन्हें चढ़ने नहीं दिया गया, इनकी साइकिलें तक नहीं निकलने दीं। आज अव्यवस्थित यमुना ताज हाई वे, वहां कोई सुख सुविधा नहीं है, टैक्स वसूला जा रहा है। अध्यक्ष जी, आज इनको कोई कहे, आज अध्यक्ष जी मुझको कहने में कतई संकोच नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लोग थाना और तहसील की दलाली पर उतारू हो गये हैं। (शोर) जो काम यह करते थे वही काम यह कर रहे हैं। आज अध्यक्ष जी, राजस्व मंत्री जी बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आज भूमिहीन किसान, भूमिहीन व्यक्ति उम्र उसकी 70 साल और उसको आय प्रमाण-पत्र अपनी बेटी और बेटा की शादी के लिये, वजीफा के लिये बनवाने के लिये 21 हजार से कम रुपया नहीं देना पड़ रहा है। अध्यक्ष जी, यह तो सरकार के सामने कसीदे पढ़ेंगे। इनकी तो आदत है। (शोर) अध्यक्ष जी, आज 21 हजार रुपया (सत्ता पक्ष की तरफ से व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने के लिये कहने पर) अध्यक्ष जी, आप व्यवस्था दीजिये। सत्ता पक्ष के लोग अगर इस तरह की बात करेंगे तो यह सदन की गरिमा के खिलाफ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, राजस्व मंत्री जी बैठे हैं। भूमिहीन, वृद्ध, दलित और पिछड़ी जाति का व्यक्ति जब जाति प्रमाण-पत्र या अनापत्ति प्रमाण-पत्र बनवाने जाता है जो अध्यक्ष जी, 21 हजार रुपये से कम नहीं देना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बन्द करिये।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

अध्यक्ष जी, एक मिनट चाहूंगा। अध्यक्ष जी, यदि हमारी बात पसन्द नहीं आ रही है। (शोर) देखिये अध्यक्ष जी, हमारा न सपा से कोई बैर है न बसपा से दोस्ती है। सच्चाई यह है कि नौकरशाही हावी है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है।

श्री अध्यक्ष-

अब बस हो गया। जाकर जेवर सुधारो।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। जाति विशेष की हद आज इस कद्र हावी हो गयी है उत्तर प्रदेश में कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। यदि इनकी सरकार की लोकप्रियता है अध्यक्ष जी, तो 2014 में इनकी सरकार की लोकप्रियता का आप सबको पता चल जायेगा। जय हिन्द जय भारत।

श्री अध्यक्ष-

मा0 पहाड़िया जी यह विधान सभा है कोई सार्वजनिक मंच नहीं है भाषण करने के बाद जय हिन्द, जय भारत नहीं कहा जाता है। लगता है आप चौराहे पर भाषण दे रहे हैं।

*डा0 अजय कुमार-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद। अभी हमारे साथी पहाड़िया जी कह रहे थे, काफी विषयों पर हमारे बहुत से साथियों ने चर्चा की। मैं जनपद इलाहाबाद को विलांग करता हूं। कुंभ के बारे में हमारे साथियों ने बड़ी आलोचना की। कुंभ की जो घटना हुई मैं समझता हूं कि उसके बारे में जितना हम लोग जानते हैं जितना इलाहाबाद जनपद के प्रतिनिधि जानते हैं शायद हमारे दूसरे जनपद के साथी इसको नहीं जानते हैं। उस सम्बन्ध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जिस संवेदनशीलता से काम लिया इसके लिये प्रदेश सरकार प्रसंशा का पात्र है। विशेषकर में इसके साथ एक शब्द और जोड़ देता हूं कि इलाहाबाद के निवासी, कुंभ को सफल बनाने के लिये, इलाहाबाद के सारे निवासी बधाई के पात्र हैं। तीन करोड़ लोगों को भोजन और पानी की सुविधा शायद प्रदेश सरकार भी उतनी अच्छी तरह से उपलब्ध न करा पाती जितने अच्छे ढंग से इलाहाबाद के निवासियों ने अपनी जिम्मेदारी इलाहाबाद का होने के नाते निभायी। हर चौराहे पर लोगों ने भोजन और पानी की व्यवस्था कराई। इसके लिये इलाहाबाद के लोग बधाई के पात्र हैं। उनकी भी मैं सदन में प्रसंशा करता हूं। मान्यवर, जिस दिन घटता घटित हुई।

श्री अध्यक्ष-

कुंभ पर चर्चा लगी है आप उस पर तब बोल लीजियेगा।

डा0 अजय कुमार-

मैं बता देना चाहता हूं यह देखें कि किसकी जिम्मेदारी है। यह कहते हैं कि रेलिंग टूट गई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस प्रशासन ने लाठी चार्ज बिल्कुल नहीं किया। बस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्हें रोकने को प्रयास किया। रेल प्रशासन के द्वारा ट्रेनों का तात्कालिक समय परिवर्तित करने के कारण जो भगदड़ हुई। उसके कारण यह घटना घटित हुई। हमारी सरकार ने तो जांच बैठा दी पूरा काम किया लेकिन आज मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूं बड़ी जोरदार भाषा में विरोध कर रहे थे इनका डी0आर0एम0, हम लोग दो बजे रात तक इलाहाबाद स्टेशन पर मौजूद रहे अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुये। इनका डी0आर0एम0, जी0एम0 मंडल अधीक्षक, एक भी रेलवे का अधिकारी मौके पर उपस्थित ही नहीं रहा। सब के सब भाग गये। घर छोड़ कर भाग गये कोई मोबाइल उठाने की तैयार नहीं। कोई फोन उठाने को तैयार नहीं, क्या आप अपनी सरकार के मुखिया से यह पूछेंगे, इसमें भी जिम्मेदारी तय करेंगे। उसके लिये कौन जिम्मेदार होगा। यह बहुत ही दुखद घटना है हम इस पर राजनीति न करें। हम किसी की आलोचना न करें कि सामूहिक रूप से जो घटना घटित हुई उस पर हम दुख व्यक्त करते हैं। आगे कोई ऐसी दुर्घटना न हो ऐसा प्रयास होना चाहिये। यह अस्थाई शहर है जिसमें तीन करोड़ लोगों की व्यवस्था करना, मैं समझता हूं चाहे इनकी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, मैं समझता हूं ऐसी व्यवस्था करना सम्भव नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो किया वह निश्चित रूप से सम्भव नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार उनके मंत्रीगण इलाहाबाद के निवासी, हमारे उत्तर प्रदेश के सभी साथी धन्यवाद् के पात्र हैं। इसके साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं हमारा विधान सभा क्षेत्र बारा है यह उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश से लगा क्षेत्र है मैं समझता हूं कि जिस तरह से बुन्देलखण्ड को सुविधा दी जाती है उसको भी देना चाहिये। हमारे यहां कमला पम्प नहर के दो फेज बन चुके हैं एक फेज बाकी है। वहां कम से कम दो ढाई बीघा जमीन असिंचित रह जाती है।.. और तीसरा फेज बाकी है, अगर वह तीसरा फेज बना दिया जाये तो मैं समझता हूं कि जो बुन्देलखण्ड से जुड़ा हुआ भाग है, उसमें अन्न उत्पादित करके प्रदेश और राष्ट्रीय हित में अपना योगदान दे सकते हैं और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय दिया है, उसके लिये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार बधाई की पात्र हैं। हम इलाहाबाद के लोग माननीय मुख्य मंत्री जी के सदैव ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे और निश्चित रूप से इलाहाबाद में कोई विश्वविद्यालय नहीं था, शिक्षा के क्षेत्र में, पठन-पठान में इलाहाबाद का जो इतिहास रहा है, जो महिमा रही है, उसको बढ़ाने में हमारी सरकार ने योगदान दिया है, इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी और उनके सहयोगीगण सभी बधाई के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री सुरेश बंसल-

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देने के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मै आपका आभारी हूँ। मै गाजियाबाद

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद के शहर से विधायक हूँ, पहली बार विधायक बना हूँ। मेरे क्षेत्र की एक सबसे बड़ी समस्या है कि मेरे शहर के बीचोंबीच रेलवे लाइन जाती है, इधर की तरफ विजय नगर है, जिसमें अधिकांश गरीब लोग रहते हैं, वह पूर्वांचल से आते हैं या दूसरे प्रदेशों से आते हैं या देहात से आये हुए लोग है, वह वहाँ रहते हैं। जिसकी आबादी 6 लाख है और शहरी आबादी 3 लाख है। इसकी कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ एक अण्डरपास है, वह इतना सकरा है कि उसमें घण्टों जाम लगा रहता है। हमने 2011 में जिलाधिकारी से निवेदन किया कि यहाँ रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज बनवाया जाय। उन्होंने रेलवे से पत्राचार किया और फिर रेलवे के अधिकारियों की एक समिति बनी और उसने अपनी रिर्पोट दी कि धोबी घाट पर ओवर ब्रिज बन सकता है। उसके लिए करीब 90 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान था और उसमें यह तय होना था कि कितना रेलवे देगा और कितना हमारा शासन देगा। मैने पहली बार भी हाउस में यह सवाल उठाया था, माननीय नगर विकास मंत्री जी जो हमारे जिले के प्रभारी है, जब हमारे जिले की मीटिंग में गए थे, सभी दल के नेताओं ने दलीय नीति से ऊपर उठकर मेरी बात का सर्मथन किया था और माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि यह ओवर ब्रिज बनेगा, परन्तु मुझे खेद है कि आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इस ओवर ब्रिज का बनना जनहित में, गरीब लोगों के हित में बहुत जरूरी है। माननीय अध्यक्ष जी, गाजियाबाद जिला जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, वहाँ इंजीनियरिंग कालेज बहुत हैं, डेण्टल कालेज बहुत हैं, लेकिन पिछले 20-25 वर्षो से वहाँ कोई डिग्री कालेज नहीं बना है। सरकारी डिग्री कालेज कोई है ही नहीं, प्राइवेट डिग्री कालेज भी किसी ने नहीं बनाया है, उन्होंने इंजीनियरिंग कालेज बनाये है, डेण्टल कालेज बनाये हैं। जो गरीब बच्चे हैं, उनको बी0ए0, बी0एस0सी0 और बी0काम0 करने के लिए कोई साधन नहीं है, एडमीशन होते नहीं हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि वहाँ पर एक डिग्री कालेज बनना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि विजय नगर क्षेत्र में लड़कियों का एक इंटर कालेज है, जिसकी 2000 की कैपिसिटी है लेकिन उसमें 3300 बच्चियाँ पढ़ती हैं, 2000 के पास फर्नीचर है, बाकी के पास फर्नीचर भी नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, जब यह बच्चियाँ इण्टर पास कर लेगी, कहाँ पढ़ेगी, कैसे शिक्षा का विस्तार होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सत्तापक्ष के लोगों से आप कहें कि वह दलीय भावना से ऊपर उठकर जनहित में मेरे क्षेत्र मे एक डिग्री कालेज जरूर बनवायें। इसके साथ ही विजय नगर क्षेत्र में जो गरीब लोग रहते हैं, वहाँ एक प्राइमरी हेल्थ सेण्टर है, उस पर एक महिला डाक्टर है और कोई डाक्टर नहीं है, कोई दवा नहीं है, गरीब लोगों के लिए यह बहुत जरूरी है। मेरा पूरा क्षेत्र नगर निगम में आता है, पीडब्ल्यूडी से एक पैसा नही मिलता, कहीं से कोई विकास के लिए कोई पैसा नहीं मिलता, नगर निगम से कहते हैं तो वह कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, कैसे विकास होगा डेढ़ करोड़ की जो निधि मिलती है, उसमें हम कितना काम करा सकते हैं।

हमारे क्षेत्र में बहरामपुर, डूंडाहेरा, विजयनगर आदि जो क्षेत्र हैं यह सब क्षेत्र ग्रामीण अंचल हैं जो इसमें मिल गया है। परन्तु वहा का विकास नहीं है। कहने के लिए महा नगर है, सबसे ज्यादा रेवन्यू देता है लेकिन यदि आप मेरे क्षेत्र विजय नगर की स्थिति देखें तो आप कहेंगे कि यह गांव से भी बद्तर है। वहाँ के विकास के लिए कोई व्यवस्था की जाये। हमारे क्षेत्र में तो सीवर है ही नहीं। शहरी क्षेत्र का 25 साल पुराना सीवर जाम हो गया है। उल्टा घरों में पानी बहता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में यह सुधार कराये जाये। टूटी फूटी सड़कों को बनवाया जाये, बच्चियों के लिए स्कूल बनवायें जायें और अस्पताल की व्यवस्था करायी जाये। मै आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ धन्यवाद।

साध्वी निरंजन ज्योति-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम श्री राज्यपाल जी अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मै आपका आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, पहले सत्र में हम चुनकर आये थे और शायद 27 जून में मैने बोला था। हमको बहुत बड़ी उम्मीद थी कि हम विधान सभा में पहुचेंगे और वहाँ पर पहुँचकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ मुद्दे उठायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जो उस बार वही इस बार भी मुझे दिखायी पड़ रहा है। यद्यपि मैं संत हूँ और संत की अपेक्षा होती है 'वसुधैव कुटुम्बकम्'। यदि हम जनता की दृष्टि से विकास पर विचार करें, चाहे बसपा की पार्टी रही हो चाहे आपकी पार्टी रही हो। मेरी पार्टी में पक्षपात नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहती हूँ। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा था। पूरी विधान सभा के अन्तर्गत किसी अस्पताल में दो डाक्टर, किसी में ताला पड़ा हुआ है और सदर अस्पताल में 25 डाक्टर कागजी तैनात हैं लेकिन वर्तमान में वहाँ 10 डाक्टर भी नहीं है। मा0 मंत्री से कहना चाहती हूँ सदर का अस्पताल उससे कानपुर नगर जो घाटमपुर विधान सभा है भोगिनीपुर विधान सभा के आधे लोग, आधे लोग जहानाबाद विधान सभा के आधे लोग तिन्दवारी विधान सभा के आधे लोग उस अस्पताल में पहुंचते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ की हड्डी टूट जाये तो उस हड्डी के आपरेशन के लिए कानपुर जाना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमीरपुर का जो सदर अस्पताल है वहाँ एक आई0सी0यू0 की व्यवस्था की जाये और एक हड्डी रोग विशेषज्ञ डाक्टर वहा तैनात किया जाये। यदि कोई महिला प्रसव पीड़ित है, खून की कमी हो गयी है तो उसको हमीरपुर में इलाज नहीं मिलता है और वह कानपुर जाते जाते दम तोड़ देती है। मैं उम्मीद करती हूँ और मैं होनहार मुख्य मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि 'यदि तुम ठान लो तारे गगन के तुम तोड़ सकते हो, यदि तुम ठान लो तूफान का पथ तुम मोड़ सकते हो, यदि तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में तुम एक नया अध्याय भी जोड़ सकते हो।' इस प्रदेश के विकास के लिए चिंतन

होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक और अनुरोध करना चाहती हूँ । लोहिया गांव का क्या मानक रखा गया है। लोहिया गांवों में इंटरलाकिंग, आर0सी0सी0, लाइट की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, यह मानक रखा गया है। मान्यवर मेरे क्षेत्र में जो गांव चिन्हित हुए है, दो गांव ऐसे हैं जिन गांवों में लाइट भी है, इंटरकालिंग भी है, आर0सी0सी0 भी बिछी है।, स्वास्थ्य केन्द्र भी है लेकिन कारण क्या है, वह गांव लोहिया गाँव चिन्हित हो गया है। ..माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यही अनुरोध करना चाहती हूं, हम सन्त चुन कर के आये हैं। जनता की भावनाओं को देखते हुये क्षेत्र में विकास के लिये मा0 अध्यक्ष जी, मा0 राजस्व मंत्री जी भी बैठे हुये हैं, आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूं कि हमारे जिले की प्रभारी मा0 अरूणा कोरी जी हैं, तीन बार जिले में गई हैं, एक बार भी हमको सूचना नहीं हुई। जिले की जिला योजना की बैठक या जिले में विकास की बैठक, मुझे जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी मिली कि सौ हैण्ड पम्प हमीरपुर विधान सभा में गये हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसके माध्यम से कहां लगने जा रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी मैं बहुत गम्भीरता से इस बात को कहना चाहती हूं कि यदि क्षेत्र में विकास होगा तो आपका नाम होगा, यदि जिले में अस्पताल बनेगा तो आपका नाम होगा, जिले में चिकित्सालय खुलेगा तो आपका नाम होगा, जिले में कोई आई0टी0आई0 खुलता है, कोई विद्यालय खुलता है तो आपका नाम होगा, विधायक तो सिर्फ एक माध्यम होता है सरकार का नाम होता है, इसलिये मै आपसे अनुरोध करती हूं और हमारे चिकित्सा मंत्री जी बैठे हुये हैं, उनसे एक निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में एक मेडिकल कालेज हमीरपुर जनपद में खोलने का कष्ट करेंगे तो महान दया होगी। आपको मा0 अध्यक्ष जी बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री वीरपाल राठी-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं यहां पर देख रहा हूं, चाहे सत्ता पक्ष के मा0 सदस्य हों, चाहे विपक्ष के मा0 सदस्य हों, जितने भी यहां सदस्य हैं, अभी सत्ता पक्ष का एक सदस्य बोल रहा था और उसने अम्बार लगा दिया कि पूरे प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है, अभी कहा कि सड़कों के लिये मा0 शिवपाल जी, लोक निर्माण मंत्री जी ने तमाम गड्ढे भर दिये, लेकिन बाद में बोलता-बोलता वह भी उसी समस्या पर आ गया जो विपक्ष के सदस्य बोल रहे हैं कि प्रदेश के अन्दर तमाम सड़कें जर्जर है, कहीं ट्रान्सफार्मर नहीं है। मुझे भी वही बात कहनी पड़ी, विपक्ष के भी वही बात कहते हैं और मैं यह बात कहना चाहता हूं कि चाहे विपक्ष का सदस्य हो, चाहे सत्ता पक्ष का सदस्य हो, जो बात इस सदन में रखें, उस पर अमल होना चाहिये। चिल्लाते होंगे हमसे पहले भी यहां पर सदस्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और आज हम भी चिल्ला रहे हैं। बहुत से मा0 सदस्यों ने यहां पर बात कहीं गन्ना पेमेन्ट की चर्चा की। मैं 95 दिन तक धरने पर रहा, 11 महीने की सरकार है, 11 महीने का मैं विधायक हूं और 95 दिन तक मैने मलकपुर शुगर मिल में धरना दिया। अरबों रुपयें की संख्या में उसका गन्ना पेमेन्ट था, कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की। हमने धरना दिया, धरने के बल पर हमने पेमेन्ट लिया। सरकार को चिन्ता होनी चाहिये थी कि किसानों का पेमेन्ट है, एक विधायक का पेमेन्ट नहीं है। आज भी वहीं हालात हैं 01 अरब 30 करोड़ रुपये के करीब उसी मलकपुर चीनी मिल पर बकाया है। पहले सदस्य भी चिल्लाते होंगे, मैं भी चिल्ला रहा हूं, आखिर क्या कारण है, आखिर क्या बात है कि सदन के अन्दर बात उठाते हैं, उस पर कोई अमल नहीं होता। घटतौली की चर्चा करते हैं, आजादी के बाद से लेकर आज तक घटतौली चल रही है, आखिर क्या बात है कि सदस्य यहां चिल्लाते हैं और उसके चिल्लाने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं मिल पाती। अभी एक सदस्य शिवालखास के कह रहे थे कि मा0 चौधरी अजीत सिंह जी के क्षेत्र से मैं आया हूं और वहां पर बहुत सी समस्याओं का अम्बार है। अब आप सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं आप करिये, आप विधायक हैं। 673 गांव पूरे प्रदेश के अन्दर हैं जनेश्वर मिश्र योजना में, मण्डल मेरठ में 32 गांव हैं और मेरा बागपत जिला शून्य है एक भी गांव नहीं है, उपेक्षा है बागपत जिले की और मैं तो यह कहूंगा कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा है। जो यहां बड़े-बड़े ओहदों पर बैठे हैं, वह अपनी मन-मानी करते हैं। यहां पर कोई सदस्य चुन कर के आता है उसका कोई औचित्य नहीं है। वह सदस्य अपनी बात रख सके, हम यहां भेंट कराने के लिये नहीं आये, हम यहां पर जनता की बात कहने के लिये आये हैं। अमल होना चाहिये यहां पर सदस्य की बात पर।...मान्यवर, बड़े अफसोस की बात है। मुझे कहना पड़ रहा है कि यहां पर सबने विद्युत की समस्या उठायी और कैसा कानून है, बसपा की सरकार में भी वही कानून और सपा की सरकार में भी वही कानून। चिन्तन-मनन होना चाहिये। ये चिन्ता होनी चाहिये कि यह कानून जनता के हित का है या नहीं है। अगर एक व्यक्ति के ऊपर 25 हजार का देय है तो क्या कानून है कि पर पावर के हिसाब से 400 पर किलो वाट के ऊपर उस पर एसेसमेण्ट लगाया जाता है, पुलिस को शमन शुल्क दिया जाता है। अगर वह 25 हजार रुपये नहीं दे पा रहा है तो वह 50 हजार रुपये कैसे देगा। पुलिस का डण्डा उसके पीछे है, ये कानून हैं, इस कानून को बदलना चाहिये। हमें इस बात से ऊपर उठना चाहिये कि हम विपक्ष के हैं या सत्ता पक्ष के हैं। हमें अगर सत्ता पक्ष का कोई ईमानदारी से काम कर रहा है तो मेज थपथपाकर उसका समर्थन करना चाहिये। मगर विपक्ष का कोई विधायक या विपक्ष का कोई नेता अपनी बात कर रहा है तो सत्ता पक्ष को ये कहना चाहिये कि ये वास्तव में एक सुझाव के रूप में है, उसे अपने पल्ले बांध लेना चाहिये और उस पैटर्न पर चलना चाहिये। अगर हम ऐसी व्यवस्था पैदा नहीं करेंगे तो इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। यहां पर बात करते हैं, अभी एक

मुस्लिम सदस्य थे, उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज पिछड़ा हुआ है। मैं बैठा-बैठा सुन रहा था उसकी बात, कौन सा ऐसा समाज है जो पिछड़ा हुआ नहीं है। यहां पर इस सदन में हम जाति की बात करें। मान्यवर, जाति की बात करना देश के लिये कलंक है, प्रदेश के लिये कंलक है। छोड़ो जाति की बात और प्रदेश में ऐसे कानून बनाओं, प्रदेश को ऐसी व्यवस्था दो। यहां पर हम कहते है, जितने भी उठते हैं, जो भी सदस्य उठता है कि बड़े ऊर्जावान मंत्री हैं, मुख्य मंत्री हैं। आज मुझे प्रदेश में कहने में संकोच नहीं है कि मायावती की सरकार को समाजवादी की सरकार से कहीं अच्छा बता रहे हैं लोग। ये हालात हैं आज प्रदेश के लेकिन हम जानते हैं कि वो सरकार कैसी थी और ये सरकार कैसी है। हमें परिवर्तन और भेद करना चाहिये, हमें ऐसे कानून बनाने चाहिये, ऐसी व्यवस्था पैदा करनी चाहिये कि जो जनता के हित में हो और जनता को एक अच्छा संदेश प्रदेश की सरकार दे। हमारे नौजवान मुख्य मंत्री हैं, हमें आशायें थी मुख्य मंत्री जी से। 10 वर्ष हो चुके हैं मेरे क्षेत्र में एक सड़क को टूटे हुये जिस पर काँवरिया चलते हैं, श्रद्धा के लोग चलते हैं, जिनकी श्रद्धा है। वह नहीं बन पाई आज तक 20 करोड़ रुपये का मेरे से पहले विधायक थे उन्होंने धरना भी दे लिया। मैंने कल मा0 शिवपाल जी से भी कहा कि मा0 मंत्री जी, मेरी दस वर्षों से सड़क खराब है। ये हालात हैं प्रदेश के और हम कुम्भ के मेले में इतना खर्चा करते हैं। क्या जरूरत है कुम्भ के मेले में इतना खर्चा करने की। अगर हम गरीब है, इस प्रदेश के अन्दर गरीबी हैं तो ऐसी व्यवस्था पैदा करो, जो रूस के अन्दर व्यवस्था थी और रूस के अन्दर क्या व्यवस्था थी कि जब जार नाम का प्रधानमंत्री था देश के अन्दर तो लेनिन ने वहां व्यवस्था बदली थी। जार की हत्या की थी और लेनिन ने ऐलान कर दिया था कि कोई 7 वर्ष तक जूता नहीं पहनेगा। जो मेरी ड्रेस होगी, वही जनता की ड्रेस होगी। पूरा देश पैदल चला था, जूता नहीं पहना था जितना कपड़ा था उसका व्यापार हुआ था, जितना चमड़ा था उसका व्यापार हुआ था। देश की व्यवस्था बदली थी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री वीरपाल राठी-

मान्यवर, तो व्यवस्था बदलिये। अगर यहां कोई भी विधायक चिल्लाता है। मेरे यहां चिल्लाने का कोई औचित्य नहीं तो मेरा औचित्य बनना चाहिये। मैं विधायक हूं, मेरा औचित्य बनना चाहिये। अगर मैं रो रहा हूं, मैं चीख रहा हूं तो आपको सोचना चाहिये। सरकार को गम्भीरता से उस प्रश्न को लेना चाहिये। बिजली का कानून है, आपके जिले के अन्दर और मेरे जिले के अन्दर अलग कानून और पूरे प्रदेश में अलग कानून। मैं कई बार सवाल लगा चुका हूं, मेरा सवाल इस सदन में नहीं आया। हाई पावर की वृद्धि कर दी गयी मेरे जिले के

अन्दर। कोई शासन में नहीं, मात्र एक छोटे से, अदने से अधिकारी ने कर दी बसपा की सरकार में। आपकी सरकार में भी वही रवैया, चिन्तन करो उस पर, मनन करो।...मनन करो, अगर वहां के लोगों के साथ अन्याय हुआ है तो उस अन्याय के बदले उनको लाभ देने का काम करो। मान्यवर, मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करके निवेदन करूंगा कि मेरी बात पर ध्यान दिया जायेगा और मैं संशोधन प्रस्ताव पर बल्कि मैं तो संशोधन और धन्यवाद प्रस्ताव, दोनों को मानता हूं। दोनों को ही मानना चाहिये अगर उनकी अच्छी बात है तो धन्यवाद भी होना चाहिये और अगर उनकी कोई खराब बात है तो उसमें संशोधन भी होना चाहिये। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री महावीर सिंह राणा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं सहारनपुर जनपद से, बहेट विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं। सहारनपुर जनपद के और मेरी विधान सभा क्षेत्र के तीनों ओर दूसरे प्रदेश हैं, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखण्ड। अभी हमारे विधान सभा सत्र में बात चल रही थी कि बहुत तरक्की की मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में, जो मा0 ओझा जी ने रखा था। अपने को नेता प्रतिपक्ष से सम्बद्ध रखते हुये मैं कहना चाहता हूं कि आप किसान परिवार से आते हैं। हमारी विधान सभा में लगभग 80 परसेन्ट सभी सदस्य किसान हैं, मा0 नेता सदन, मा0 नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ मंत्रीगण सभी कृषक परिवार से हैं। हमारे यहां से हरियाणा केवल 800 मीटर दूर है, यू0पी0 से। यमुना नदी की यह दूरी है। वहां पर किसानों को बहुत सुविधायें हैं। मैं चाहता हूं कि वह सब सुविधायें हम लोगों को भी, यहां के किसानों को भी मिले। मान्यवर, वहां पर 3 लाख से ऊपर 4 प्रतिशत पर ऋण मिलता है। मान्यवर, ब्याज दर 4 परसेन्ट है। मा0 राजस्व मंत्री जी बैठे हुये हैं, वहां पर 5 लाख तक सोसाइटी से लोन है। 5 लाख से ऊपर यदि लड़की की शादी करनी है, यदि ट्रैक्टर लेना है, मकान बनाना है तो एक हजार रुपये मात्र की रसीद कटती है। 1000/-रुपये की रसीद कटती है 5 लाख से ऊपर लोन में। यदि 10 लाख से अधिक लोन लेना होता है, किसान को अपने लड़के के लिये फैक्ट्री लगानी होती है तो 5000/-रुपये की मात्र रसीद कटती है। मैं चाहता हूं कि यह सुविधा, क्योंकि कृषक मुख्य मंत्री हैं हमारे, ये उत्तर प्रदेश के किसानों को भी मिले। जब हरियाणा में अष्टास स्टाम्प शुल्क किसान को कर्ज लेने में नहीं देना पड़ता है, तो यू0पी0 में क्यों ? इसको संशोधित करने का मैं आपसे अनुरोध करता हूं ताकि आप सरकार से संशोधन करायें इससे रोजगार बढ़ेगा। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 हमारे सहारनपुर से मा0 मंत्री जी बैठे हैं और सरकार के अन्य वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं, मैं अनुरोध करना चाहूंता हूं कि सहारनपुर में मेडिकल कालेज तैयार है, उस पर 322 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, मात्र 63 करोड़ रुपये की डिमाण्ड शेष है और इस बजट में भी वहां के लिये कोई

पैसा रखा नहीं गया यह बड़ी दुखःद बात है। यदि वह मेडिकल कालेज चलेगा तो सहारनपुर मण्डल के स्वास्थ्य सुविधाओं में उसका बड़ा योगदान होगा और बहुत कम रुपया शेष है मात्र 63 करोड़ रुपये बचा है, जबकि वहां सवा तीन सौ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में जहां 80 परसेन्ट बागान हैं। जंगल से लगा हुआ क्षेत्र है। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हरियाणा और उत्तराखण्ड में किसान के पेड़ काटने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यहां पर परमीशन है और 100 रुपये सिक्योरिटी और 200 रुपये टैक्स है। आम, शीशम, सागौन इत्यादि पर टैक्स है, जो हरियाणा में बिल्कुल नहीं है। उत्तराखण्ड में बिल्कुल नहीं है। लगभग डेढ़ लाख लोगों को रोजगार मिल जायेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यदि आरा मशीन का लाइसेंस फ्री कर दिया जाए। उससे प्लाईवुड की फैक्ट्रियां लगेगी। मा0 अध्यक्ष जी, हरियाणा में यमुना नगर में 700 के लगभग प्लाईवुड की फैक्ट्रियां हैं और लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किसानों की सरकार होते हुये इस पर प्रतिबन्ध क्यों है? ये प्रतिबन्ध हटना चाहिये ताकि किसानों के लड़कों को रोजगार मिल सके। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं मैं मुख्य मंत्री जी का बजट पढ़ रहा था उसमें डेरी लखनऊ में खोलने का प्राविधान किया गया है। सहारनपुर में पराग की सौ बीघा जमीन में डेरी है, जो बहुत अच्छी चलती थी, जो पचासों करोड़ रुपये से बनी हुई बिल्डिंग है, परन्तु पिछले 4 सालों से बंद पड़ी है। मेरा अनुरोध है कि यदि उसके लिये डेरी विभाग का पैसा दे दिया जाए तो वह डेरी बहुत अच्छी चलेगी और सहारनपुर में दूध का बहुत बड़ा प्रोडक्शन होगा। मा0 अध्यक्ष जी मेरा आपसे अनुरोध है कि किसान को उसकी उपज का सही मूल्य कई कारणों से नहीं मिल पा रहा है। उस पर मण्डी शुल्क है, जो नहीं होना चाहिये। मेरा आपसे अनुरोध है कि आज मा0 कृषि मंत्री जी, हमारे बीच नहीं बैठे हैं, जो हरियाणा में कृषि की पालिसी है। इसमें कोई रुपया सरकार का खर्च नहीं होना है, सिर्फ पालिसी को अधिग्रहण करना है। यदि हम हरियाणा की पालिसी ले लेंगे, उत्तराखण्ड की पालिसी ले लेंगे, भगवानपुर जो पहले हमारी विधान सभा का हिस्सा होता था। मान्यवर हरियाणा क्षेत्र में प्लाइवुड की फैक्ट्रियां लगी हैं, हमारे सहारनपुर से, बेहट क्षेत्र से लड़कियां वहाँ जाती हैं उसमें 12 रु0 कुन्तल किराया लग जाता है और पांच रुपये वन उपज के नाम पर निकासी का टैक्स लग जाता है। इस तरह से 38 रुपये फारेस्ट टैक्स के नाम पर लग जाता है। हमारा कहना यह है कि यह फारेस्ट रवना टैक्स को समाप्त किया जाय किसानों के हित में और यह प्लाईवुड फैक्ट्रियां बेहट में, सहारनपुर में स्थापित करायी जाय तो उससे लगभग डेढ़ लाख लोगों को रोजगार भी मिल जायेगा और किसानों को उनकी उपज का पूरा पैसा भी मिलेगा। मान्यवर, हमारे यहाँ वन विभाग जब किसानों को पेड़ नहीं देता है तो फिर यह उपज के नाम पर जो टैक्स लगता है उसको समाप्त कराया जाय। मान्यवर हमारे यहाँ बेहट से उत्तराँचल 22 कि0मी0 दूर है बीच

में जगंल का क्षेत्र है, मान्यवर बेहट में सिंचाई विभाग का जो खारा प्रोजेक्ट बादशाही बाग में था उसमें काम करने वाले लोगों के बच्चों के पढ़ने के लिए इण्टर कालेज की स्थापना हुई थी मान्यवर, वहाँ से इण्टर कालेज से टीचर और प्रिन्सिपल उत्तराँचल में चले गये हैं । बेहट से 22 कि0मी0 तक कोई इण्टर कालेज नहीं हैं हम चाहते हैं कि सरकार उस इण्टर कालेज के भवन को सिंचाई विभाग से अधिग्रहीत कर ले और शिक्षा विभाग को दे दे तो उससे हजारों बच्चों को पढ़ने का मौका मिल जायेगा। मान्यवर इसी तरह से खेती करने के लिए रूटावेटर पर पचहत्तर हजार की छूट है और हैरो टीलर पर धान लगाने की व गेंहूं कटान की मशीन पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी है हरियाणा में। हम चाहते हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी किसानों के हित में हरियाणा की तर्ज पर इस सब्सिडी स्कीम को लागू करे। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में मेरे सुझाव जुड़वा दिये जायें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं सहारनपुर की जनता सरकार से जानना चाहती है कि वहां मेडिकल कालेज कब चालू होगा। उसे चालू कराने का कष्ट करें। धन्यवाद

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

मान्यवर माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखें गये धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधनों पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी। आप कल बोल लीजिएगा।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम 51 की सूचनाओं को लेता हूँ। आज दिनांक 20-2-2013 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 48 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत अमवा ए0पी0 तटबन्ध का एक्सटेंशन के लिये केन्द्र सरकार द्वारा उपलबध करायी गई धनराशि में की गई अनियमितता की जांच कराये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दूसरी सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की जनपद सीतापुर स्थित दुलारी देवी राधे श्याम डिग्री कालेज बरई जलालपुर की मान्यता संबंधी पत्रावली शासन के काफी दिनों से लम्बित होने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

तीसरी सूचना श्री विजय कुमार दुबे की जनपद कुशीनगर की खड्डा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आई0पी0एल0 शुगर मिल द्वारा कमजोर किसानों की पर्ची रोक कर गन्ना माफियाओं को दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

चौथी सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील मिलक ग्राम तिराह में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराए जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

पांचवी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा) की जनपद वाराणसी स्थित बी0एच0यू0 हास्पिटल में हीमोफीलिया रोगियों की प्राण रक्षक दवा (फैक्टर 8 व 9) न उपलब्ध कराएं जाने से हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

छठी सूचना साध्वी निरंजन ज्योति की जनपद हमीरपुर के थाना सिसोलर के ग्राम गढ़ा में दो नाबालिग लड़कियों के साथ दुराचार करने वाले अपराधियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

सातवीं सूचना श्री राजेश अग्रवाल की बरेली महानगर घोषित होने के उपरान्त भी बिजली पानी सड़क आदि मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

आठवीं सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की बहराइच स्थित जरवल रोड से नैपालगंज रोड की सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

नौवीं सूचना श्री अगयश राम शरन वर्मा की पीलीभीत स्थित पंचायत विलसण्डा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दसवीं सूचना श्री भीमप्रसाद सोनकर की जनपद अम्बेडकरनगर के आलापुर अन्तर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना के कार्यों में अनियमितता किये जाने के संबंध में है, शासन का ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

ग्यारहवीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी की आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के यूपी अरबन प्लानिंग एण्ड डेवेलपमेन्ट एक्ट के अनुसार विवादित भूमि का मानचित्र स्वीकृत किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, शासन का ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

बारहवीं सूचना श्री अजय मिश्रा 'टेनी' की जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र निघासन के अन्तर्गत ग्राम सभा स्तर पर विद्यालयों के निर्माण आदि हेतु बनी समिति में ग्राम प्रधान व अन्य जनप्रतिनिधियों को शामिल करने के संबंध में है, शासन का ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

तेरहवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड निगोही अन्तर्गत ग्राम रधवापुर मृतक राम निवास वर्मा के परिवार को कृषि बीमा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, शासन का ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

चौदहवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के अन्तर्गत जेड ए एल आर ऐक्ट के तहत धारा 161 एवं धारा 143 के तहत उक्त लाभ जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई न कर भू-माफियों को अनुचित लाभ पहुँचाने के सम्बन्ध में है, शासन का ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

पंद्रहवीं सूचना श्री राजकुमार रावत की जनपद मथुरा-गोवर्धन में स्थापित रिफाइनरी की स्थापना के समय कतिपय ग्रामों को विकसित करने का निर्धारण होने के पश्चात भी अभी तक विकास कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, शासन का ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं-

1-श्री दलजीत सिंह,

2-श्री मनीष असीजा,

3-श्री पंकज मलिक

4-श्री जियाउद्दीन रिजवी,

5-श्री बाला प्रसाद अवस्थी,

6-श्री मुकेश श्रीवास्तव,

7-श्री गेंदा लाल चौधरी,

8-श्री रामलाल अकेला,

9-श्री प्रदीप माथुर,

10-श्री सुरेश राणा,

11-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल,

12-डा0 धर्म सिंह सैनी,

13-श्री दीपक पटेल,

14-श्री राकेश बाबू एम0एल0ए0,

15-डॉ0 रमेश चन्द्र बिन्द,

16-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या,

17-श्री संजय प्रताप जायसवाल,

18-श्री विजय कुमार पासवान,

19-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

20-श्रीमती विमला सिंह सोलंकी,

21-श्री सुरेश बंसल,

22-श्री आलम बदी,

23-श्री नीरज कुशवाहा,

24-श्री केशव प्रसाद मौर्य,

25-श्री राजनारायण बुधौलिया,

26-श्री वीरपाल राठी,

27-मो0 आसिफ जाफरी,

28-श्री काली चरन सुमन,

29-श्री बृजेश कुमार,

30-श्री मुसर्रत अली बिट्टन,

31-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,

32-ठाकुर दलवीर सिंह, तथा

33-श्री बब्बन सिंह चौहान।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक अनुरोध है अभी हाल ही में 42 कार्यकत्रियों की सेवायें समाप्त कर दी गयी। मान्यवर, 42 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

आपको तो उसके लिये लड़ना ही चाहिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, वह शासनादेश के खिलाफ हुआ। वह 3 बार का शासनादेश है कि 3 बार अनुपस्थित रहने पर होगा यह एक बार में कर दिया। उसे कम से कम वक्तव्य के लिये स्वीकार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय खन्ना जी, आप तो वरिष्ठ हैं जब आप यह सूचना दे देते हैं, यह सूचना की कापी जिले में जाती है यहां स्वीकार हो या न स्वीकार हो जो स्वीकार होता है उसका तो

उत्तर सदन में आ जाता है जो नहीं स्वीकार होता है तो भी कार्यवाही होती है। वह गया होगा आप पता करियेगा शाहजहांपुर में।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इन 42 का शासनादेश के खिलाफ हुआ है।

जनपद फैजाबाद के समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों में वृद्धा पेंशन, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन व चयनित शादी अनुदान के पात्रों को लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

(श्री राम चन्द्र यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

श्री राम चन्द्र यादव उपस्थित हैं। नियम-51 के अन्तर्गत समाज कल्याण मंत्री जी का केवल वक्तव्य है इसमें आप पूछेंगे नहीं। मंत्री जी एक लाइन पढ़ दीजिये।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद फैजाबाद अन्तर्गत सभी तहसीलों की सभी ग्राम पंचायतों में वृद्धा पेंशन, रानी लक्ष्मी बाई पेंशन...

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द सिंह गोप)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)।

श्री अम्बिका चौधरी-

[वर्ष 28-7-2012 को चयनित शादी अनुदान के सभी श्रेणी के पात्रों को शादी अनुदान तथा पारिवारिक लाभ योजना का अनुदान न दिये जाने के कारण लगभग 75 हजार लाभार्थी भुखमरी के कगार पर हैं जबकि इन सभी योजनाओं का धन भी समाज कल्याण विभाग को मिल चुका है। समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद व उप निदेशक, समाज कल्याण,

---

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फैजाबाद द्वारा कहा जा रहा है कि अभी रोक लगी है, आदेश आने पर ही लाभार्थियों को लाभ दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष के मात्र 4 माह ही शेष बचे हैं, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही व उदासीनता के कारण सरकार की इन कल्याणकारी योजनाओं की मंशा पर पानी फिर रहा है। इन योजनाओं के जिम्मेदार अधिकारियों की मिली भगत से पूरे जनपद दलालों का एक बड़ा गिरोह इन गरीब, असहाय लाभार्थियों से अवैध वसूली कर रहा है। जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में उपरोक्त सभी योजनाओं का धन पात्रों को अब तक की अवधि का दिया जा चुका है। पूर्व से चयनित 60954 वृद्धा पेंशन, लगभग 16000 हजार पानी लक्ष्मीबाई पेंशनरों को कार्यालय दौड़ाना, दशहरा, दीपावली जैसे त्यौहारों पर भी पेंशन न देना तथा जनपद की 729 ग्राम पंचायतों में एक भी नई पेंशन की स्वीकृति न देने से जनपद के पात्र लाभार्थियों में भयंकर असंतोष है।

''अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये पात्रों को पेंशन का लाभ तत्काल दिलाये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।''

2-इस सम्बन्ध में अगवत कराना है कि जनपद फैजाबाद में वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत 60954 पेंशनरों को उनके खाते में धनराशि स्थानान्तरित की जा चुकी है।

रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में 14606 पेंशनरों को उनके खाते में धनराशि भेजी जा चुकी है।

अनुसूचित जाति/सामान्य जाति शादी-बीमारी अनुदान योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में दिनांक 28-7-2012 को जनपद स्तरीय की गई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार 503 लाभार्थियों को अनुदान की धनराशि उनके खाते में स्थानान्तरित कराई जा चुकी है। इसी प्रकार सामान्य वर्ग के शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत 161 लाभार्थियों को धनराशि वितरित की जा चुकी है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में 508 लाभार्थियों को धनराशि उनके खाते में स्थानान्तरित की जा चुकी है।]

नोएडा में डिप्टी डायरेक्टर (फैक्ट्रीज) के विरुद्ध जांच कराये जाने एवं उनका स्थानान्तरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री संतोष पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे पूर्वाह्न फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 37 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 20 फरवरी, 2013

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30-31 पर)

उ0 प्र0 मार्ग विकास नीति, 1998 के अनुसार मार्गों के नवीनीकरण हेतु राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग व ग्रामीण मार्ग हेतु क्रमशः 03 वर्ष, 05 वर्ष, 06 वर्ष एवं 08 वर्ष का नवीनीकरण चक्र निर्धारित था। शासनादेश सं0-3720/23-1-2003-16सा0/2003, दिनांक 25.12.03 द्वारा उक्त नवीनीकरण चक्र को संशोाधित कर राज्य मार्ग पर 04 वर्ष में, प्रमुख जिला मार्ग पर 04 वर्ष में, अन्य जिला मार्ग पर ग्रामीण भाग में 05 वर्ष में एवं शहरी भाग में 04 वर्ष में तथा ग्रामीण मार्ग पर 08 वर्ष में नवीनीकरण का कार्य वर्तमान में कराये जाने की व्यवस्था है, परन्तु वास्तविक स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

2-मार्गों पर पैच मरम्मत का कार्य पूरे वर्ष आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। क्षतिग्रस्त मार्गों के सुद्ढ़ीकरण हेतु यातायात के अनुसार क्रस्ट डिजाइन करते हुए आवश्यकता आंकलित की जाती है तथा वित्तीय संसाधनों के अनुसार सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाता है। वर्ष 2012-13 में राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्गों की लगभग 12227 किमी0 लम्बाई में नवीनीकरण हेतु रुपये 977.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिसके सापेक्ष अब तक 10175 किमी0 लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त अब तक 21841 किमी0 राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग तथा 21402 किमी0 ग्रामीण मार्ग गड्ढ़ामुक्त किये गये हैं।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर)

बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाली नहरों की सूचना वर्ष 2000 से अगस्त, 2012 तक

नहर का नाम	बीसलपुर विधान सभा में पड़ने वाली एवं संबन्धित कि0मी0		कुल कि0मी0	वर्ष 2000–2001				वर्ष 2001–2002				वर्ष 2002–2003				वर्ष 2003–2004				वर्ष 2004–2005			
	कहाँ से	कहाँ तक	कुल लम्बाई	कहाँ से	कहाँ तक	कुल किमी0	धनराशि	कहाँ से	कहाँ तक	कुल किमी0	धनराशि	कहाँ से	कहाँ तक	कुल किमी0	धनराशि	कहाँ से	कहाँ तक	कुल किमी0	धनराशि	कहाँ से	कहाँ तक	कुल किमी0	धनराशि
बीसलपुर शाखा	59.00	74.02	15.02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
भिढौरा राजवाह	24.00	29.65	5.65	20.00	29.65	9.65	46144	24.00	29.65	5.65	69356	–	–	–	–	24.00	29.65	5.65	144764	24.00	29.65	5.65	36988
टिकरी राजवाह	1.600	5.97	4.37	0.00	4.800	4.800	11663	–	–	–	–	1.600	5.47	4.37	50.891	11600	5.97	4.37	74526	1.60	5.97	4.37	44716
शेरगंज माइनर	0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	2.90	15806	0.00	2.90	2.90	19358	–	–	–	–	0.00	2.90	2.90	13780	0.00	2.90	2.90	14939
परासी माइनर	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	18062	0.00	5.00	5.00	16024	0.00	5.00	5.00	3844	0.00	5.00	5.00	27667	0.00	5.00	5.00	51136
कनगवा माइनर	0.00	3.05	3.05	0.00	3.05	3.06	41683	0.00	1.00	1.00	11464	0.00	–	–	–	0.00	3.05	3.05	47305	0.00	3.05	3.05	29843
सावेपुर राजवाह	0.00	9.94	9.94	0.00	9.94	9.94	44204	0.00	9.44	9.94	72713	0.00	9.94	9.94	4171	0.00	9.94	9.44	104475	0.00	9.94	9.94	114865
जसोली माइनर	0.00	2.22	2.22	0.00	2.22	2.22	11176	0.00	2.22	2.22	12573	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00	2.22	2.22	26738

भोगापुर माइनर	0.00	4.70	4.70	0.00	4.70	4.70	18381	0.00	4.70	4.70	36944	–	–	–	–	0.00	4.70	4.70	33785	0.00	4.70	4.70	64290
गोवल राजवाह	0.00	11.40	11.40	0.00	11.40	11.40	166491	0.00	11.40	11.40	31074	0.00	11.40	11.40	9529	0.00	11.40	11.40	88194	0.00	11.40	11.40	143056
लौनी माइनर	0.00	7.75	7.75	0.00	4.00	4.00	40581	0.00	7.75	7.75	56624	–	–	–	–	0.00	7.75	7.75	47288	0.00	7.75	7.75	64245
खरगापुर माइनर	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	11305	0.00	3.00	3.00	16172	0.00	3.00	3.00	9851	0.00	3.00	3.00	13015	0.00	3.00	3.00	35013
शिवपुरी माइनर	0.00	5.74	5.74	0.00	5.74	5.74	42884	0.00	5.74	5.74	28817	–	–	–	–	0.00	5.74	5.74	35465	0.00	5.74	5.74	82994
तनीपुर माइनर	0.50	10.17	9.67	0.00	10.17	10.17	57934	0.50	10.17	9.67	64558	–	–	–	–	0.50	10.17	9.67	15508	0.50	10.17	9.67	32162
कोकिला माइनर	3.600	8.20	4.60	4.200	5.200	1.00	9407	4.40	5.80	1.40	16672	3.60	8.20	4.60	26869	3.60	8.20	4.60	44489	3.60	8.20	4.60	41426

बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाली नहरों की सूचना वर्ष 2000 से अगस्त, 2012

वर्ष 2000 से अगस्त, 2012 तक

नहर का नाम	बीसलपुर विधान सभा में पड़ने वाली नहरें एवं संबन्धित किमी0		कुल किमी0	वर्ष 2005–2006				वर्ष 2006–2007				वर्ष 2007–2008				वर्ष 2008–2009				वर्ष 2009–2010			
	कहाँ से	कहाँ तक	कुल लम्बाई	कहाँ से	कहाँ तक	कुल किमी	धनराशि	कहाँ से	कहाँ तक	कुल किमी	धनराशि	कहाँ से	कहाँ तक	कुल किमी	धनराशि	कहाँ से	कहाँ तक	कुल किमी	धनराशि	कहाँ से	कहाँ तक	कुल किमी	धनराशि
बीसलपुर शाखा	50.00	74.02	15.02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
भिढौरा राजवाह	24.00	29.65	5.65	24.00	29.65	5.65	78715	21.00	29.65	8.65	164064	20.00	29.65	9.65	190640	20.100	29.65	9.55	196036	-	-	–	–
टिकरी राजवाह	1.600	5.97	4.37	0.00	5.00	5.00	84139	0.00	5.97	5.97	103034	0.00	5.97	5.97	107733	0.00	5.97	5.97	124547	.600	5.97	4.37	(मनरेगा) 50800
शेरगंज माइनर	0.00	2.90	2.90	–	–´	–´	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00	2.90	2.90	मनरेगा 28000	0.00	2.90	2.90	मनरेगा 31000
परासी माइनर	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	45000	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00	5.00	5.00	मनरेगा 70400	0.00	5.00	5.00	मनरेगा 43000
कनगंवा माइनर	0.00	3.05	3.05	0.00	2.22	2.22	49100	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00	3.05	3.05	मनरेगा 38000	0.00	3.05	3.05	मनरेगा 40900
सावेपुर राजवाह	0.00	9.94	9.94	–	–	–	–	0.00	9.94	9.94	164125	0.00	9.94	9.94	164125	0.00	9.94	9.94	188148	-	-	–	–

जसोली माइनर	0.00	2.22	2.22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00	2.22	2.22	मनरेगा 20900	.00	.22	2.22	मनरेगा 23900
भोगापुर माइनर	0.00	4.70	4.70	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00	4.70	4.70	50000	0.00	4.70	4.70	मनरेगा 35700	.00	.70	4.70	45100
गोवल राजवाह	0.00	11.40	11.40	–	–	–	–	0.00	11.40	11.40	180718	0.00	11.40	11.40	178106	0.00	11.40	11.40	197397	–	–	–	–
बौनी माइनर	0.00	7.75	7.75	0.00	5.00	4.00	67035	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00	7.75	7.75	मनरेगा 30200	.00	.75	7.75	मनरेगा 57800
खरगापुर माइनर	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00		–	–	–	–	–	–	–	–	0.00	3.00	3.00	मनरेगा 9500	.00	.00	3.00	मनरेगा 23000
शिवपुरी माइनर	0.00	5.74	5.74	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00	5.74	5.74	54633	0.00	5.74	5.74	मनरेगा 22500	.00	.74	5.74	मनरेगा 27200
बेनीपुर माइनर	0.50	10.17	9.67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.50	10.17	9.67	मनरेगा 54700	–	–	–	–
कोकिला माइनर	3.60	8.20	4.60	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00	8.20	8.20	100000	–	–	–	–	.60	.20	4.60	मनरेगा 40100

बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाली नहरों की सूचना वर्ष 2000 से अगस्त, 2012

वर्ष 2000 से अगस्त, 2012 तक

नहर का नाम	बीसलपुर विधान सभा में पड़ने वाली नहरें एवं संबन्धित किमी0		कुल किमी0	वर्ष 2010–2011				वर्ष 2011–2012				अगस्त, 2012 तक			
	कहाँ से	कहाँ तक	कुल लम्बाई	कहाँ से	कहाँ तक	कुल किमी	धनराशि	कहाँ से	कहाँ तक	कुल किमी0	धनराशि	कहाँ से	कहाँ तक	कुल किमी0	धनराशि
बीसलपुर शाखा	59.00	74.02	15.02	–	–	–	–	–	–	–	–	60.500 63.945	62.00 66.500	1.45 1.55	365719 388290
भिढौरा राजवाह	24.00	29.65	5.65	20.00	29.65	9.65	264000	–	–	–	–	20.00	29.65	9.65	198000
टिकरी राजवाह	1.600	5.97	4.37	0.00	3.00	3.00	81000	0.00	3.00	3.00	115800	–	–	–	–
शेरगंज माइनर	0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	2.90	मनरेगा 34200	0.00	2.90	2.90	मनरेगा 41280	–	–	–	–
परासी माइनर	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	मनरेगा 63000	0.00	5.00	5.00	मनरेगा 50040	–	–	–	–
कनगवा माइनर	0.00	3.05	3.05	0.00	3.05	3.05	मनरेगा 43000	0.00	3.05	3.05	मनरेगा 53520	–	–	–	–
सावेपुर राजवाह	0.00	9.94	9.94	–	–	–	–	0.00	9.94	9.94	246000	–	–	–	–
जसोली माइनर	0.00	2.22	2.22	0.00	2.22	2.22	मनरेगा 26100	0.00	2.22	2.22	मनरेगा 32160	–	–	–	–
भोगापुर माइनर	0.00	4.70	4.70	0.00	4.70	4.70	मनरेगा 50000	0.00	4.70	4.70	मनरेगा 61900	–	–	–	–
गोवल राजवाह	0.00	11.40	11.40	–	–	–	–	1.00	4.200	3.200	मनरेगा 83400	4.200	11.400	7.200	94250

बौनी माइनर	0.00	7.75	7.75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
खरगापुर माइनर	0.00	5.74	5.74	–	–	–	–	0.00	3.00	3.00	मनरेगा 23280	–	–	–	–
शिवपुरी माइनर	0.00	5.74	5.74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बेनीपुर माइनर	0.50	10.17	9.67	–	–	–	–	0.00	6.00	6.00	मनरेगा 77400	–	–	–	–
कोकिला माइनर	3.600	8.200	4.600	3.600	8.200	4.60	मनरेगा 105500	2.00	8.200	6.200	मनरेगा 89160	–	–	–	–

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 21 विधान सभा (49)-15-5-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।